

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



नवंबर 2020

खंड 74 अंक 11

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
देब प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
एस. गंगाधरन

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

एनबीएफसी विनियमन – भविष्य पर विचार एम. राजेश्वर राव	1
--	---

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	7
भारत का आर्थिक गतिविधि सूचकांक	23
हाउसहोल्ड वित्तीय बचतों के प्रारंभिक अनुमान – 2020-21 की पहली तिमाही	33
भारत में टर्म प्रीमियम के निर्धारकों का पुनरावलोकन	41
भारत का गिल्ट बाज़ार	51
लाइबोर: अभ्युदय और अंत	65
फिनटेक: रचनात्मक बदलाव की ताकत	75
वर्तमान सांख्यिकी	95
हाल के प्रकाशन	141

भाषण

एनबीएफसी विनियमन – भविष्य पर विचार
एम. राजेश्वर राव

एनबीएफसी विनियमन – भविष्य पर विचार *

एम. राजेश्वर राव

डॉ. चरण सिंह, श्री दीपक सूद, श्री रमेश अय्यर, श्री विनीत अग्रवाल, श्री एस रमन, श्री सुनील कनोरिया, श्री रमन अग्रवाल, देवियो और सज्जनो,

"वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और निरंतरता" के थीम पर गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों पर राष्ट्रीय ई-शिखर सम्मेलन को संबोधित करने हेतु एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एशोचैम) के इस उदार आमंत्रण के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।

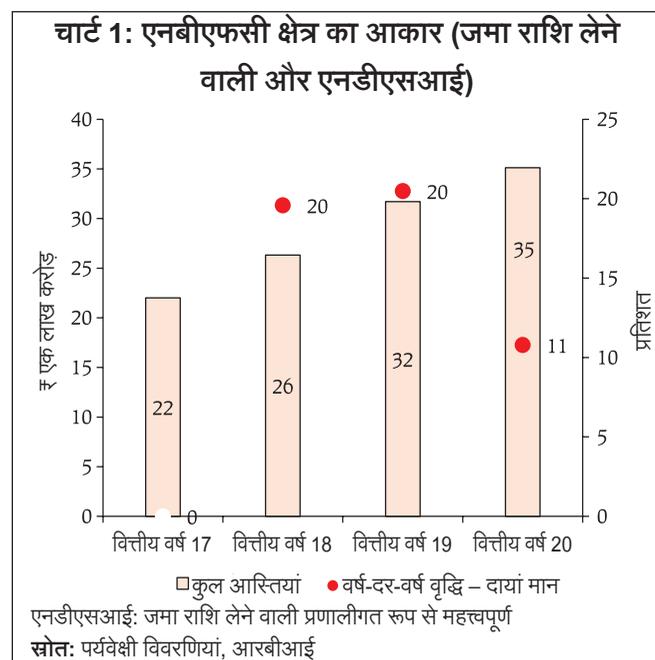
इस समय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। हाल में कुछ बड़े एनबीएफसी की विफलताएं, क्षेत्र में तरलता (चलनिधी) का घोर दबाव और इसके चलते होने वाली वित्तीय स्थिरता की चिंताओं ने एनबीएफसी विनियमों पर ध्यान खींचा है। मैंने महसूस किया कि एनबीएफसी सेक्टर में हो रहे नवोन्मेषी परिवर्तनों और रिजर्व बैंक की विनियामक प्रतिक्रिया पर कुछ चर्चा का यह उपयुक्त समय है। विनियामक ध्यान की दिशा और भविष्य में एनबीएफसी विनियमों के संभावित आकार का जायजा लेना प्रासंगिक होगा। इस विश्लेषण का उद्देश्य विषय पर चर्चा और बहस को उद्बलित करना है।

एनबीएफसी क्षेत्र की वृद्धि और विवेक की आवश्यकता

अपने आकार व संचालन की विविधता की दृष्टि से एनबीएफसी ने एक लंबी यात्रा तय की है। वे अब बैंकों से अल्पतर-सेवित ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में वित्तीय सेवाओं को आखिरी मील तक उपलब्ध कराके वित्तीय मध्यस्थता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में

अहम भूमिका निभाते हैं। विगत वर्षों में, यह वर्ग तेजी से बढ़ा है, और कुछेक बड़े एनबीएफसी आकार में कतिपय प्राइवेट सेक्टर बैंकों के बराबर हो गए हैं। इस क्षेत्र में कई गैर-पारंपरिक खिलाड़ियों का प्रवेश भी हुआ है जो तकनीक आधारित नवोन्मेषी कारोबारी मॉडल अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं।

31 मार्च, 2009 और 31 मार्च, 2019 के बीच, एनबीएफसी की कुल आस्तियां 18.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि (कम्पाउंडेड) वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ीं, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की बैलेंस शीट 10.7 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ीं। नतीजतन, एनबीएफसी की समग्र बैलेंस शीट का आकार इसी अवधि के दौरान एससीबी की समग्र बैलेंस शीट आकार के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 18.6 प्रतिशत हो गया। निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ (एबसोल्यूट टर्म्स) में, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार एनबीएफसीसेक्टर [हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज (एचएफसी) सहित] का एसेट साइज (आस्ति आकार) ₹51.47 लाख करोड़³ है। मार्च 2020 के अंत में, वित्तीय



² भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति (2010 और 2019)

³ एनबीएफसीज की एसेट साइज (जमा राशि लेने वाली, एनडीएसआई, नॉन-एनडीएसआई) - ₹37,38,162 करोड़। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) का आस्ति आकार (एसेट साइज) - ₹14.09 लाख करोड़।

⁴ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई, जुलाई 2020।

* श्री एम राजेश्वर राव, उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। एसोचैम द्वारा 6 नवंबर, 2020 को आयोजित 'नेशनल ई-समिट ऑन नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज' में दिया गया भाषण। मनोरंजन मिश्र, श्री चंदन कुमार और श्री प्रदीप कुमार से प्राप्त इनपुट के लिए आभार।

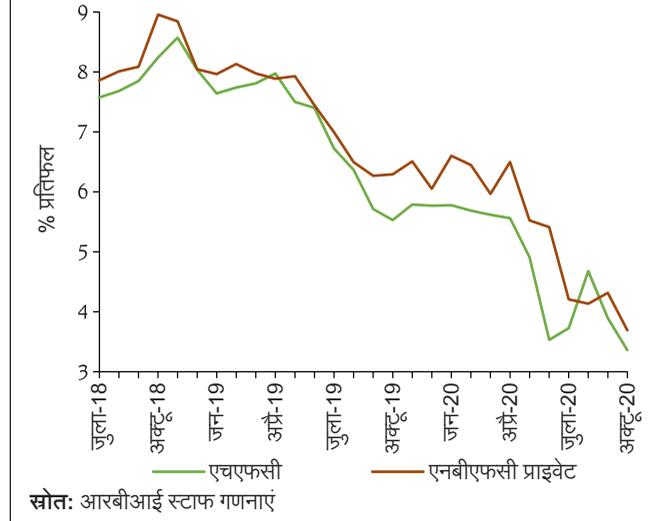
प्रणाली⁴ से निधियों के सबसे बड़े निवल उधारकर्ता एनबीएफसी रहे हैं, जिनमें से आधी से अधिक निधियां एससीबी से थीं, जिसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनियां-म्युचुअल फंड्स (एएमसी-एमएफ) और बीमा कंपनियां थीं। जैसे-जैसे वित्तीय मध्यस्थता बदली है, वैसे-वैसे अंतरसंबद्धता बढ़ी है। कई एनबीएफसी अब धन और आपातकालीन तरलता /चलनिधि (लिक्विडिटी) जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर हैं। इसलिए, केवल बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियों को समझना और उनसे निपटना काफी नहीं। इस समय जरूरत है एनबीएफसी क्षेत्र की कमजोरियों समझने की और यह जानने की कि आघात कैसे या इस क्षेत्र से या की ओर संचरित होते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार और अन्य वित्तीय क्षेत्र संस्थाओं के साथ इस क्षेत्र की अंतरसंबद्धताएं बैलेंस शीट के दोनों ओर हैं ओर उत्तरोत्तर जटिल। वैसे भी, वित्तीय बाजारों और हमारे जीवन पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव के पहले से ही अन्य वित्तीय मध्यस्थों की तरह एनबीएफसी भी प्रतिपक्ष, वित्त पोषण, बाजार और आस्ति संकेंद्रण जोखिमों के प्रति अधिकाधिक एक्सपोज्ड हैं।

महामारी का प्रभाव

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएफएचएल) की घटनाओं के बाद तरलता दबाव (लिक्विडिटी स्ट्रेस) के कारण, एनबीएफसी के लिए बाजार फंडिंग की स्थितियां मुश्किल हो गईं। अभिशासन के बेहतर मानकों और काम-काज के बेहतर तौर-तरीकों वाली एनबीएफसी जहाँ ठीक चलीं वहीं दूसरों को बाजार का प्रकोप झेलना पड़ा। छोटे एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थान /माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई), जो आखिरी मील तक तक क्रेडिट वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, वे भी प्रभावित हुए क्योंकि उनके धन (फंडिंग) के स्रोत सूख गए। रिज़र्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति और चलनिधि उपायों द्वारा फंडिंग और लिक्विडिटी की उपलब्धता में सुधार करने के लिए तेजी और अग्रसक्रियता से काम किया और इसके परिणामस्वरूप, सभी

चार्ट 2: फंडिंग लागत: 3-माह वाणिज्यिक पत्र (सीपी) भारत औसत प्रतिफल



रेटिंग श्रेणियों के लिए एनबीएफसी और एचएफसी के लिए धन की लागत काफी कम हो गई है (चार्ट-2)।

यह समझना अहम है कि कुछ एनबीएफसी जो चुनौतियां झेल रही हैं, वे उनकी अंतर्निहित कमजोरियों के चलते हैं। जैसे-जैसे वित्तीय बाजारों ने मजबूत / सुप्रबंधित और स्पष्ट: कमजोरियों से ग्रसित एनबीएफसी के बीच अंतर करना शुरू किया, बाजार अनुशासन का प्रभाव दिखने लगा - आस्ति-देयता विसंगति या आस्ति गुणवत्ता की समस्या वाली इकाइयों को बाजार तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। यह देखते हुए रिज़र्व बैंक ने, एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण प्रवाह लाने और क्षेत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता में सुधार के लिए कई नपे-तुले कदम उठाए।

सारणी 1: एनबीएफसी क्षेत्र (जमाराशि लेने वाली और एनडीएसआई) की लाभप्रदता

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभप्रदता मानक	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020
निवल लाभ (₹ करोड़)	31,923	42,434	17,460	41,257
वार्षिकीकृत आरओए (%)	1.5	1.6	0.6	1.2
वार्षिकीकृत आरओई (%)	6.3	6.8	2.4	5.1

टिप्पणी: आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओई)।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई

यह क्षेत्र जब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा था (जैसा कि नीचे दी गई सारणी (टेबल) -1 से देखा जा सकता है), कोविड -19 का प्रकोप और लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान के कारण वित्तीय प्रणाली में भारी दबाव बना। पूरी वित्तीय प्रणाली प्रभावित हुई थी, एनबीएफसी के अंतर्निहित व्यापार मॉडल के कारण उन पर असर अधिक हुआ, और उनकी लाभप्रदता पर बोझ पड़ा।

विनियामक दृष्टिकोण

एनबीएफसी क्षेत्रके अंतर्गत आने वाली इकाइयों की बढ़ती जटिलता और वित्तीय क्षेत्र में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व के अनुसार रिज़र्व बैंक ने अपने विनियामक दृष्टिकोणको ढाला है। तथापि एनबीएफसी विनियम के मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात् ए) जमाकर्ताओं (जमा-स्वीकार करने वाली कंपनियों के मामले में) और ग्राहकों की सुरक्षा ; और बी) वित्तीय स्थिरता का संरक्षण। अलग-अलग समय पर इन उद्देश्यों के महत्व में परिवर्तन को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने अलग-अलग नीतिगत साधनों का प्रयोग किया है। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि हाल के वर्षों में एनबीएफसी विनियमन में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं।

इनमें से पाँच सबसे महत्वपूर्ण बदलावों की संक्षिप्त जानकारी दे दूँ

- (i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, स्वामित्व-तटस्थ नियमों को प्राथमिकता देने के रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार के स्वामित्व वाले एनबीएफसी मई 2018 से विवेकपूर्ण नियमन के दायरे में लाए गए हैं। यह देखते हुए कि पूरे एनबीएफसी क्षेत्र का एक तिहाई से अधिक सरकारी स्वामित्व वाला है, मुख्यतः बुनियादी ढांचे की फाइनेंसिंग में, यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
- (ii) दूसरा, तरलता (चलनीधि/लिक्विडिटी) दबाव के कारण कुछ एनबीएफसी द्वारा हाल में झेले गए उथल-पुथल को देखते हुए, ₹100 करोड़ से ऊपर की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी के लिए चलनिधि (तरलता) जोखिम प्रबंधन ढाँचा (फ्रेमवर्क) लागू कर एनबीएफसी

द्वारा तरलता जोखिम के अच्छे प्रबंधन के महत्व पर बल दिया गया है। सभी एनबीएफसी, चाहे वे किसी भी आकार के हों, इस फ्रेमवर्क को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। दिशा-निर्देशों में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा प्रकाशित 'अच्छे चलनिधि (तरलता) जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांतों' पर जोर दिया गया है। ढाँचे में एनबीएफसी के बोर्ड्स से प्रत्याशित है कि तरलता जोखिम के प्रबंधन में एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे और अपने व्यावसायिक स्वरूप के लायक आंतरिक निगरानी के साधनों की व्यवस्था करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विनियमों ने बड़े एनबीएफसी के लिए सरलीकृत और उनके अनुरूप चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाया है। इसकी सहायता से बड़े एनबीएफसी 30 दिनों तक की अवधि के गंभीर चलनिधि दबाव वाले परिदृश्यों में भी नकदी के बहिर्गमन (ऑउटफ्लो) से प्रभावी ढंग से निपट सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (लिक्विड एसेट्स) बनाए रखने का एनबीएफसी के समग्र प्रतिफल पर असर होगा, लेकिन परिपक्वता / चलनिधि परिवर्तन के जो कार्य एनबीएफसी करते हैं, यह विनियमन उनसे संबंधित जोखिमों को कम करने की आवश्यकता के अनुरूप है।

- (iii) तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम फिनटेक आधारित उत्पादों की डिलीवरी से जुड़ा है। अब यह व्यापक मान्यता है कि बैंकेतर वित्तीय क्षेत्र वित्तीय उत्पादों व सेवाओं में प्रयोग की उपजाऊ भूमि होगी। विनियमों ने इस दिशा में सहायक परिवेश बनाने की कोशिश की है उदाहरण के लिए, समकक्षीय उधार माध्यमों (पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) संबंधी दिशा-निर्देशों के समय से लाए जाने से इस वर्ग का सुव्यवस्थित विकास हो पाया जो विवेक के उच्च मानकों से संचालित है। विनियमों ने जोखिम कम किए हैं और व्यसाय के अवसरों के वैध विस्तार हेतु उपयुक्त माहौल बनाया है। खाता समूहक (एए) के अंतर्गत बनाया गया परितंत्र तकनीक-आधारित गतिविधियों

में अग्रसक्रिय विनियमन का एक और उदाहरण है। एए फ्रेमवर्क से ग्राहक की वित्तीय आस्तियों संबंधी सूचना के संरक्षित, सुरक्षित ढंग से और सहमति से शेयर किए जाने हेतु अपेक्षित फ्रेमवर्क शुरुआत हुई है। यहाँ ध्यान देने योग्य विनियामक पक्ष यह है कि खाता समूहक अपने यहाँ से गुजर रहे डेटा को स्टोर नहीं करता और न ही देखता है जिससे वित्तीय डेटा के कुप्रयोग/दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं होती। मैं यह भी रेखांकित करना चाहूँगा कि पंजीकृत एनबीएफसी को वित्तीय मध्यस्थता में पूर्णतः ऐप-आधारित होने की अनमति देने में रिज़र्व बैंक का रुख लचीला रहा है।

- (iv) रिज़र्व बैंक ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (सीआईसी) के लिए आनुपातिकता के सिद्धांतों के तहत नियामक ढांचे को संशोधित किया जिसमें संशोधित पारदर्शिता व खुलासों पर ध्यान दिया गया है। एक बड़ी एनबीएफसी - एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की विफलता से मिला सबक इस विनियामक नवीनीकरण का कारण बना। समूह स्तर पर बड़े समग्र लीवरेज और जटिल, बहुस्तरीय स्वामित्व वाली संरचनाएं वित्तीय अस्थिरता और कमजोरी के बीजों का पोषण करती पाई गई। इसके अलावा, होल्डिंग कंपनी स्तर पर जोखिम का समग्र दृष्टिकोण नहीं था। संशोधित नियामक ढांचा सीआईसी से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विनियामक अंतराल को पाटने की कोशिश करता है।
- (v) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन को हाथ में लेना और एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद एचएफसी के नियामक ढांचे में परिवर्तन जारी किए गए हैं। विचार है कि एचएफसी को एनबीएफसी की एक श्रेणी माना जाए और एचएफसी को अपनी विशिष्ट विशेषताएं बनाए रखने देते हुए विनियमों का सामंजस्य स्थापित किया जाए और संशोधित विनियमों की ओर उनको क्रमिक रूप से इस तरह बढ़ने दिया जाए जो शेष वित्तीय क्षेत्र के लिए कम से कम उथल-पुथल वाला हो।

आकार और अंतर्संबद्धता बढ़ने के साथ, एनबीएफसी तेजी से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं और वित्तीय स्थिरता

पर अधिक ध्यान देने के लिए एनबीएफसी क्षेत्र के विवेकपूर्ण नियम विकसित हुए हैं। तथापि, हम यह न भूलें कि अल्प-विनियमन-संरचना के चलते एनबीएफसी को लचीलेपन का लाभ मिला है। प्राथमिक रूप से यह लचीलापन बैंकों के मुकाबले एनबीएफसी को तुलनात्मक लाभ देता है, जिससे वे वित्तीय मध्यस्थता के अंतिम मील की सेवा कर पाते हैं। इसलिए, एनबीएफसी को अधिक सख्ती से विनियमित करने और उन्हें अपेक्षित लचीलापन देने की आवश्यकता के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। जब हम एनबीएफसी हेतु विनियमन के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो यह उसका आधार रहेगा।

भविष्य

आनुपातिकता सिद्धांत

एक दृष्टिकोण यह है कि आदर्शतः कोई भी विनियामक ढाँचा आनुपातिकता के सिद्धांत पर बनाया जाएगा। तदनुसार, वित्तीय स्थिरता पर स्पष्ट प्रभाव डाल सकने वाले प्रणालीगत रूपसे महत्वपूर्ण एनबीएफसी से फैलने वाले जोखिम का निपटान भी तदनुसार होना चाहिए। अतः, महत्वपूर्ण बाह्य प्रभाव वाले एनबीएफसी, जिनका प्रणालीगत जोखिम में बड़ा योगदान है, की पहचान और उन पर उच्चतर स्तर का विनियमन आवश्यक है। कोई यह भी तर्क दे सकता है कि ऐसे एनबीएफसी हेतु विवेकसम्मत विनियामक ढाँचा बैंकों के तुल्य हो ताकि प्रणालीगत जोखिम की गंभीरता की एक हद के बाद ये एनबीएफसी वाणिज्य बैंकों में बदलने को प्रेरित हों अथवा वित्तीय व्यवस्था में अपने बाह्य प्रसार को घटाएं। इससे वित्तीय व्यवस्था स्वस्थ व सुदृढ़ बनेगी साथ ही, अधिकांश एनबीएफसी अल्प-विनियमन संरचना के तहत बनी रह सकेगी।

आनुपातिकता सिद्धांत के अंतर्गत उन इकाइयों पर ध्यान आवश्यक है जो प्रणालीगत रूप से न बेहद अहम हैं और न ही अपने आकार व जटिलता में बहुत छोटी हैं। बैंकों की तुलना में ये एनबीएफसी वर्तमान में विनियामक अंतरपणन का लाभ काफी अधिक ले रही हैं। विनियामक अंतरपणन के कारण समूह के रूप में, प्रणालीगत जोखिम को बढ़ाने में इन इकाइयों का हाथ है; इसलिए विनियमों को तदनुसार फिर से समायोजित करने की आवश्यकता है।

आनुपातिकता सिद्धांत की चर्चा में, मैं माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के विनियमन का भी उल्लेख करना चाहूँगा। हम सभी उन परिस्थितियों से अवगत हैं जिनके तहत एनबीएफसी-एफएमआई के लिए नियामक ढांचा तैयार किया गया था। तब से काफी समय बीत चुका। कई बड़े एमएफआई लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित हो गए हैं। समग्र माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में एनबीएफसी-एफएमआई की हिस्सेदारी घटकर 30 प्रतिशत से कुछ अधिक हो गई है। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जहाँ विनियामक कठोरता केवल माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के एक छोटे हिस्से पर लागू है। माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में विनियामक साधनों को फिर से प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि हमारे नियम इकाई-आधारित होने के बजाय गतिविधि-आधारित हों। आखिरकार, माइक्रोफाइनेंस विनियमन का मूल ग्राहक / उपभोक्ता संरक्षण में निहित है।

हमें विनियमन की हद और लचीलेपन के बीच सही संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है - एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। एनबीएफसी के लिए संभवतः हम एक क्रमिक विनियामक ढाँचे पर विचार कर सकते हैं जो प्रणालीगत महत्ता में उनके योगदान के अनुसार निर्धारित हो।

फिनटेक का विनियमन

अब मैं समकालीन रुचि के किसी अन्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। यद्यपि फिनटेक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक कदम पहले ही उठाए गए हैं, लेकिन फिनटेक केंद्रित एनबीएफसी की गतिशील प्रकृति नई चुनौतियाँ लाती रहती है। एनबीएफसी क्षेत्र फिनटेक-प्रदत्त अभिनव उत्पादों और सेवाओं को अपनाने में सबसे आगे रहा है, जो इन सेवाओं की उपलब्धता और इनसे आदान-प्रदान के बारे में सोच को बदल रहे हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उन्नत तकनीकी समाधान को खिलाड़ी बड़ी संख्या में अपना रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुशल तरीके से ऋण (क्रेडिट) उपलब्ध करा रहे हैं। नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास हेतु समर्थकारी परिवेश बनाने में रिजर्व बैंक सबसे आगे रहा है। वास्तव में, नॉन-बैंकिंग दुनिया में, रिजर्व बैंक औरों से आगे रहा है और उद्योग की शैशवावस्था

में ही उत्पादों और सेवाओं के नियम लेकर आया है। समकक्षी उधार (पीयर टू पीयर लेंडिंग), अकाउंट एग्रीगेटर और “केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म” पर ऋण मध्यस्थता इस संदर्भ के दृष्टांत हैं जहाँ नियमों ने उद्योग को व्यवस्थित और मजबूत तरीके से बढ़ने में मदद की है। फिनटेक क्षेत्र में भविष्य के नियम बनाते समय, व्यवस्थित वृद्धि व ग्राहक सुरक्षा और डेटा सुरक्षा रिजर्व बैंक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बने रहेंगे।

पारदर्शिता और अच्छा अभिशासन सुनिश्चित करना

अच्छा अभिशासन सुनिश्चित करना किसी भी विनियामक परिवर्तन का मूल है। यह उद्देश्य आसान नहीं है, क्योंकि अच्छा अभिशासन तत्त्वतः एक आकांक्षामूलक उपलब्धि है और केवल विनियामकीय निर्देशों के आधार पर शायद ही इसे स्थापित किया जा सके। प्रमोटर/स्वामी व वरिष्ठ प्रबंधन यदि मूलतः ‘योग्य एवं उपयुक्त’ हों तो अच्छा अभिशासन उसकी स्वाभाविक परिणति होगी। ऐसी फिल्टरिंग व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है जो केवल खरे और सक्षम प्रमोटरों को ही एनबीएफसी का कारोबार शुरू करने दे। आखिर, नई एनबीएफसी को पंजीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) जारीकर हम उन्हें जनता के पैसे तक पहुँचाने का अधिकार-पत्र देते हैं जो उनकी निवल मालियत का कई गुना होता है। साथ ही, यह आवश्यक है कि एनबीएफसी के रास्ते किसी भी तरह धन-शोधन और आतंक का वित्तपोषण न होने पाए। रिजर्व बैंक की वर्तमान व्यवस्था में उपर्युक्त उद्देश्य पर उन कंपनियों के मामले में तो ध्यान दिया जाता है जो रजिस्ट्रेशन चाहती हैं, ऐसी ही सख्ती व अपेक्षित सावधानी उन मामलों में भी जरूरी है जब कभी मौजूदा एनबीएफसी के स्वामित्व/नियंत्रण में कोई परिवर्तन हो।

उपभोक्ता संरक्षण व उचित आचरण

बैंक हो या एनबीएफसी, किसी भी विनियमित इकाई की सेवाओं का उपभोक्ता उचित व्यवहार एवं शिकायत निवारण के मार्गों के बारे में एक जैसी प्रत्याशा रखता है। लोकपाल योजना को बढ़ाकर एनबीएफसी क्षेत्र तक ले जाने का कदम इसी दिशा में है। भविष्य के लिए एक पारदर्शी व आत्मानुशासी तंत्र के बारे में सोचना होगा जहाँ करोबार के बदलते मॉडल और ऋण उपलब्ध

कराने की व्यवस्थाएं ग्राहक के प्रति उचित व्यवहार के मार्ग से विचलित न हों।

निष्कर्ष

वैश्विक वित्तीय संकट का कारण मुख्यतः हल्के विनियामकीय दृष्टिकोण को माना गया था जिसमें अबाध वित्तीय नवाचार और वित्तीय मध्यस्थों द्वारा चलनिधि जोखिमों को अनदेखा किया गया। प्रचुर चलनिधि, हल्के विनियमन और वित्तीय नवाचार ने एनबीएफसी के बढ़ने में भी मदद की है। एक दशक से भी पहले वित्तीय संकट की शुरुआत की तुलना में आज की वित्तीय प्रणाली काफ़ी अलग है। उस संकट पर कार्रवाई के रूप में भारत में लागू किए गए विनियामक सुधार, तकनीक में परिवर्तन और, इससे भी अहम, एनबीएफसी के विकास ने इस गतिमान परिदृश्य में योगदान दिया है। एनबीएफसी क्षेत्र अत्यंत विविध हो गया है। एनबीएफसी की श्रेणी के अनुसार, कारोबार के मॉडल, ग्राहक व वित्तीय उत्पादों के स्वरूप में बहुत विभिन्नता होती है। विभिन्न एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की अंतर्निहित विविधता में इस क्षेत्र की विशिष्टता है और विनियामकीय कसौटी में सबके लिए एक ही मानदंड नहीं हो सकता। इकाइयों की प्रणालीगत

महत्ता के अनुपात में संभवतः एक नपा-तुला व क्रमिक विनियामक ढाँचा ही इसका उपाय है।

तकनीकी नवाचार तथा फिन-टेक के आधार पर वित्तीय सेवाओं व उत्पादों के दिए जाने से एक ओर जहाँ सामान्य जनता के लिए वित्तीय उत्पाद की बेहतर उपलब्धता का उद्देश्य आगे बढ़ता है, वहीं विनियामक पर यह दबाव पड़ता है कि विनियामकीय हस्तक्षेप का तदनुसार नपा-तुला पुनर्निर्धारण किया जाए ताकि उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य प्राप्त हो। इन पृथक व कभी-कभी विरोधी लक्ष्यों का तालमेल बिठाने में विनियामक के लिए चुनौतियां कई हैं, तथापि उद्देश्य की स्पष्टता सही नीतिगत निर्णय लेने में हमारी सहायता करेगी।

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि महामारी के विरुद्ध इस लंबी लड़ाई में आप और आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहें। आपको खुशियों भरी और सुरक्षित दीपावली की भी शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत का आर्थिक गतिविधि सूचकांक

हाउसहोल्ड वित्तीय बचतों के प्रारंभिक अनुमान –
2020-21 की पहली तिमाही

भारत में टर्म प्रीमियम के निर्धारकों का पुनरावलोकन

भारत का गिल्ट बाज़ार

लाइबोर: अभ्युदय और अंत

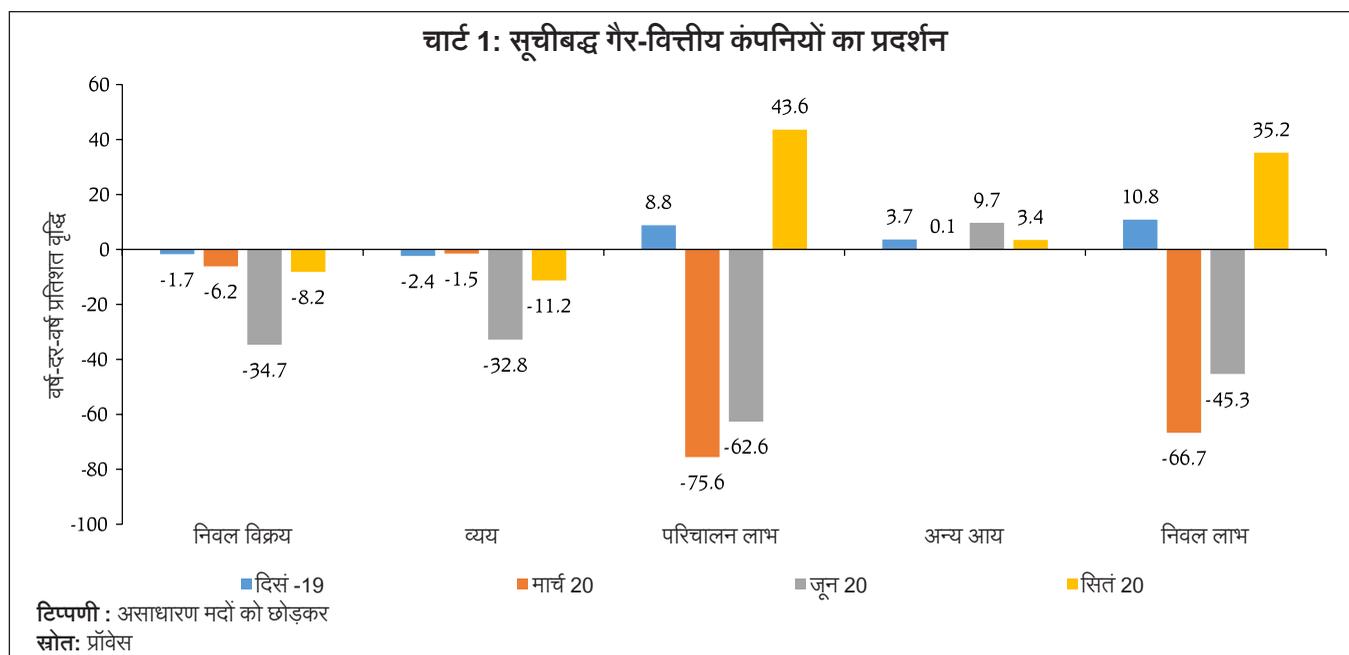
फिनटेक: रचनात्मक बदलाव की ताकत

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक गतिविधि कोविड-19 की दूसरी लहर के चंगुल में है, अक्टूबर 2020 के महीने के इनकमिंग डेटा ने अल्पावधि परिदृश्य में चमक भरी है तथा उपभोक्ता व कारोबारी विश्वास को बढ़ाया है। तथापि, समुत्थान के मार्ग में बड़े अधोमुखी जोखिम हैं।

अक्टूबर 2020 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में प्रस्तुत भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन के समय से कई घटनाक्रम राहत की एक खिड़की के खुलने तथा त्यौहारों के मौसम के शुरू होने के साथ आर्थिक गतिविधि के बंधनमुक्त होने के संकेत दे रहे हैं। इस बुलेटिन में आगे एक लेख में प्रस्तुत तात्कालिक¹ अनुमान बताता है कि ति1 (पहली तिमाही) : 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 23.9 की अभूतपूर्व गिरावट के बाद जीडीपी में संकुचन की गति ति2

(दूसरी तिमाही):2020-21 में नरम पड़ कर 8.6 प्रतिशत पर आ गई। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस (एनएसओ) के आकलन से, जो नवंबर 2020 के अंत में प्रत्याशित हैं, विगत तिमाही में हुई वृद्धि की औपचारिक पुष्टि प्राप्त होगी। अब तक परिणाम घोषित कर चुकी 887 गैर-वित्तीय सूचीबद्ध कंपनियों (समस्त सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के बाजार पूँजीकरण का लगभग अस्सी फीसदी/ पाँच में चार हिस्सा) के लिए ति2 (दूसरी तिमाही): के लिए बिक्री में संकुचन रहा पर ति1 की तुलना में इसकी गति कम रही। तथापि विक्रय की तुलना में इन कंपनियों का व्यय अधिक तेजी से गिरा जिससे लगातार दो तिमाहियों के संकुचन के बाद परिचालन लाभ तेजी से बढ़ा। अन्य आय में हल्की वृद्धि से, परिचालनीय लाभ की प्रकृति के अनुसार, निवल लाभ तेजी से बढ़ा जो बताता है कि ति2 में कंपनी क्षेत्र द्वारा समग्र वर्धित मूल्य चकित कर सकती है (चार्ट 1)।



* इस लेख को आशीष थॉमस जॉर्ज, कृष्ण मोहन कुशवाहा, शशि कांत, सप्तर्षि घोषाल, कुणाल प्रियदर्शी, अभिनंदन बोर्ड, जितेंद्र सोकल, सोनम चौधरी, मनु शर्मा, बरखा गुप्ता, अवनीश कुमार, ऋषभ कुमार, ऋग्जेन यांगडोल, मधुरेश कुमार, एसएम लोकरे और माइकल देवव्रत पात्रने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

¹ तात्कालिक अनुमान (नाऊकास्टिंग) अर्थव्यवस्था की स्थिति के वर्तमान या बहुत निकट भविष्य का अनुमान है(आरबीआई, 2020)।

सारणी 1: विनिर्माण कंपनियों के चुनिंदा अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि के अंत में	इक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात	आस्ति की तुलना में ऋण अनुपात	कुल आस्तियों की तुलना में नकद अनुपात
छमाही2:2018-19	35.9	19.2	2.4
छमाही1:2019-20	32.6	17.7	2.7
छमाही2:2019-20	45.7	22.4	3.2
छमाही1:2020-21	40.5	21.5	4.1

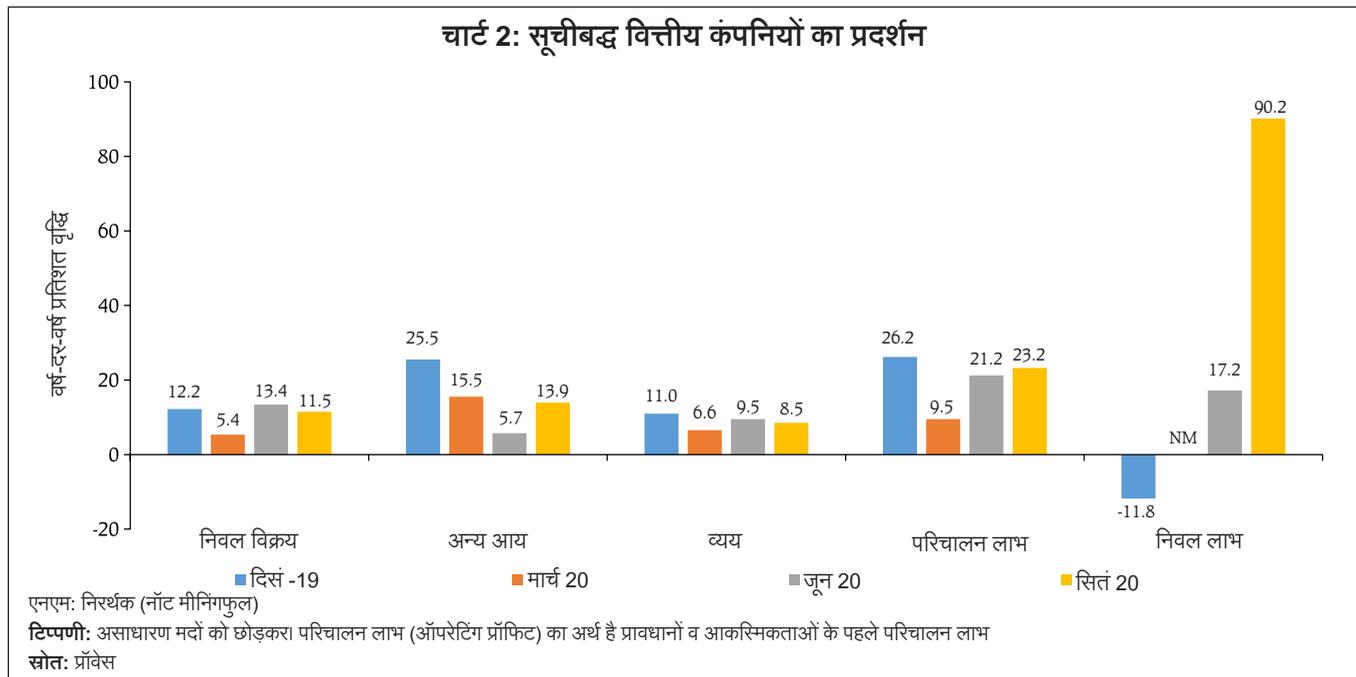
स्रोत: कैपिटालाइन.

पहले रिपोर्ट करने वाली 423 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की अलेखापरीक्षित बैलेंस शीट से पता चलता है कि पिछले महीनों की तुलना में छमाही (एच) 1: 2020-21 में लीवरेज (इक्विटी व ऋण अनुपात और परिसंपत्ति ऋण अनुपात द्वारा मापित) में मामूली गिरावट आई थी (सारणी 1)।

स्पष्ट है कि फंड जुटाने के लिए छमाही (एच) 1: 2020-21 में इन कंपनियों ने अपनी आस्तियां घटाईं। महामारी के दौरान अचल आस्तियों (फिक्स्ड एसेट्स) में निवेश मंद रहा। इक्विटी व आस्तियों के परिसमापन के रूप में इन कंपनियों द्वारा जुटाए गए फंड का उपयोग मुख्यतः देयताओं को घटाने व नकद धारिताओं (कैश होल्डिंग्स) को बढ़ाने में किया गया था। नकद धारिताओं को बढ़ाना अनिश्चित समय में एहतियाती बचत का संकेत देता है। इन कंपनियों द्वारा निवेश मंद रहा।

भारत में सूचीबद्ध बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र की 225 कंपनियों (जो बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से सभी सूचीबद्ध बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र कंपनियों का लगभग अस्सी फीसदी/ पाँच में चार हिस्सा हैं) की आय के परिणामों में ब्याज आय में हल्की वृद्धि दिखाई देती है (चार्ट2)। दूसरी ओर, निवेश व आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि जैसे आय प्रवाहों ने स्वस्थ वृद्धि दर्ज की। ब्याज व्यय के कम बढ़ने से कुल व्यय में कमी आई जिससे परिचालन लाभों (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) में अच्छी वृद्धि हुई। इसके अलावा, ऋण व अग्रियों पर प्रावधान, केवल मामूली रूप से बढ़ा जिससे निवल लाभों में उछाल आया। केयर (सीएआरई) रेटिंग्स के अनुसार, कुल आस्तियों में सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अनुपात पिछली तिमाही के 8.2 प्रतिशत से सुधर कर 7.7 प्रतिशत हो गया।

इस शृंखला का यह पहला लेख अक्टूबर 2020 के लिए उपलब्ध अर्थव्यवस्था के संकेतकों के विविध पहलुओं की पड़ताल करता है ताकि इस संक्रमण के चल रहे आकलन को आगे बढ़ाया जा सके जिस पर ति3 में भारतीय अर्थव्यवस्था अवस्थित है। परिकल्पना ये है कि अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा बुलेटिन की नियमित विशेषता होगी। ऐसा करने से वह महान परंपरा पुनर्जीवित होगी जो जनवरी 1947 में बुलेटिन के

चार्ट 2: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

पहले अंक से शुरू हुई थी, लेकिन 1995 से अब तक उसमें कहीं व्यवधान आ गया था।

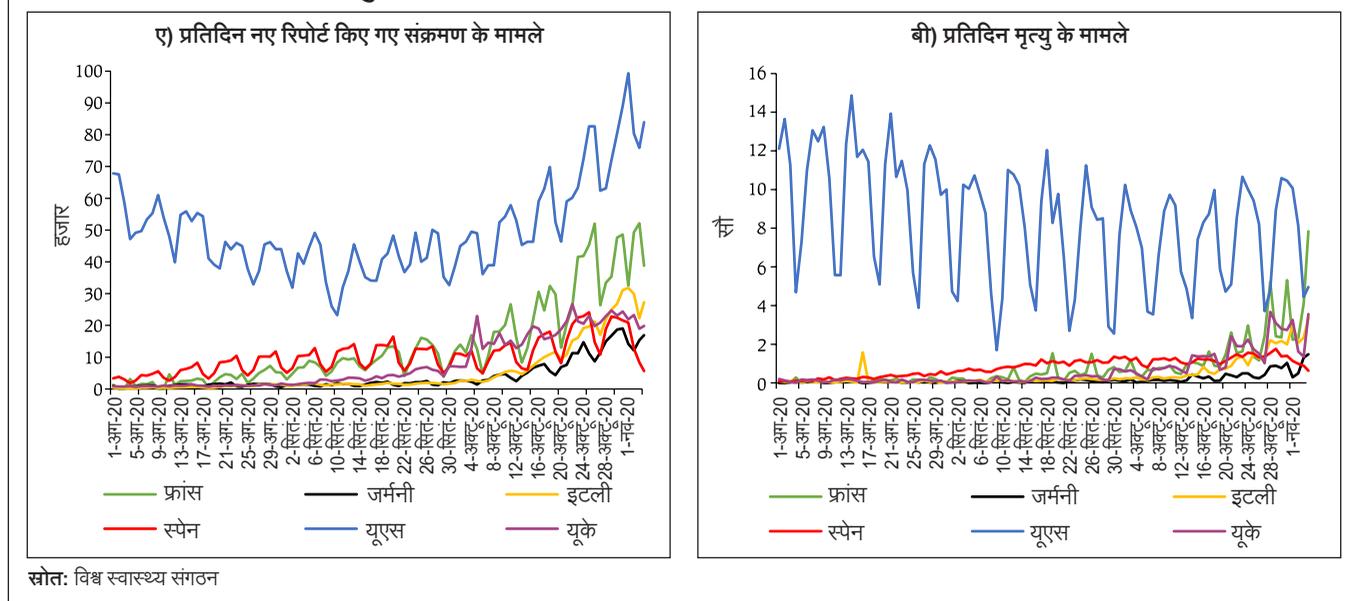
इस पृष्ठभूमि में यह लेख विभिन्न संकेतकों को परखते हुए अक्टूबर 2020 में अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करता है। लेख का शेष भाग पाँच खंडों में विभाजित है। अगला खंड उभरते वैश्विक आर्थिक व वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों को समेटता है। खंड III उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों पर इनकमिंग डेटा का विश्लेषण वास्तविक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से करता है। खंड IV चलनिधि प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा हाल में उठाए गए कदमों के बाद वित्तीय बाजार की स्थितियों की पड़ताल करता है। अंतिम खंड चर्चा का सार प्रस्तुत करता है।

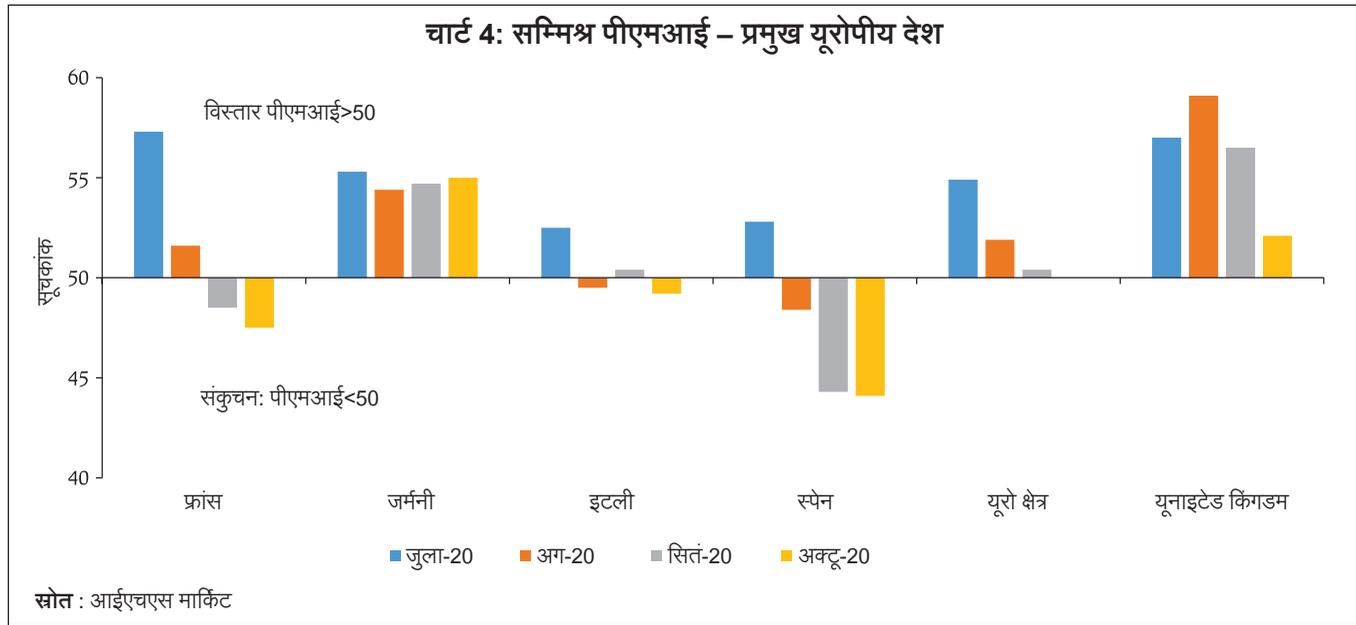
II. वैश्विक पृष्ठभूमि

वैश्विक आर्थिक गतिविधि कोविड-19 की दूसरी लहर के चंगुल में है जिसके चलते यूरोप में फिर से तालाबंदी (लॉकडाउन) की नौबत है और अमेरिका में संक्रमण फिर से सर उठा रहा है (चार्ट 3)। परिणामतः, वैश्विक सम्मिश्र क्रेता प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) का हिचकिचाहट भरे उदय का विस्तार जुलाई

2020 से जोखिम में है। सितंबर और अक्टूबर में प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की सम्मिश्र पीएमआई में यह पहले ही स्पष्ट है जो जुलाई में दर्ज स्तरों से नीचे गई हैं जिसमें कुछ देश, मुख्यतः सेवा क्षेत्र गतिविधि के कमजोर पड़ने के कारण, पुनः संकुचन में चले गए हैं (चार्ट 4)। वैश्विक सम्मिश्र पीएमआई जहाँ एक महीने पूर्व के 52.5 से बढ़कर अक्टूबर में 53.3 हो गया, फिर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच संघर्षरत ग्राहकोन्मुखी उद्योग समुत्थान की पूरी गति पकड़ने में बड़ी बाधा बने हुए हैं। वैश्विक व्यापार (ट्रेडिंग) गतिविधि का पुनरुत्थान, जो 2020 की ति3 में प्रगति पर था, इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा - संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने अनुमान लगाया कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर व्यापार में गिरावट के ति2 के (-) 19 प्रतिशत से घटकर ति3 में (-) 5 प्रतिशत पर आई। परिणामतः विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2020 के लिए किए गए इस अनुमान के मार्ग में बाधाएं आ गई हैं कि विश्व पण्य व्यापार मात्रा अप्रैल के (-) 12.9 प्रतिशत (-) से अक्टूबर में बढ़कर (-)9.2 प्रतिशत हो जाएगी। मध्य सितंबर से दूसरी लहर के भय से कूड ऑयल कीमतों की गर्मी पहले ही कम पड़ने लगी है; अक्टूबर का यूएस\$40.5 प्रति बैरल एक महीने पहले के स्तर से 0.6 प्रतिशत

चार्ट 3: प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमणों का फिर से उभरना





कम रहा। चीन द्वारा फिर से स्टॉक किए जाने के कारण आधार धातु कीमतें लगातार छठे महीने बढ़ीं जबकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में जोखिम विमुखता के बीच सुरक्षित आश्रय की माँग पर स्वर्ण मूल्य ऊँचाई पर रहा, अलबत्ता मजबूत डॉलर के कारण अक्टूबर में इसमें कुछ नरमी आई। वैश्विक उत्पादन पूर्वानुमानों के बारे में हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अपने अक्टूबर 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में उल्लिखित वृद्धि के लिए ये घटनाक्रम बड़े अधोमुखी जोखिम हैं (सारणी 2)।

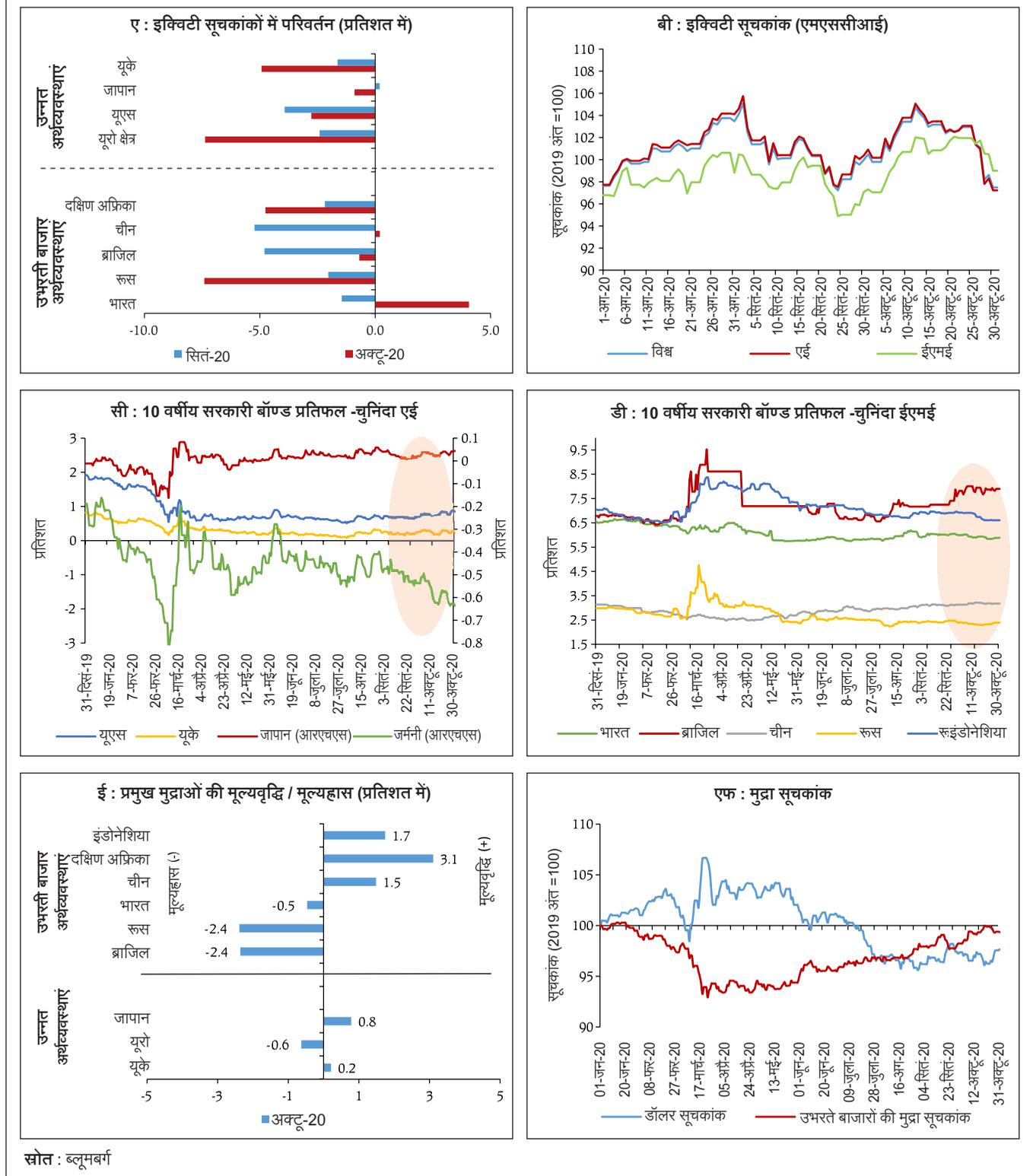
कोविड के फिर से उभरने से और नीतिगत समर्थन के बारे में अनिश्चितताओं के कारण संशोधन को बाध्य वैश्विक इक्विटी बाजार लुढ़के हैं (चार्ट 5ए और 5बी)। वैश्विक बॉण्ड बाजारों में मिला-जुला ट्रेड देखने को मिला जो देश विशेष के कारकों को दर्शाता है (चार्ट 5सी और 5डी)। मुद्रा बाजारों में, यद्यपि यूएस डॉलर में अक्टूबर में 0.2 प्रतिशत की मामूली मजबूती आई, तथापि संघर्षी वर्ष-से-आज तक (ईयर-टू-डेड) आधार पर समीक्षाधीन माह तक इसमें 2.4 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ। उभरती बाजार (ईएम) मुद्राओं के लिए – मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स (एमएससीआई-ईएम) में, अक्टूबर में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, वर्ष-से-आज तक (ईयर-टू-डेड) आधार पर 0.6 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ

सारणी 2: 2020 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिंदा आई और ईएमई

देश	अप्रैल डब्ल्यूईओ	जून डब्ल्यूईओ	अक्टूबर डब्ल्यूईओ
विश्व	-3.0	-4.9	-4.4
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं			
यूएस	-5.9	-8.0	-4.3
यूके	-6.5	-10.2	-9.8
यूरो क्षेत्र	-7.5	-10.2	-8.3
जापान	-5.2	-5.8	-5.3
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं			
चीन	1.2	1.0	1.9
ब्राज़िल	-5.3	-9.1	-5.8
रूस	-5.5	-6.6	-4.1
दक्षिण अफ्रिका	-5.8	-8.0	-8.0
भारत	1.9	-4.5	-10.3

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

चार्ट 5: वित्तीय बाजार घटनाक्रम



स्रोत : ब्लूमबर्ग

(चार्ट 5ई और 5एफ)। आईएमएफ की अक्टूबर ग्लोबल फाइनेंसियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने बताया कि इक्विटी बाजारों में

खिंचे हुए मूल्यांकनों (स्ट्रेचड वैल्यूएशंस), बढ़ते कॉर्पोरेट ऋण, और बैंकों व बैंकेतर वित्तीय क्षेत्र की आंतरिक दुर्बलताओं से

वित्तीय कमजोरियां बढ़ रही हैं और मध्यावधि समष्टि-आर्थिक स्थिरता व वृद्धि को जोखिम में डाल रही हैं। आईएमएफ के फिस्कल मॉनिटर ने चेताया कि सरकारी कर्ज (सॉवरिन डेट) ऐतिहासिक ऊँचाई पर हैं और इस स्तर पर त्वरित व निर्णायक नीतिगत कार्रवाई के बिना कई अल्प-आय वाले देशों तथा कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण संकट अवश्यभावी हो सकता है।

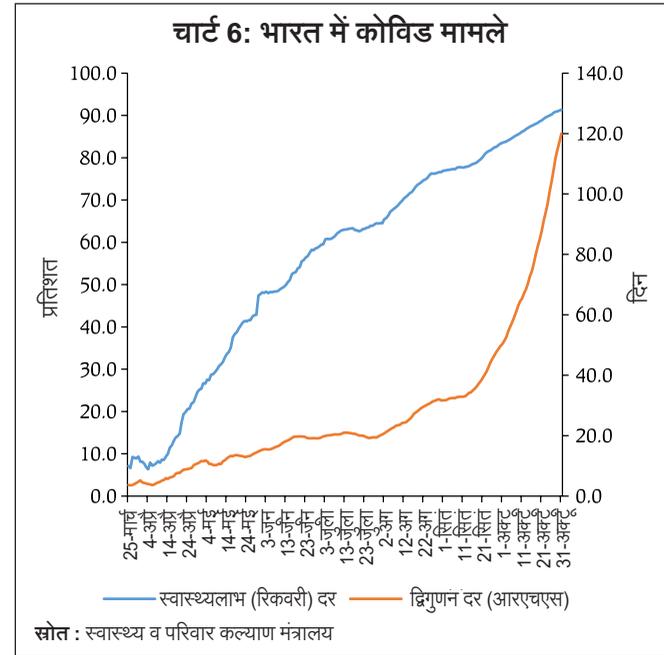
III. घरेलू घटनाक्रम

वैश्विक घटनाक्रम के विपरीत, भारत में स्वास्थ्य संकट के घटने के संकेत बढ़ रहे हैं और इससे लोगों को नियंत्रण (कंटेनमेंट) के बाहर आने तथा सामाजिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजेशन के मानकों के तहत आर्थिक गतिविधियां करने का विश्वास व साहस मिला है। मध्य सितंबर भारत कोविड वक्र (कर्व) को झुका रहा है। नए मामलों में क्रमिक कमी आई है जो अक्टूबर में कायम रही है। सात-दिवसीय औसत अथवा मामला मार्ग (केस ट्रेजेक्टरी) 18 सितंबर के 93,180 से गिरकर 31 अक्टूबर को 46,062 पर आ गया है। स्वास्थ्य लाभ दर (रिकवरी रेट)² 90 प्रतिशत को पार कर चुकी है। अक्टूबर में स्वास्थ्य लाभ (रिकवरी) की संख्या नए मामलों से अधिक है। द्विगुणन दर³ लगभग 120 दिनों तक बढ़ गई है जो मार्च 25 को, जब लॉकडाउन लागू किया गया था, 3.7 दिन थी। कर्व के नीचे जाने से प्राधिकारियों को अर्थव्यवस्था को उत्तरोत्तर खोलने (अनलॉक करने) को प्रोत्साहित किया है (चार्ट 6)।

प्रशांत महासागर पर व्याप्त ला निना की स्थितियां हवा में ढंड कुछ पहले ही लेकर आ गई हैं और त्योंहारों की शुरुआत के साथ उम्मीदें भी बढ़ी हैं। यह विश्वास भी बढ़ रहा है कि दूसरी लहर यदि आई भी तो ति1:2020-21 की तरह भरभरा कर नीचे जाने की संभावना दुबारा नहीं है क्योंकि संपर्क-निर्भर उद्योग व सेवाओं पर प्रभाव की प्रखरता घटित हो चुकी है और वे जल्द से जल्द वर्चुअल नॉर्मल को अपना रहे हैं। साथ ही, असाधारण

² रिकवरी दर को कुल संक्रमणों में उन रोगियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है जो ठीक (रिकवर) हुए हैं।

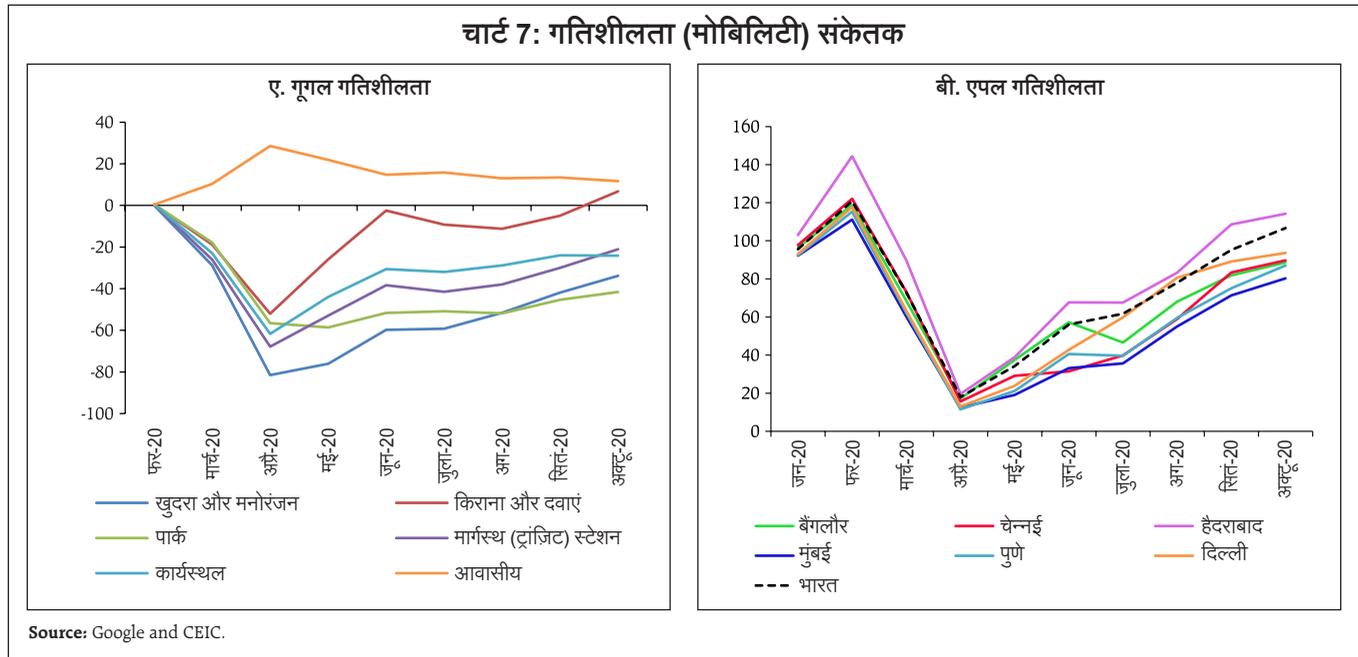
³ द्विगुणन दर को $\ln 2 / \ln (1 + r)$ के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ r संघयी मामलों में वृद्धि के पिछले सात दिनों का औसत है।



नीतिगत उपायों ने अर्थव्यवस्था के नीचे एक तल लगा दिया है। वायरस को फैलने देकर खो गई जिंदगियों और जीविका के बीच अब और समझौता नहीं। आशावाद के नए स्रोतों को प्रज्ज्वलित करना और संक्रामक निराशावाद को काटना ही कुंजी है।

कोविड-19 और सामाजिक दूरी के समय आवाजाही के संकेत दुर्लभ हो गए हैं और इनकी खोज की जा रही है, बल्कि बाह्य अंतरिक्ष या उपग्रह से भी। भौगोलिक क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लोगों की आवाजाही को अंकित करने वाला गूगल गतिशीलता (मोबिलिटी) सूचकांक बताता है कि किराने व दवा की दुकानों व आवासीय स्थानों के आस-पास लोगों की आवाजाही कोविड-पूर्व के स्तरों से अधिक हुई है परंतु कार्यस्थलों, मनोरंजन के क्षेत्रों व खुदरा दुकानों के आस-पास कम बनी हुई है। इन संकेतों की पुष्टि एपल गतिशीलता (मोबिलिटी) इंडेक्स से भी हुई है जो 13 जनवरी 2020 को सेट अपने बेसलाइन से आगे चला गया है, जिसमें दक्षिण के शहर अगुआ रहे। (चार्ट 7)। अक्टूबर में सामानों की आवाजाही भी बढ़ी जैसा कि ई-वे बिलों के वर्ष-दर-वर्ष निर्गम में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि से पता चलता है – राज्यांतर्गत 23.3 प्रतिशत और अंतर्राज्यीय 18.8 प्रतिशत।

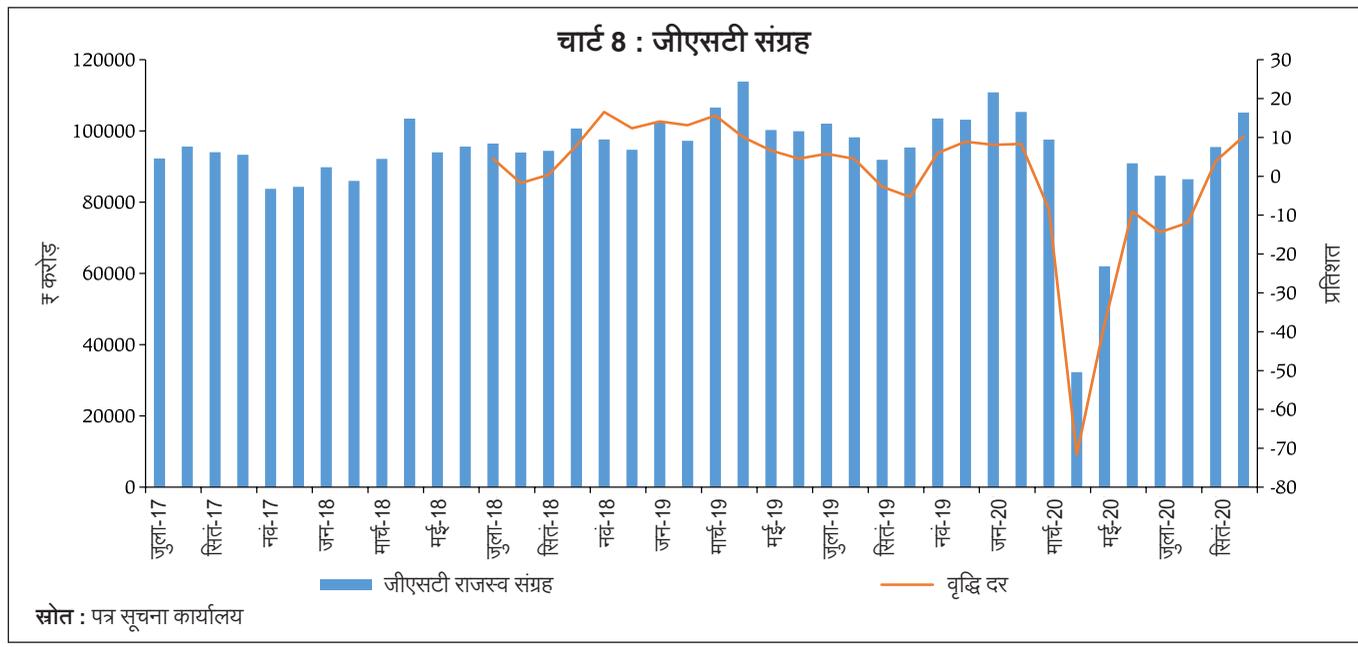
⁴ गूगल मोबिलिटी इंडेक्स बेसलाइन की तुलना में भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्थानों में विजिट में प्रतिशत परिवर्तन बताता है।



कुल मांग

कुल मांग के संकेतक अभी भी आ रहे हैं, परंतु त्योंहारों का मौसम जैसे-जैसे जोर पकड़ रहा है, इसमें वृद्धि के संकेत हैं। वर्ष में अब तक संकुचन में रहने के बाद अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने बिजली की खपत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़ी। पेट्रोल व डीजल का खपत भी संकुचन से बाहर आया इसमें क्रमशः 4 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। हर वर्ग में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे स्मार्टफोन, उपभोक्ता

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमोबाइलों, की बिक्री बढ़ी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मर्स ने बिक्री में 50 प्रतिशत की तेजी दर्ज की। घरेलू व्यय में इन संकेतकों में उत्थान के चलते वित्तीय वर्ष में पहली बार अक्टूबर में माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत संग्रह ने ₹ 1लाख करोड़ की सीमा को भेदा जो कि वर्ष-दर-वर्ष 10.2 प्रतिशत की वृद्धि है (चार्ट 8)। रिजर्व बैंक उपभोक्ता विश्वास (कनज्यूमर कॉन्फिडेंस) सर्वेक्षण (सीसीएस) के सितंबर राउंड में भी आशावाद दिखता है जहाँ गृहस्थों (हाउसहोल्ड्स) में



आगामी वर्ष को लेकर अधिक विश्वास है और साथ ही सामान्य आर्थिक परिस्थिति, रोजगार के हालात और आय के परिदृश्य में सुधार की प्रत्याशाएं भी।

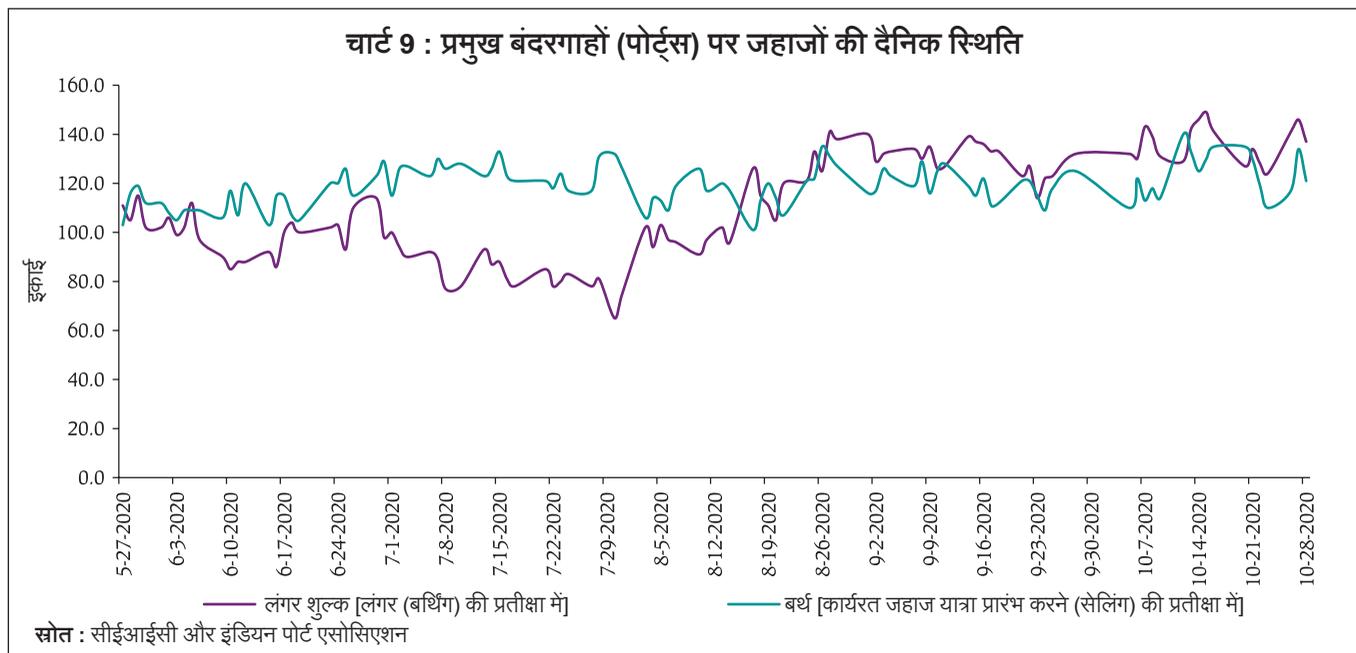
रोजगार परिदृश्य के बेहतर होने से भी इस सकारात्मकता को बल मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआई) के अनुसार बेरोजगारी दर अप्रैल 2020 की 23.2 प्रतिशत की ऊँचाई से लगातार घटते हुए अक्टूबर में 7 प्रतिशत पर आई है जहाँ शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 100 में 7.2 व्यक्तिबेरोजगार हैं जबकि अप्रैल में 100 में 25 बेरोजगार रहे। ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत गृहस्थों द्वारा माँगा गया रोजगार अक्टूबर में 91.3 प्रतिशत बढ़ा जो यह दर्शाता है कि लोग खोई हुई जीविका को बहाल कर रहे हैं।

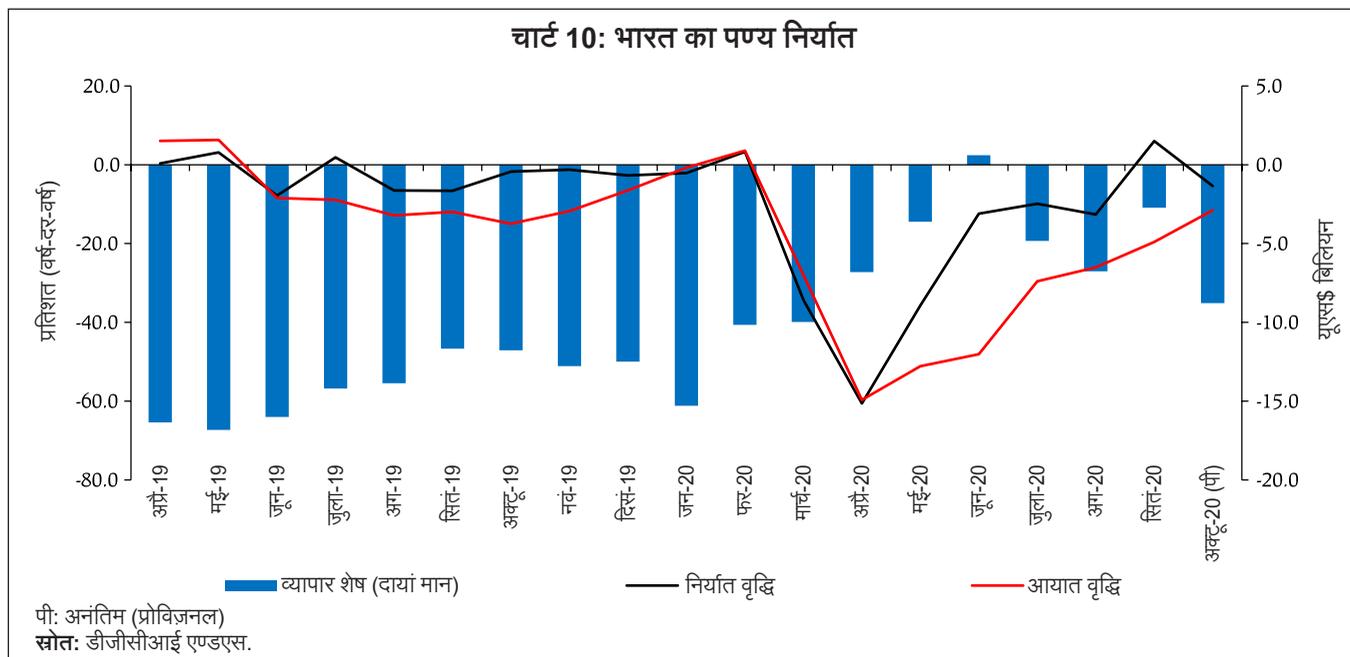
13 प्रमुख बंदरगाहों (पोर्ट्स) पर समुद्र-गामी जहाजों की आवाजाही सितंबर में प्रारंभ हुए समुत्थान के बाद संकुचन का संकेत दे रही है जिसकी पुष्टि सीमा-शुल्क सीमांतों व प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों के यहाँ निर्यात दस्तावेजों की प्रोसेसिंग संबंधी सूचना से भी होती है (चार्ट 9)। दस्तावेजों की प्रोसेसिंग के अनुसार आयात माँग, इस बीच, कमतर संकुचन दर्ज कर रहा है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अक्टूबर 2020 के लिए भारत के पण्य व्यापार पर प्रारंभिक डेटा के अनुसार यूएस \$ 24.8 बिलियनका निर्यात विगत माह की 6.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.4 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। तेल निर्यात में जहाँ 53.3 प्रतिशत का संकुचन दर्ज हुआ, वहीं तेल से इतर निर्यात में 1.8 प्रतिशत की तेजी आई जिसमें कृषिवस्तुओं तथा दवाओं व औषधियों (ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स) अग्रणी रहे। आयात में गिरावट लगातार आठवें महीने जारी रही, पर मांग की बेहतर स्थितियों के कारण इसमें संकुचन की गति एक महीने पूर्व की 19.6 प्रतिशत की तुलना में घटकर अक्टूबर में 11.6 प्रतिशतहो गई (चार्ट10)। परिणामतः, अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर यूएस \$ 8.8 बिलियन हो गया जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक है।

कुल आपूर्ति

कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में कुल आपूर्ति स्थितियों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जबकि संपर्क-सघन सेवाएं अभी भी पीछे हैं जो समुत्थान की गति में विविधता को दर्शाता है।





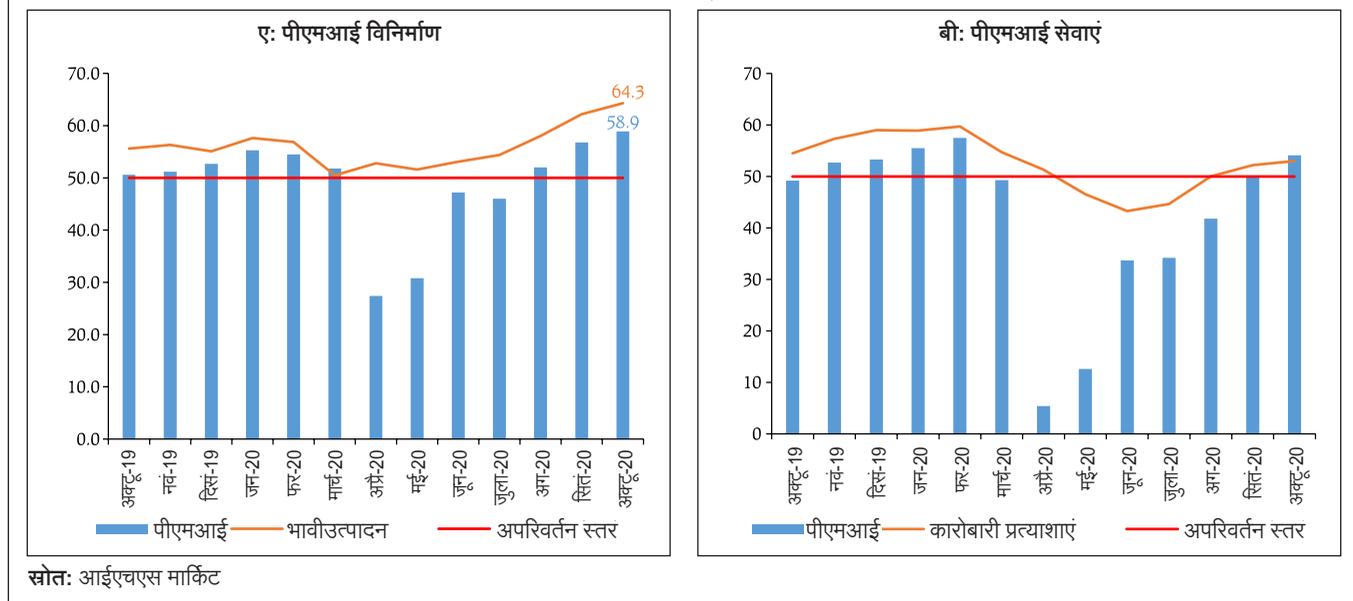
कृषि क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में असाधारण विलंब ने आगामी रबी की बुवाई के मौसम के लिए मिट्टी व जलाशय की स्थितियां अनुकूल कर दी हैं। 6 नवंबर, 2020 तक, कुल रबी का कुल रकबा (एकरेज) 100.9 लाख हेक्टेयर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.8 प्रतिशत अधिक है। इस बीच, अक्टूबर के अंत तक, खरीफ चावल की खरीद एक साल पहले की तुलना में 24.6 प्रतिशत अधिक रही जो स्टॉक को बफर मानदंड से 2.6 गुना अधिक के स्तर पर ले गई। रिकॉर्ड गेहूँ की खरीद के कारण बफर मानकों से 2.1 गुना अधिक स्टॉक हो गया। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त वितरण के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कुल वितरण अक्टूबर के अंत तक एक साल पहले की तुलना में 63.3 प्रतिशत अधिक रहा।

औद्योगिक गतिविधि की ओर रुख करें तो, भारत का विनिर्माण पीएमआई व्यापक-आधार के साथ बढ़ा और अक्टूबर में 58.9 जो एक दशक में इसका उच्चतम स्तर है। इसमें मुख्यतः माल (इन्वेंटरी) के पुनर्भंडारण के साथ नए आदेशों और उत्पादन का हाथ रहा (चार्ट 11)। भावी उत्पादन सूचकांक 64.3 हो गया, जो पिछले 50 महीनों में उच्चतम था। रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस) की प्रत्याशा है

कि ति 2: 2020-21 में दिखा उछाल उत्पादन, क्षमता उपयोग और ऑर्डर बुक में सुधार के साथ ति3 में मजबूत होगा। बाहरी मांग की स्थिति और नौकरी के परिदृश्य में सुधार की प्रत्याशाएं हैं और वित्त की उपलब्धता को लेकर आशावाद है।

सेवाओं में जहां गतिविधि महामारी के प्रभाव में लगभग ढह गई थी, वहाँ कई संकेतक नए व्यापार मॉडल और कार्य आचार को अपना कर स्थिति में तेजी से सुधार ला रहे हैं। नए कार्य मिलने से सेवा (सर्विसेज) पीएमआई संकुचन क्षेत्र से पहली बार बाहर निकली और अक्टूबर में 54.1 पर रही। सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों में, निर्माण गतिविधि बढ़ रही है जैसा कि स्टील की बढ़ती खपत में स्पष्ट रूप दिख रहा है, तथापि इस बेहतरी की पक्की पुष्टि सीमेंट उत्पादन संबंधी सूचना से होगी। जीएसटी संग्रह और ई-वे बिल की बढ़ते मात्रा के अनुसार ट्रेडिंग गतिविधि कोविड-पूर्व स्तरों से ऊपर है। विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं में रेलवे माल ढुलाई में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि ने परिवहन को बल दिया है, और यात्री यातायात भी इसके पदचिह्नों पर है, पर विलंब के साथ, लॉकडाउन में ढील के अनुसार। त्यौहारी मांग और सार्वजनिक परिवहन की जगह निजी वाहनों को तरजीह दिए जाने के कारण कार के बड़े विनिर्माताओं से दोहरे अंकों में वृद्धि की सूचना मिल रही है। हालाँकि, यह उत्साह डीलरशिपों

चार्ट 11: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



में नहीं दिखता। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (एफएडीए) के अनुसार, अक्टूबर 2020 में दोपहिया और यात्री वाहनों की बिक्री में क्रमशः 27 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट वाणिज्यिक वाहनों और तिपहिया वाहनों के मामले में तेज थी, जहाँ क्रमशः 30 प्रतिशत और 65 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया।

मुद्रास्फीति

अक्टूबर का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एनएसओ द्वारा 12 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से जारी किया जाना है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से दैनिक आधार पर खुदरा मूल्यों पर उपलब्ध सूचना बताती है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से बने हुए खाद्य मूल्य दबाव अक्टूबर में भी अबाध रूप से हर वर्ग में जारी रहे, सिवाय अनाज, टमाटर और चीनी के। विशेषतः प्याजों व टमाटरों की मुद्रास्फीति-संवेदी कीमतें इस महीने के दौरान ऊँचाई पर अड़ी रहीं (सारणी 3)।

खाद्येतर श्रेणी में, पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य करों और उत्पाद शुल्क ने इस समूह में खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है तथा इसके दूसरे दौर (सेकेंड राउंड) के प्रभाव अन्य वस्तुओं व

सेवाओं की कीमतों पर स्पष्ट हैं। अंतरराष्ट्रीय कीमतों⁵ के पद चिह्नों पर पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों में कुछ कमी अक्टूबर में देखी गई थी। सेनिटेशन-संबंधित अतिरिक्त खर्चों के कारण व्यवसाय करने की लागत में वृद्धि, सामाजिक दूरी के मानकों और श्रम की कमी ने भी कोर मुद्रास्फीति को मजबूत रखने में भूमिका निभाई है।

लॉकडाउनों में उत्तरोत्तर ढील, वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही और शहरों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी से लागत-जन्य दबावों में कुछ कमी आने की संभावना है। अक्टूबर के विनिर्माण पीएमआई में, इनपुट कीमतें बढ़ीं, लेकिन ऐतिहासिक स्तरों से कम रही। नतीजतन, आउटपुट कीमतों में केवल मामूली वृद्धि दर्ज हुई, जो बताती है कि मूल्य निर्धारण शक्ति अभी भी कमजोर है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं⁶ के एक सर्वेक्षण ने अक्टूबर में 7.3 प्रतिशत

⁵ चार प्रमुख महानगरों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों के औसत के आधार पर, अक्टूबर के महीने के लिए घरेलू पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में कुछ कमी देखी गई जिसमें पेट्रोल की कीमत पिछले महीने से ₹ 0.48 प्रति लीटर (0.6 प्रतिशत) घटकर ₹ 83.88 प्रति लीटर पर आई और डीजल की कीमतें पिछले महीने से 1.81 प्रति लीटर (2.4 प्रतिशत) घटकर ₹ 74.34 प्रति लीटर पर आई।

⁶ 9 नवंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार 32 पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण के आधार पर अक्टूबर 2020 के लिए औसत (मीडियन) सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान।

सारणी 3: डीसीए आवश्यक वस्तु कीमतें

क्रम सं.	वस्तुएं	सीपीआई में भार	₹ प्रति किलोग्राम				माह-दर-माह (प्रतिशत)			
			सितं-19	अक्टू-19	सितं-20	अक्टू-20	सितं-19	अक्टू-19	सितं-20	अक्टू-20
1	चावल	4.4	32.4	33.1	34.7	34.9	1.1	2.3	0.6	0.4
2	गेहूं और आटा	2.6	27.7	28.8	29.5	29.2	0.2	3.8	-0.5	-1.2
3	चने दाल	0.3	65.6	66.3	68.7	72.5	-0.5	1.0	3.5	5.6
4	तुअर/अरहर दाल	0.8	85.9	86.6	94.9	104.6	1.0	0.7	2.0	10.2
5	उड़द दाल	0.3	74.8	78.4	99.0	104.0	-0.2	4.9	0.3	5.0
6	मूंग दाल	0.3	83.4	84.6	101.8	102.6	1.3	1.4	-1.7	0.8
7	मसूर की दाल	0.3	62.8	63.3	77.8	78.4	0.2	0.7	0.6	0.8
8	मूँगफली का तेल	0.3	131.3	134.0	150.5	153.0	0.8	2.0	0.8	1.7
9	सरसों तेल	1.3	109.7	111.2	126.5	128.6	0.9	1.4	1.6	1.7
10	वनस्पति	0.1	79.6	80.0	93.3	94.9	0.4	0.5	2.1	1.7
11	रिफाईड तेल(सूरजमुखी, सोयाबीन और ताड़ का तेल//पाम ऑयल)	1.3	89.8	89.9	105.3	107.2	1.1	0.1	3.1	1.8
12	आलू	1.0	18.9	20.6	36.7	39.5	-0.7	8.8	10.4	7.7
13	प्याज	0.6	38.3	47.0	31.6	50.2	54.3	22.8	39.5	59.0
14	टमाटर	0.6	31.2	38.6	51.8	45.4	-19.4	23.7	13.3	-12.4
15	चीनी	1.1	39.2	39.4	40.4	40.2	1.2	0.6	0.4	-0.4
16	गुड़	0.1	45.2	46.2	49.5	49.3	1.4	2.2	0.4	-0.2
17	दूध	6.4	44.5	44.9	46.8	46.9	2.2	0.9	-0.4	0.1
18	चायखुली	1.0	213.6	215.3	228.3	231.2	0.6	0.8	1.9	1.3
19	नमक	0.2	15.5	15.4	16.5	16.5	0.5	-0.3	1.0	0.0
20	भारित औसत मूल्य (1से19)	22.9	55.8	57.0	62.2	63.5	1.4	2.1	1.8	2.1

स्रोत : उपभोक्ता मामले विभाग , भारत सरकार और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

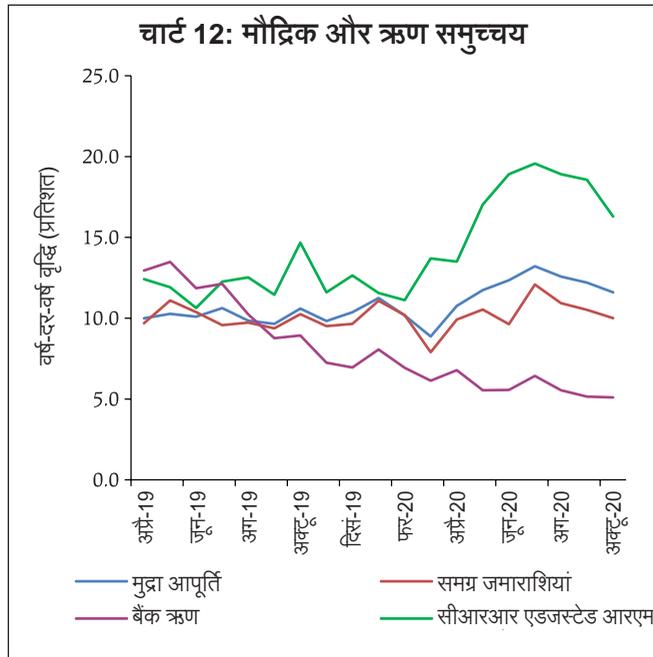
की औसत (मीडियन) सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के साथ बढ़े हुए मुद्रास्फीति दबाव के बने रहने की संभावना बताई।

IV. वित्तीय स्थितियां

भारत सरकार (जीओआई) नकद शेष में बड़ी वृद्धि के बावजूद चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अवशोषण बढ़कर ₹4,46,802 करोड़ हो गया और अक्टूबर 2020 में, प्रणालीगत चलनिधि और बढ़ गई। सितंबर में कुछ शांत सी रही संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में त्यौहारों के मौसम के प्रारंभ होने के साथ कुछ बेहतरी देखी गई और प्रणाली से कुछ चलनिधि बाहर निकली। चलनिधि प्रबंधन की प्रक्रिया में तीन खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) क्रयों के माध्यम से चलनिधि डाली गई, जबकि अल्पकालिक चलनिधि हलचलों को एलएएफ परिचालनों के जरिये संभाला गया।

मांग की स्थितियों के मौन होते हुए भी, मुद्रास्फीति में उर्ध्वमुखी दबाव रहा एवं 2020-21 में मौद्रिक व ऋण स्थितियां नरम पड़ीं।

आरक्षित नकद निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए एडजस्ट की गई आरक्षित मुद्रा 30 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार 16.3 प्रतिशत बढ़ी जिसका मुख्य कारण घटक पक्ष की ओर सीआईसी और स्रोत पक्ष की ओर निवल विदेशी आस्तियों में उच्च वृद्धि रही। 23 अक्टूबर 2020 के अनुसार यह मुद्रा आपूर्ति (एम3) के 11.6 प्रतिशत वृद्धि (एक वर्ष पूर्व 10.6 प्रतिशत) में सहायक रही। 23 अक्टूबर 2020 के अनुसार वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण एक वर्ष पूर्व के 8.9 प्रतिशत की तुलना में 5.1 प्रतिशत पर मंद रहा; तथापि, समग्र जमाराशियों में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि रही (चार्ट 12)। लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालनों (टीएलटीआरओ) के प्रभाव से कंपनी निकायों (कॉरपोरेट बॉडी) के वाणिज्यिक पत्र, बॉण्डों/डिबेंचरों व शेयरों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹24,495 करोड़ की गिरावट तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹15,561 करोड़ की वृद्धि हुई।



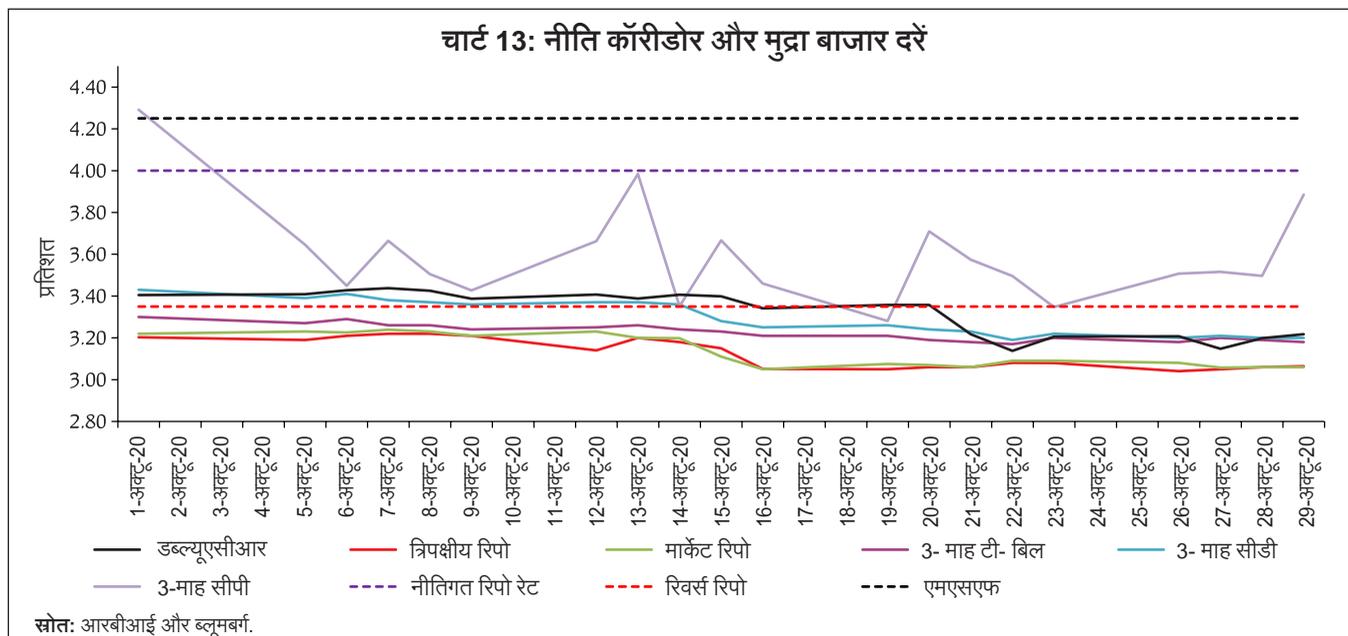
मौद्रिक नीति के निभावी रुख के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने पॉलिसी रिपो रेट से जुड़े फ्लोटिंग रेट पर ₹1,00,000 करोड़ तक की कुल राशि के तीन वर्ष तक की अवधि के सदा सुलभ (ऑन टैप) टीएलटीआरओ की घोषणा की। योजना के तहत ली गई चलनिधि को कृषि, कृषि-आधारभूत संरचना, सुरक्षित खुदरा, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स व स्वास्थ्य सेवा लगी ईकाइयों द्वारा जारी कॉरपोरेट बॉण्डों, वाणिज्यिक पत्र, बॉण्डों/डिबेंचरों व शेयरों में लगाई जाए तथा यह 30 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार इन उपकरणों/लिखतों (इन्सट्रुमेंट्स) में उनके निवेश के बकाया स्तर के अतिरिक्त हो। योजना के तहत उठाई गई राशि का उपयोग इन क्षेत्रों को बैंक ऋण व अग्रिम देने के लिए भी किया जा सकता है। यह कदम क्षेत्र विशेष की चलनिधि संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए है ताकि वृद्धि पर जिनका गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) है उनकी फंडिंग स्थितियों में सुधार से समुत्थान में सहयोग मिले। रिज़र्व बैंक ने, विशेष मामले के रूप में, चालू वित्तीय वर्ष में राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में ओएमओ करने का निर्णय लिया ताकि एसडीएल के सक्षम मूल्य निर्धारण में सहायता मिले और चलनिधि में सुधार हो। एसडीएल के लिए ऐसा पहला ओएमओ ₹10,000 करोड़ के लिए 22

अक्टूबर 2020 को किया गया। इस प्रकार अक्टूबर में एकमुश्त ओएमओ के जरिये ₹66,305 करोड़⁷ की टिकाऊ चलनिधि डाली गई। इसके अलावा 31 मार्च 2022 तक बैंक एसएलआर प्रतिभूतियों के नवीन अधिग्रहणों (1 सितंबर से) को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 22 प्रतिशत (19.5 से बढ़ाकर) की समग्र सीमा तक रख सकते हैं।

चलनिधि प्रचुरता की ये स्थितियां अक्टूबर 2020 में मुद्रा बाजार में व्याप्त रहीं। एक दिवसीय असंपार्श्विकृत खंड में मांग मुद्रा दर (कॉल मनी रेट) एलएएफ कॉरीडोर के निचले दायरे के इर्द-गिर्द ट्रेड हुई और महीने अंतिम सप्ताह में रिवर्स रिपो रेट से भी नीचे गई। संपार्श्विकृत खंड –बाजार रिपो और त्रि-पक्षीय रिपो– में दरें कॉल रेट के क्रमशः 18 आधार अंक और 20 आधार अंक नीचे चलीं। अल्पावधि खंड अर्थात् जमाराशि प्रमाण पत्र 91-दिवसीय खजाना बिल में दरें सब-रिवर्स रिपोस्तरों पर रहीं (क्रमशः 3.30 और 3.23 प्रतिशत के औसत पर) जबकि वाणिज्यिक पत्र पर छूट दरें एलएएफ रिवर्स रिपो दर के मुश्किल से 25 आधार अंक ही ऊपर रहीं (चार्ट 13)। चलनिधि के विस्तार से कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल और जोखिम प्रीमिया भी नरम पड़े जैसा कि समूचे रेटिंग दायरे में तत्संबंधी परिपक्वता के जोखिम मुक्त दर के कॉरपोरेट बॉण्ड की नरमी में देखने को मिला (सारणी 4)।

चलनिधि अधिशेष, निभावी मौद्रिक नीति रुख, बाह्य बेंचमार्क के आधार पर ऋण के मूल्य निर्धारण की शुरुआत, कमजोर ऋण मांग स्थितियों और नीतिगत दरों में कटौतियों के विलंबित प्रभाव के मिले-जुले असर से नीतिगत रिपो दरों में परिवर्तन का वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार (लेंडिंग) दरों में संचरण बेहतर हुआ है। मार्च से अक्टूबर 2020 तक फंड-आधारित उधार दर की 1-वर्षीय माध्यिका सीमांत लागत (मीडियन मार्जिनल कॉस्ट) 90 आधार अंक घटी है जबकि माध्यिका मीयादी जमा दर (मीडियन टर्म डिपॉजिट रेट) में कमी 137 आधार अंकों तक की है।

⁷ इस राशि में 2 नवंबर, 2020 के निपटान वाली 29 अक्टूबर को की गई ओएमओ खरीद शामिल है।



बॉन्ड बाजारों में, सरकारी प्रतिभूति खंड में बेंचमार्क 10-वर्षीय प्रतिफल पिछले महीने की तुलना में नरमी की ओर झुकाव के साथ ट्रेड हुआ तथा रिजर्व बैंक द्वारा ओएमओ के आकार में वृद्धि और पहली बार एसडीएल में ओएमओ के संचालन से मिजाज बेहतर हुआ। कॉरपोरेट बॉन्ड खंड में, 5-वर्षीय एए बॉन्ड 22 आधार अंक (बीपीएस) तक संकुचित हो गया जो कि एक महीने पहले की तुलना में 28 बीपीएस कम है। रेटिंग परिधि (स्पेक्ट्रम) के सबसे निचले छोर, यानी, बीबीबी-पर भी, स्प्रेड्स थोड़े संकुचित हुए हैं। निजी निवेशक को कॉरपोरेट बॉण्डों के सीधे आबंटन द्वारा जुटाया जाने वाला

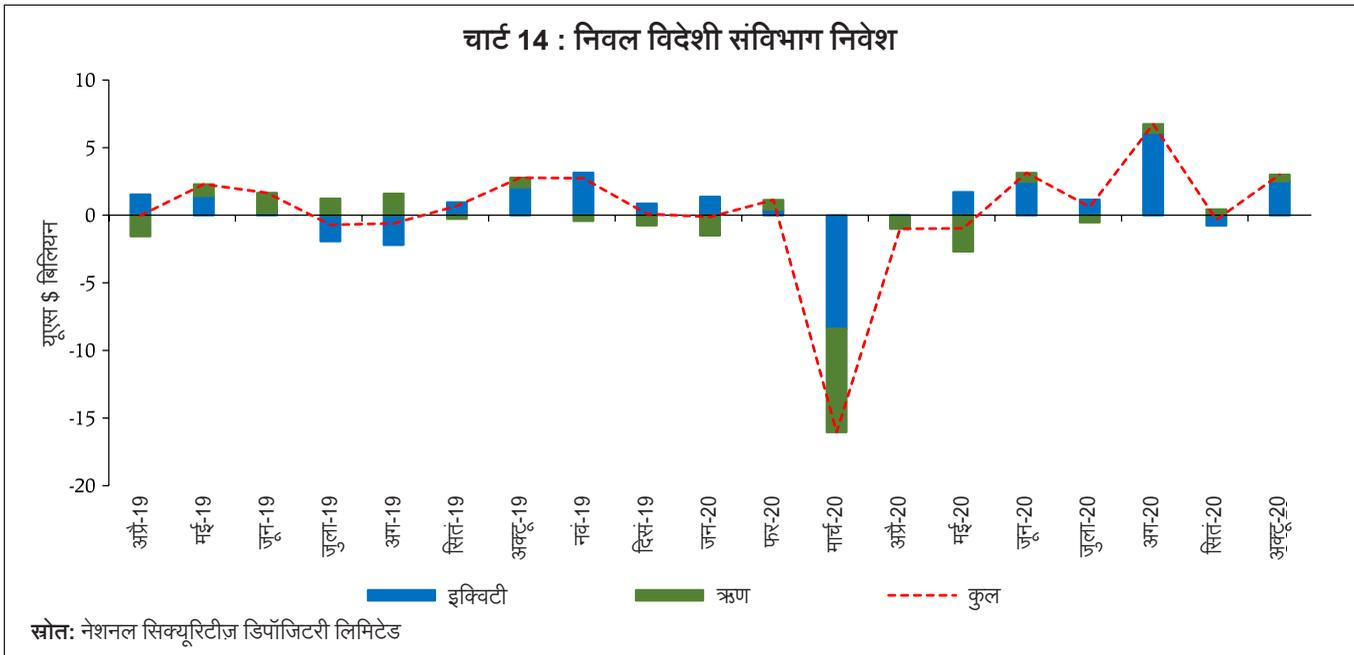
संसाधन सितंबर 2020 के ₹64,389 करोड़ से घटकर अक्टूबर 2020 में ₹62331 हो गया। माह के दौरान विदेशी संविभाग निवेशक ऋण बाजार में यूएस \$ 0.4 बिलियन (सरकारी प्रतिभूति और कॉरपोरेट बॉण्ड को मिलाकर) का प्रवाह लेकर आए (चार्ट 14)। स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) द्वारा भी यूएस \$ 0.1 बिलियन के प्रवाह का आगम हुआ।

महामारी के संदर्भ में उटाए गए मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत उपायों तथा ति2:2020-21 में प्रत्याशा से अधिक कॉरपोरेट आय के प्रभाव से घरेलू इक्विटी बाजार में

सारणी 4: वित्तीय बाजार – दरें और स्प्रेड

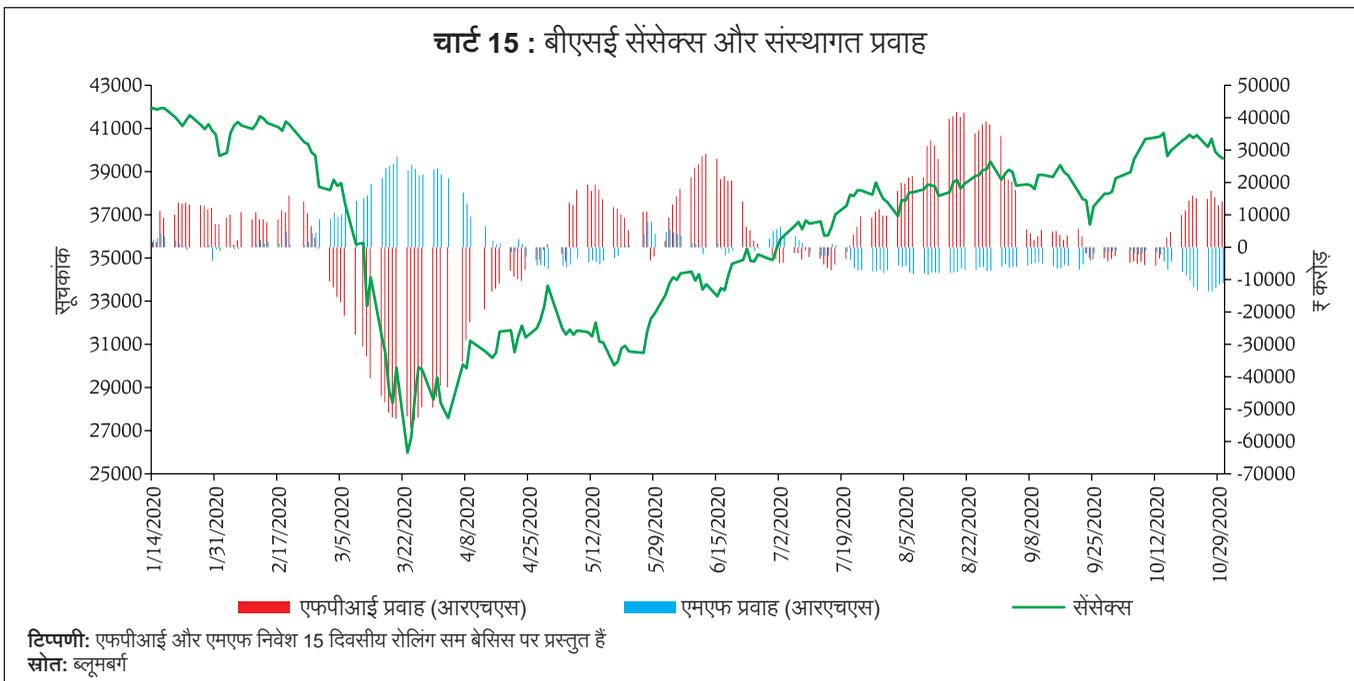
लिखत (इन्सट्रूमेंट)	ब्याज दरें (प्रतिशत)			बीपीएस मएं स्प्रेड (तत्संबंधी जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	30 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार	29 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार	अंतर (बीपीएस में)	30 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार	29 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार	अंतर (बीपीएस में)
(1)	(2)	(3)	(4 = 3-2)	(5)	(6)	(7 = 6-5)
सीपी (3-माह)	4.32	3.89	-43	105	69	-36
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एए (1-वर्ष)	4.35	4.00	-35	47	36	-11
(ii) एए (3-वर्ष)	5.35	4.90	-45	43	28	-15
(iii) एए (5-वर्ष)	6.10	5.60	-50	50	22	-28
(iv) एए (3-वर्ष)	6.13	5.84	-29	121	122	1
(v) बीबीबी-माइनस (3-वर्ष)	10.10	9.79	-31	518	517	-1
10-वर्षीय जी-सेक	6.01	5.89	-12	-	-	-

स्रोत: सीसीआईएल; एफ-टीआरएसी; एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग



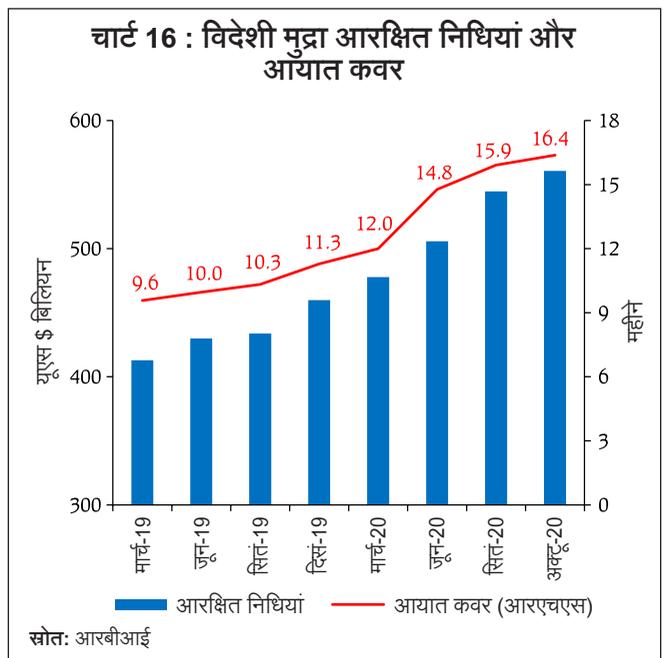
औचित्यहीन उत्साह अक्टूबर 2020 तक चला। बैंकिंग, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) स्टॉक्स ने इस उछाल को ऊर्जा दी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बेंचमार्क इंडेक्स (सेंसेक्स) ने सात महीने की ऊँचाई पार की और आने वाले दिनों में आगे बढ़ते हुए 23 मार्च को झेले नुकसान के 52 प्रतिशत की

भरपाई कर दी (चार्ट 15)। विदेशी संविभाग निवेशक जो एक माह पूर्व निवल विक्रेता थे अक्टूबर में निवल क्रेता बन गए और इक्विटी खंड में यूएस \$ 2.5 बिलियन लेकर आए। इसके विपरीत मोचन (रिडेम्पशन) दबावों के कारण म्यूचुअल फंड निवल विक्रेता रहे।



विदेशी मुद्रा बाजार में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की तरह भारतीय रुपए (आईएनआर) का मामूली रूप से मूल्यहास हुआ, अपितु मार्च 2020 अंत के अपने स्तर से यह 1.9 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। अंतर्निहित बुनियादी बातों में सुधार जैसे व्यापार घाटे का तेजी से संकुचन और पोर्टफोलियो प्रवाहों में सुधार से बाजार के मिज़ाज में उछाल आया। 36-मुद्रा व्यापार-भारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संदर्भ में, आईएनआर एक महीने पहले के अपने स्तर से अक्टूबर में 0.2 प्रतिशत से कम हो गया। जून 2020 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यूएस \$ 560.7 बिलियन हो गया, जो 16.4 महीनों के आयात के तुल्य था और भारत के बकाया बाहरी ऋण को पूरी तरह से कवर करता था (चार्ट 16)।

भुगतान क्षेत्र में, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) पर डिजिटल लेनदेन ने मात्रा व मूल्य दोनों में वृद्धि दर्ज की। अक्टूबर में, कुल लेन-देन 2 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया और मूल्य के मामले में ₹3.9 लाख करोड़ हो गया। तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) खुदरा लेनदेन भी सितंबर 2020 की तुलना में मात्रा में 14 प्रतिशत और मूल्य में 10.4 प्रतिशत बढ़ी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में, मात्रा में 11.9 प्रतिशत और मूल्य में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।



सारणी 5: 2020-21 में भुगतान लेन-देन

(करोड़ ₹ में)

	आरटीजीएस	एनईएफटी	यूपीआई	आईएमपीएस
अप्रै-20	64,43,653	13,06,406	1,51,141	1,21,141
मई-20	70,41,869	14,81,750	2,18,392	1,69,402
जून-20	86,51,978	19,06,586	2,61,835	2,06,951
जुला-20	83,35,279	19,63,113	2,90,538	2,25,775
अग-20	72,92,380	19,30,552	2,98,308	2,35,137
सित-20	94,89,066	21,65,515	3,29,032	2,48,662
अक्टू-20	84,96,046	22,35,389	3,86,107	2,74,645

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई).

बड़े मूल्य वाले भुगतानों की ओर चलें तो, तत्काल सकल निपटानों (आरटीजीएस) में मात्रा के संदर्भ में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन मूल्य में 10.5 प्रतिशत का संकुचन हुआ (सारणी 5)।

V. निष्कर्ष

अक्टूबर 2020 के लिए आ रहे आंकड़ों ने संभावनाओं को उज्ज्वल किया है तथा उपभोक्ता व व्यापार विश्वास को प्रोत्साहित किया है। सितंबर की गति के कायम रहने से, यह आशा बनी है कि आर्थिक गतिविधि का समुत्थान केवल अनलॉक द्वारा मुक्त हुई दबी (पेंट-अप) मांग के पूरा होने और माल (इन्वेंटरी) के पुनर्निर्माण मात्र से कहीं अधिक मजबूत है। यदि यह तेजी आगामी दो महीनों में बनी रहती है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विगत छह महीने के संकुचन से बाहर आ जाएगी और ति3: 2020-21 में सकारात्मक वृद्धि पर वापस आ जाएगी जो 9 अक्टूबर, 2020 को मौद्रिक नीति समिति के संकल्प में उल्लिखित पूर्वानुमान से एक तिमाही आगे होगा।

इस संदर्भ में, हालांकि, समुत्थान की संभावनाओं के सामने प्रस्तुत दुर्जेय अधोमुखी जोखिमों को पहचानना समझदारी होगी। सबसे प्रमुख है मुद्रास्फीति का लगातार बना हुआ दबाव जिसमें आपूर्ति प्रबंधन उपायों जैसे प्याज व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाने, आलू और प्याज के आयात (धूमन (फ्यूमिगेशन) के बिना) और दालों पर आयात शुल्क में अस्थायी कमी के बावजूद कमी के कोई संकेत नहीं हैं। कीमत दबावों के सामान्यीकरण,

मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं के अस्थिरीकरण (अनएंकरींग) का नीतिगत हस्तक्षेपों में विश्वसनीयता की क्षति से जा मिलने और परिणामतः सामने आ रहे नवजात वृद्धि आवेगों के क्षरण का गंभीर खतरा है। अर्थव्यवस्था को दूसरा बड़ा जोखिम कोविड-19 की दूसरी लहर की जोखिम का सामना कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था से है। यदि बाहरी मांग फिर से गिरती है जैसा कि कमोडिटी की कीमतें पूर्व संकेत देती प्रतीत हो रही हैं, तो हाल

ही में निर्यात में हुआ सुधार मृतजात हो सकता है। आसपास ही घात लगाए तीसरा बड़ा जोखिम है - गृहस्थों और कॉरपोरेशंस में गहराता तनाव जो विलंबित है पर कम नहीं हुआ है, और अभी भी फैल कर वित्तीय क्षेत्र में मिल सकता है। यदि नए अंकुर इन जोखिमों को झेल जाते हैं और अपनी जड़ जमा पाते हैं हैं, तो प्रमुख सवाल यह है कि इस समुत्थान के चालक क्या होंगे? हम चुनौतियों से भरे समय में रह रहे हैं।

भारत का आर्थिक गतिविधि सूचकांक*

डायनेमिक फैक्टर मॉडल का उपयोग करके सत्ताईस मासिक संकेतकों से बनाए गए भारत के आर्थिक गतिविधि सूचकांक से यह पता चलता है कि मई-जून 2020 से अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के कारण अर्थव्यवस्था में फिर से वृद्धि हुई, जिसमें संपर्क-सघन सेवा क्षेत्रों की तुलना में उद्योग तेजी से सामान्य हो गए। जीडीपी की गतिशीलता को सूचकांक बारीकी से ट्रैक करता है और ति2: 2020-21 में (-) 8.6 प्रतिशत तात्कालिक जीडीपी वृद्धि दर्शाया है।

परिचय

कोविड-19 से उत्पन्न स्वास्थ्य आपातस्थिति से पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में अचानक रोक लग गई। रोकथाम उपायों के कारण रोजगार की मांग न होना तथा आय का नुकसान, उपभोक्ता और व्यापार विश्वास कमजोर होना, बढ़ी हुई अनिश्चितता, वैश्विक व्यापार और पर्यटन में संकुचन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे स्वैच्छिक व्यवहारिक परिवर्तन से आपूर्ति अवरोधों का फैलाव बढ़ा। भारत में 4 नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार कोविड-19 से 83 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमित थे तथा 1.2 लाख मृत्यु दर्ज हुए, ति1:2020-21 में जीडीपी में वर्ष-दर-वर्ष 23.9 प्रतिशत (व-द-व) की गिरावट से अर्थव्यवस्था पर भारी प्रहार हुआ।

अत्यधिक अस्थिरता के समय में, प्रगामी नीति के लिए कठिन चुनौतियों का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के वर्तमान और भविष्य के दृष्टिकोण का पता लगाना कठिन हो जाता है। विविध संकेतकों से उभरने वाले परस्पर विरोधी संकेतों का अर्थ अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति के लिए अलग-अलग हो सकता है। तथ्य यह है कि आधिकारिक जीडीपी अनुमान लगभग दो महीने के अंतराल में उपलब्ध होने के कारण कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। तेजी से बदलते परिवेश में, समय बहुत महत्वपूर्ण है और आधिकारिक आँकड़ों की उपलब्धता में देरी से

अनुकूल नीतिगत निर्णय लेने में बाधाएं आती हैं। इस पृष्ठभूमि में, आर्थिक गतिविधियों के छोटे अंतराल के उच्च आवृत्ति संकेतक, प्रगामी नीति की सहायता के लिए अर्थव्यवस्था के वास्तविक समय ट्रैकिंग हेतु एक विकल्प प्रदान करते हैं।

तदनुसार, केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख और समवर्ती गतिविधि संकेतकों से लगातार मिलने वाली जानकारी के एक मेजबान पर भरोसा करते हैं ताकि वास्तविक समय पर अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति का पता लगाया जा सके। अर्थमितीय मॉडलिंग और कम्प्यूटेशनल शक्ति में हाल के घटनाक्रमों ने अत्याधुनिक, वास्तविक समय और निरंतर अद्यतन रूपरेखाओं का समर्थन किया है जो जीडीपी की वर्तमान गतिशीलता का अनुमान करने के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकेतकों में उपलब्ध जानकारी का संश्लेषण करते हैं। ये मॉडल स्थिर आर्थिक पैटर्न की पहचान करने हेतु विविध संकेतकों से जानकारी लेने के लिए परिष्कृत अर्थमितीय तरीकों, मशीन लर्निंग टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। कई केंद्रीय बैंकों ने "तात्कालिक अनुमान" मॉडल विकसित किए हैं, जिनका वर्तमान, बहुत निकट भविष्य और अतीत की गतिविधि संकेतकों पर जारी उच्च आवृत्ति डेटा (गियानोन, रीचिलन और स्मॉल (2008)) का उपयोग करके वास्तविक समय पर अनुमान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इस लेख में, भारत के लिए एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) के निर्माण का प्रयास किया गया है तथा सूचकांक का ति2:2020-21 के वास्तविक जीडीपी के तात्कालिक अनुमान हेतु उपयोग करना, साथ-साथ वास्तविक समय में अंतर्निहित तात्कालिक अनुमान मॉडल की सुदृढता का मूल्यांकन करना तथा नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए यह नियमित रूप से अद्यतन किया जा सके, इस अध्ययन की मुख्य प्रेरणा है।¹ इसके अलावा, कोविड व्यवधानों के बाद के क्षेत्रीय विकास की पहचान करने के लिए उद्योग, सेवाओं, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों का उपयोग

* यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के पंकज कुमार ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ ईएआई के निर्माण मॉडल में शामिल कई संकेतक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा तिमाही योजित सकल मूल्य (जीवीए) के अग्रिम अनुमानों को संकलित करने में उपयोग किए जाते हैं। एनएसओ द्वारा ति1: 2020-21 के लिए 31 अगस्त 2020 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट में जीवीए के संकलन में प्रयुक्त संकेतकों की सूची दी गयी है।

करके क्षेत्रीय सूचकांक बनाए गए हैं। इस लेख के शेष भाग को इस प्रकार नियोजित किया गया है। भाग II में संक्षिप्त साहित्य समीक्षा शामिल है। भाग III लेख में उपयोग किए जाने वाले डेटा और पद्धति के बारे में बताया गया है। भाग IV मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और भाग V में लेख समाप्त होता है।

II. साहित्य की समीक्षा

कुल आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने के लिए कई आर्थिक चक्र का दोहन करने पर व्यवसाय चक्र के मापन (बर्न्स एंड मिशेल, 1946) के रूप में साहित्य का मौलिक कार्य हुआ है। व्यवसाय चक्र स्वयं कई आर्थिक चक्र और क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव की व्यापकता के बीच सह-आन्दोलन है, जो किसी न किसी समकालिकता के साथ होता है (ज़र्वाइट्ज़, 1991)।

इस अंदाज में, व्यवसाय चक्रों को समझाने के लिए अधिक औपचारिक और गणितीय सटीक मॉडलों की शुरुआत को भी एक मौलिक योगदान माना जाता है। इस उद्देश्य के लिए, एक "अप्रेषित एकल सूचकांक" या "गतिशील कारक" का अनुमान है, जो दो स्टोचस्टिक घटकों से प्रभावित है - एक, संकेतकों में सह-आंदोलन को चलाने वाले एकल सूचकांक और दो, विशेष प्रकृति घटक और माप त्रुटियाँ। अप्रेषित एकल सूचकांक की चार श्रृंखलाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति के रूप में व्याख्या की है: औद्योगिक उत्पादन; वास्तविक व्यक्तिगत आय कम हस्तांतरण भुगतान; वास्तविक विनिर्माण और व्यापार बिक्री; और गैर कृषि प्रतिष्ठानों में कर्मचारी घंटे (स्टॉक और वाटसन, 1989)।

डायनेमिक फैक्टर मॉडल से जीडीपी जैसे तात्कालिक अनुमान कम आवृत्ति चक्र का उपयोग हाल ही में लोकप्रिय (गिनानोन, रिचलिन और स्मॉल, 2008) हुआ है। केंद्रीय बैंक भी तेजी से प्रमुख चक्र के निकट अवधि के अनुमानों के लिए तात्कालिक अनुमान मॉडल पर निर्भर कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यू यॉर्क का अब तक का मॉडल इन योगदानों पर आधारित है और यह दर्शाता है कि तिमाही के लिए प्रासंगिक उच्च आवृत्ति डेटा का परिवर्धन और अद्यतन, तात्कालिक अनुमान प्रदर्शन (बोक और अन्य, 2017) में सुधार करता है। दूसरी ओर, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा का जीडीपीनाउ नामक तात्कालिक अनुमान मॉडल मासिक स्रोत डेटा को

जीडीपी उप-घटकों में मैप करने के लिए एक ब्रिज समीकरण दृष्टिकोण का उपयोग करता है तथा वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा उपयोग किए गए तरीकों की नकल करता है (हिर्गिस, 2014)। आधिकारिक आंकड़ों (अनेस्टी और अन्य, 2017) के जारी होने से पहले चालू तिमाही में बैंक ऑफ इंग्लैंड का जीडीपी तात्कालिक अनुमान मौद्रिक नीति समिति के आर्थिक वृद्धि अनुमान का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर, केंद्रीय बैंकों के तात्कालिक अनुमान सांख्यिकीय मॉडल के एक सूट द्वारा सूचित किए जाते हैं, जो सावधानी से अनुमान और निर्णय द्वारा थोपे जाते हैं, और आर्थिक गतिविधि, सर्वेक्षण तथा वित्तीय बाजारों पर सभी उपलब्ध उच्च आवृत्ति डेटा को दर्शाते हैं।

हालांकि अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, तात्कालिक अनुमान साहित्य में उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को शामिल किया गया है। यह प्रमुख वृहद आर्थिक चक्रों के बारे में जानकारी की कमी के मामले में (उदाहरण के लिए रोजगार और आय) डेटा अंतराल और अज्ञात मूल्यों के रूप में, छोटे नमूना आकार और अत्यधिक अस्थिरता, की विशिष्ट चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। डायनेमिक फैक्टर मॉडल ब्राजील, रूस, भारत, चीन, और मेक्सिको (बीआरआईसी + एम) में वास्तविक जीडीपी वृद्धि को तात्कालिक अनुमान करने के लिए नियोजित किया गया है और विश्वसनीय (डालहाउस और अन्य, 2017) पाया गया। भारत पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक और उल्लेखनीय योगदान पाया गया है कि अनुमानों में सुधार तब होता है जब अधिक समय पर अंतरराष्ट्रीय डेटा स्रोतों से अतिरिक्त चक्र (ब्रागोली और फोस्टन, 2017) शामिल होते हैं। वर्तमान तिमाही जीडीपी अनुमान के लिए मासिक संकेतकों में जानकारी का उपयोग करके एक ब्रिज समीकरण दृष्टिकोण भारतीय मामले में नियोजित किया गया है (भट्टाचार्य और अन्य 2011)।

III. डेटा और कार्यप्रणाली

अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति को मापने के लिए अध्ययन में उद्योग, सेवाएं, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ताईस मासिक संकेतकों का उपयोग किया गया है (सारणी 1)।² नमूना अप्रैल 2004 से सितंबर 2020

² यह संकेतक, ज्यादातर सॉफ्ट सर्वे डेटा या वित्तीय संकेतकों के बजाय मुश्किल आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें 60 से अधिक संभावित संकेतकों से चुना जाता है।

सारणी 1: उच्च-आवृत्ति संकेतक

उद्योग	सेवा	वैश्विक	विविध
आईआईपी	घरेलू हवाई यात्री यातायात	यूएस औद्योगिक उत्पाद	सकल कर
ऑटोमोबाइल बिक्री (कुल)	घरेलू एयर कार्गो यातायात	बाल्टिक ड्राय इंडेक्स	जॉब स्पिक इंडेक्स
गैर तेल निर्यात	पोर्ट कार्गो यातायात	यूएस परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स -एमएफजी	खाद्येतर ऋण
गैर-तेल-गैर-सोने का आयात	रेल मालभाड़ा	ओइसीडी कंपोजिट लिडिंग इंडिकेटर्स	व्यापक मुद्रा (एम3)
परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स -एमएफजी	विदेशी पर्यटकों का आगमन	यूएस पेरोलस	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक -खाद्येतर
बिजली आपूर्ति	परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स - सेवा		कूड की कीमत (ब्रेट दुबई तथा डब्ल्यूटीआई का औसत)
ट्रेक्टर बिक्री	ईंधन की खपत		
	सीमेंट उत्पादन		
	स्टील की खपत		

तक का है। ये संकेतक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। उन्हें पूरे महीने में अलग अलग तरीके से जारी किया जाता है (अनुबंध सारणी ए (iii))।

डायनेमिक फैक्टर मॉडल

समय-श्रृंखला अर्थमितीय में हाल ही में हुई प्रगति ने संकेतकों की अधिकता से जानकारी का सार निकालने के लिए स्वचालित प्लेटफार्म प्रस्तुत किए हैं। मूलतः, यह विशेष प्रकृति और माप त्रुटियों (नॉइज) के उतार चढ़ाव (संकेत) में व्यापक सह आंदोलन को अलग करने की एक संकेत निष्कर्षण समस्या को हल करता है। डायनेमिक फैक्टर मॉडल कुछ सामान्य कारकों (बॉक और अन्य 2017) के समष्टि आर्थिक संकेतकों में सामान्य उतार-चढ़ाव को देखने के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक गतिशील कारक मॉडल का सामान्य विवरण इस प्रकार है:

$$y_{it} = \lambda_{i,1}f_{1,t} + \dots + \lambda_{i,r}f_{r,t} + e_{i,t}, \quad i = 1, \dots, n \quad (1)$$

जहां y_i संकेतक है, f_j अव्यक्त आम कारक है और λ_{ij} संकेतक y_i पर f_j का कारक लोड है। संकेतक के विशेष प्रकृति घटक को ईआईटी शब्द द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार, किसी

भी संकेतक में देखे गए संचार में दो अव्यक्त घटक शामिल हैं - आम कारकों से प्रेरित एक सामान्य घटक, और प्रत्येक संकेतक के लिए विशिष्ट एक विशेष प्रकृति घटक। डायनेमिक फैक्टर मॉडल का वर्णन एक स्टेट-स्पेस फॉर्म में किया जाता है, जहां (1) ऑब्जर्वेशन समीकरण है और सामान्य कारकों और विशेष प्रकृति त्रुटियों को पहचानने वाली ऑटोरिग्रेसिव प्रक्रिया संक्रमण समीकरणों का प्रतिनिधित्व करता है। मॉडल का उपयोग कलमैन फिल्टर और एक्सपेक्टेडेशन - मैक्सिमाईजेशन (ईएम) एल्गोरिदम (बोक और अन्य 2017) का उपयोग करके किया गया है। सभी संकेतकों को मानकीकृत वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त किया जाता है।

उपर वर्णित मॉडल को वास्तविक समय में मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों की निगरानी के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह मिश्रित आवृत्ति, अज्ञात मान और अ समकालिक प्रकाशित डेटा शामिल करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। कलमैन फिल्टर एल्गोरिदम डायनेमिक फैक्टर और अन्य मॉडल मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए संकेतक के अनुमानित (या अपेक्षित) मूल्य का उपयोग करता है। जिनका आवर्ती अद्यतन किया जाता है यदि संकेतक का वास्तविक मूल्य, अनुमानित मूल्य से अलग है। इस प्रकार, कलमैन फिल्टर डेटा की अनियमितताओं से निपटने के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करता है (बॉक और अन्य, 2017; बंबुरा और अन्य, 2013)।

एकल सामान्य कारकों का अनुमान पहले सभी सत्ताईस संकेतकों को एक साथ लेकर उद्योग, सेवाएं, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों के सबसेट के लिए अलग से किया जाता है तथा इसके बाद अनुमानित एकल सामान्य कारक f_t का उपयोग सिरियल कोरिलेशन के लिए बायवेरिएट रिग्रेशन लेखांकन का उपयोग करके वर्तमान तिमाही जीडीपी वृद्धि के तात्कालिक अनुमान हेतु किया जाता है।⁴ मॉडल विवरण नीचे दिया गया है।

³ अनुबंध चार्ट ए (i) आम कारक और संकेतकों को एक साथ प्रस्तुत करता है। अनुबंध चार्ट ए (ii) कारक लोडिंग प्रस्तुत करता है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग और सेवाओं के सूचकांक वैश्विक और विविध संकेतकों की तुलना में अधिक प्रभावी है।

⁴ सत्ताईस मासिक उच्च आवृत्ति संकेतकों से प्राप्त मासिक गतिशील कारक साधारण औसत से तिमाही आधार पर परिवर्तित किया जाता है। रिग्रेशन मॉडल में तिमाही लक्ष्य चर जीडीपी के लिए मैप करने के लिए तिमाही श्रृंखला का उपयोग किया जाता है।

$$GDPGr_t = \beta_0 + \beta_1 f_t + u_t, \quad (2)$$

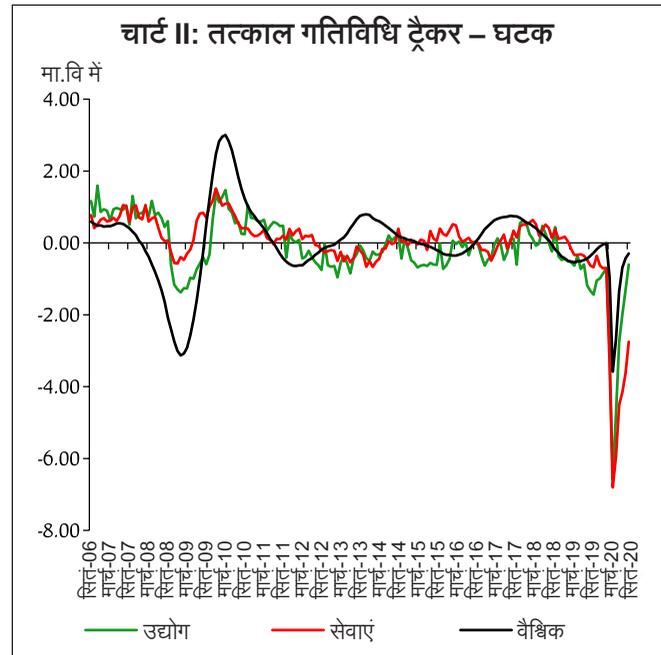
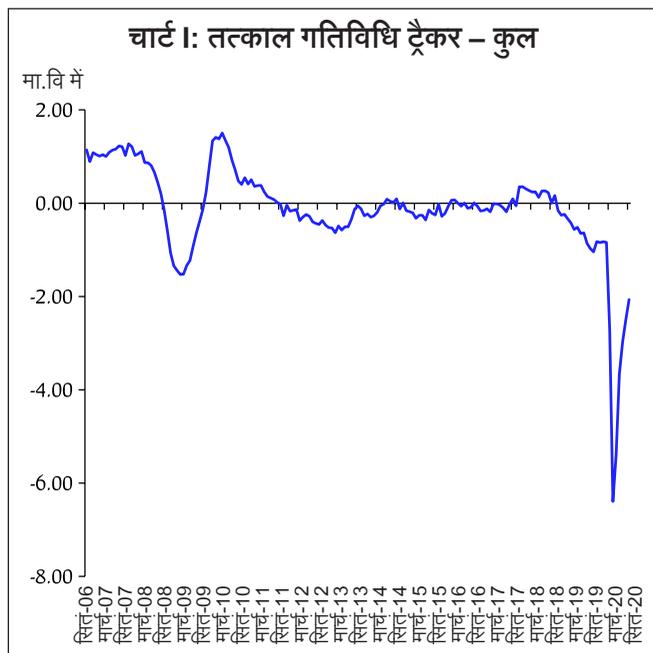
$$u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3)$$

मॉडल विवरण का तात्पर्य है कि जीडीपी वृद्धि का सशर्त पूर्वानुमान (या तात्कालिक अनुमान) समकालीन डायनेमिक फैक्टर f_t और पिछले त्रुटि दोनों से प्रेरित है।

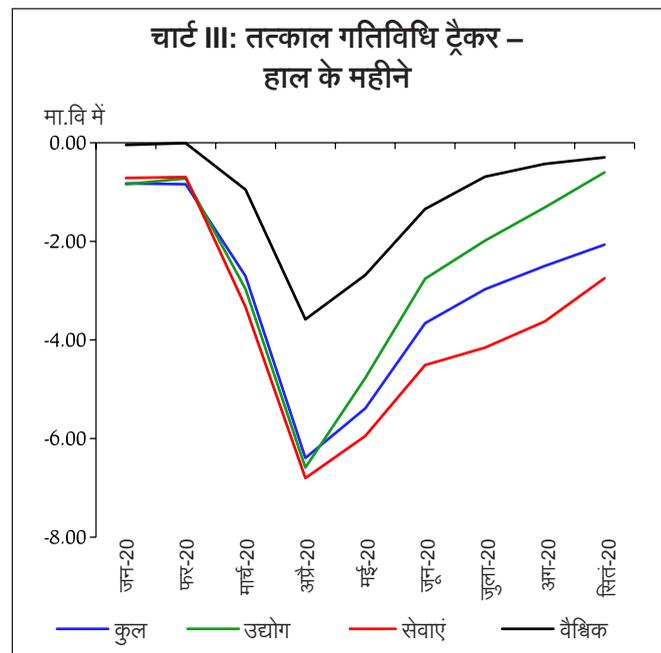
IV. तात्कालिक अनुमान परिणाम

डायनेमिक सामान्य फैक्टर, जिसे आर्थिक गतिविधि का समग्र सूचकांक कहा जाता है, चार्ट I में प्रस्तुत किया गया है। यह देखा गया है कि सूचकांक, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी), बाद की बहाली और हाल ही में 2018-19 से शुरू मंदी जैसी प्रमुख आर्थिक घटनाओं को कैप्चर करता है। इसके अलावा, यह पता चलता है कि कोविड-19 के बाद गतिविधियों में असफलता, जीएफसी के दौरान की तुलना में बहुत तेज थी। हाल के महीनों पर ध्यान केंद्रित करने पर, यह देखा गया है कि लॉकडाउन के मद्देनजर अप्रैल में -6.4 तक बढ़ने के बाद, सितंबर 2020 में सूचकांक धीरे-धीरे -2.1 तक बहाल हुआ। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था फिर से खुलने के कारण मई और जून में तेज उभार आया लेकिन जुलाई-सितंबर में कुछ धीमा हो गया।

क्षेत्रीय विविधताओं को रेखांकित करने के लिए, उद्योग, सेवाएं और वैश्विक गतिविधियों के लिए अलग सूचकांकों का



निर्माण किया गया है (चार्ट II)। हाल के महीनों पर ध्यान केंद्रित करने पर (चार्ट III), यह देखा गया है कि उद्योग और सेवा गतिविधियों दोनों में गिरावट लॉकडाउन के मद्देनजर समकालिक और समान परिमाण की थी, जबकि उद्योग में बहाली अधिक तेजी से आयी और सेवाओं के लिए बहुत धीमी रही। इस प्रकार, विश्लेषण से यह पता चलता है कि संपर्क-सघन सेवा क्षेत्रों (जैसे, खुदरा व्यापार, परिवहन, होटल और रेस्तरां, और मनोरंजन) में



टू-स्पिड बहाली देखी गयी, जो निरंतर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण सुस्त थी।⁵ इसके अलावा, घरेलू उद्योग और सेवा सूचकांकों के विपरीत वैश्विक सूचकांक में कुछ हद तक गिरावट आई है और जुलाई-सितंबर में कुछ टेपरिंग के बावजूद बेहतर बहाली भी हुई है।

भाग III में समीकरण 2 और 3 में वर्णित बायवेरिएट रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके जीडीपी वृद्धि तात्कालिक अनुमान के लिए आर्थिक गतिविधियों के समग्र सूचकांक का उपयोग किया गया है (सारणी 2)। मॉडल 1 एक यथोचित उच्च विनिर्देशन है जिसमें समायोजित आर-वर्ग और अवशिष्ट ऑटोकोरिलेशन का कोई सबूत नहीं है। गतिविधि सूचकांक पर गुणांक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है तथा सूचकांक काफी हद तक जीडीपी डायनेमिक को स्पष्ट करता है। अनुमानित गुणांक और गतिविधि के वर्तमान तिमाही सूचकांक का उपयोग करना, ति 2:2020-21 के लिए जीडीपी वृद्धि तात्कालिक अनुमान (-) 8.6 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (चार्ट IV) है।⁶ तात्कालिक अनुमान के लिए 90 प्रतिशत

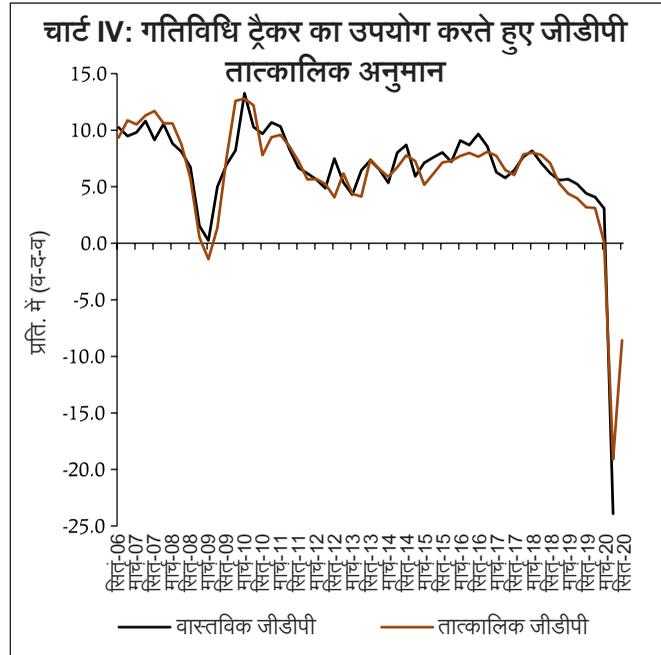
सारणी 2: रिग्रेशन अनुमान

आश्रित चर (वर्ष दर वर्ष)	जीडीपी		जीडीपी-कृषितर	जीडीपी-उद्योग	जीडीपी-सेवा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गतिविधि सूचकांक - कुल	5.568 (0.174)	4.410 (0.259)	6.081 (0.133)		
गतिविधि सूचकांक - उद्योग				6.952 (0.321)	
गतिविधि सूचकांक - सेवाएं					5.418 (0.181)
एआर (1)	0.641 (0.104)		0.751 (0.089)	0.600 (0.109)	0.612 (0.128)
स्थिर	6.597 (0.603)	6.767 (0.241)	7.086 (0.982)	6.171 (0.935)	7.715 (0.509)
समायोजित आर-स्क्वेअर	0.855	0.820	0.862	0.726	0.873
डीडब्ल्यू स्टेट	1.913	1.155	1.679	2.160	2.055
क्यू-स्टेटिस्टिक्स (12 अंतराल, पी-मूल्य)	0.954	0.011	0.233	0.000	0.448

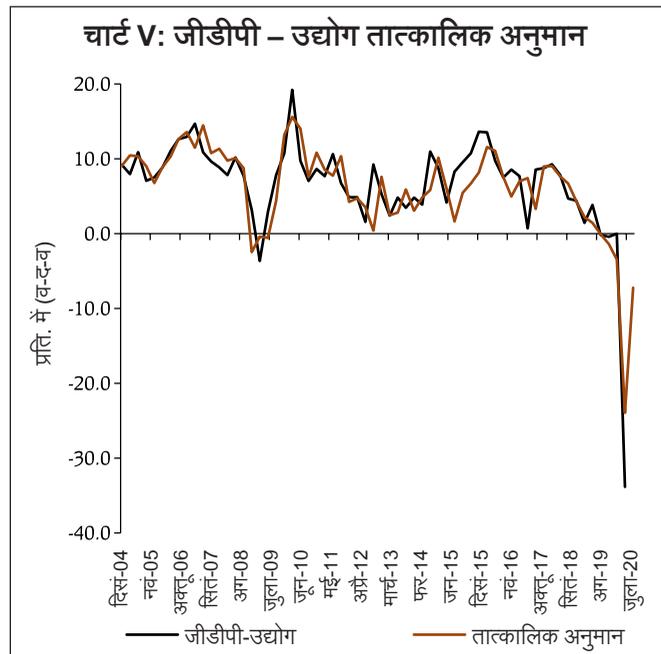
टिप्पणी: कोष्टक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियां हैं।

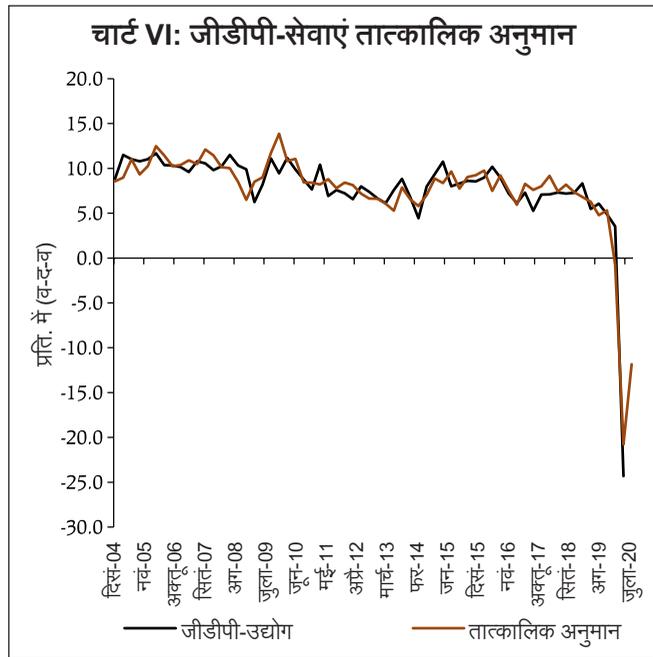
⁵ उद्योग और सेवाओं के बीच ठोस पूरकता देखी गयी है, उदाहरण के लिए, परिवहन के लिए सामान और कार तथा कपड़े और जूते खरीदने वाले लोगों में यदि उन्हें अधिक बार बाहर जाने की आवश्यकता होती है, तो अंततः अंतर कम हो सकता है। इसके अलावा, आईटी, ऑनलाइन खरीद और मनोरंजन जैसे कुछ सेवा क्षेत्रों को भौतिक संपर्कों पर निर्भर पारंपरिक सेवा क्षेत्रों का विकल्प देने पर लाभ होने की संभावना है।

⁶ ति 2- 2020-21 के लिए अक्टूबर अंत तक उपलब्ध उच्च आवृत्ति डेटा के आधार पर वृद्धि का तात्कालिक अनुमान अक्टूबर के शुरुआती डेटा का उपयोग करते हुए (-) 9.8 प्रतिशत से कुछ अधिक है। अगस्त के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और सीमेंट उत्पादन, रेल माल, बंदरगाह कार्गो, एयर कार्गो, गैर-तेल-गैर-सोने के आयात, ईंधन और इस्पात की खपत और सितंबर के महीने के लिए बिजली की आपूर्ति जैसे कुछ उच्च आवृत्ति संकेतक अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।



विश्वास अंतराल (-)4.8 - (-)12.3 प्रतिशत है। इसके अलावा, मॉडल 3, 4 और 5 गैर-कृषि, उद्योग और सेवाओं के लिए अलग से जीडीपी अनुमान करता है और सेवा क्षेत्र के लिए एक उच्च इन-सैंपल फिट का सुझाव देता है; उद्योग के लिए, क्यू-स्टेट, शेष उच्च क्रम अवशिष्ट आटोकोरिलेशन का सुझाव देता है। फिर भी, उद्योग और सेवाओं के लिए व्यक्तिगत गतिविधि सूचकांक क्षेत्रीय जीडीपी का चलन दर्शाता है (चार्ट V और VI)।





V. निष्कर्ष

कोविड-19 के कारण आर्थिक स्थितियों में तेज उतार-चढ़ाव ने स्विफ्ट इंटेलिजेंस पर प्रीमियम लगा दिया है। यह अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की पहचान करने के लिए लगातार प्रवाहित डेटा की बड़ी मात्रा के माध्यम से विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। डायनेमिक फैक्टर मॉडल उच्च आवृत्ति गतिविधि संकेतकों की मेजबानी से अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति मापने के लिए एक लोकप्रिय उपकरण बन गया है। तदनुसार, यहां निर्मित

आर्थिक गतिविधि सूचकांक एनएसओ के अग्रिम तिमाही जीडीपी के अनुमानों का एक कुशल कारक है। सूचकांक की हाल ही में गतिशीलता से पता चलता है कि आर्थिक गतिविधि में अप्रैल 2020 से गर्त के बाद एक क्रमिक बहाली हो रही है, जिसमें जुलाई-सितंबर 2020 के दौरान कुछ नरमी आई। मार्च और अप्रैल में क्षेत्रीय सूचकांकों में समकालिक गिरावट आई है, लेकिन बहाली चरण बदल गए हैं, निरंतर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण संपर्क-प्रधान सेवा क्षेत्रों की तुलना में उद्योग तेजी से सामान्य हो गया है। सूचकांक नमूना जीडीपी की गतिशीलता को काफी अच्छी तरह से ट्रैक करता है और भारत में संयोग जानकारी के नीति मैट्रिक्स में विचार प्रस्तुत करता है। विश्लेषण से निम्नलिखित नीतिगत निहितार्थ सामने आते हैं:

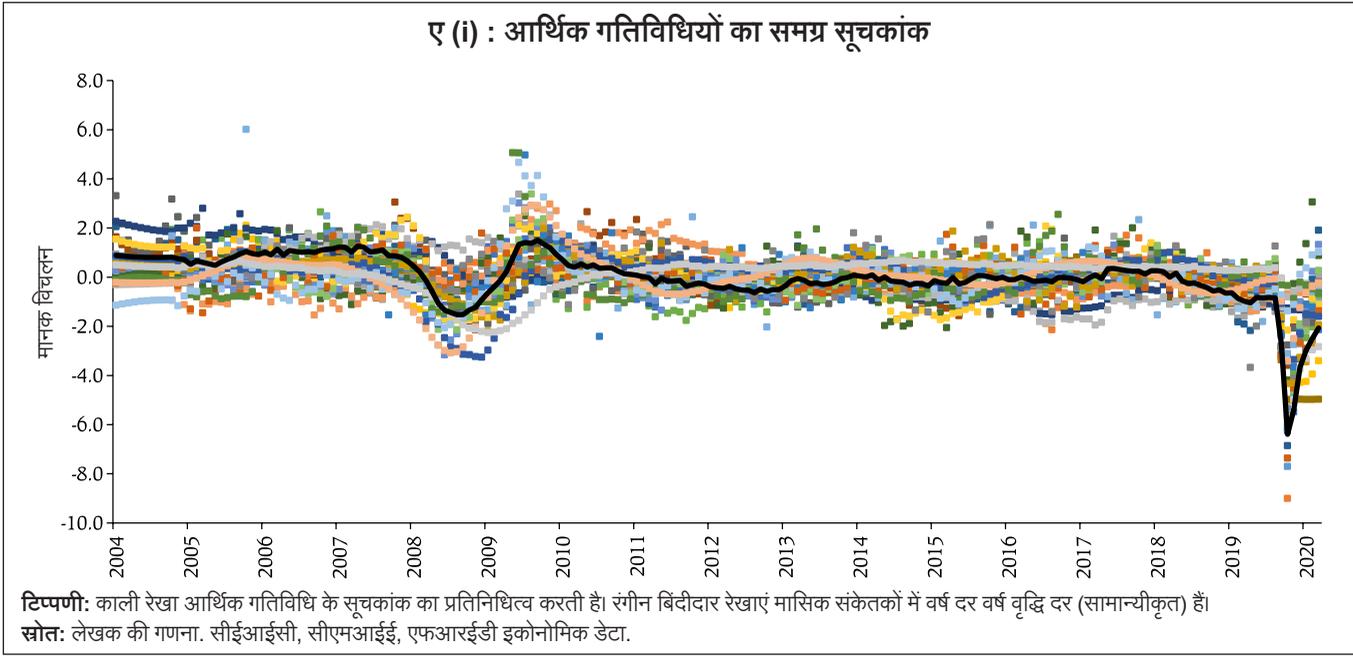
- अपने इतिहास में पहली बार भारत ने 2020-21 की पहली छमाही में तकनीकी मंदी में प्रवेश किया है, जिसमें ति 2:2020-21 में जीडीपी संकुचन लगातार दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड होने की संभावना है।
- गतिविधियों में क्रमिक सामान्यीकरण के साथ संकुचन कम हो रहा है और अल्पकालिक होने की उम्मीद है।
- आधिकारिक प्रकाशन के पहले जीडीपी वृद्धि में दिशात्मक संचार मापने के लिए आर्थिक गतिविधि सूचकांक का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है।

संदर्भ

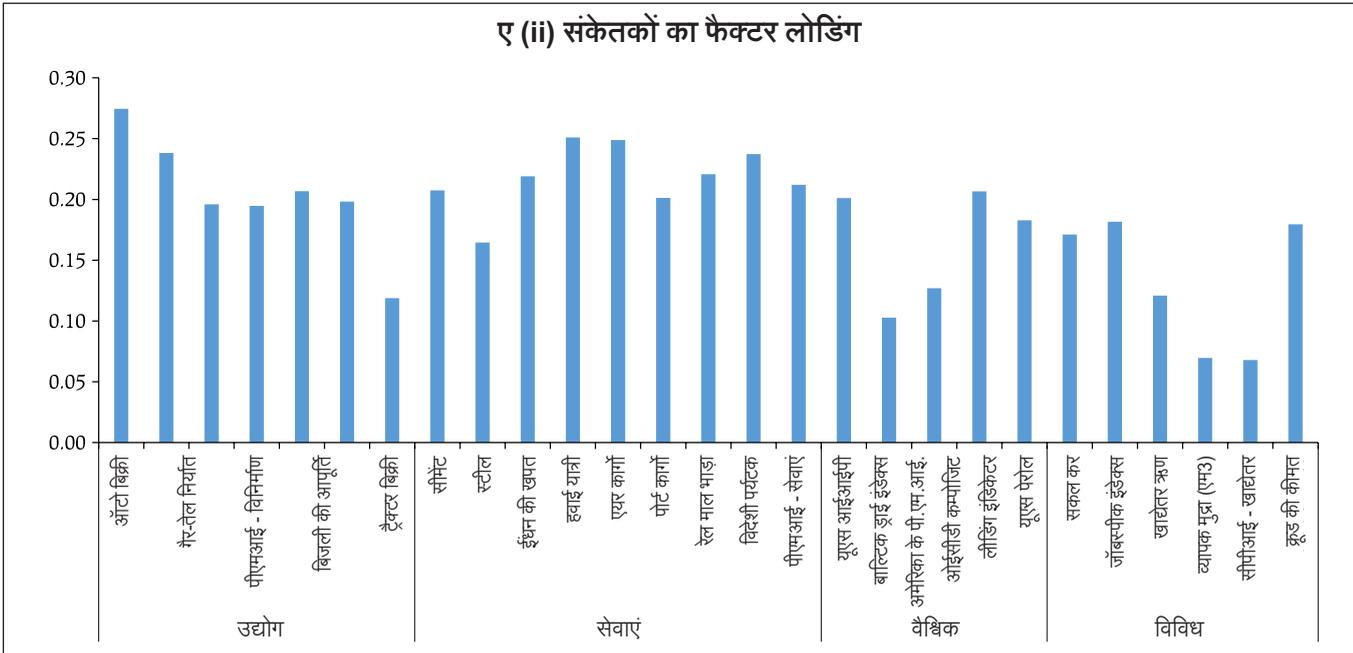
- Anesti, N., S. Hayes, A. Moreira and J. Tasker (2017). Peering into the present: the Bank's approach to GDP nowcasting. *Quarterly Bulletin: Q2*, Bank of England.
- Banbura, M., D. Giannone, M. Modugno, and L. Reichlin (2013). Nowcasting and the Real-Time Data Flow. In G. Elliott and A. Timmermann, eds., *Handbook of Economic Forecasting*, Vol. 2. Amsterdam: Elsevier-North Holland.
- Bhattacharya, R., R. Pandey and G. Veronese (2011). Tracking India Growth in Real Time. *National Institute of Public Finance and Policy, Working Papers 2011/90*.
- Bok, B., D. Caratelli, D. Giannone, A. Sbordone and A. Tambalotti (2017). Macroeconomic Nowcasting and Forecasting with Big Data. *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports*.
- Bragoli, D. and Fosten, J. (2018). Nowcasting Indian GDP. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. 80(2) 259-282.
- Burns, A. F. and W. C. Mitchell (1946). Measuring Business Cycle. *NBER Book Series*.
- Dahlhaus, T., J. Guénette and G. Vasishtha (2017). Nowcasting BRIC+M in real time. *International Journal of Forecasting*. 33(4) 915-935.
- Giannone, D., L. Reichlin and D. Small (2008). Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data. *Journal of Monetary Economics*. 55(4) 665-676.
- Higgins, P. (2014). GDPNow: A Model for GDP "Nowcasting". *Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper Series 2014-7*.
- Stock, J. and M. Watson (1989). New Indexes of Coincident and Leading Economic Indicators. *Macroeconomics Annual, National Bureau of Economic Research*. 4, 351-409.
- Zarnowitz, V. (1991). What is a Business Cycle? *NBER Working Paper No. 3863*, October.

अनुबंध – चार्ट और सारणी

ए (i) : आर्थिक गतिविधियों का समग्र सूचकांक



ए (ii) संकेतकों का फेक्टर लोडिंग



ए (iii). संकेतक जारी करने में प्रकाशन अंतराल

संकेतक	प्रकाशन अंतराल (अनुमानित)
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	6 सप्ताह
ऑटो बिक्री	2 सप्ताह से कम
गैर-तेल निर्यात	2 सप्ताह
गैर-तेल-गैर-सोने का आयात	2 सप्ताह
पीएमआई - विनिर्माण	एक दिन
बिजली की आपूर्ति	1 सप्ताह से कम
ट्रेक्टर बिक्री	2 सप्ताह से कम
सीमेंट उत्पादन	1 महीना
स्टील की खपत	7 सप्ताह
ईंधन की खपत	2 सप्ताह से कम
हवाई यात्री	3-4 सप्ताह
एयर कार्गो	3-4 सप्ताह
पोर्ट कार्गो	1 सप्ताह
रेल माल भाड़ा	1 सप्ताह
विदेशी पर्यटक	2-3 सप्ताह
पीएमआई - सेवाएं	1 सप्ताह से कम
यूएस आईआईपी	1.5 महीने
बाल्टिक ड्राई इंडेक्स	दैनिक (बिना अंतराल)
अमेरिका के पी.एम.आई.	एक दिन
ओईसीडी कम्पोजिट लीडिंग इंडिकेटर	1 महीने से अधिक
यूएस पेट्रोल	दो दिन
सकल कर	1 महीना
जॉबस्पीक इंडेक्स	2 सप्ताह से कम
खाद्येतर ऋण	2 सप्ताह
व्यापक मुद्रा (एम3)	2 सप्ताह
सीपीआई - खाद्येतर	2 सप्ताह से कम
कूड की कीमत	दैनिक (बिना अंतराल)

हाउसहोल्ड वित्तीय बचतों के प्रारंभिक अनुमान – 2020-21 की पहली तिमाही*

2020-21 की पहली तिमाही में हाउसहोल्ड वित्तीय बचतों के प्रारंभिक अनुमानों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है जो कि कोविड-19 के बाद बनी परिस्थितियों के कारण अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की हाउसहोल्ड वित्तीय बचतों में हुई वृद्धि के अनुरूप ही है। भारत में हाउसहोल्ड वित्तीय बचतों में हुई बड़ी वृद्धि बेमौसमी है और ऐसा लगता है कि यह कोविड-19 के कारण विवेकपूर्ण खर्च में आयी कमी और इसी से जुड़ी जबरन बचत तथा निकट भविष्य में आय के प्रवाह से जुड़ी चिंताओं के कारण एहतियातन की जाने वाली बचत का प्रभाव है। वित्तीय बचतों में हुई वृद्धि का जो अनुमान व्यक्त किया गया है, वह अन्य उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों से मेल खाता है, खास तौर पर निजी अंतिम उपभोग खर्च में आयी गिरावट से एवं बाह्य चालू खाते में उत्पन्न अधिशेष की स्थिति से।

भूमिका

जून 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में हाल के तीन वर्षों में (2017-18 से 2019-20) हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं के तिमाही आंकड़े (जिसमें हाउसहोल्ड वित्तीय बचतें भी शामिल हैं) प्रकाशित किए गए थे। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कोविड-19 के प्रभाव, जो कि जीडीपी के शुरुआती सरकारी आंकड़ों से पहले ही स्पष्ट हो चुका है, के कारण महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक संकेतकों से जुड़े आंकड़ों में उत्पन्न हुए बड़े अंतराल के मद्देनजर इस आलेख में 2020-21 की पहली तिमाही के लिए हाउसहोल्ड वित्तीय बचत के प्रारंभिक अनुमान व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस तिमाही के दौरान भारत के जीडीपी में वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर 23.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ और निजी उपभोग में 26.7 प्रतिशत (व-द-व) की गिरावट आयी, जिससे हाउसहोल्ड बचत में भी समतुल्य बड़े बदलावों के संकेत मिलते हैं। कोविड-19 का प्रभाव कितना पड़ा,

* यह लेख राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के संजय कुमार हांसदा, अनुपम प्रकाश और आनंद प्रकाश एक्का द्वारा तैयार किया गया है। लेखकगण डॉ. मृदुल कुमार सागर के आभारी हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट पर गहन विचार-विमर्श के लिए अपना समय दिया। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

इसका सटीक आकलन करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इससे जुड़े जो भी अंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं वे काफी पीछे के हैं। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान जहाँ एक ओर हाउसहोल्ड वित्तीय बचत के प्रमुख निर्धारकों, मुख्य रूप से आय (जीडीपी) और ब्याज दर में काफी परिवर्तन हुआ, वहीं गैर-जरूरी वस्तुओं के उपभोग में, एहतियातन बचत और उपभोग सुगमता के लिए हाउसहोल्ड्स द्वारा उधार/कर्ज लेने में भी बदलाव देखा गया। इस आलेख को मूर्त रूप देने के पीछे निहित प्रमुख प्रेरणा है - हाउसहोल्ड वित्तीय बचत जैसे एक अति महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक चर के बारे में विद्यमान सूचना के अभाव को दूर करना।

शेष आलेख पाँच भागों में विभाजित है। भाग II में समग्र रूप से हाउसहोल्ड वित्तीय बचत के प्रारंभिक अनुमानों पर चर्चा की गयी है। भाग III कोविड-19 के कारण हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में हुई वृद्धि की जाँच वैश्विक परिप्रेक्ष्य में करता है। भाग IV हाउसहोल्ड वित्तीय आस्तियों और देयताओं में बैंकिंग क्षेत्र के लिखतों के वर्चस्व को दर्शाता है। भाग V में हाउसहोल्ड्स के तुलन-पत्र के आस्ति और देयता दोनों पक्षों में हुए महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। भाग VI में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। हाउसहोल्ड वित्तीय आस्तियों और देयताओं में लिखत-वार निधि-प्रवाह की सारणीबद्ध प्रस्तुति अनुबंध में देखी जा सकती है।

II. प्रारंभिक अनुमान: प्रमुख आंकड़े

इस आलेख में प्रस्तुत प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि 2020-21 की पहली तिमाही में घरेलू वित्तीय बचत में सकल घरेलू उत्पाद के 21.4 प्रतिशत के समतुल्य वृद्धि हुई है जो कि 2019-20 की पहली तिमाही के 7.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही के 10.0 प्रतिशत से अधिक है (सारणी 1)।

संभव है कि हाउसहोल्ड्स में महामारी के दौरान बचत की प्रवृत्ति मुख्य रूप से दो कारणों से उत्पन्न हुई हो। पहला, हाउसहोल्ड्स अपने सामान्य स्तर तक उपभोग करने में असमर्थ हो जाने के कारण अधिक बचत करने के लिए मजबूर हुए हों। कोविड-पूर्व की अवधि के दौरान वे जितनी चीजों का उपभोग किया करते थे, संभवतः अब उनकी संख्या अपेक्षाकृत सीमित रह गयी हो। दूसरा, यह भी हो सकता है कि उन्होंने भविष्य में अपनी आय के बारे में अनिश्चितता के कारण अपनी एहतियाती बचत को बढ़ा दिया हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों से इस प्रकार की चेतावनी भरी प्रतिक्रियाएं मिलती रही हैं जिनमें नौकरियाँ वास्तव

सारणी 1: हाउसहोल्ड वित्तीय बचत

₹ लाख करोड़

	2018-19					2019-20					2020-21
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1*
वित्तीय बचत (ए-बी)	2.76 (6.1)	2.29 (4.9)	2.13 (4.4)	6.56 (13.2)	13.73 (7.2)	3.86 (7.9)	4.31 (8.8)	3.31 (6.4)	5.32 (10.0)	16.81 (8.3)	8.16 (21.4)
ए. वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रवाह	3.58 (7.9)	4.82 (10.4)	3.52 (7.3)	9.31 (18.8)	21.23 (11.1)	3.90 (7.9)	5.70 (11.6)	5.47 (10.6)	7.13 (13.4)	22.19 (10.9)	8.27 (21.7)
बी. वित्तीय देनदारियों का प्रवाह	0.83 (1.8)	2.53 (5.5)	1.38 (2.9)	2.75 (5.6)	7.50 (3.9)	0.03 (0.1)	1.39 (2.8)	2.16 (4.2)	1.80 (3.4)	5.38 (2.6)	0.11 (0.3)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

*: अनुमान इस धारणा पर आधारित हैं कि जमा राशियों में हाउसहोल्ड्स की हिस्सेदारी उतनी ही बनी हुई है जितनी 2019-20 की चौथी तिमाही में थी।

स्रोत: लेखकों द्वारा गणना

में छूट जाने और भविष्य में छूटने की आशंका की बातें की जाती रही हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2019-20 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में हाउसहोल्ड्स की वित्तीय बचत के प्रारंभिक अनुमान व्यक्त करते हुए इसे सकल घरेलू उत्पाद का 7.7 प्रतिशत (जीएनडीआई का 7.6 प्रतिशत) बताया था जो अब संशोधित होकर जीडीपी का 8.3 प्रतिशत हो गयी है¹। इस लेख में 2018-19 से सीरीज को भी अपडेट किया गया है। आंकड़ों में हुए इस संशोधन में मुख्य योगदान बैंक ऋण, बैंक जमा में हाउसहोल्ड्स की हिस्सेदारी और हाउसहोल्ड्स द्वारा बीमा पॉलिसियों को खरीदने संबंधी अद्यतन जानकारी का है।

III. वैश्विक स्तर पर हाउसहोल्ड्स बचत को बढ़ाने में कोविड-19 का प्रभाव

वैश्विक रूप से, COVID-19 के कुप्रभाव के कारण लॉकडाउन में हाउसहोल्ड्स में एहतियाती बचत / जबरन बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह जबरन बचत का तत्त्व इस प्रकार आया कि वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए उठाए गए लॉकडाउन के कदम से हाउसहोल्ड्स जितनी वस्तुओं का उपभोग पहले किया करते थे, उनमें से बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करने में वे अब असमर्थ हो गए। इसके अलावा, अचानक महामारी के प्रकोप के कारण भविष्य में उनकी आय से जुड़ी अनिश्चितता और विशेष रूप से, आगे चलकर बेरोजगारी के खतरे की वजह से एहतियाती बचत में वृद्धि हुई (एर्कोलानी, 2020)। हाउसहोल्ड्स बचत में

अचानक वृद्धि दुनिया भर के आधिकारिक आंकड़ों में देखी गयी। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, व्यक्तिगत बचत दर मार्च 2020 के 12.9% की तुलना में अप्रैल 2020 में बढ़कर 20.7 प्रतिशतता अंकों तक पहुंच गयी (प्रयोज्य आय की 33.6 प्रतिशत)², और यूके में 2020 की पहली तिमाही में हाउसहोल्ड्स बचत अनुपात³ प्रयोज्य आय के 9.6% से बढ़कर 2020 की दूसरी तिमाही में 29.1 प्रतिशत हो गया⁴। भारतीय संदर्भ में, कथित तौर पर यह देखा गया है कि जबरन बचत औपचारिक क्षेत्र में बढ़ी है क्योंकि वहाँ आय की निरंतरता बनी रही है, परंतु अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित श्रम का एक बड़े हिस्से ने अपना उपभोग तो घटाया ही है अपितु आय की निरंतरता न रहने तथा घटी हुई आय में भी एहतियातन बचत में वृद्धि की है⁵।

IV. हाउसहोल्ड्स की वित्तीय परिसम्पत्तियों / देयताओं में बैंकिंग लिखतों की बड़ी हिस्सेदारी

भारत में हाउसहोल्ड्स की वित्तीय बचत उनके द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में किए गए जमा और लिए गए उधार से अत्यधिक प्रभावित होती है। हाउसहोल्ड्स की वित्तीय परिसम्पत्तियों / देयताओं का

² "खर्च करने और करों का भुगतान करने के बाद लोगों के पास जो पैसा बचा रह जाता है, वह उनकी व्यक्तिगत बचत होती है। व्यक्तिगत बचत दर उनकी प्रयोज्य आय का प्रतिशत है जिसे लोग बचाते हैं", आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो, यूएसए।

³ आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो, यूएसए, वाणिज्य विभाग (<https://www.bea.gov/data/income-saving/personal-saving-rate>).

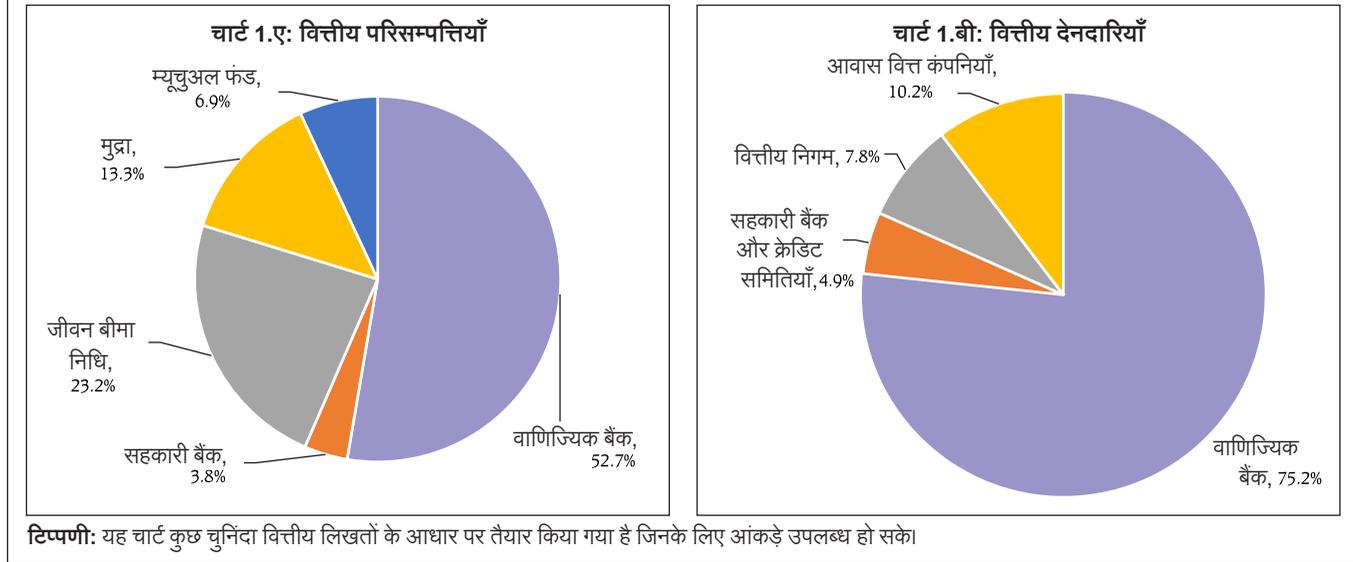
⁴ बचत अनुपात बचायी गयी प्रयोज्य आय का प्रतिशत होती है (घरेलू बचत को हाउसहोल्ड प्रयोज्य आय से विभाजित करके)।

⁵ राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, यूनाइटेड किंगडम (<https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/dgd8/ukea>).

⁶ ड इंडियन एक्सप्रेस, "सेक्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स सी राइज़ इन सेविंग्स आफ्टर लॉकडाउन", 09 जुलाई 2020, <https://indianexpress.com/article/business/sections-of-households-see-rise-in-savings-after-lockdown-6496812/>.

¹ राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जनवरी 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए हाउसहोल्ड्स वित्तीय बचत जीडीपी का 6.5 प्रतिशत रही है। एनएसओ द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए हाउसहोल्ड्स वित्तीय बचत के अनुमानित आंकड़े क्रमशः 29 जनवरी 2021 और 31 जनवरी 2022 को जारी किए जाएंगे।

चार्ट 1: हाउसहोल्ड वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का संघटन- बकाया की स्थिति (जून 2020 की स्थिति)



बड़ा हिस्सा बैंक जमा और बैंक ऋण का होता है, क्रमशः लगभग 56 प्रतिशत और 80 प्रतिशत⁷ (चार्ट 1.ए और 1.बी)।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जून 2020 में भारत में सकल बैंक जमाराशियों ने लगभग ₹138.7 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ है, जो मार्च 2020 के बाद से ₹3.0 लाख करोड़ की वृद्धि दर्शाता है, जबकि अग्रिमों में मार्च 2020 की तुलना में गिरावट आयी है और वे ₹102.5 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक रह गए हैं। इससे अप्रैल-जून 2020 तिमाही के दौरान जमा संग्रहण और क्रेडिट वितरण के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है।

जून 2020 तक बैंकों के पास जमाओं में वर्ष-दर-वर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 2019-20 में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी और जून 2019 के अंत में यह 10 प्रतिशत थी। यह वृद्धि मार्च 2020 के बाद पिछले तीन महीनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों में 40 बीपीएस की और भी गिरावट आने के बावजूद हुई है। इसके विपरीत, जून 2020 में क्रेडिट वृद्धि दर जून 2019 की 12 प्रतिशत से कम होकर 6.2 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जमा और क्रेडिट वृद्धि के बीच विचलन

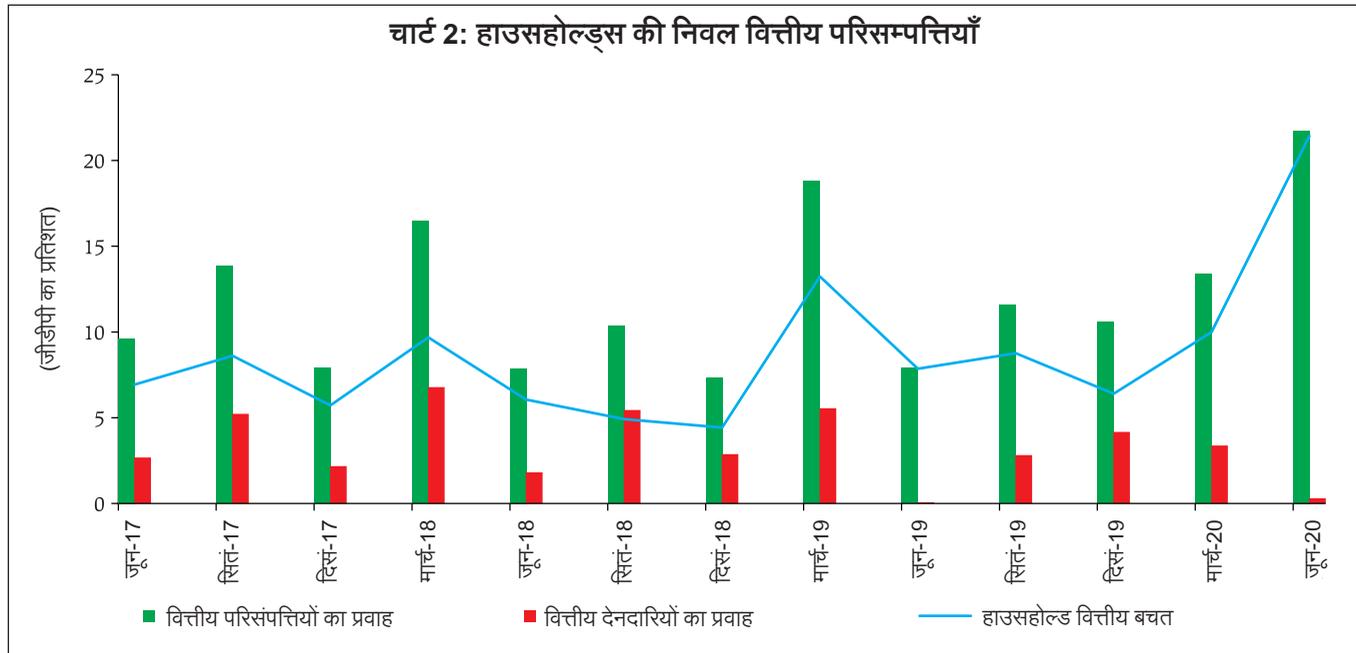
ने हाउसहोल्ड्स की निवल वित्तीय बचत को बढ़ाने में योगदान दिया है।

V. प्रारंभिक अनुमान: गहन अन्वेषण

ऐसा अनुमान है कि 2020-21 की पहली तिमाही में हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है जिससे क्रेडिट और जमा में वृद्धि का रुझान परिलक्षित होता है (चार्ट 2)। यदि यह मान लिया जाए कि 2020-21 की पहली तिमाही में कुल जमा में हाउसहोल्ड्स की भागीदारी अपरिवर्तित रही, तो 2020-21 की पहली तिमाही में हाउसहोल्ड्स वित्तीय बचत जीडीपी के 21.4 प्रतिशत के बराबर ठहरती है। कोविड-19 के प्रभाव के कारण औपचारिक क्षेत्र में नियोजित हाउसहोल्ड्स के विवेकाधीन खर्चों में आयी गिरावट तथा जबरन बचत और अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित हाउसहोल्ड्स की बाधित/कम हो चुकी आय के बावजूद उनके द्वारा एहतियातन की जाने वाली बचत में आया तेज उछाल बेमौसम है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। सांकेतिक जीडीपी में हुई उल्लेखनीय कमी से भी हाउसहोल्ड वित्तीय बचत-जीडीपी अनुपात बढ़ा है। इतना ही नहीं, निरपेक्ष रूप से भी हाउसहोल्ड वित्तीय बचत (वास्तविक और सांकेतिक दोनों) बढ़ी है।

मौसमी कारकों की वजह से वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में आम तौर पर हाउसहोल्ड्स वित्तीय बचत चरम पर होती है,

⁷ जमाराशियों में हाउसहोल्ड्स की हिस्सेदारी से संबंधित 2019-20 तक के आधिकारिक आंकड़े आरबीआई द्वारा प्रकाशित आधारभूत सांख्यिकीय विवरणी में उपलब्ध हैं।



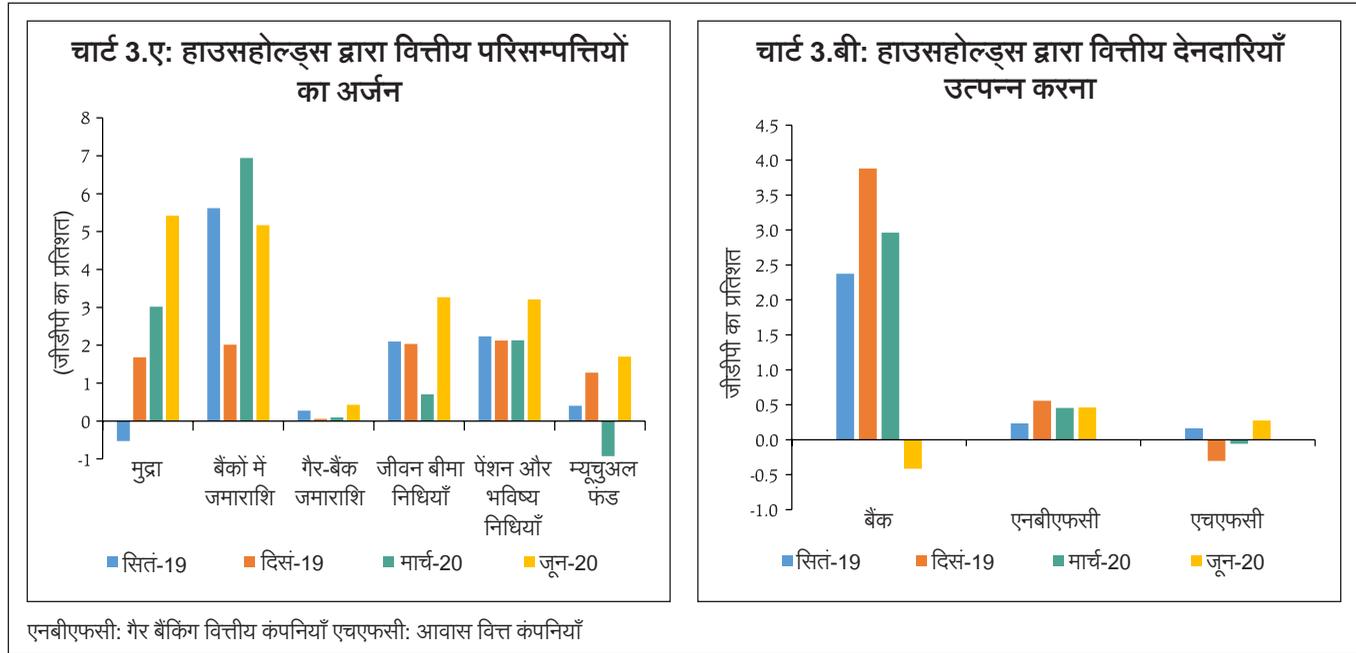
जिसके बाद पहली तिमाही में यह कम हो जाती है (प्रकाश, और अन्य, 2020)। तदनुसार, बीते समय में हाउसहोल्ड्स वित्तीय बचत के तिमाही अनुमानों में भिन्नता भी देखी गई है। हाल के दिनों में जीडीपी का उच्च स्तर 2018-19 की चौथी तिमाही में देखा गया जो 13.2 प्रतिशत था (सारणी 1)।

वर्ष 2020-21 में हाउसहोल्ड्स वित्तीय बचत में उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे मुख्य अवलोकन और कारण निम्नवत हैं :-

- हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने और हाउसहोल्ड वित्तीय देनदारियों में कमी आने से 2020-21 की पहली तिमाही में हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में वृद्धि हुई।
- हाउसहोल्ड वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि में सर्वाधिक योगदान म्यूचुअल फंडों, बीमा उत्पादों और मुद्रा के रूप में हाउसहोल्ड्स की धारिता का था। म्यूचुअल फंडों में हाउसहोल्ड बचत बढ़कर 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी के 1.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी जबकि यह 2019-20 की चौथी तिमाही में (-) 0.9 प्रतिशत और 2019-20 की पहली तिमाही में 0.2 प्रतिशत रही थी। बीमा उत्पादों में हाउसहोल्ड बचत बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है जबकि

समान अवधि में यह क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत थी। इसी तरह, हाउसहोल्ड द्वारा मुद्रा धारिता 2019-20 की चौथी तिमाही के 3.0 प्रतिशत तथा 2019-20 की पहली तिमाही के 1.3 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गयी (चार्ट 3 ए और संलग्नक 1)।

- ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक डिपॉजिट पर प्रतिलाभ कम मिलने के कारण म्यूचुअल फंडों की ओर निधियों का प्रवाह बढ़ा और कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में शुरुआती झटकों के बाद शेयर बाजार नई ऊंचाइयाँ छूने लगा।
- बीमा उत्पादों में अभिदान में हुई वृद्धि यह दर्शाती है कि महामारी के कारण हाउसहोल्ड्स में जीवन बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस प्रकार के आपातकाल में, जीवन बीमा एक आवश्यकता बन गया है, न कि केवल लाभ का विषय (माजी, 2020)।
- दूसरी ओर, हाउसहोल्ड्स द्वारा धारित मुद्रा में हुई वृद्धि इस बात का परिचायक है कि वे महामारी के कारण आयी अतिशय असुरक्षा से लड़ने के लिए सुरक्षा की तलाश में 'नकदी की होड़' में लग गए (आरबीआई, 2020)।



- यद्यपि बैंक जमा के रूप में बचत किसी भी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आम तौर पर ऋणात्मक स्तर पर पहुंच जाती है, तथापि ऐसा अनुमान है कि यह 2020-21 की पहली तिमाही में बढ़कर जीडीपी के 5.2 प्रतिशत के धनात्मक स्तर पर रहेगी। यह वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निजी उपभोग में आये 26.7 प्रतिशत के गंभीर संकुचन से भी समर्थित है। इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान, जब गरीबों की आय अधिक प्रभावित होने की संभावना थी, अप्रैल-जून तिमाही में उनके जन-धन जमा खातों में शेष राशि में संचयी रूप से लगभग ₹400 प्रति खाता की वृद्धि देखी गयी जो संभवतः प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन खातों में डाली गयी उस राशि के कारण था जो इनके लाभार्थियों को महामारी के चलते होने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए प्रदान की गयी थी।⁸ ऐसा लगता है कि गरीब लोगों ने अपनी आय के बाधित/घट जाने की बावजूद इस पैसे के कुछ हिस्से को बचत के रूप में रखा है।
- ऐसा अनुमान है कि बैंकों से लिए जाने वाले ऋण में संकुचन आने के कारण हाउसहोल्ड्स की वित्तीय

देनदारियों में कमी आयी है। जमा राशि में हुई भारी वृद्धि और रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में किए गए चलनिधि अंतर्वेशन के कारण बैंकों के पास पर्याप्त चलनिधि मौजूद है; लेकिन मांग में कमी आने और अनिश्चितता वाले माहौल में ऋण देते हुए वे सशंकित हैं और उन्हें भय है कि उनके अनर्जक ऋणों में वृद्धि न हो जाए (चार्ट 3. बी)। एनबीएफसी, जो कि हाउसहोल्ड्स के लिए ऋण के दूसरे सबसे बड़े स्रोत हैं, का कारोबार भी मंद रहा है जिससे यह प्रकट होता है कि अचल संपत्ति और यात्री वाहनों की माँग में कमी आयी है।

VI. निष्कर्ष

2020-21 की पहली तिमाही में हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में अभूतपूर्व वृद्धि केवल भारत में ही नहीं हुई। हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में इस वृद्धि को कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, जिसने प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं की मांग और आपूर्ति दोनों को गंभीर आघात दिए हैं। भविष्य में जैसे-जैसे कोविड का वक्र समतल होगा और लॉकडाउन वापस ले लिया जाएगा, उपभोगों के कुछ प्रकारों विशेष रूप से, विवेकाधीन घटक में तेजी आएगी। बैंकों में जमा का बढ़ना, ऋण की गिरती मांग और उधार देने के लिए बैंकों की अनिच्छा ने बचत को बढ़ा दिया है। बाहरी मोर्चे पर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसने

⁸ द इंडियन एक्सप्रेस, वही।

परंपरागत रूप से भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा ही देखा है, उसमें 2020-21 की पहली तिमाही में अधिशेष देखा गया। चूंकि चालू खाता शेष आमतौर पर बचत-निवेश अंतराल की तस्वीर हुआ करता है, पहले वाला यदि अधिशेष की स्थिति में होता है तो इसका तात्पर्य है कि पहली तिमाही में घरेलू बचत निवेश की तुलना में अधिक रही। इस बात की पुष्टि अर्थव्यवस्था में कमजोर पड़ती घरेलू मांग से भी होती है जो कि हाउसहोल्ड क्षेत्र की बढ़ी हुई बचत में प्रतिबिंबित होती है।

हाउसहोल्ड वित्तीय बचत के सामान्य से अधिक रहने की प्रवृत्ति आगे भी कुछ समय तक बनी रह सकती है, जब तक कि महामारी का प्रभाव कम नहीं हो जाता और उपभोग अपने सामान्य स्तर पर नहीं पहुंच जाता। यह भी कहना उचित है कि हाउसहोल्ड की वित्तीय बचत संबंधी जो डेटा इस लेख में दिए गए हैं, वे प्रारंभिक हैं और भविष्य में इनका स्थान संशोधित आंकड़े ले सकते हैं। वित्तीय बचत में हुई वृद्धि का सही आकलन कुछ वर्षों बाद ही किया जा सकेगा। इस बीच, वित्तीय अधिशेष के एक बहुत बड़े भाग का लाभ अभिनव तरीके से मध्यस्थता के लिए उठाया जा सकता है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में हुई अभूतपूर्व वृद्धि समय के साथ कम होने की उम्मीद है, विशेष रूप से तब जब कोविड वक्र समतल होने लगेगा और हाउसहोल्ड्स खर्च करना शुरू करेंगे और आगे आने वाली तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों में फिर से तेजी आएगी।

संदर्भ

Ercolani, Valerio (2020), "Covid-induced Precautionary Saving in the US: The Role of Unemployment Rate", Analysis of Current Economic Conditions and Policy, Econbrowser, <http://econbrowser.com/archives/2020/06/guest-contribution-covid-induced-precautionary-saving-in-the-us-the-role-of-unemployment-rate>.

Maji, Priyadarshini (2020), "Why Buying Life, Health Insurance has Become a Necessity Today", Financial Express, April 30, 2020, <https://www.financialexpress.com/money/why-buying-life-health-insurance-has-become-a-necessity-today/1944271/>

Prakash, Anupam, Anand Prakash Ekka, Kunal Priyadarshi, Chaitali Bhowmick and Ishu Thakur (2020), "Quarterly Estimates of Households' Financial Assets and Liabilities", *RBI Bulletin*, June 2020.

RBI (2020), "Annual Report 2019-20", Reserve Bank of India.

The Indian Express, "Sections of Households See Rise in Savings After Lockdown", July 09, 2020, <https://indianexpress.com/article/business/sections-of-households-see-rise-in-savings-after-lockdown-6496812/>

⁹ सावधानी के तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि 2020-21 की पहली तिमाही के लिए हाउसहोल्ड्स वित्तीय बचत के प्रारंभिक अनुमानों में परिसम्पत्तियों और देनदारियों दोनों पक्षों में सामान्य से अधिक बदलाव भी हो सकते हैं क्योंकि हाउसहोल्ड्स की हिस्सेदारी के मौजूदा पूर्वानुमानों के आकलन में कोविड-पूर्व के अनुपातों को प्रयोग में लाया गया है।

अनुबंध 1
हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ : सकल प्रवाह

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2018-19					2019-20					2020-21
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1
वित्तीय आस्तियाँ											
वित्तीय आस्तियाँ	7.9	10.4	7.3	18.8	11.1	7.9	11.6	10.6	13.4	10.9	21.7
जिनमें से											
1. कुल जमाराशियाँ (ए)+(बी)	-1.2	6.5	0.5	10.2	4.0	0.2	5.9	2.1	7.0	3.8	5.6
(ए) बैंकों में जमाराशियाँ	-1.4	6.3	0.3	10.2	3.8	-0.2	5.6	2.0	6.9	3.6	5.2
i. वाणिज्यिक बैंक	-1.4	6.2	0.2	9.9	3.7	-0.3	5.5	1.2	6.9	3.3	5.1
ii. सहकारी बैंक	-0.1	0.1	...	0.3	0.1	0.1	0.1	0.8	0.1	0.3	...
(बी) बैंकेतर जमाराशियाँ	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4
2. जीवन बीमा निधियाँ	1.5	2.1	1.1	3.1	1.9	2.3	2.1	2.0	0.7	1.8	3.3
3. भविष्य निधियाँ और पेंशन निधियाँ (पीपीएफ सहित)	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	3.2
4. मुद्रा	2.5	-0.7	2.1	1.9	1.5	1.3	-0.5	1.7	3.0	1.4	5.4
5. निवेश, जिनमें से	1.7	-0.8	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	1.3	-0.8	0.4	2.2
i. म्यूचुअल फंड	1.5	-1.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	1.3	-0.9	0.2	1.7
6. लघु बचतें (पीपीएफ को छोड़कर)	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	2.0
वित्तीय देयताएँ											
वित्तीय देयताएँ	1.8	5.5	2.9	5.6	3.9	0.1	2.8	4.2	3.4	2.6	0.3
निम्नलिखित से लिया गया ऋण (उधार)											
क. वित्तीय निगम (i+ii)	1.8	5.5	2.9	5.6	3.9	0.1	2.8	4.2	3.4	2.6	0.3
(i) बैंकिंग क्षेत्र,	1.0	3.7	2.9	4.7	3.1	-0.3	2.4	3.9	3.0	2.2	-0.4
जिसमें से											
वाणिज्यिक बैंक	0.9	3.7	2.9	4.5	3.0	-1.1	2.3	3.4	2.9	1.9	-0.5
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	0.8	1.8	-0.1	0.9	0.9	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	0.2	1.1	-0.1	0.6	0.5	...	0.2	0.6	0.5	0.3	0.5
(बी) आवास वित्त कंपनियाँ	0.5	0.6	...	0.3	0.3	0.3	0.2	-0.3	-0.1	...	0.3
(सी) बीमा कंपनियाँ	0.1	0.1	0.1
ख. गैर वित्तीय निगम (निजी कॉर्पोरेट कारोबार)	...										
ग. सामान्य सरकार	...										

... : नगण्य

स्रोत: लेखकों द्वारा गणना

भारत में टर्म प्रीमियम के निर्धारकों का पुनरावलोकन*

टर्म प्रीमियम को संचालित करने वाले अंतर्निहित संबंध जटिल और निरंतर अस्थिर होते हैं। जनवरी 2006 से सितंबर 2020 तक के अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितता और चलनिधि भारत में टर्म प्रीमियम के मुख्य संचालक हैं।

आर्थिक चक्र के अंतर्निहित मंदी वाली आठवीं-तिमाही में जब अर्थव्यवस्था सुस्ती की जाल में फंसी तब अर्थव्यवस्था पर मानो कोविड-19 का प्रकोप थोप दिया गया हो। ऐसे में इसको और असाधारण मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति कार्रवाई के मद्देनजर, भारत में सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में टर्म प्रीमियम के रवैये में दिलचस्पी बढ़ी है। इस बहस को बल देने वाले कुछ हद तक ध्रुवीय दृष्टिकोण हैं। एक तरफ, यह तर्क दिया जाता है कि वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उधारियों का भारत औसत लागत 5.82 प्रतिशत है जो पिछले 16 वर्षों में सबसे कम है। केंद्र की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारत औसत परिपक्वता भी अब तक सबसे अधिक रही है (दास, 2020)। दूसरी तरफ, यह माना जाता है कि भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक प्रतिफल देने वाले कर्व हैं। अत्यधिक उच्च दीर्घकालिक दरें अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि की दरों पर संचरित करने की अनुमति न देकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश तेजी से गिर रहा है (वर्मा, 2020)।

भारत में टर्म प्रीमियम का निर्धारण करने वाले कारकों में अनुभवजन्य जांच-पड़ताल ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (दुआ, राजे और साहू, 2003; कपूर, जॉन और मित्रा; दिलीप 2019) सहित सरकार द्वारा उधार लेने की लागत को प्रभावित करने में उनकी केंद्रीय भूमिका के दृष्टिकोण से उतना प्रसार किया

* यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक के माइकल देवब्रत पात्र, हरेन्द्र बेहरा और जोइस जॉन, द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

है (राठी और प्रधान, 2017, अकरम और दास, 2019), जितना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य वित्तीय लिखतों द्वारा जारी किए गए बाजारों से वित्तीय लिखतों की कीमत निर्धारित करने के लिए। हालांकि, ये निष्कर्ष कोविड-19 जैसी काले हंस की घटनाओं के परिणाम के बजाय शांतिकाल में प्रासंगिक हैं। क्या महाविपत्ति टर्म प्रीमियम और उनके अंतर्निहित निर्धारकों को प्रभावित करती है? क्या टर्म प्रीमियम असाधारण नीतिगत उपायों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं जो ऐसे अपरिहार्य समय में उठाए जाते हैं या, क्या वे अभेद्य बने रहते हैं और उन संकेतों का उत्सर्जन करना जारी रखते हैं, जो वे आम तौर पर तब करते हैं जब सब ठीक हो जाता है? इस लेख की प्रमुख प्रेरणा यही है, जो अनुभवजन्य साहित्य में एक अवशिष्ट अंतर को कम की उम्मीद करता है, जिस पर टर्म प्रीमियम का व्यवहार करने का कारण बनता है क्योंकि वे अत्यधिक अनिश्चित समय में ऐसा करते हैं।

लेख के बाकी हिस्सों को तीन खंडों में व्यवस्थित किया गया है। अगला खंड समय अंतराल पर टर्म प्रीमियम में हाल के उतार-चढ़ाव के संबंध में शोधपरक तथ्यों के माध्यम से और भारत में जी-सेक बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में छान-बीन करता है। खंड III, टर्म प्रीमियम और उनके निकटवर्ती निर्धारकों के हालिया व्यवहार और उसके परिणामों के परीक्षण के लिए एक पद्धतिगत फ्रेमवर्क प्रदान करता है। खंड IV में लेख को कुछ नीतिगत दृष्टिकोणों के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं।

II. कुछ शोधपरक तथ्य

दीर्घ परिपक्वता बॉन्ड पर प्रतिफल आम तौर पर (i) भावी अल्पावधि ब्याज दर और (ii) टर्म प्रीमियम की राशि होती है। पहला टर्म दीर्घ अवधि के बॉन्ड के बराबर कुल परिपक्वता वाले अल्पावधि बॉन्ड की एक श्रृंखला पर रोलिंग से अपेक्षित प्रतिलाभ है। इसके अलावा, अतिरिक्त रिटर्न है जोकि निवेशक परिपक्वता तक या लंबे समय तक बॉन्ड को धारण करने के लिए अतिरिक्त जोखिम लेने के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने की मांग करते हैं, जैसा कि पहले बताया गए दूसरे टर्म में सन्निहित है (कोहेन एवं अन्य, 2018)। किसी दीर्घावधि बॉन्ड और एक अल्पावधि बॉन्ड या टर्म प्रीमियम पर प्रतिफल के बीच अंतर को प्रतिफल कर्व¹ के ढलान के रूप में भी माना जाता है - एक

घनात्मक मीयाद प्रसार एक ऊपर की ओर ढलान प्रतिफल कर्व से मेल खाता है और एक ऋणात्मक प्रसार एक औंधा प्रतिफल कर्व का वर्णन करता है।

मौद्रिक नीति टर्म प्रीमियम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। संकुचनात्मक मौद्रिक नीति के संदर्भ में, नीतिगत दर में वृद्धि से अल्पावधि ब्याज दरों में वृद्धि होती है, लेकिन दीर्घावधि ब्याज दरें अपूर्ण रूप से और अंतराल के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। इसलिए, टर्म प्रीमियम, जो दीर्घावधि और अल्पावधि ब्याज दरों के बीच फैला हुआ है, संकुचित हो जाता है। इसके विपरीत, सुगम मौद्रिक नीति के प्रसार में वृद्धि होगी (एस्ट्रेला, 2005; एस्ट्रेला और मिस्किन, 1997)। यह घटना आज भारत में, दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह देखने योग्य है। हालांकि, टर्म प्रीमियम कई अन्य कारकों से प्रभावित है, जैसे कि जोखिम धारणा में परिवर्तन (डी बैकर एवं अन्य, 2019) और प्रत्याशाएँ - यदि बाजार सहभागियों को आर्थिक उछाल और निवेश पर प्रतिलाभ की उच्च दर का अनुमान है। दीर्घावधि बॉन्ड पर प्रतिफल अल्पावधि प्रतिफल के सापेक्ष बढ़ती है और प्रीमियम को बढ़ाती है। यह बातचीत मंदी की प्रत्याशाओं और उससे बचने के समक्ष होगी (मोदिग्लिआनी और सेंच, 1966; वियानोस और विला, 2009; डी अमिको एवं किंग, 2013; बॉनिस एवं अन्य, 2017)। मुद्रास्फीति में गिरावट और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं में ढील से प्रीमियम में गिरावट आ सकती है क्योंकि एजेंटों का मानना है कि मौद्रिक नीति को संकुचनात्मक तरीके से काम करने की आवश्यकता नहीं होगी (होर्दहल एवं ट्रिस्टन, 2014; कम्बा-मेंडेज एवं वेरर, 2017; डी बक्कर एवं अन्य, 2019)। आर्थिक नीति में अनिश्चितता बढ़ने से जोखिम बढ़ जाता है और प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है (लिपिपोल्ड और मैथिस, 2015)।

इन कारकों के अलावा, बॉन्ड बाजार का माइक्रोस्ट्रक्चर भी प्रतिफल और टर्म प्रीमियम को प्रभावित करता है। बॉन्ड मार्केट के किसी भी सेगमेंट में चलनिधि इसकी कीमत पर असर डालती है और इस तरह प्रतिफल पर भी असर पड़ता है (अमीहुड और मेंडल्सन, 1991, फ्लेमिंग, 2003, गोल्डरिच एवं

अन्य, 2005; राठी और प्रधान, 2017)। उदाहरण के लिए, दीर्घावधि सेगमेंट में चलनिधि का सोख लेना, कम मांग, कम कीमत और इसी तरह की उच्च प्रतिफल का संकेत देगा। यदि अन्य खंडों में प्रतिफल अप्रभावित रहता है, तो प्रीमियम में परिवर्तन होता है। संभावित परिणाम में बदलाव, और राजकोषीय रुख भी दीर्घावधि बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित करते हैं, जिससे अल्पावधि प्रतिफल काफी हद तक अप्रभावित रहता है (पोगहोस्यान, 2014)।

भारत में, जी-सेक बाजार में कारोबार, मुद्रास्फीति जोखिम, घरेलू बॉन्ड में विदेशी निवेश और नीतिगत अनिश्चितता जैसे कारक टर्म प्रीमियम को प्रभावित करते पाए गए हैं (दिलीप, 2019)। दीर्घावधि सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के अन्य संभावित वाहकों में, मौद्रिक नीति कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक पाई जाती है, जबकि सरकारी ऋण अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है (अकरम और दास, 2019)। जहां मौद्रिक नीति का प्रभाव ब्याज दरों की अवधि के दौरान मजबूत पाया जाता है, वहीं, वायदा प्रीमियम, मुद्रास्फीति और आधारभूत धन स्पेक्ट्रम के दीर्घावधि के लिए अपने सांख्यिकीय महत्व को खो देते हैं (दुआ और राजे, 2014)। आरबीआई में निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) में परिलक्षित बैंकिंग प्रणाली के लिए चलनिधि प्रावधान संबंधी नीतियां भी विभिन्न परिपक्वता प्रतिफल को प्रभावित कर सकती हैं (दुआ, राजे और साहू, 2003; सिंह, 2011)। सरकार के बाजार उधारी कार्यक्रम का आकार, घरेलू बॉन्ड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और घरेलू बॉन्ड प्रतिफल को स्थानांतरित करने के लिए विदेशी बॉन्ड प्रतिफल भी पाए जाते हैं (कपूर, जॉन और मित्रा 2018)।

परिपक्व जी-सेक बाजारों में वित्तीय टिप्पणीकार आमतौर पर प्रतिफल कर्व में दोनों बिंदुओं पर बड़ी मात्रा में चलनिधि को देखते हुए 10 साल और 2 साल के बॉन्ड प्रतिफल के बीच के अंतर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अकादमिक साहित्य में, प्राथमिकता 10 वर्षीय प्रतिफल और मुद्रा बाजार दर के बीच अंतर के लिए है, जैसे कि तीन महीने के ट्रेजरी बिल की दर, क्योंकि मौद्रिक नीति रुख के संबंध में बाद वाले की मजबूत भविष्यवाणी शक्ति है (बाऊर एंड मर्टेंस, 2018)। हम

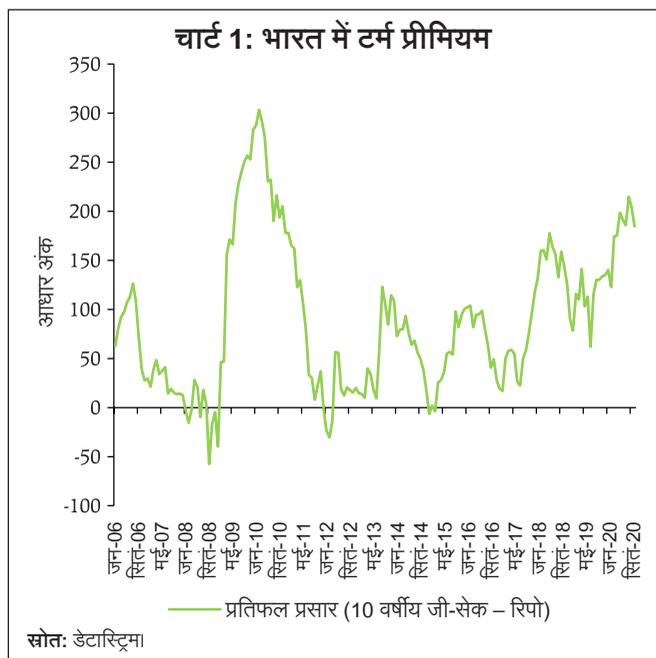
¹ ब्याज दरों के अंतर के आधार पर विभिन्न टर्म स्प्रेड पर विमर्श के लिए, बाऊर और मर्टेंस (2018) देखें

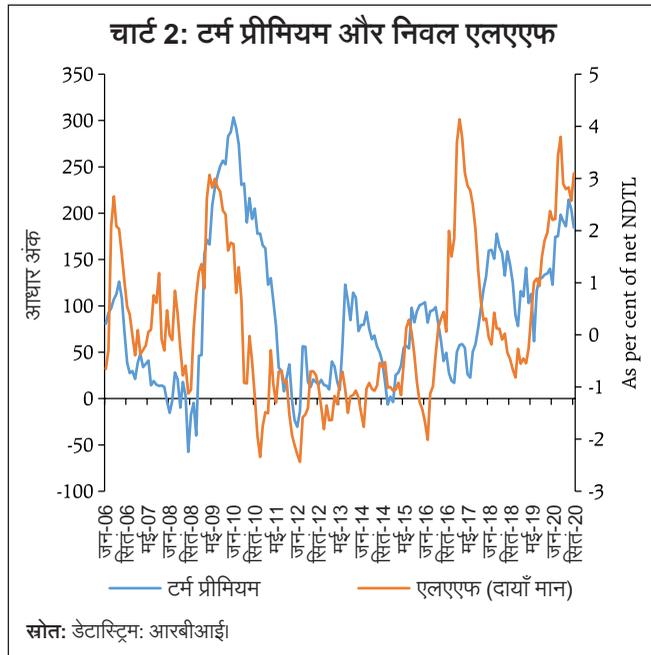
10 वर्षीय प्रतिफल और एकदिवसीय नीतिगत दर के बीच अंतर को हमारे मियाद के प्रसार के माप के रूप में चुनते हैं, क्योंकि ये भारत में प्रतिफल कर्व पर सबसे अधिक अर्थसुलभ बिंदु हैं और मौद्रिक नीति का रुख पूरी तरह से नीतिगत दर में शामिल है। यह देखा गया है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद मौद्रिक नीति प्रोत्साहन से बाहर निकलने की प्रत्याशा, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा बाजार उधारों की विस्तारित मात्रा और बढ़ती मुद्रास्फीति की प्रत्याशा से फरवरी 2010 में यह टर्म चरम पर पहुंच गया (चार्ट 1)। इसके बाद यह टर्म फैल गया, हालांकि, रिज़र्व बैंक द्वारा जी-सेक की खरीद के रूप में बड़े पैमाने पर खुले बाजार के परिचालन के कारण जनवरी 2012 तक नकारात्मक क्षेत्र में फिसल गया, जो सिस्टम में टिकाऊ चलनिधि को प्रभावित करता था और तेजी से प्रतिफल को कम कर रहा था। इसके अलावा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जी-सेक में निवेश की सीमा रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ा दी गई थी, और यह भी एक लाभप्रद परिणाम था क्योंकि मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएँ कुछ हद तक कम हुई थीं और बाजार की धारणा ऊपर उठ गयी थी।

इस बिंदु और जुलाई 2017 के बीच, प्रतिफल का प्रसार एक संकीर्ण सीमा में हो गया, लेकिन मई 2018 में अमेरिका में मौद्रिक नीति को मजबूत करने की गति के बारे में बाजार की

चिंताओं पर 178 आधार अंक से शिखर पर पहुंच गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रतिबंधित मजबूती कूड की कीमतें और भारत में अपेक्षित मुद्रास्फीति रीडिंग से अधिक है। जुलाई 2019 से अगस्त 2020 के ठीक ऊपर, टर्म प्रीमियम लगभग एकतरफा होकर 150 अंकों से बढ़कर 215 आधार अंक तक पहुंच गया। इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतिगत दर को कम से कम 250 आधार अंक तक कम कर दिया और चूंकि 10 वर्षीय प्रतिफल एक अंतराल के साथ प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इस पर प्रसार के तुरंत फैलने का प्रभाव था। पहले आर्थिक गतिविधि में मंदी और फिर महामारी से लड़ने के लिए, विस्तारी राजकोषीय रुख के कारण बजटीय लक्ष्यों के विचलन के कारण पेपर की अधिक आपूर्ति की आशंका और कोविड-19 के कारण आपूर्ति व्यवधानों की वजह से महंगाई दर के बढ़ जाने से प्रीमियम में वृद्धि हुई। चलनिधि के प्रसार की स्थिति को बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर अक्टूबर 2020 की शुरुआत से ही इस टर्म के प्रसार में ढील शुरू हो गई है, और आगे के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति के रुख को ध्यान में रखते हुए बाज़ार में चलनिधि और आसान वित्तपोषण के लिए प्रतिभागियों को आश्चस्त करने हेतु अपेक्षित उपाय करने के लिए तैयार है (दास, 2020)।

साहित्य से पहचाने जाने वाले विभिन्न अंतर्निहित संकेतकों के साथ प्रीमियम के इस ऐतिहासिक समय प्रोफ़ाइल को समझना अलगाव या सह-संचलन, जैसा भी मामला हो, के स्तर हैं। टर्म प्रीमियम का निकटतम संबंध आरबीआई की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत निवल स्थिति द्वारा दर्शाई गई चलनिधि शर्तों के साथ है (चार्ट 2)। प्राप्त मुद्रास्फीति के साथ, टर्म प्रीमियम का सहसंबंध मध्यम (0.3) है; आश्चर्यजनक रूप से, पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं के साथ संबंध सांकेतिक और सांख्यिकीय रूप से विवादास्पद हैं, जिससे पता चलता है कि बॉन्ड बाजार अपने स्वयं के मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में पिछड़ा हुआ है, और लगभग एक महीने के अंतराल के साथ प्राप्त मुद्रास्फीति के प्रिंटों को स्वीकार करता है (चार्ट 3ए)। समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) द्वारा अनुमानित प्रीमियम और आर्थिक गतिविधि के बीच संबंध कमजोर (0.1) है और

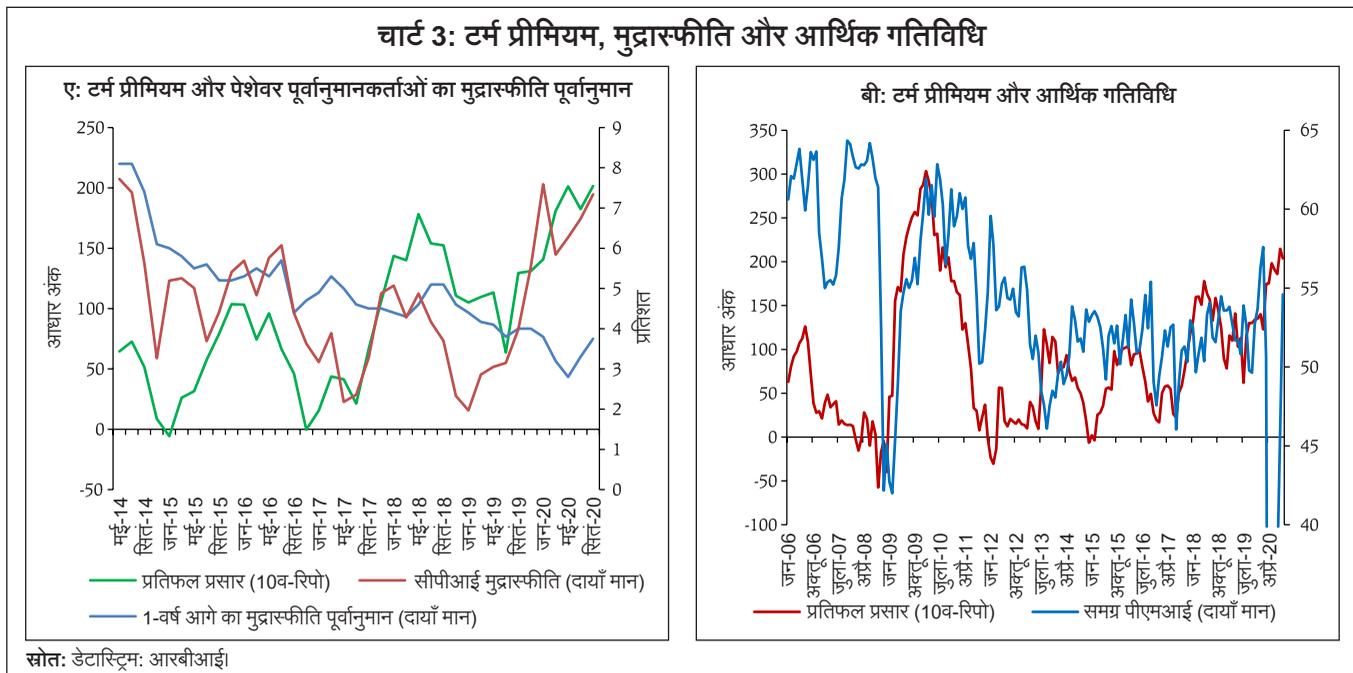




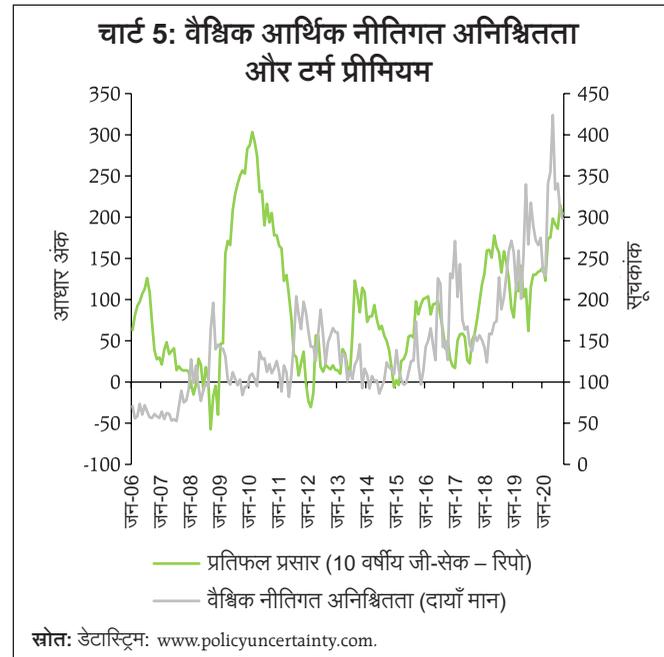
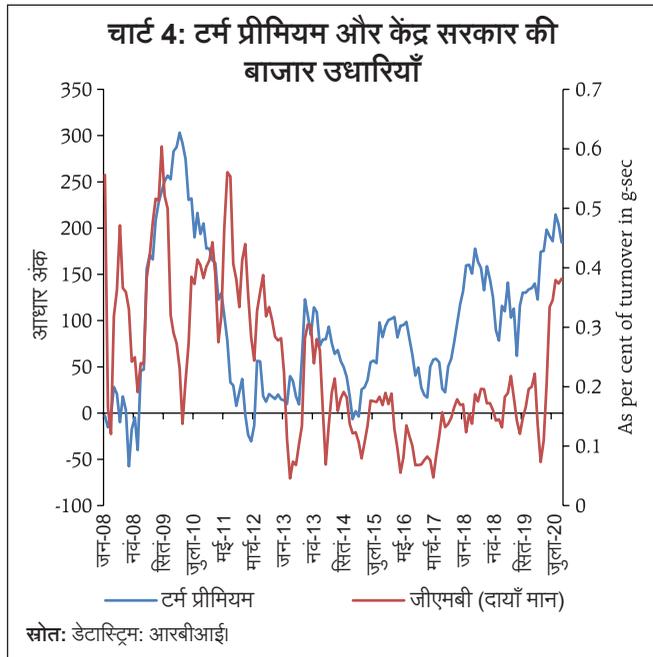
समग्र रूप से महत्वहीन है; हालांकि, सहसंबंध 2012 के बाद से ऋणात्मक और महत्वपूर्ण हो गया (चार्ट 3 बी)। जी-सेक

टर्मओवर के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार के बाजार उधारी की तीन महीने की चल औसत द्वारा दर्शाए जाने वाले बाजार को कागज की आपूर्ति के साथ, टर्म प्रीमियम का सहसंबंध लगभग 0.3 है, यानी प्राप्त मुद्रास्फीति के जैसा ही (चार्ट 4)।

वैश्विक स्तर पर, भारत में टर्म प्रीमियम वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता या जीईपीयू (बेकर, एवं अन्य, 2016)² के लोकप्रिय सूचकांक द्वारा प्रस्तुत की गई आर्थिक नीति अनिश्चितता के साथ एक महत्वहीन सहसंबंध प्रदर्शित करता है, अगर विचाराधीन अवधि को वर्ष 2006 से लिया जाता है तो। (चार्ट 5)। हालांकि, वर्ष 2012 से सहसंबंध महत्वपूर्ण हो जाता है और अब तक लिए गए सभी चर (0.56) में सबसे अधिक है। यह वैश्विक स्पिलओवर की तुलना में भारत के बॉन्ड बाजार टर्म प्रीमियम की बढ़ती संवेदनशीलता को इंगित करता है। विभिन्न उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिफल घटने के हाल के व्यवहार की दूसरे देशों की तुलना से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के बाद प्रतिफल कर्व के



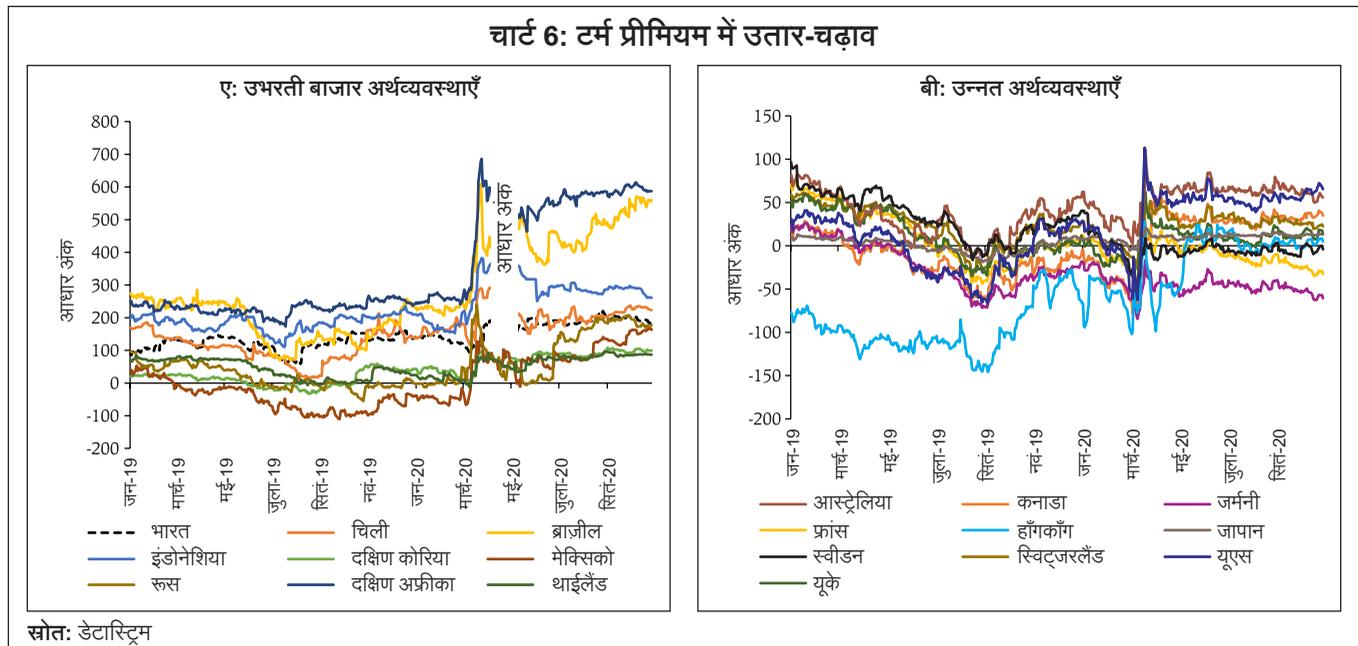
² जीईपीयू सूचकांक 21 देशों के लिए राष्ट्रीय ईपीयू सूचकांकों का जीडीपी-भारत औसत है, जो प्रत्येक देश के समाचार पत्रों के लेखों की सापेक्ष आवृत्ति को दर्शाता है जिसमें अर्थव्यवस्था (ई), नीति (पी) और अनिश्चितता (यू) से संबंधित टर्म्स की एक त्रय शामिल है।



घटने के साथ, टर्म प्रीमियम का सभी देशों, दोनों उभरते और उन्नत, में व्यापक रूप से प्रसार हुआ है (चार्ट 6ए और 6बी)। भले ही यह वृद्धि भारत के मामले में उल्लेखनीय रही हो, लेकिन इसे कई अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम पाया गया था।

III. कार्यपद्धति और अनुभवजन्य परिणाम

शोधपरक तथ्यों और साहित्य में उपलब्ध बिंदुओं के आधार पर भारत में टर्म प्रीमियम के निर्धारकों की आनुभविक रूप से जांच करने के लिए दो पद्धतिगत तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले, एकीकरण के विभिन्न क्रम के चर की उपस्थिति के कारण, लेकिन अति-भिन्नता के माध्यम से इन चर के आंतरिक गुणों को खोए



बिना, एक स्वतः प्रतिगामी वितरित लैंग (एआरडीएल) मॉडल का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा, एक प्रतिबंधित वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर) मॉडल का उपयोग एक मजबूती जांच के रूप में और टर्म प्रीमियम के ऐतिहासिक अपघटन को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

जिन चरों पर विचार किया गया है वे हैं: (i) 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल और नीतिगत रिपो दर (टर्म_प्रीमियम) के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित प्रीमियम; (ii) समग्र पीएमआई द्वारा प्रस्तुत घरेलू आर्थिक गतिविधि; (iii) अपने लक्ष्य (INFL_gap) से सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) का विचलन; (iv) जी-सेक बाजार (जीएमबी) में कारोबार करने के लिए भारत सरकार के बाजार उधारियों का अनुपात; (v) एलएएफ के तहत बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और समय देनदारियों (एलएएफ) के अनुपात में निवल चलनिधि की स्थिति; और वैश्विक नीतिगत अनिश्चितता सूचकांक (जीईपीयू), जनवरी 2006 से सितंबर 2020 तक की समूची अवधि के लिए।

एआरडीएल मॉडल में उपयोग किए जाने वाले चर मुद्रास्फीति के अंतर या INF_gap (लक्ष्य के बिना मुद्रास्फीति) को छोड़कर स्तरों में स्थिर पाए जाते हैं, जो पहले अंतर में स्थिर है। परिबंध परीक्षण टर्म प्रीमियम, आर्थिक गतिविधि, मुद्रास्फीति के अंतर और चलनिधि की स्थिति के बीच एक आकस्मिक संबंध की उपस्थिति की पुष्टि करता है (सारणी 1)। सरकार के बाजार ऋण का लंबे समय में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अल्पावधि में यह वैश्विक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति की खाई और आर्थिक गतिविधि में बदलाव के साथ टर्म प्रीमियम को प्रभावित करता है (सारणी 2)।

मानदंड अनुमानों की स्थिरता उचित स्तर के विश्वास के साथ वर्ग-फल के संचयी योग (सीयूएसयूएम) द्वारा सत्यापित

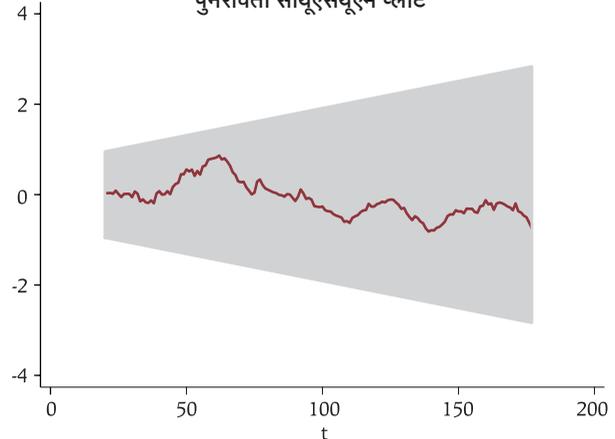
सारणी 1: सहसमेकन के लिए एआरडीएल बाउन्ड्स परीक्षण

फंक्शन	एफ-स्टैटिस्टिक्स		
Term_prem=f(PMI, INFL_gap, LAF)	6.64*		
क्रिटिकल बाउन्ड्स	10%	5%	1%
लोअर बाउन्ड्स	2.72	3.23	4.36
अपर बाउन्ड्स	3.79	4.40	5.70

*: 1% पर महत्वपूर्ण

चार्ट 7: स्थिरता परीक्षण

शून्य के आसपास 95% विश्वास बैंड के साथ टर्म प्रीमियम में परिवर्तन के पुनरावर्ती सीयूएसयूएम प्लॉट



टिप्पणी: पैरामीटर स्थिरता परीक्षण सांख्यिकीय के लिए संचयी योग परीक्षण = 0.560 [5% क्रिटिकल मान = 0.948]। इसलिए, हम 5% के स्तर पर कोई संरचनात्मक विराम की शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहते हैं।
स्रोत: लेखक की गणना

किया जाता है (चार्ट 7)। अन्य नैदानिक परीक्षण श्रेणीगत सहसंबंध की अनुपस्थिति और विषमविसरिता को इंगित करते हैं (सारणी 2)। त्रुटि संशोधन टर्म शब्द (ईसीएम) को अपेक्षित

सारणी 2: एआरडीएल परिणाम: दीर्घकालिक और अल्पकालिक अनुमान

	गुणांक	एफ-मान
दीर्घकालिक अनुमान		
PMI	-0.159*	0.011
INFL_gap	0.185*	0.017
LAF	0.352*	0.025
अल्पकालिक अनुमान		
Δ Term_prem(-1)	-0.131**	0.089
Σ Δ PMI (0 to -3)	0.028*	0.014
Σ Δ INFL_gap (0 to -1)	0.075*	0.012
Σ Δ GMB (0 to -1)	0.113**	0.080
Δ GEPU (-3)	0.001***	0.118
ecm(-1)	-0.083*	0.000
Constant	0.819*	0.000

डाइग्नोस्टिक्स:

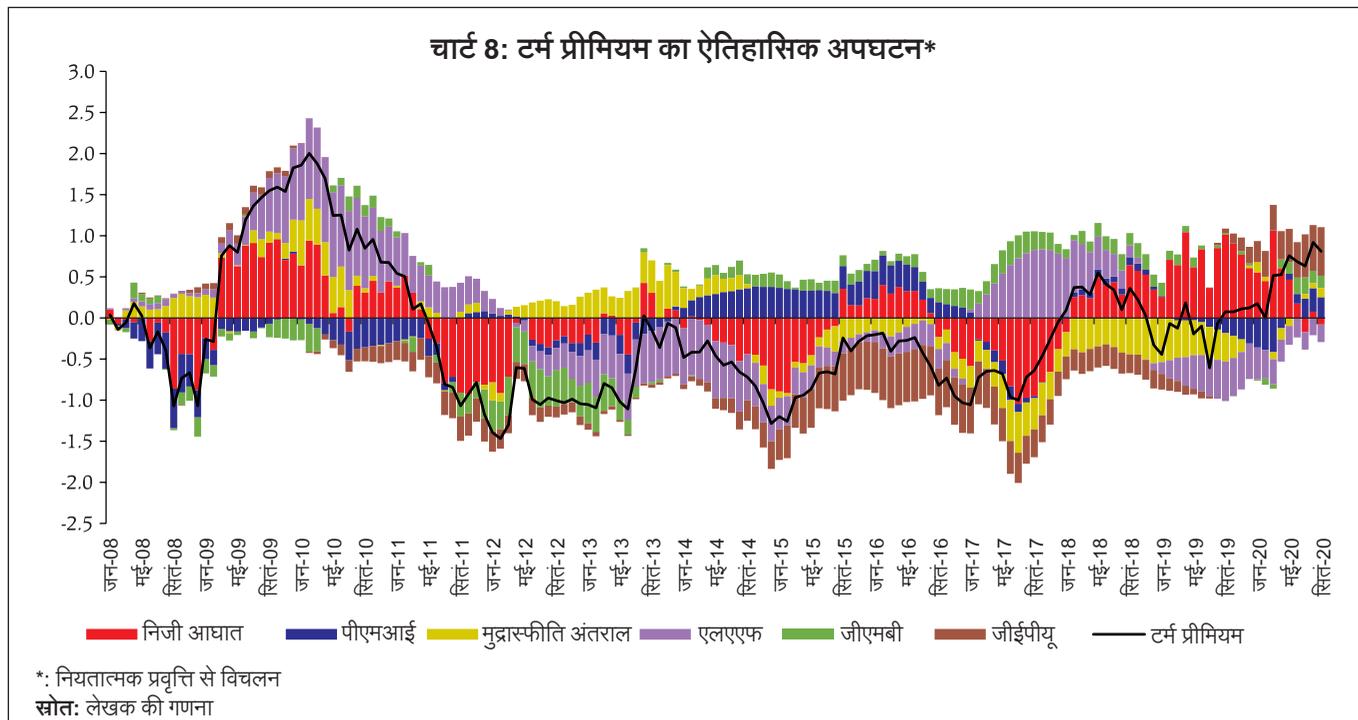
आटोकोरिलेशन पी-वैल्यू के लिए ब्रेसच-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट	0.211
एलएम टेस्ट फॉर ऑटोरिग्रेशन कंडीशनल हिट्रोस्केडस्टीसिटी (एआरएचसी) पी-वैल्यू	0.963
पोर्टमैन्टो टेस्ट फॉर व्हाइट न्वाइज़ पी-वैल्यू	0.616

***, **, *: क्रमशः 15%, 10% और 5% के स्तर पर महत्वपूर्ण

नकारात्मक संकेत के साथ सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया जाता है; हालांकि, ईसीएम टर्म पर गुणांक का छोटा आकार इंगित करता है कि जी-सेक बाजार में निर्मित किसी भी असंतुलन को दूर करने में लंबा समय लगता है।

एक प्रतिबंधित वीएआर³, जिसमें एआरडीएल मॉडल में उपयोग किए जाने वाले सभी चर शामिल हैं, को एक मजबूती की जांच के रूप में अनुमानित किया गया है। परिणाम मोटे तौर पर समान पाए जाते हैं - एआरडीएल मॉडल में गुणांक के संकेत और परिमाण वीएआर से आवेग प्रतिक्रियाओं की दिशा और आकार के बराबर हैं। टर्म का ऐतिहासिक अपघटन (चार्ट 8) वीएआर से अनुमानित 'दीर्घावधि के औसत से फैलता है, जो दर्शाता है कि जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच, जी-सेके मार्केट के हिस्टैरेटिक जड़त्व के अलावा, मियादी प्रीमियम के सख्त होने का सबसे हालिया घटना गतिकी, वैश्विक अनिश्चितता मुख्य प्रेरक

शक्ति थी, जिसका मियादी प्रीमियम में कुल भिन्नता का 90 प्रतिशत हिस्सा था। इसके बाद सरकार की बाजार उधारी (20 प्रतिशत) थी। दूसरी ओर, चलनिधि का कूलिंग प्रभाव होता है, जो टर्म प्रीमियम को घटाता है और आंशिक रूप से अपसाइड फैक्टर (-109 प्रतिशत) की भरपाई करता है। पीएमआई में आर्थिक गतिविधियों का धीमा होना और उस अवधि में मुद्रास्फीति का कम होना भी प्रीमियम (-33 प्रतिशत और - क्रमशः 30 प्रतिशत) को कम करने में भूमिका निभाता है। अप्रैल से सितंबर 2020 तक, वैश्विक अनिश्चितता प्रमुख कारक (66 प्रतिशत) रही, इसके बाद हिस्टैरिसिस (25 प्रतिशत), बाजार उधारी (22 प्रतिशत) और आर्थिक गतिविधियों में तेजी (19 प्रतिशत) रही। चलनिधि एक शांत प्रभाव (-32 प्रतिशत) का प्रयोग करती रही। कोविड-19 की अवधि में टर्म प्रीमियम की भिन्नता में मुद्रास्फीति का कोई योगदान नहीं था।



³ वीएआर में मापदंडों का एक रैखिक प्रतिबंध केवल भारत में टर्म प्रीमियम पर जीईपीयू के प्रभाव को कम करने के लिए लगाया गया है और इसे उसकी दो अवधि के अंतराल द्वारा निर्धारित की जा रही है। चरों का क्रम सख्ती जनित से कदाचित जनित है और एआईसी मानदंड का उपयोग करके लैम्स का चयन किया जाता है। रिग्रेशन डाइग्नोस्टिक्स संतोषजनक पाए गए - ए) लैंग्रेंज-मल्टीप्लायर टेस्ट: वृत्तियों का कोई स्वतः सहसंबंध नहीं; बी) अभिलक्षणिक मान स्थिरता की स्थिति: सभी अभिलक्षणिक मान इकाई सर्कल के अंदर स्थित हैं; वीएआर स्थिरता की स्थिति को पूरा करता है। ऐतिहासिक अपघटन सामान्यीकृत आवेग प्रतिक्रियाओं पर आधारित है और अपने निर्धारक प्रवृत्ति पर टर्म प्रीमियम के उतार-चढ़ाव की व्याख्या करने में प्रत्येक चर के योगदान को दर्शाता है।

IV. निष्कर्ष

बॉन्ड बाजार अतिशय दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति कहां बैठता है, यह उस पर निर्भर करता है। टर्म प्रीमियम वाले अंतर्निहित संबंध जटिल और लगातार बदलने वाले हैं। यह फलते-फूलते साहित्य और दिन-प्रतिदिन के बाजार उतार-चढ़ाव में परिलक्षित होता है। मूल सिद्धांत और विशेष प्रवृत्ति एक दूसरे मिले हुए हैं और समझदार नीति निर्माता के लिए परीक्षण स्व से संकेतों को निकालने के लिए है। यह आधुनिक समय की मौद्रिक नीति के लिए प्रासंगिकता मानी जाती है और मुद्रास्फीति को कम करते हुए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु दीर्घावधि के लिए त्वरित और पूर्ण संचरण की मांग करती है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां ब्याज दरें शून्य या इसके करीब हैं, वहाँ वास्तविक या नाममात्र की, मौद्रिक नीति अनजाने में कदम उठाता है, जिसमें टर्म प्रीमियम को कम करने और दीर्घावधि ब्याज दरों को अधिक मात्र में सीधे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। क्या चलनिधि की असाधारण मात्रा का प्रावधान अधिक अनिश्चितता का कारण होगा? या यह वास्तविक गतिविधि पर बगैर किसी खास प्रभाव के साथ मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा? यह तो केवल समय ही बताएगा।

संदर्भ

Akram, T., & Das, A. (2019). The long-run determinants of Indian government bond yields. *Asian Development Review*, 36(1), 168-205.

Amihud, Y. and Mendelson, H. (1991), "Liquidity, Maturity, and the Yields on U.S. Treasury Bonds", *The Journal of Finance*, 46(4):pp. 1411-1425.

Bauer, M.D. and Mertens, T.M. (2018), "Information in the Yield Curve about Future Recessions," *FRBSF Economic Letter*, Federal Reserve Bank of San Francisco, No. 2018-20, August 27.

Bonin B., J. Ihrig and M. Wei (2017), "The Effect of the Federal Reserve's Securities Holdings on Longer-term Interest Rates", Federal Reserve Board of Governors, FEDS Notes, April 20.

Camba-Mendez G. and T. Werner (2017), "The Inflation Risk Premium in the Post-Lehman Period", ECB, Working Paper 2033.

Cohen B. H., P. Hördahl and D. Xia (2018), "Term Premia: Models and Some Stylised Facts", *BIS Quarterly Review*, September.

D'Amico S. and T. B. King (2013), "Flow and Stock Effects of Large-scale Treasury Purchases: Evidence on the Importance of Local Supply", *Journal of Financial Economics*, 108(2), 425-448.

Das, S. (2020), *Governor's Statement – October 9, 2020*, Reserve Bank of India.

De Backer, B., Deroose, M., & Van Nieuwenhuyze, C. (2019), "Is a Recession Imminent? The Signal of the Yield Curve", *Economic Review*, (i), 69-93.

Dilip, A. (2019), "Term Premium Spillover from the US to Indian Markets", *RBI Working Paper Series No. 05*, Reserve Bank of India, December.

Dua, P., N. Raje and S. Sahoo (2003), "Interest Rate Modelling and Forecasting in India", *Development Research Group Study 24*, Reserve Bank of India.

Fleming, M. J. (2003). Measuring treasury market liquidity. *Economic policy review*, 9(3).

Goldreich, D., Hanke, B., and Nath, P. (2005). The price of future liquidity: Time-varying liquidity in the us treasury market. *Review of Finance*, 9(1):1-32.

Hördahl P. and O. Tristani (2014), "Inflation Risk Premia in the Euro Area and the United States", *International Journal of Central Banking*, 10(3), 1-47.

Kapur, M., J. John and P. Mitra (2018). *Monetary Policy and Yields on Government Securities*, Mint Street Memo No. 16, Reserve Bank of India, December 18.

Leippold, M. and F. H. Matthys (2015), "Economic Policy Uncertainty and the Yield Curve", url: https://www.frbsf.org/economic-research/files/S02_P1_Felix-Matthys.pdf

Modigliani F. and R. Sutch (1966), "Innovations in Interest Rate Policy", *The American Economic Review*, 56 (1 / 2), 178-197.

Poghosyan, T. (2014). Long-run and short-run determinants of sovereign bond yields in advanced economies. *Economic Systems*, 38(1), 100-114.

Rathi, K., & Pradhan, H. K. (2017). Determinants of Yield Spread in the Government of India Bond Markets. Available at SSRN 3104333.

Singh, B. (2011), "How Asymmetric is the Monetary Policy Transmission to Financial Markets in India?", *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 32(2), pp.1-37.

Varma, J.R. (2020). *Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting October 7 to 9, 2020*, Reserve Bank of India.

Vayanos D. and J.-L. Vila (2009), A Preferred Habitat Model of the Term Structure of Interest Rates, NBER, Working Papers 15487.

भारत का गिल्ट बाज़ार*

किसी भी देश का वित्तीय विकास गहरे और अर्थसुलभ सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के अस्तित्व के इर्द-गिर्द टिका हुआ होता है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए पुनरुत्थान कार्यों की बदौलत, भारत में गिल्ट बाज़ार ने हालिया महामारी समेत अस्थिरता और संकटों के दौरान लचीलापन दर्शाते हुए गहराई, तरलता और जीवंतता दिखाई है। आगे, सरकारी प्रतिफल वक्र में सभी परिपक्वता-कालों में चलनिधि में वृद्धि, निवेशक आधार को बढ़ाना और डेरिवेटिव बाज़ार को विकसित करना ध्यान देने योग्य क्षेत्र हो सकते हैं ताकि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनवरत प्रयासों से निर्मित बाज़ार परिवेश को बढ़ावा मिल सके।

भूमिका

किसी भी देश का वित्तीय विकास गहरे और अर्थसुलभ सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के अस्तित्व के इर्द-गिर्द टिका हुआ होता है। उधार संबंधी कर्तव्यों का निर्वाह करने और रोलओवर जोखिमों को कम करते हुए सरकारी कर्ज के परिपक्वता प्रोफाइल की देखभाल करने के लिए सरकारी ऋण प्रबंधक को लचीलापन प्रदान करने के अलावा, यह बाज़ार जोखिम-मुक्त ब्याज दरों को भी निर्धारित करता है, जिससे बाज़ार स्पेक्ट्रम के अन्य खंडों में मूल्य की खोज होती है जैसे मुद्रा बाज़ार लिखतों और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बाज़ार। यह अप्रत्यक्ष लिखतों जैसे कि रेपो और खुले बाज़ार के परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पिछले कुछ वर्षों में किए गए पुनरुत्थान कार्यों की बदौलत, भारत में गिल्ट बाज़ार ने हालिया महामारी समेत अस्थिरता और संकटों के दौरान लचीलापन दर्शाते हुए गहराई, तरलता और जीवंतता दिखाई है। भारत का गिल्ट बाज़ार एशिया में तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बॉन्ड बाज़ार बन गया है (राजाराम और घोष, 2019)।

* यह लेख वित्तीय बाज़ार विनियम विभाग (एफएमआरडी) के ऋतुराज, जी. राजशेखरन, अभिषेक कुमार, अमित मीणा और एम. जगदीश तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के रोहित कुमार द्वारा तैयार किया गया है। सीसीआईएल के शोध दल एवं एफएमआरडी के अक्षय झा के सहयोग के लिए उनका अत्यंत आभार। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

यह लेख भारत में सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के विकास की जांच करता है, विशेष रूप से इसके क्रमिक विकास को रेखांकित करने वाली नीतिगत पहल के संदर्भ में। खंड II में सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में समय-समय पर आए बदलाव के संबंध में चर्चा की गई है, जबकि खंड III में उभरते बाज़ार (ईएम) समकक्षों की तुलना में इस बीच आए इन बदलावों की चर्चा की गई है। खंड IV में बाज़ार के आगे के विकास को बाधित करने वाले कारकों पर चर्चा की गई है। खंड V को, वैश्विक एकीकरण में अधिकाधिक प्रवृत्त अर्थव्यवस्था के साथ सुसंगत सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए संभावित नीतिगत उपायों के मूल्यांकन के साथ समाप्त किया गया है।

II: बाज़ार की सूक्ष्म-संरचना

एक कारगर सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के विकास में निम्नलिखित शामिल हैं (ए) सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम और व्यापार को सहारा देने के लिए विधिक वास्तुकला एवं विनियामक फ्रेमवर्क की स्थापना; (बी) एक संभावित निवेशक आधार का निर्माण; और (सी) डेरिवेटिव क्षेत्रों के लिए बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास जिसमें कीमत और व्यापार को लेकर विभिन्न जोखिम होते हैं (आईएमएफ और विश्व बैंक, 2001)।

II.1. विधिक ढांचा

कर्ज प्रबंधन के लिए एक मजबूत विधिक और विनियामक ढांचा प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए; और सुदृढ़ प्रवर्तनीय पर्यवेक्षी प्रथाओं के साथ बाज़ार विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की सुविधा प्रदान करता है (आईएमएफ और विश्व बैंक, 2001)।

आरबीआई अधिनियम, 1934, रिज़र्व बैंक को भारत सरकार (समझौता अनुसार) और राज्य सरकारों के सरकारी कर्ज के प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपता है। सरकारी कर्ज अधिनियम, 1944 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम और सर्विसिंग, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित निक्षेपागार सेवाओं और सरकारी कर्ज के समग्र प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 2006 में, सरकारी प्रतिभूतियों, डेरिवेटिव्स और मुद्रा बाज़ार लिखतों के मामले में रिज़र्व बैंक को स्पष्ट नियामक शक्तियां देने के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसके

अलावा, भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 रिज़र्व बैंक को देश के भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार देता है, जो मल्टीलैटरल नेटिंग, निपटान को अंतिम रूप देने और गारंटी युक्त निपटान के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है, और ये सभी गिल्ट बाज़ार की कुशलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस व्यापक वैधानिक ढांचे के भीतर, रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के विनियमन और विकास के लिए विनियम जारी करता रहा है। नीलामी के जोखिम के बेहतर प्रबंधन और वितरण के माध्यम से ऋण जारी करने की रूपरेखा को मजबूत करने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों में “जब, जैसा और यदि जारी किया गया” (या जब जारी किया गया (डब्ल्यूआई)) व्यापार हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए (2006)। उसी वर्ष सरकारी प्रतिभूतियों में मंदडिया बिक्री¹ की अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए ताकि ब्याज दरों पर दो तरफा विचारों की अभिव्यक्ति सुविधानजक हो सके और मूल्य खोज में सुधार हो सके। गहरे और तरल रेपो बाज़ार सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में तरलता को सहारा देते हैं। रेपो बाज़ार खरीद से अधिक बिक्री की भी सुविधा देता है क्योंकि रेपो बाज़ार के जरिए प्रतिभूति उधार लेकर खरीद से अधिक बिक्री करने का दायित्व पूरा किया जाता है। रेपो बाज़ार में वृद्धि करने के लिए, उसके भागीदार आधार जिसमें केवल एसजीएल खाता² धारक शामिल हैं, में इजाफा कर उसमें गैर-एसजीएल खाता धारकों को शामिल किया गया (2003), सरकारी प्रतिभूतियों के री-रेपो को अनुमति दी गई थी (2015) और त्रि-पक्ष रेपो शुरू किया गया था (2017)। जुलाई 2018 में रेपो बाज़ार को लेकर व्यापक निर्देश जारी किए गए थे।

सक्रिय डेरिवेटिव बाज़ार जोखिम के खिलाफ प्रतिरक्षा के लिए लिखत उपलब्ध कर पूंजी बाज़ार के क्रियाकलापों में मदद करता है जबकि साथ ही अंतर्निहित में मूल्य खोज में सहयोग करता है। काउंटर पर (ओटीसी) रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव और ब्याज दर वायदा के लिए दिशानिर्देश क्रमशः 1999 और 2003 में जारी किए गए थे। विनियामक ढांचा वर्षों से विकसित

¹ मंदडिया बिक्री का आशय ऐसी प्रतिभूति की बिक्री से है जो पहले किसी और के स्वामित्व में थी।

² एसजीएल खाता: सब्सिडियरी जनरल लेजर खाता पत्र संस्थाओं द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों का खाता है।

हुआ है ताकि ब्याज दर डेरिवेटिव बाज़ार के विभिन्न पहलुओं का समाधान किया जा सके जिसमें अन्य के साथ-साथ पत्र संस्थाएं, अनुमेय लिखत, एक्सपोजर सीमाएं तथा रिपोर्टिंग शामिल हैं। ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव दोनों को शामिल करते हुए व्यापक दिशा-निर्देश 2019 में जारी किए गए थे। खरीद-बिक्री की जानकारी को लेकर पारदर्शिता, उचित पहुंच एवं प्रसार को बढ़ावा देने एवं व्यापार में ईमानदारी तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी), जिस पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित लिखतों में लेनदेन अनुबंधित किया जा सकता है, को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 जारी करने के साथ विनियामकीय दायरे में लाया गया। अनुचित बाज़ार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए, 2019 में बाज़ार दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप दिशानिर्देश लागू किए गए थे। रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाज़ारों में बेंचमार्क प्रक्रियाओं के अभिशासन में सुधार के लिए, विशेष रूप से लाइबोर घोटाले³ के बाद, वित्तीय बेंचमार्क सिद्धांतों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) की रिपोर्ट (2013) और रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय बेंचमार्क समिति की रिपोर्ट (2014) में अनुशंसित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निर्देश 2019 में जारी किए गए थे।

सरकारी कर्ज के कुशल प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और द्वितीयक बाज़ारों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों का विधिक और विनियामक ढांचा इस प्रकार वर्षों से विकसित हुआ है।

II.2. आपूर्ति पक्ष

सरकारी प्रतिभूतियों को भिन्न-भिन्न परिपक्वता वर्गों के अनुसार जारी किया जाता है, जिसकी वजह से कम समय से लेकर 40 साल तक के लंबे समय का प्रतिफल वक्र का निर्माण हो पाता है। नतीजतन, बकाया स्टॉक में 20 साल और उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का हिस्सा मार्च 2012

³ लाइबोर घोटाला एक ऐसी योजना थी जिसमें कई प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के बैंकों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (लाइबोर) में हेरफेर किया।

सारणी 1 – दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों का परिपक्वता प्रोफाइल

परिपक्वता (वर्ष)	31 मार्च 2012			30 सितंबर 2020		
	प्रतिभूतियों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़)	कुल बकाया में हिस्सा (प्रतिशत)	प्रतिभूतियों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़)	कुल बकाया में हिस्सा (प्रतिशत)
0-5	39	7,82,017	30	34	19,39,139	29
5-7	12	4,22,251	16	10	8,74,072	13
7-10	14	4,77,846	18	13	11,25,350	17
10-15	11	3,61,451	14	16	13,52,702	20
15-20	6	2,09,367	8	4	2,27,151	3
20-25	7	2,37,307	9	6	5,06,002	8
25-30	3	1,03,000	4	3	2,77,798	4
>30				5	3,54,468	5
कुल	92	25,93,328		91	66,56,682	

टिप्पणी : विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर। स्रोत : सीसीआईएल, आरबीआई, आरबीआई स्टाफ गणना।

के अंत में 13 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2020 के अंत में 17 प्रतिशत हो गया है (सारणी 1)। इसके साथ ही, निर्गम के आकार में अनुगामी नीलामियों में पुनर्निर्गमों के जरिए इजाफा किया गया ताकि चलनिधि में वृद्धि करने वाले समान ब्याज और परिपक्वता तारीखों वाली प्रतिभूतियों के समरूप स्टॉक का सृजन किया जा सके। बड़े आकार के निर्गमों के रोलओवर जोखिम को बाइबैक/स्विट्चस का उपयोग कर सक्रिय समेकन के जरिए संभाला गया ताकि पुनर्निर्गमों के तरीके से निष्क्रिय समेकन को सहारा दिया जा सके। नतीजतन, प्रतिभूतियों की संख्या पिछले दशक में काफी हद तक अपरिवर्तित बनी रही, क्योंकि सरकारी ऋण का स्टॉक दुगुना से अधिक हो गया है।

सरकारी कर्ज आपूर्ति में पारदर्शिता को अप्रैल 2002 से सरकारी प्रतिभूतियों में नीलामियों के संबंध में निर्गम कैलेंडर पेश करने के जरिए बढ़ाया गया। हाल के वर्षों में, विस्तृत अर्धवार्षिक उधार कैलेंडरों की घोषणा की गई, जिनमें जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के परिपक्वता-काल और रकम समेत निर्गमों की साप्ताहिक समय-सारणियां दी गई हैं। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों को मुख्यतः स्थिर-कूपन बॉन्ड के रूप में जारी किया जाता है। तथापि, मुद्रास्फीति-संबद्ध बॉन्ड, पूंजी-इन्डेक्स बॉन्ड, अस्थिर-दर बॉन्ड एवं एमबेडेड विकल्पों वाले बॉन्ड जैसे लिखतों के माध्यम से उत्पाद विविधता लाई गई। ट्रेजरी बिलों (टी-बिल्स) और नकदी प्रबंधन बिलों (सीएमबी) को डिस्काउंटड लिखतों के रूप में जारी किया जाता है। प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन के पृथक व्यापार के

निर्गम के लिए विनियामक प्रावधान भी किया गया है ताकि शून्य-ब्याज दर प्रतिफल वक्र के विकास को सुगम बनाया जा सके। खुदरा निवेशकों को लक्ष्य बनाने वाले आला उत्पादों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (स्वर्ण में मूल्यवर्गीकृत सरकारी प्रतिभूति) और बचत बांड शामिल हैं।

दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों को 21 प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) का सहारा प्राप्त है जो इन नीलामियों की हामीदारी देते हैं जिनमें बोली प्रतिबद्धताओं/सफलता अनुपात (टी-बिल/सीएमबी के मामले में) को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 2019-20 के दौरान, पीडी ने व्यक्तिगत रूप से 40 प्रतिशत का निर्धारित न्यूनतम सफलता अनुपात हासिल किया, और वह भी लगभग 60 प्रतिशत के औसत से। इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा राज्य विकास ऋणों (एसडीएल)⁴ की अधिसूचित नीलामी राशियों के 100 प्रतिशत तक के लिए सामूहिक रूप से बोली लगाने के लिए पीडी को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

II.3. मांग पक्ष

भिन्न-भिन्न समय सीमाओं और जोखिम तरजीह वाले वैविध्य निवेशक आधार कर्ज बाजारों के लचीलेपन को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करते हैं जिसके लिए वे सभी परिपक्वता-काल में सक्रिय व्यापार और चलनिधि सुनिश्चित करते हैं। पिछले एक दशक में, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निवेशक आधार का

⁴ एसडीएल राज्य सरकारों द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां हैं।

सारणी 2: सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता (बकाया स्टॉक में प्रतिशत हिस्सा)

समाप्त तिमाही	वाणिज्यिक बैंक	बीमा कंपनियों	कॉर्पोरेट	एफपीआई	भविष्य निधि	आरबीआई	राज्य सरकारें	अन्य वित्तीय संस्थाएं	अन्य
मार्च 2010	47.25	22.16	2.99	0.59	6.76	11.76	-	4.24	4.24
मार्च 2020	40.41	25.09	0.81	2.44	4.72	15.13	2.05	4.24	5.12

टिप्पणी : डीबीआईई।

विस्तार हुआ है। सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक सबसे बड़े निवेशक बने हुए हैं। हालांकि, कुल धारिताओं में उनकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है जबकि बीमा कंपनियों और अनिवासी निवेशकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (सारणी 2)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को बकाया स्टॉक के 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) की शुरुआत के साथ, एफपीआई समेत गैर-निवासी, कतिपय निर्दिष्ट प्रतिभूतियों⁵ में बगैर कोई सूक्ष्म-विवेकपूर्ण सीमाओं के निवेश कर सकते हैं। एफपीआई किसी भी सरकारी प्रतिभूति में, न्यूनतम प्रतिधारण अवधि के भीतर, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर)⁶ के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जिसमें उनको सूक्ष्म-विवेकपूर्ण सीमाओं से कई छूट हैं।

जैसा कि विश्व स्तर पर है, भारत में सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश मुख्य रूप से बीमा, पेंशन और म्यूचुअल फंड जैसी सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। कर लाभ वाली लघु बचत योजनाएं और सरकारी क्षेत्र के बैंक में रखी गई सावधि जमाएं भी खुदरा ब्याज के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। बहरहाल, सरकारी कर्ज में प्रत्यक्ष खुदरा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:

⁵ 31 अक्टूबर, 2020 तक, 10 दिनांकित प्रतिभूतियां एफएआर के तहत निवेश के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 5-वर्ष, 10-वर्ष और 30-वर्ष के परिपक्वता-काल की सरकारी प्रतिभूतियों के सभी नए निर्गम 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में एफएआर के तहत निवेश के लिए पात्र होंगे।

⁶ सरकार और कॉर्पोरेट ऋण में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 01 मार्च, 2019 को शुरू किए गए एफपीआई निवेशों के लिए वीआरआर एक अलग मार्ग है। कई सूक्ष्म-विवेकपूर्ण कंट्रोल से प्रदान करने के अलावा, यह योजना एफपीआई को रेपो और डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन को स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति देती है।

- (i) खुदरा निवेशकों के पास सरकारी प्रतिभूतियों की समुचित रूप से कीमत पता लगाने की विशेषज्ञता नहीं हो सकती है, इसलिए प्राथमिक नीलामियों में एक गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा उनके लिए शुरू की गई थी जिसमें प्रतिभूतियों को नीलामी में पता लगाई गई भारत औसत कीमत पर जारी किया गया;
- (ii) सभी प्राथमिक निर्गमों में खुदरा निवेश के लिए अधिसूचित राशि की 5 प्रतिशत की एक अलग सीमा निर्धारित की गई है;
- (iii) खुदरा निवेशक बैंक, पीडी और स्टॉक एक्सचेंज जैसे वैकल्पिक एग्रीगेटर / फेसिलिटेटर चैनलों का उपयोग कर सकते हैं;
- (iv) खुदरा निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड लॉन्च किए गए हैं और द्वितीयक बाजार में उसकी खरीद-बिक्री को एक्सचेंजों के माध्यम से सक्षम बनाया गया है; 2007 के बाद से तयशुदा लेनदेन प्रणाली ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) में ₹5 करोड़ के मानक खेप आकार के मुकाबले ₹10,000 के न्यूनतम बाजार खेप आकार के एक अलग न्यून-खेप वर्ग का सृजन किया गया।
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)-विनियमित निक्षेपागारों की तरह कन्स्ट्रिक्टूअन्ट सब्सिडियरी जनरल लेजर (सीएसजीएल) खाताधारकों को विभिन्न निक्षेपागारों के डीमैट धारकों के बीच शेयर बाजारों पर खरीद-बिक्री के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) सीधे रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) पर करने की अनुमति दी गई है। सीएसजीएल खाताधारकों के लाभ के लिए ई-कुबेर पर सीधे फाइल अपलोड की सुविधा विकसित की जा रही है।

II.4. बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर

एक सुदृढ़, मजबूत और सुरक्षित बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर बाहरी झटके के खिलाफ सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के लचीलेपन को बढ़ाता है और मूल्य की निरंतर खोज में योगदान करता है, जिससे बाज़ार चलनिधि में वृद्धि होती है (बीआईएस, 1999)। रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए ट्रेडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में लगा हुआ है, जिसमें एकमुश्त और रेपो दोनों बाज़ारों में कारोबार की जानकारी की रिपोर्टिंग और समय पर प्रसार शामिल हैं। फरवरी 2002 में रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) एक मजबूत बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित हुई है।

अप्रैल 2005 में ऑनलाइन बोली-प्रक्रिया को सक्षम करके परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एनडीएस (पब्लिक डेट ऑफिस-एनडीएस) में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी चालू की गई थी। एनडीएस-नीलामी प्लेटफॉर्म ने शुरूआती नीलामियों में अक्टूबर 2012 तक अपनी भूमिका निभाई जब ई-कुबेर, जो एक प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान है और जो बाज़ार-आधारित मूल्य खोज को बढ़ावा देता है, ने बागडोर संभाला। यह निर्बाध रूप से एनडीएस-ओएम और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) (नीचे देखें) समेत रिज़र्व बैंक के पब्लिक डेट ऑफिस में धारित सरकारी प्रतिभूतियों के निक्षेपागार, भुगतान प्रणालियों और द्वितीयक बाज़ार ट्रेडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत हो गया है ताकि प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ारों के बीच की कड़ी सुनिश्चित की जा सके। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयर बाज़ारों के साथ एक इंटरफ़ेस को भी शामिल करता है जिसके माध्यम से बोलियां एकत्रित की जा सकती हैं और रिज़र्व बैंक के समक्ष रखी जा सकती हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों में लगभग 80 प्रतिशत द्वितीयक बाज़ार लेनदेन एनडीएस-ओएम पर किए जाते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए एक गुणनाम ऑर्डर मिलान प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सहारा देना वितरण-बनाम-

भुगतान (डीवीपी)-III⁸ आधार पर लेनदेन के निपटान की एक पद्धति है और केंद्रीय प्रतिपक्ष के माध्यम से प्रतिपक्ष जोखिम समाप्त होते हैं एवं, बहुपक्षीय नेटिंग के माध्यम से चलनिधि आवश्यकताओं में कमी आती है। 2001 में स्थापित सीसीआईएल, पीएसएस अधिनियम, 2007⁹ के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करने के लिए भुगतान प्रणाली के रूप में अधिकृत है। सीसीआईएल का मूल्यांकन वित्तीय बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीएफएमआई)¹⁰ संबंधी सिद्धांतों के तहत निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के रूप में किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन मुख्य रूप से दो प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं - क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) और त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग सिस्टम (टीआरईपीएस)। एनडीएस-ओएम समेत ये प्लेटफॉर्म, क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा चलाए जाते हैं जो सीसीआईएल की सहायक कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 के अधीन आते हैं। एकमुश्त लेनदनों के साथ-साथ रेपो ट्रेड को डीवीपी-III प्रक्रिया के तहत सीसीआईएल द्वारा भी निपटाया जाता है ताकि निपटान के दौरान चलनिधि एवं नेटिंग क्षमता को सुरक्षित किया जा सके। इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाओं के तहत व्यापार संबंधी जानकारी का तत्काल प्रसार शामिल है। व्यापार भंडार बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरक है जिसमें संबंधित ब्याज दर डेरिवेटिव (साथ ही विदेशी मुद्रा और क्रेडिट डेरिवेटिव) में सभी ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन रिपोर्ट किए जाते हैं, इस प्रकार सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित बाज़ारों में सभी लेनदेन का 360 डिग्री दृश्य मिलता है, जिसकी बदौलत प्रभावी बाज़ार निगरानी और पर्यवेक्षण संभव हो पाता है।

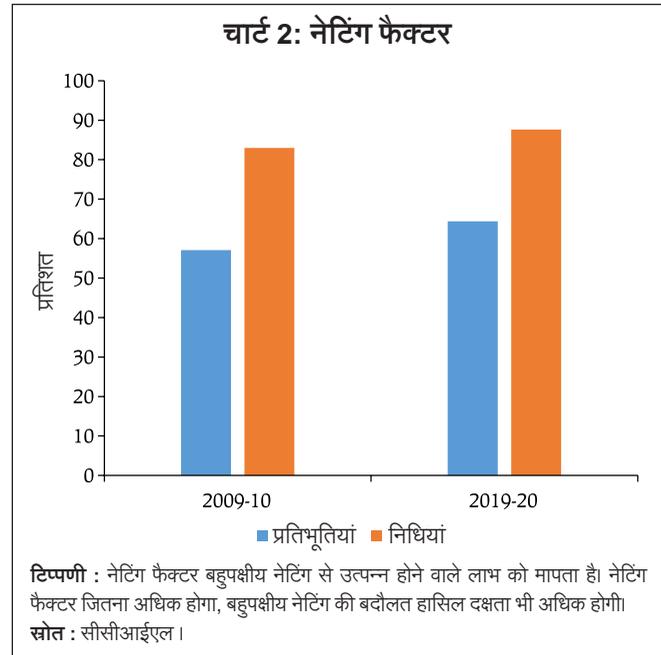
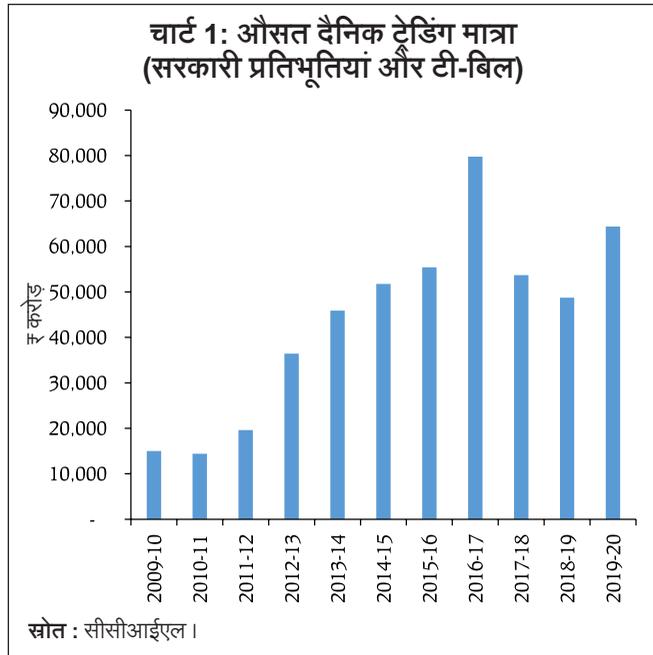
पिछले एक दशक के दौरान, एकमुश्त सेगमेंट में औसत दैनिक कारोबार 2009-10 में ₹15,000 करोड़ से 16 प्रतिशत के

⁸ वितरण बनाम भुगतान - III (डीवीपी-III) एक निपटान विधि है जिसमें प्रतिभूतियों और धन दोनों चरणों को शुद्ध आधार पर निपटाया जाता है और केवल किसी एक प्रतिभागी द्वारा किए गए सभी लेनदेन की अंतिम शुद्ध स्थिति का निपटान किया जाता है।

⁹ सीसीआईएल को सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाज़ार लिखतों, विदेशी मुद्रा और रुपया डेरिवेटिव में लेनदेन के समाशोधन और निपटान के लिए पीएसएस अधिनियम के तहत एक अधिकृत भुगतान प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया गया है।

¹⁰ पीएफएमआई वित्तीय बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कमिटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ सिक्योरिटीज कमिशन द्वारा जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। https://www.bis.org/cpmi/info_pfm.htm

⁷ शेष लेनदेन ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) में होते हैं और एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किए जाते हैं।



संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर 2019-20 में ₹64,000 करोड़ हो गया (चार्ट 1)। प्रतिभागियों को मिलने वाले नेटिंग लाभों में तेजी से वृद्धि हुई है, जैसा कि नेटिंग फैक्टर में सुधार के द्वारा देखा जा सकता है, जो बहुपक्षीय नेटिंग के कारण प्राप्त दक्षता को मापता है (चार्ट 2)। बाज़ार चलनिधि में वृद्धि और बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार से भी बड़े व्यापार करने में आसानी हुई है (सारणी 3)।

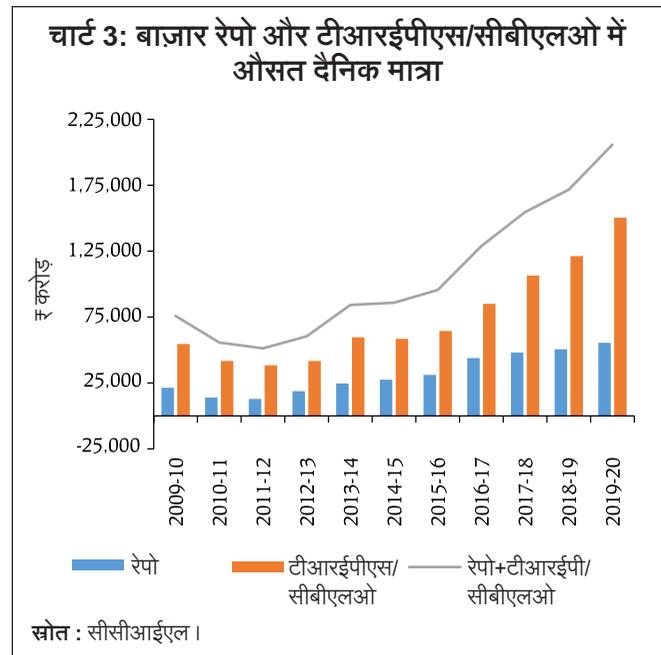
रेपो बाज़ार में पर्याप्त वृद्धि देखी गई और औसत दैनिक मात्रा 2009-10 में ₹75,000 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में लगभग ₹2 लाख करोड़ हो गई (चार्ट 3)। इसके साथ ही, डेरिवेटिव बाज़ार (ब्याज दर स्वैप या आईआरएस; ब्याज दर

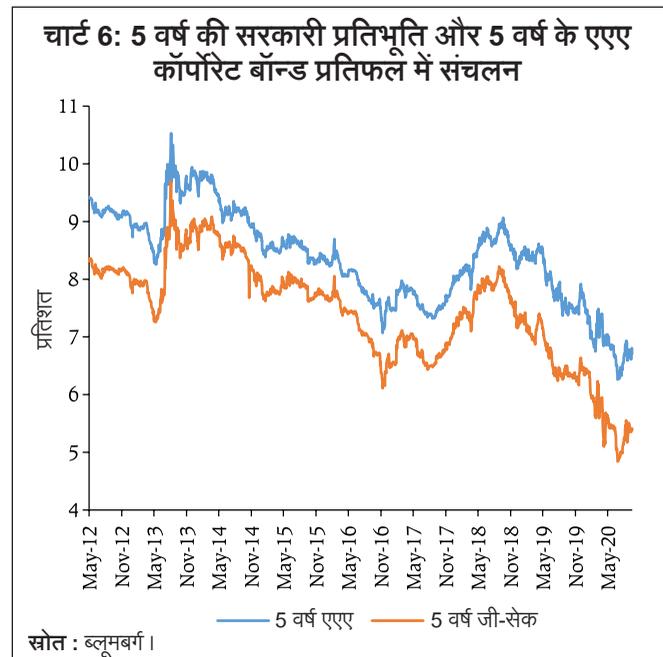
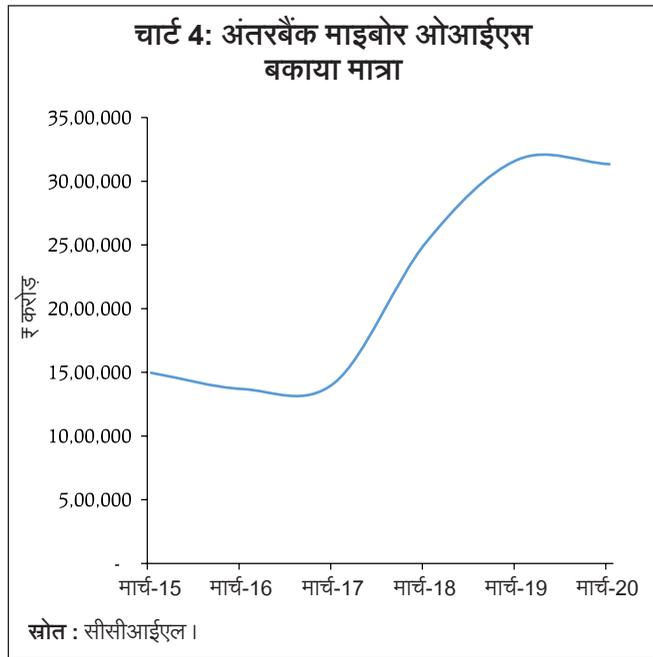
वायदा या आईआरएफ) में भी विकास हुआ है। विशेष रूप से, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) बाज़ार में चलनिधि में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई (चार्ट 4)।

सारणी 3: एकमुश्त व्यापार के लिए लेनदेन के आकार का विश्लेषण

वित्त वर्ष	लेनदेन आकार (कुल लेनदेन का प्रतिशत)				
	₹5 करोड़ से कम	₹5 करोड़	₹5-10 करोड़	₹10-20 करोड़	₹20 करोड़ से अधिक
2009-10	5.7	65.1	18.0	3.3	7.8
2019-20	3.4	52.9	21.1	7.8	14.9

स्रोत : सीसीआईएल।



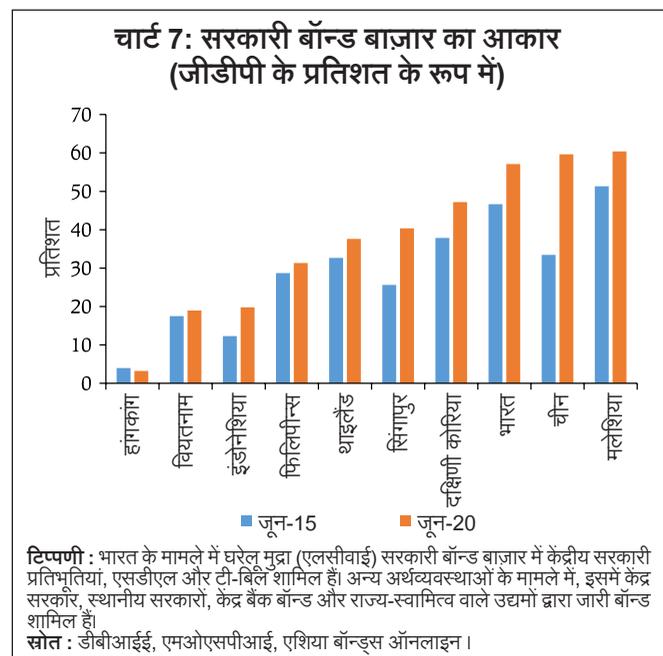
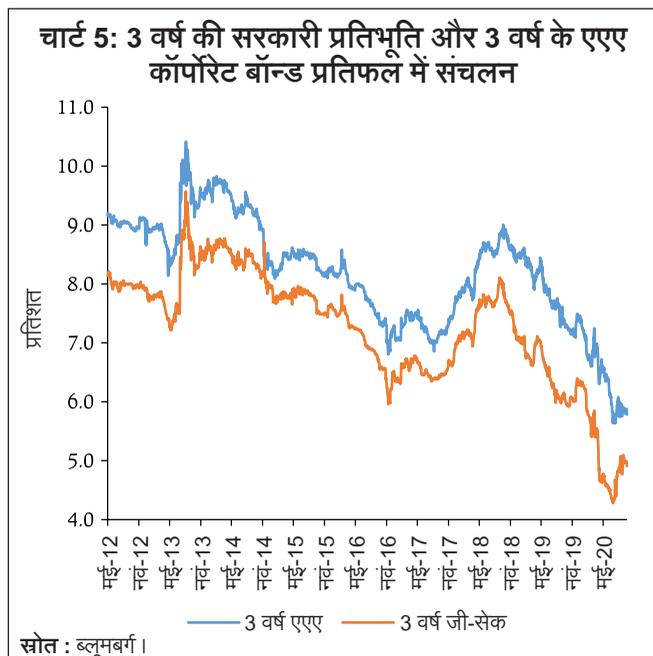


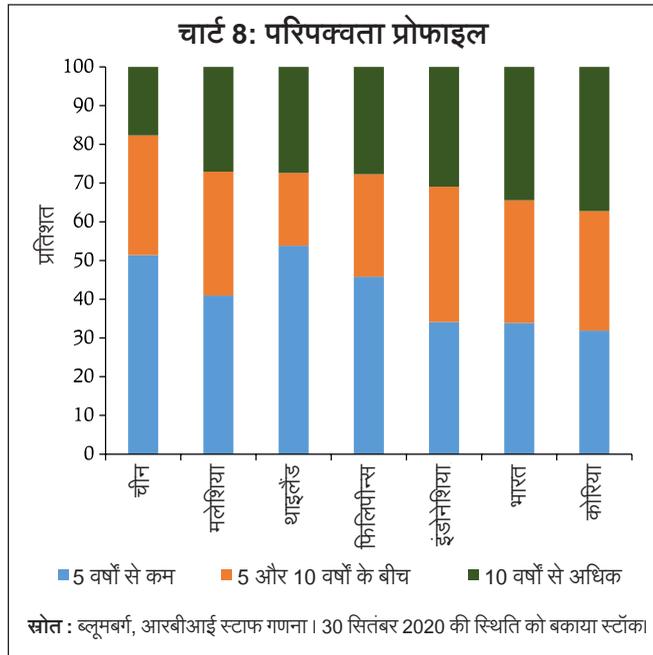
सरकारी प्रतिभूति बाजार ने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। स्थिर क्रेडिट स्प्रेड (सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफलों के बीच का अंतर) लंबे समय तक सरकारी प्रतिभूति सेगमेंट से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में आवेगों के अपेक्षाकृत सुचारु ट्रान्समिशन का साक्ष्य देता है (चार्ट 5 और 6)।

III. बहु-देशीय अनुभव

चीन और मलेशिया को छोड़कर अधिकांश एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत सरकार के बांड बाजार का आकार बड़ा है (चार्ट 7)।

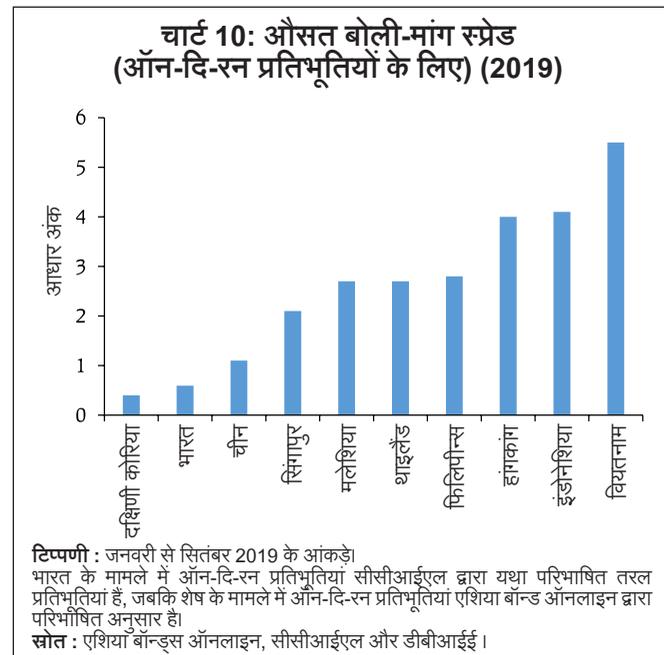
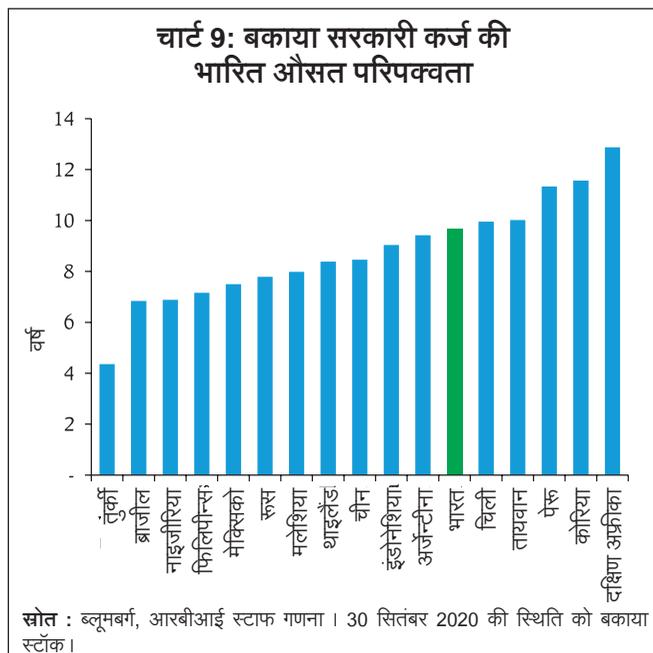
एशियाई साथियों की तुलना में, बकाया भारतीय सरकारी कर्ज के परिपक्वता प्रोफाइल को छोटे (5 वर्ष से कम), मध्यम (5



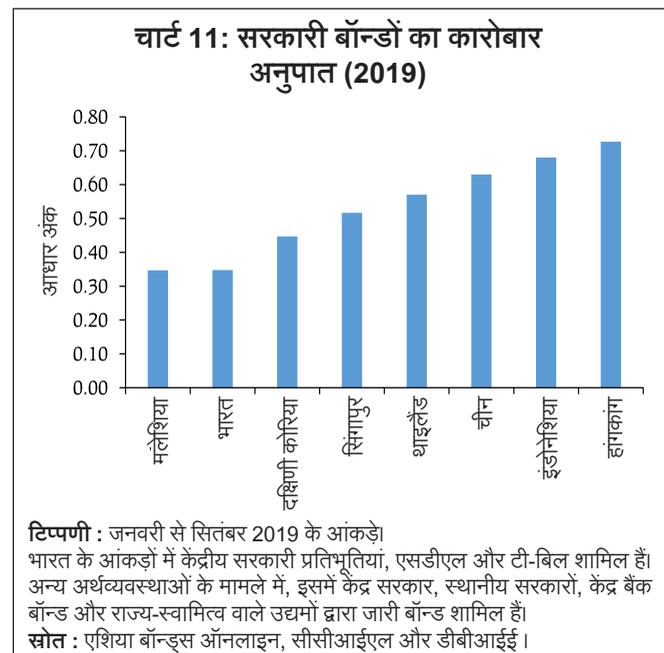


से 10 वर्ष) और लंबे (10 वर्ष से अधिक) परिपक्वता काल (चार्ट 8) के अनुसार अधिक समान रूप से बांटा जाता है, जिससे निवेशकों को अपनी समय सीमाओं के मुताबिक निवेश करने की सहूलियत मिलती है। व्यापक उभरते बाज़ार (ईएम) जगत के सापेक्ष भी, बकाया सरकारी कर्ज की औसत परिपक्वता अपेक्षाकृत अधिक है, जो कम रोलओवर जोखिम का संकेत देता है (चार्ट 9)।

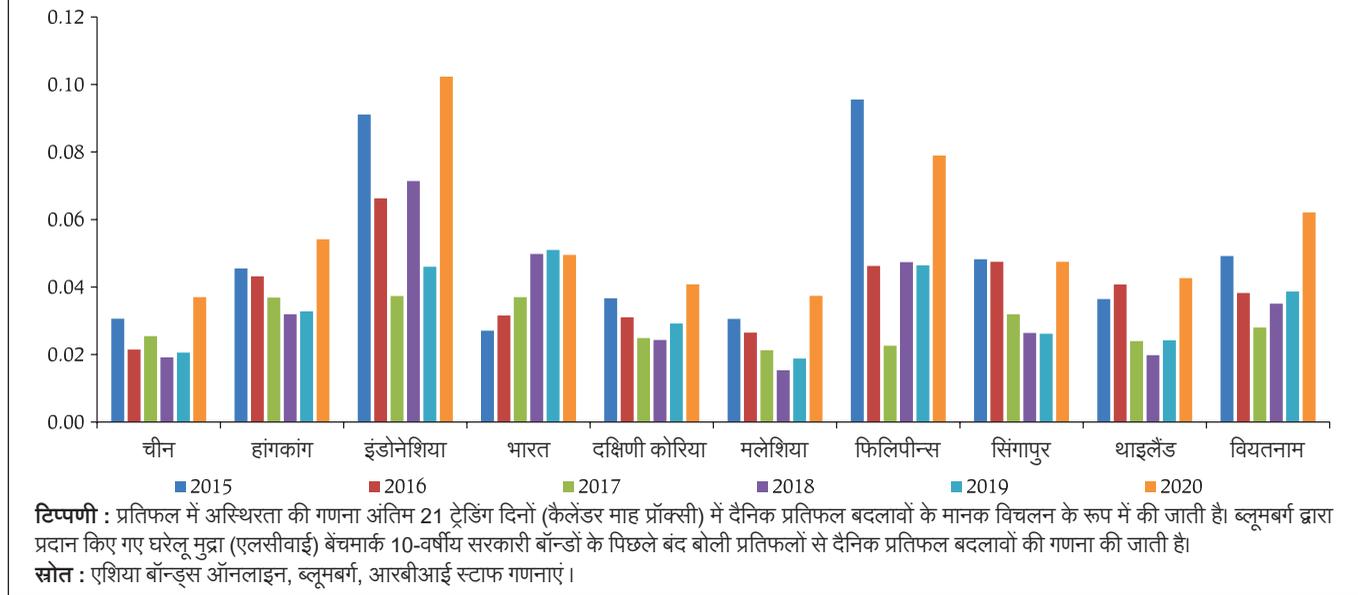
एक तरल बाज़ार सामान्यतः छोटी बोली/मांग स्प्रेड की विशेषता युक्त होती है जिसमें बड़े लेनदेनों के मामले में भौतिक रूप



से वृद्धि नहीं होती है (गर्बर, 1997)। भारत सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में औसत बोली-मांग स्प्रेड एशियाई ईएम समकक्षों में सबसे कम है (चार्ट 10)। वास्तव में, बाज़ार चलनिधि की प्रभाव लागत और बोली-मांग स्प्रेड (बीआईएस, 2019) के संदर्भ में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी अच्छी-खासी तुलना की जाती है। हालांकि, कारोबार अनुपात – बकाया बॉन्ड स्टॉक की तुलना में कारोबार का अनुपात - भारतीय मामले में कम है, जो द्वितीयक बाज़ार में अपेक्षाकृत कम मात्रा का संकेत देता है (चार्ट 11)।



चार्ट 12: प्रतिफल में अस्थिरता – 10 वर्ष की सरकारी प्रतिभूतियां



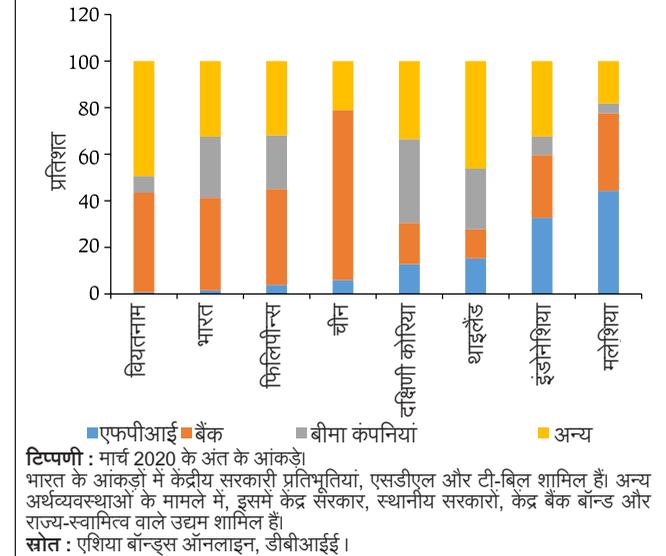
प्रतिफल अस्थिरता को सामान्यतः पिछले 21 ट्रेडिंग दिनों (कैलेंडरमाह के लिए एक प्रॉक्सी) में दैनिक प्रतिफल परिवर्तनों के मानक विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उच्च प्रतिफल अस्थिरता बॉन्ड प्रतिफलों में दैनिक संचलनों की कम भविष्यवाणी बताती है, जबकि निम्न अस्थिरता का आशय है कि प्रतिफल औसत प्रतिफलों के इर्द-गिर्द अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं और इस प्रकार अधिक तरल बाजार के संकेतक हो सकते हैं (कवाई, 2019)। हाल के वर्षों में, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिफल अस्थिरता कच्चे तेल की कीमतों में आपूर्ति संबंधी चिंताओं और उतार-चढ़ाव के चलते चीन और मलेशिया के बॉन्ड की अपेक्षा सामान्यतः अधिक रही। फिर भी, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स और वियतनाम में जारी बॉन्डों की अपेक्षा अस्थिरता निम्न रही (चार्ट 12)।

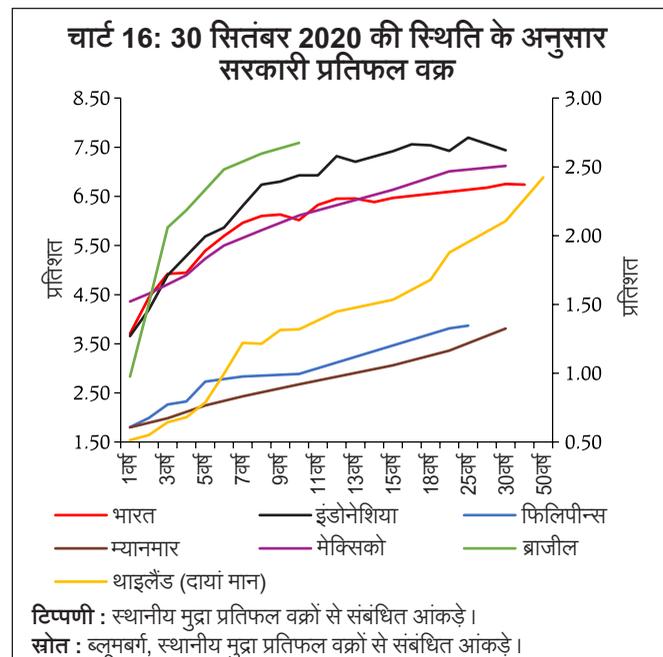
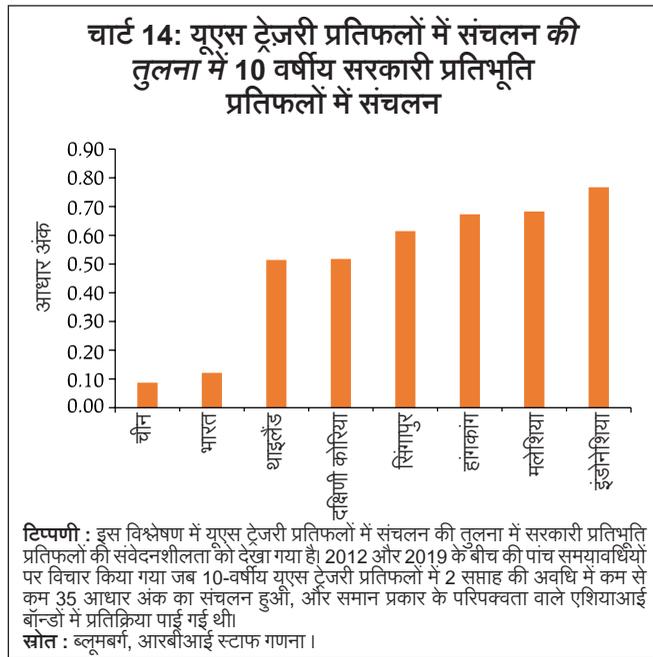
भारत सरकार की प्रतिभूतियों में गैर-निवासी निवेश एशियाई ईएम समकक्षों की अपेक्षा कम है (चार्ट 13), जो आंशिक रूप से भारत में विदेशी निवेश के लिए घरेलू कर्ज बाजारों को खोले जाने को लेकर अपनाए गए सोचे-समझे दृष्टिकोण की वजह से है। तथापि, कर्ज बाजारों में अपेक्षाकृत रूप से कम विदेशी मौजूदगी ने भारतीय बाजार को बाहरी झटकों के प्रति

कम संवेदनशील बनाया जैसे कि यूएस ट्रेजरी नोटों में प्रतिफल का संचलन (चार्ट 14)।

भारत के मामले में प्रतिफल वक्र 40 साल तक लंबा होता है, जो अधिकांश उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में

चार्ट 13: सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशक प्रोफाइल

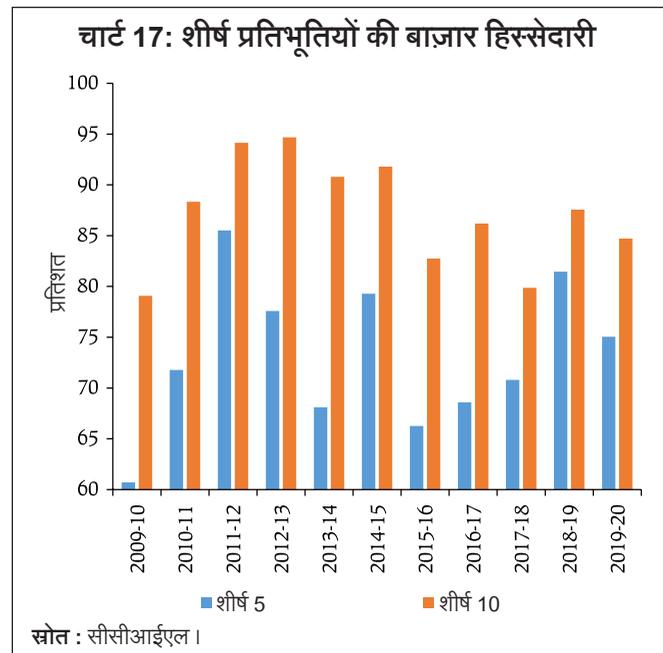
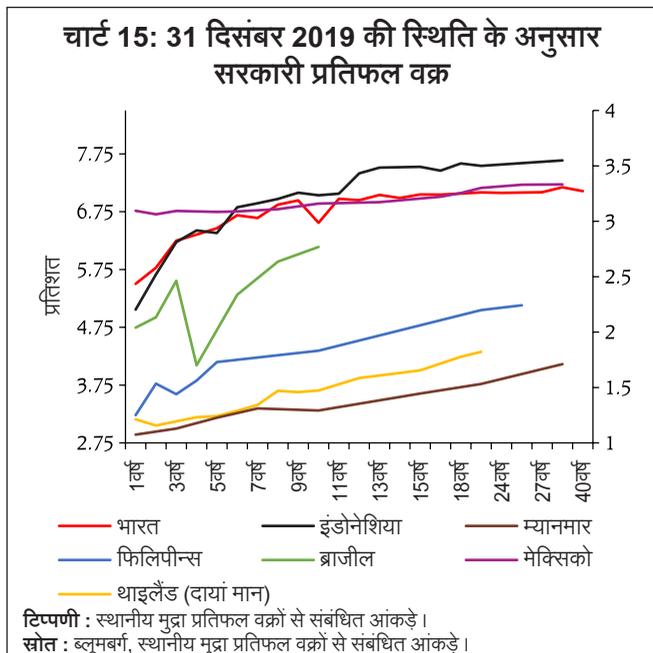


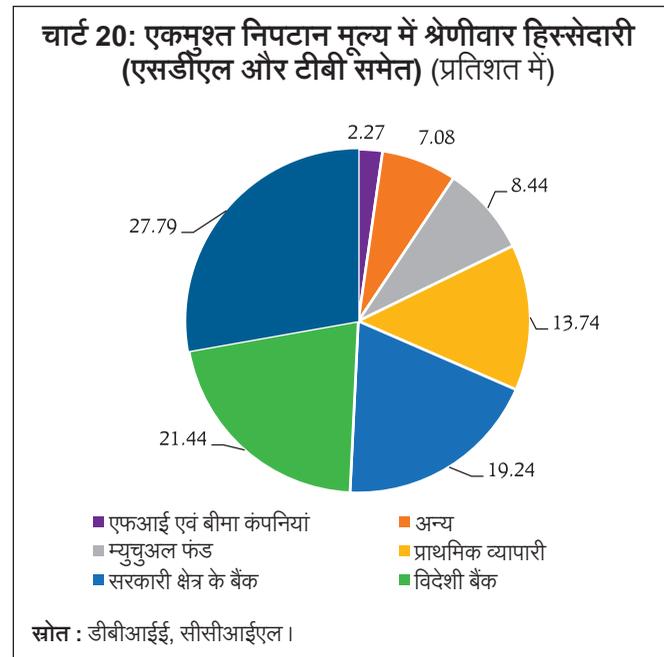
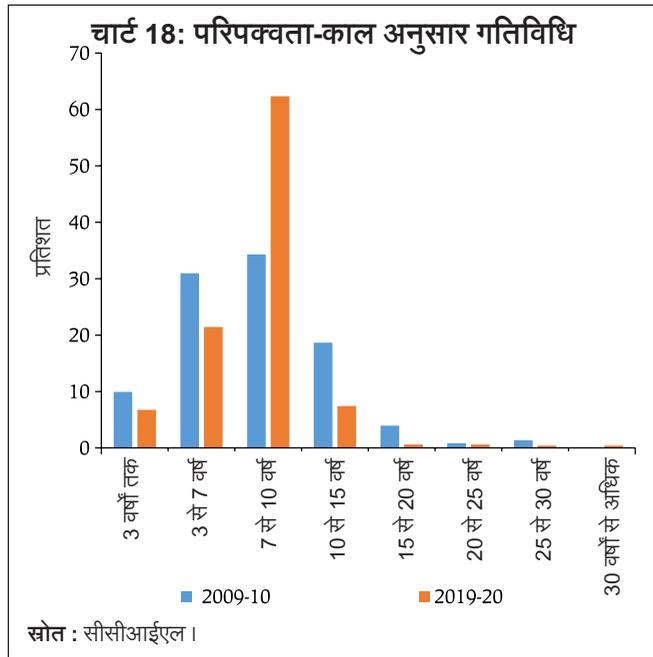


नहीं देखा गया (चार्ट 15)। भारत का प्रतिफल वक्र सबसे सपाट भी है, जो मीयादी संरचना में निम्नतर मीयाद प्रीमियम को दर्शाता है। उसी समय, भारत का प्रतिफल वक्र चुनिंदा परिपक्वता-कालों में असहज रूप से बर्ताव करता है जो दर्शाता है कि चलनिधि प्रीमियम चुनिंदा प्रतिभूतियों/परिपक्वता-कालों के अनुसार संचालित होते हैं। ऐसे असहज बर्ताव कुछ अन्य ईएम के प्रतिफल वक्रों में भी पाया गए हैं (चार्ट 16)।

IV. कुछ असाधारण विशेषताएं

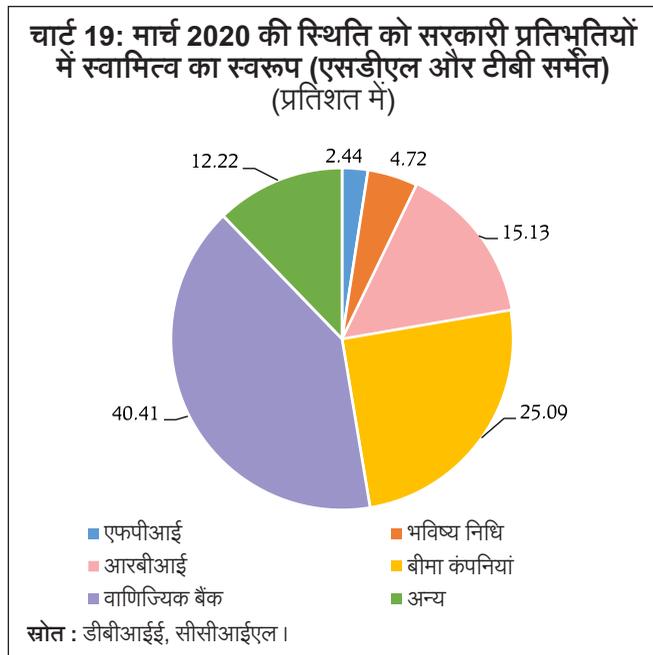
सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार चलनिधि कुछ एक प्रतिभूतियों व परिपक्वता-कालों में संकेद्रित है। 2019-20 में द्वितीयक बाजार के कारोबार में शीर्ष की 5 प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी उच्च अर्थात लगभग 75 प्रतिशत थी (चार्ट 17)। अधिकांश ट्रेडिंग 7 और 10 साल के बीच के परिपक्वता-कालों वाली प्रतिभूतियों में संकेद्रित रही (चार्ट 18)। भिन्न-भिन्न





परिपक्वता-कालों में द्वितीयक बाजार चलनिधि का व्यापक वितरण जोखिम-मुक्त दरों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में सरकारी प्रतिफल वक्र की विश्वसनीयता को और बढ़ा सकता है और इसके परिणामस्वरूप, गैर-सरकारी कर्ज के मूल्य में सुधार होगा। हालांकि, यह भारत में बाजार के माइक्रोस्ट्रक्चर के विशिष्ट पहलुओं को भी दर्शाता है।

बीमा और भविष्य निधि अपने नकदी प्रवाह के स्वरूप और संबंधित निवेश कार्यनीतियों के कारण 'क्रय और धारण' निवेशक होते हैं, जो उनकी देयता प्रतिबद्धताओं के अनुरूप लंबी दिनांकित प्रतिभूतियों को प्राथमिकता देते हैं। दैनिक ट्रेडिंग मात्रा में ऐसी संस्थाओं की हिस्सेदारी सरकारी प्रतिभूतियों की धारिताओं में उनकी हिस्सेदारी की अपेक्षा काफी कम है (चार्ट 19 और 20 और सारणी 4)।



सारणी 4: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के संबंध में परिपक्वता समूह-वार धारिताएं (प्रतिशत)

श्रेणी	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 25 वर्ष	25 वर्ष से अधिक
वाणिज्यिक बैंक	54.2	52.1	43.2	11.6	3.1
बीमा	7.6	10.6	31.5	65.2	90.4
म्युचुअल फंड	2.5	3.7	2.2	0.3	0.5
सहकारी बैंक	0.3	1.3	0.8	0.3	0.2
आरबीआई	28.2	23.2	11.6	6.2	0.0
भविष्य निधि	2.0	2.3	4.4	10.8	3.9
राज्य सरकारें	2.2	3.9	3.2	0.0	0.0
अन्य	3.0	2.9	3.1	5.6	1.8
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

टिप्पणी : 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

सरकारी प्रतिभूति बाजारों में बड़ी संख्या में प्रतिभागी 'केवल लंबे समय' के खिलाड़ी होते हैं, जिनके पास विनियामक बाधाएं या व्यापारिक कार्यनीतियां हैं जो उन्हें मंदड़िया बाजारों में खरीद से अधिक बिक्री करने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, जहां रिजर्व बैंक ने सभी संस्थाओं को खरीद से अधिक बिक्री करने की अनुमति दी है, वहीं उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की संस्थाएं जैसे कि म्यूचुअल फंड अपने संबंधित विनियामकों द्वारा प्रतिबंधित हैं। बैंकों के बीच भी, कुछ व्यापारिक कार्यनीति के रूप में खरीद से कम बिक्री करने की स्थिति पर बने रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार, चलनिधि मंदी के बाजारों में और अनिश्चितता के समय सूख जाती है, जिसमें प्रतिभागी मूल्यों को लेकर अपनी राय देने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हैं।

पिछले कुछ वर्षों में आईआरडी बाजार सेगमेंट विकसित हुए हैं। हालांकि, एकमात्र प्रमुख तरल उत्पाद मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (एमआईबीओआर) आधारित ओआईएस है (सारणी 5)। आईआरडी बाजारों में भागीदारी विदेशी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और पीडी तक भी सीमित है, जो संयुक्त रूप से अधिकांश ट्रेडिंग मात्राओं का कारण है। बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों में सरकारी प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण मात्रा होती है, लेकिन बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों को बाजार में अपने निवेश को चिह्नित करने की आवश्यकता नहीं होती है और बैंकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के बड़े हिस्से को 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) श्रेणी में रखने की अनुमति होती है, ऐसे प्रतिभागियों को हेज करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हेज को लेकर असममित लेखांकन व्यवहार के निदेशों - मार्क-टू-मार्केट मूल्यहासों को हिसाब में लिया जाना है, लेकिन नकदी स्थितियों के मामले में मूल्यवृद्धियों को नज़रअंदाज

आईआरएस व्यापारों की ट्रेडेड मात्रा

(₹ बिलियन में)

वर्ष	माइबोर	माइफॉर	आईएनबीएमके
2013-14	22.967	798	4
2014-15	20.292	1.198	3
2015-16	21.329	993	3
2016-17	19.235	1.254	-
2017-18	33.808	1.112	-
2018-19	58.617	1.709	-
2019-20	39.181	2.886	-
2020-21 (अग-20 तक)	6.745	668	-

किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि और मूल्यहास दोनों को डेरिवेटिव स्थितियों¹¹ के मामले में हिसाब में लिया जाना है - जो बैंकों के हेजिंग से बचने के कारणों में से एक है।

V. भावी राह

2020-21 में, प्राथमिक बाजार निर्गम कार्यनीति को दुरुस्त किया गया ताकि प्रतिभूतियों को छह 'प्रमुख' परिपक्वता-कालों, अर्थात्, 2-वर्ष, 5-वर्ष, 10-वर्ष, 14-वर्ष, 30-वर्ष और 40-वर्ष में जारी किया जा सके जिसमें प्रत्येक प्रतिभूति को एक पखवाड़े में जारी/पुनःजारी किया जा रहा है। यह कार्यनीति द्वितीयक बाजार में ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त सहूलियत के शुरुआती निर्माण में मदद करेगी और प्रतिभूति के निर्गमों के सटीक परिपक्वता-काल के बारे में विश्वास दिलाएगी।

विश्व स्तर पर, अतरल प्रतिभूतियों का आम तौर पर द्विपक्षीय रूप से कारोबार किया जाता है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में एनडीएस-ओएम पर रिक्वेस्ट फॉर क्वोट (आरएफक्यू) विधि से लेनदेन करने को प्राधिकृत किया है ताकि प्रतिभागियों को बहुविध प्रतिपक्षों से एक साथ और प्रत्यक्ष क्वोट प्राप्त करने के लिए समर्पित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा सके।

अनिवासियों के लिए निवेश व्यवस्था विकसित हो रही है ताकि सुविचारित समष्टि-विवेकपूर्ण नियंत्रण के भीतर एफपीआई निवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके, वहीं अनिवासियों द्वारा भारतीय गिल्ट का लाभ उठाया जाने के लिए और प्रयास की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी (आईसीएसडी) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर्राष्ट्रीय निपटान उन अनिवासियों को सक्षम कर सकता है जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए घरेलू पंजीकरण करने के इच्छुक नहीं हैं। हाल के विनियामक परिवर्तन, जो अनिवासियों के लिए घरेलू हेजिंग बाजारों तक पहुंच को आसान बनाने में मदद करते हैं, इस प्रयास को और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार, एनडीएस-ओएम - जो

¹¹ लेखांकन व्यवहार तब लागू होता है जब हेज प्रभावशीलता स्थापित नहीं होती है। किसी हेज को 'प्रभावी' माना जाता है अगर शुरुआत में और हेज की अवधि के दौरान हेजिंग के समय अंकित बाजार मूल्य के संदर्भ में हेज की गई वस्तुओं के मार्क-टू-मार्केट मूल्य में परिवर्तनों को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के अंकित बाजार मूल्य में बदलावों के जरिए 'लगभग पूरी तरह से बराबर' कर दिया जाता है और वास्तविक परिणाम 80 प्रतिशत से 125 प्रतिशत के दायरे में हैं।

एनडीएस-ओएम को एक्सचेंजों के साथ लिंक करने के लिए 'एनडीएस-ओएम-एक्सचेंज कनेक्ट' है - तक सीधी पहुंच को सक्षम करने के लिए तैयार किए गए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से खुदरा निवेशक आधार का विस्तार करने के प्रयास जारी हैं। गिल्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) शुरू करने को लेकर सरकार के साथ काम चल रहा है। एक समाशोधन सदस्य संरचना विकसित की गई है, जो पंजीकृत दलालों/ निक्षेपागार प्रतिभागियों को अप्रत्यक्ष सदस्य बनकर और एनडीएस-ओएम के समाशोधन सदस्यों के जरिए ट्रेडिंग करके एनडीएस-ओएम में भाग लेने में सक्षम बनाएगी।

वर्तमान में, प्रतिभागियों को तीन महीने तक खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति बनाए रखने की अनुमति है। यह अधिक समय-सीमा तक या ब्याज दर चक्र में ब्याज दर विचारों की अभिव्यक्ति को रोकता है। संबंधित विनियामक मानदंडों को कम करने के साथ ही खरीद से अधिक बिक्री के लिए समय-सीमा को बढ़ाने से बाजारों में चलनिधि को विकसित करने में मदद मिल सकती है, खासकर मंदी की स्थिति में।

'विशेष रेपो'¹² हेतु बाजार वर्तमान में प्रतिभूतियों की उधारी की सुविधा प्रदान करता है। बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड जैसे निवेशकों, जो सरकारी प्रतिभूतियों की बड़ी मात्रा रखते हैं, पर रेपो बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियां उधार देने के संदर्भ में विनियामक सीमाएं हैं। व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए एक अलग सिक्युरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग मेकेनिज्म (एसएलबीएम) द्वितीयक बाजार चलनिधि को बढ़ा सकता है।

डिलीवरेबल बॉन्ड फॉरवर्ड दीर्घावधि ब्याज दर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) समेत बीमा कंपनियों, भविष्य निधि और कॉर्पोरेट्स जैसे बाजार सहभागियों द्वारा पुनर्निवेश जोखिम की हेजिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है। बॉन्ड फॉरवर्ड, ओआईएस स्वैप की तुलना में बड़े संस्थागत प्रतिभागियों के लिए एक पूर्ण हेज समाधान प्रदान कर सकता है,

जो अनिवार्य रूप से अनिधिक लागतों को हेज करता है। विश्व स्तर पर, दीर्घावधि देनदारियों की हेजिंग के लिए बॉन्ड फॉरवर्ड का उपयोग असामान्य नहीं है।

आगे चलकर, सरकारी प्रतिफल वक्र के संबंध में भिन्न-भिन्न परिपक्वता-कालों में चलनिधि को बढ़ाना, निवेशक आधार में विस्तार और डेरिवेटिव बाजार को विकसित करना ध्यान देने योग्य क्षेत्र हो सकते हैं। यह सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मिश्रित रूप से निर्मित बाजार परिवेश में वृद्धि करेगा और बढ़ती अर्थव्यवस्था के हितों को आगे बढ़ाने और उसमें मदद पहुंचाने के लिए बाजारों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से एकीकृत होता जा रहा है।

संदर्भ

Bank for International Settlements. Committee on the Global Financial System (CGFS) Paper No. 62. (1999, January). *Establishing viable capital markets*.

Bank for International Settlements. CGFS. (1999, October). *How should we design deep and liquid markets? The case of government securities*.

IMF and World Bank. (2001, July). *Developing Government Bond Markets – A Handbook*.

Masahiro Kawai. (2019, January). Economic Research Institute for Northeast Asia Discussion Paper No. 1901e. *Asian Bond Market Development*.

Robert I. Gerber. (1997). Managing Fixed Income Portfolios. In Frank J. Fabozzi (Eds.), *A User's Guide to Buy-Side Bond Trading (Chapter 16, p. 278)*. New Hope, PA: Frank J. Fabozzi.

Sahana Rajaram & Payal Ghose. (2019, December). CCIL Monthly newsletter. *Indian Sovereign Bond Market - An update*.

¹² विशेष रेपो के मामले में, उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों विशिष्ट प्रतिभूति से अवगत होते हैं, जिसके विरुद्ध रेपो सौदा समाप्त करने की मांग की जाती है। एक विशेष रेपो सेगमेंट के अलावा, सीआरओएमएस प्लेटफॉर्म में एक सामान्य संपार्श्विक रेपो सेगमेंट होता है जिसे बार्केट रेपो कहा जाता है।

लाइबोर: अभ्युदय और अंत*

सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय बेंचमार्क, लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर), का प्रकाशन वर्ष 2021 के बाद बंद हो जाने की उम्मीद है। लाइबोर से वैकल्पिक बेंचमार्क की ओर रुख करने में जो मसले हैं वो अवसरों के साथ-साथ चुनौतियाँ भी पेश करेंगे जिसके लिए हितधारकों को जागरूक और तैयार रहने की जरूरत है।

परिचय

वित्तीय बेंचमार्क की दुनिया में 2012 एक ऐतिहासिक वर्ष था। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वित्तीय बेंचमार्क, लाइबोर के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय संस्थानों में लोगों द्वारा हेरफेर किया गया था। इस घटना ने वित्तीय प्रणाली में आघात की लहरें पैदा कर दीं - अरबों डॉलर के ऋण/बॉन्ड/डेरिवेटिव के लिए भुगतान और कीमत निर्धारण के लिए इस्तेमाल किए गए वित्तीय संदर्भ की विश्वसनीयता पर आंच आ गई। इस समस्या की जड़ इस तथ्य में है कि लाइबोर किसी बाजार में कीमतें निर्धारित करता है - बैंकों के लिए बेजमानती थोक अवधि के लिए बाजार - जिसमें घटते हुए वॉल्यूम ने कुशल कीमत निर्धारण को मुश्किल बना दिया (बेली, 2017)¹। वित्तीय बाजारों में संरचनात्मक परिवर्तन, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से, का आशय यह था कि लेन-देन आधारित प्रस्तुतियाँ लाइबोर के गठन की ओर अग्रसर थीं और जो बचा है वह अनुमान है।

वर्ष 2017 में सकारात्मक कार्रवाई करते हुए वित्तीय कंडक्ट ऑथोरिटी (एफसीए), यूके ने घोषणा की कि वह 2021 के अंत के बाद से लाइबोर को चुनने के लिए बैंकों को अधिदेश देने हेतु अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। वैकल्पिक संदर्भ दरों की खोज एक बेंचमार्क से हटकर शुरू हुई है जो लगभग पांच दशकों से वैश्विक स्तर पर वित्तीय संविदाओं में लगभग सार्वभौमिक रूप से उपयोग किया गया है और यह दुनिया भर में और भारत में भी एक कठिन चुनौती है क्योंकि इसकी अंतिम तिथि तेजी से नजदीक आ रही है।

* यह लेख वित्तीय बाजार विनियमन विभाग के वासुदेव हेमचंद्रन द्वारा तैयार किया गया है। लेखक बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए मनोज कुमार के आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

¹ <https://www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor>

इस पृष्ठभूमि के आलोक में, इस लेख में लाइबोर के विकास, इसे बदलने के निर्णय के पीछे की घटनाओं, वैकल्पिक बेंचमार्क की खोज और इसके परिवर्तन में शामिल मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। लेख के खंड II में लाइबोर की व्युत्पत्ति और वर्षों में इसे सुधारने के प्रयासों का पता लगाया गया है। खंड III में वैकल्पिक बेंचमार्क और वैकल्पिक बेंचमार्क के लिए परिवर्तन से संबद्ध समस्याओं की गहन छानबीन की गई है। खंड IV में इस बात की जांच की गई है कि परिवर्तन भारतीय क्षेत्राधिकार को कैसे प्रभावित करता है। खंड V में नीतिगत दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष दिया गया है।

II. व्युत्पत्ति

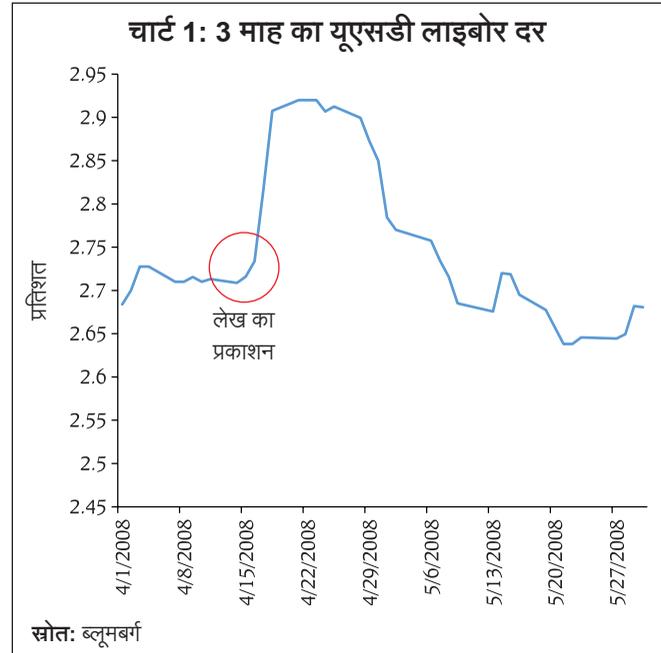
1960 के दशक में अमेरिका के बाहर बैंकों की शाखाओं में यूरोडॉलर बाजार (यूएस के बाहर धारित यूएस डॉलर मूल्यवर्गित जाराशियाँ) के अभ्युदय से लाइबोर ब्याज दरों के उपयोग का पता लगाया जा सकता है। 'लाइबोर' शब्द की व्युत्पत्ति का श्रेय मिनोस ज़ोम्बानकिस नामक एक ग्रीक बैंकर को दिया जाता है, जो मैन्यूफैक्चर के हनोवर की लंदन शाखा, जो अब जेपीमॉर्गन² का हिस्सा है, चला रहे थे। वर्ष 1969 में उन्होंने ईरान के शाह के लिए 80 मिलियन डॉलर के सिंडिकेटेड ऋण की व्यवस्था की जिसमें उन्होंने लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर का उल्लेख किया था। इन दरों को शुरू में तीन मुद्राओं - अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन के लिए गणना की जाती थी। समय के साथ, और अधिक मुद्राएं/परिपक्वताएं जुड़ गईं और लाइबोर दरों को एक दिवसीय से लेकर अधिकतम एक वर्षीय तक के 15 परिपक्वता अवधि में दस मुद्राओं के लिए की घोषणा की गई थी। वर्तमान में, 35 लाइबोर दरों को प्रत्येक दिन हरेक पांच प्रमुख मुद्राओं, अर्थात्, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और अमेरिकी डॉलर के लिए सात परिपक्वता के लिए पोस्ट किया जाता है।

लाइबोर दरों की गणना इस सवाल के जवाब के आधार पर प्रमुख बैंकों से प्राप्त पोल्ड दरों की 'ट्रीमड मीन' के रूप में की जाती है: 'आप किस दर पर धनराशि उधार ले सकते हैं, ऐसा आप पूछकर और फिर उचित बाजार आकार में ठीक सुबह 11 बजे से पहले अंतरबैंक प्रस्ताव स्वीकार करके कर सकते हैं?'

² https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr667.pdf

सवाल की व्यक्तिपरक प्रकृति, विशेष रूप से समय और आकार से संबंधित - 'उचित बाजार का आकार' और '11 बजे से ठीक पहले'- लाइबोर में हेरफेर के लिए असुरक्षित छोड़ देते हैं। लाइबोर और इसकी अभिशासन प्रक्रिया के बारे में चिंताएं, हालांकि, नई नहीं हैं। 1970 और 1980 के दशक के दौरान जैसे-जैसे लाइबोर का उपयोग बढ़ा, पोल करने वाले बैंकों ने लाइबोर से जुड़ी ब्याज दरों पर यूरोडॉलर डिपॉजिट स्वीकार करना शुरू कर दिया, जिससे कम दरों की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिकूल प्रोत्साहन मिला। इन चिंताओं के मद्देनजर, ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन ने 1986 में लाइबोर की अभिशासन प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया। समय के साथ, रिपो बाजार के विकास से बेजमानती अंतरबैंक लेनदेन की मात्रा में गिरावट आई। जैसे-जैसे ये लेन-देन कम होते गए, लाइबोर की दरें लगातार संदिग्ध होती गईं और बैंकों के विशेषज्ञ निर्णय पर उतरोत्तर आश्रित होती गईं। हितों के टकराव निहित थे - पोलिंग बैंकों की संबंधित बाजारों में 'उल्लेखनीय' उपस्थिति है, लेकिन वे बड़े डेरिवेटिव और ऋण संविदा भी रखते हैं जिनकी कीमत लाइबोर दरों का उपयोग करके की जाती है।

विसंगतियां पहली बार वर्ष 2007-08 के दौरान देखी गई थीं जब इनमें पोल्ट दर वास्तविक दरों को प्रतिबिंबित नहीं करते थे जिस पर बैंक एक दूसरे को उधार देते थे। संभावना है कि बैंक लाइबोर उद्धरणों को प्रचलित क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड्स की तुलना में काफी कम बता रहे थे, जिन्हें वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में और 2008 में विभिन्न शोध पत्रों में प्रकाशित किया गया था (मोलेनकोमो, 2008; अब्रेट्स-मेट्ज़ एवं अन्य, 2008)। इससे इस तथ्य पर ध्यान गया कि बैंकों के लिए लाइबोर दरों में हेरफेर करने के लिए लिखत के रूप में प्रोत्साहन मिल रहा था, जिसके माध्यम से बैंक अपनी कथित क्रेडिट-योग्यता का संकेत देते हैं, विशेष रूप से दबाव की अवधि में या जिसके माध्यम से व्यापारिक स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकाशन के बाद, 3-महीने के यूएसडी लाइबोर दर में तत्काल बढ़ोत्तरी हुई थी (चार्ट 1)। इससे लाइबोर निर्धारण प्रक्रिया की जांच शुरू हो गई। वर्ष 2012 तक, लाइबोर निर्धारण में हेरफेर की बात पक्की हो गई थी और बैंकों को कदाचार के लिए लगभग 9 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।



इन गतिविधियों के प्रतिक्रियास्वरूप, यूके ने लाइबोर की संरचना और अभिशासन की समीक्षा की। व्हेटली समीक्षा (जैसा कि वर्ष 2011-12 में वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्टिन व्हेटली की निगरानी में की गई समीक्षा में कहा गया है) ने निष्कर्ष निकाला कि लाइबोर को एक बेंचमार्क के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर सुधार किया जाना चाहिए। इसने लाइबोर के लिए बेंचमार्क गवर्नेंस प्रक्रिया में सुधार के बारे में व्यापक सिफारिशें कीं। इसने यह भी सिफारिश की कि कुछ मुद्राओं और परिपक्वताओं में लाइबोर का प्रकाशन जिसमें व्यापार की मात्रा विशेष रूप से कम थी, को बंद कर दिया जाना चाहिए। सिफारिशों के मद्देनजर शासन प्रक्रिया में कई सुधार किए गए। विशेष रूप से, बेंचमार्क प्रशासन की जिम्मेदारी इंटरकांटीनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) को दी गई थी, बेंचमार्क प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से चुनौती देने के लिए एक निरीक्षण समिति बनाई गई थी और इसके अधीन आने वाले बैंकों में शासन सुधार किए गए थे।

इन सुधारों के बावजूद, लाइबोर प्रक्रिया की मुख्य कमी – उसका अपर्याप्त लेनदेन बरकरार था, जिस पर प्रस्तुतियाँ आधारित थीं। वर्ष 2017 में, इसे एफसीए के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड्रयू बेली द्वारा एक मुद्रा-टेनर संयोजन के

उदाहरण के साथ समझाया गया था जिसके लिए बैंकों द्वारा प्रतिदिन बेंचमार्क संदर्भ दरों को प्रकाशित किया गया था, जिनके बीच, समूचे 2016 में उस मुद्रा और अवधि में संभावित रूप से पात्र आकार के सिर्फ पंद्रह लेनदेन निष्पादित किए गए थे। इस पृष्ठभूमि में, एफसीए ने निष्कर्ष निकाला कि यदि बाजार लाइबोर पर भरोसा करना जारी रखते हैं तो लेन-देन-आधारित बेंचमार्क की यात्रा पूरी नहीं होगी। इस प्रकार एफसीए ने घोषणा की कि वह 2021 के बाद से पैनल बैंकों को लाइबोर प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

III. एक वैकल्पिक बेंचमार्क की खोज में

लाइबोर एक संदर्भ दर के रूप में कार्य करता है, जिस पर वित्तीय लिखत करार की शर्तों को और एक बेंचमार्क दर के रूप में भी स्थापित करने के लिए संविदा कर सकते हैं जो निवेश प्रतिफल के लिए एक सापेक्ष प्रदर्शन माप को दर्शाता है (एचओ और स्कीई, 2014)। विभिन्न प्रकार के ऋण और व्युत्पन्न उत्पादों में वित्तीय लिखतों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वैश्विक वित्तीय बाजारों में लाइबोर का उपयोग लगभग सर्वव्यापी रूप से किया जाता है, जिससे गैर-प्रतिद्वंद्वी खपत गुण जटिलता कम करने, मानकीकरण, बढ़ी हुई चलनिधि और कम करने के मामले में लेनदेन कीमत सार्वजनिक रूप से अच्छा हो जाता है। वित्तीय लिखत के मूल्य निर्धारण के अलावा, लाइबोर का उपयोग बड़े पैमाने पर मूल्यांकन और लेखांकन उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है।

एक वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) - जो यह सुनिश्चित करते हुए लाइबोर की वांछनीय विशेषताओं को बरकरार रखता है

कि यह नकदी बाजारों में लेनदेन पर आधारित है - कई प्रमुख विशेषताओं को पूरा करना पड़ता है; (ए) इसे मुख्य मुद्रा बाजार में ब्याज दरों का एक मजबूत और सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए जो हेरफेर के लिए आसानी से प्रभावित होने वाला न हो; (बी) इसे वित्तीय संविदाओं के लिए संदर्भ दरों की पेशकश करनी चाहिए जो मुद्रा बाजार से परे हैं; और (सी) मीयादी उधार और निधीयन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करते हैं (बीआईएस, 2019)³

वैसे क्षेत्र जहां लाइबोर घरेलू अंतर-बैंक ब्याज दर बेंचमार्क है, वहाँ नकदी बाजारों में वास्तविक लेनदेन से जुड़े वैकल्पिक बेंचमार्क की पहचान की गई है। व्यवहार में, इसके परिणामस्वरूप एआरआर अल्पावधि संविदाओं पर आधारित होते हैं - अनिवार्य रूप से एकदिवसीय रिपो बाजार, जो सबसे अधिक अर्थसुलभ होते हैं - और बेजमानती लेनदेन के बजाय जमानती होते हैं। इसके अतिरिक्त, एआरआर एक व्यापक भागीदार आधार को तैयार करने के लिए गैर-बैंक थोक प्रतिभागियों जैसे कि मुद्रा बाजार और निवेश कोष और बीमा कंपनियों को एक बोली में शामिल करने के लिए शुद्ध अंतर-बैंक बाजारों से आगे बढ़ गए हैं (सारणी 1)।

इसके अलावा, कई क्षेत्रों में जहां लाइबोर स्थानीय ब्याज दर बेंचमार्क का एक घटक बनाया गया है, वहां अन्य बेंचमार्क की पहचान भी की गई या पहचान की जा रही है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर में, मौजूदा बेंचमार्क - सिंगापुर डॉलर स्वैप ऑफर रेट (एसओआर) - अपने घटकों में से एक के रूप में लाइबोर का उपयोग करता है। इसने सिंगापुर डॉलर ओवरनाइट रेट एवरेज (एसओआरए) की पहचान की है - बिना किसी घटक के लेनदेन आधारित बेंचमार्क - जैसा कि एआरआर और कुछ

सारणी 1: कुछ बाजारों में एआरआर का संक्षिप्त विवरण

	यूएसए	यूके	ईयू	स्विट्जरलैंड	जापान
एआरआर	सेक्योर्ड ओवरनाइट इंटरबैंक रेट (एसओएफआर)	स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट (एसओएनआईए)	यूरो शॉर्ट टर्म रेट (ईएसटीआर)	स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट (एसएआरओएन)	टोकियो ओवरनाइट एवरेज रेट (टीओएनएआर)
प्रतिभूत	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
अवधि	एकदिवसीय	एकदिवसीय	एकदिवसीय	एकदिवसीय	एकदिवसीय
प्रतिपक्षकार	बैंक और गैर-बैंक	बैंक और गैर-बैंक	बैंक और गैर-बैंक	सिर्फ बैंक	बैंक और गैर-बैंक

स्रोत: बीआईएस

³ https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1903e.pdf

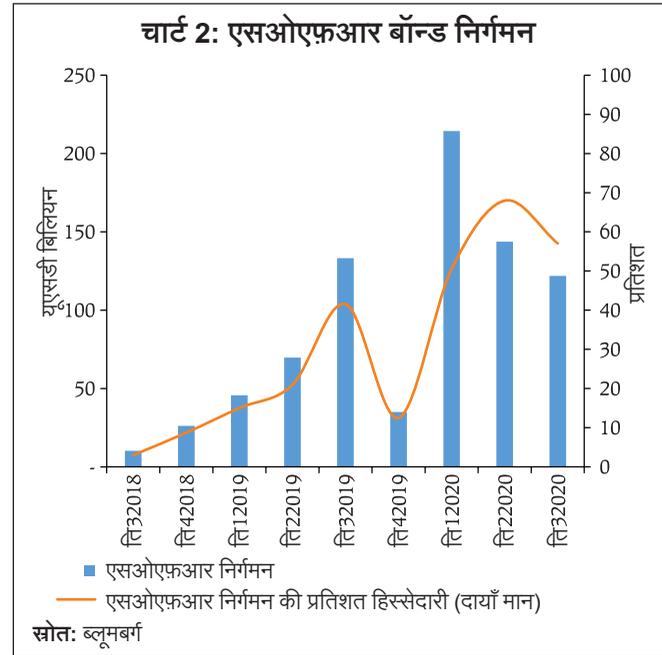
⁴ जिसे टीओएनए के नाम से भी जाना जाता है

एसओआरए आधारित लेनदेन पहले ही संविदा कर चुके हैं। थाईलैंड में, थाई बहत ब्याज दर निर्धारण (टीएचबीएफआईएक्स) लाइबोर पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र के लिए थाई ओवरनाइट रिपरचेज रेट (टीएचओआर) की पहचान एआरआर के रूप में की गई है।

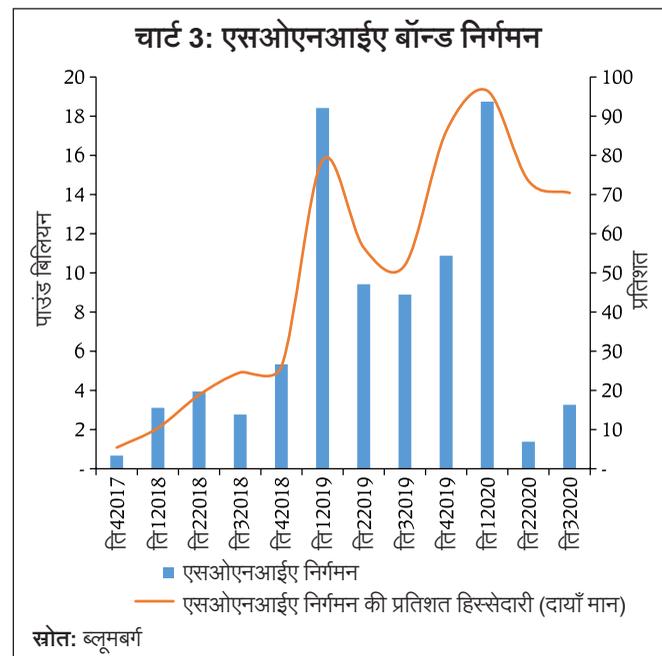
लाइबोर अंतर-बैंक दरों का एक संयोजन है जिसमें क्रेडिट जोखिम प्रीमियम, टर्म प्रीमियम और चलनिधि प्रीमियम शामिल हैं। इसके विपरीत, एआरआर एकदिवसीय बेंचमार्क दरें हैं, जिनमें एक मीयादी संरचना और क्रेडिट जोखिम घटक की कमी है। सफल होने के लिए लाइबोर से एआरआर में संक्रमण के लिए, एआरआर को नए वित्तीय संविदाओं के लिए संदर्भ दर के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए टर्म दरों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नई दरों से जुड़े अर्थसुलभ वित्तीय बाजारों का विकास महत्वपूर्ण होगा। ये दोनों पहलू काफी चुनौतियां पेश करते हैं।

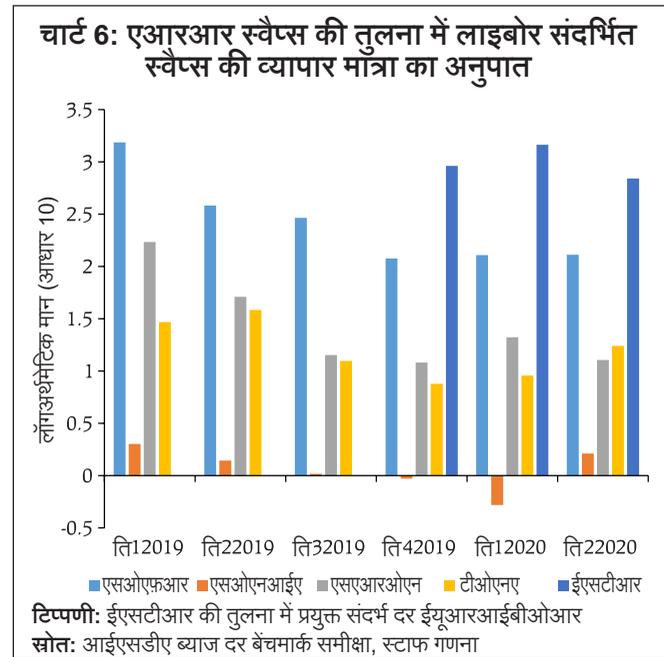
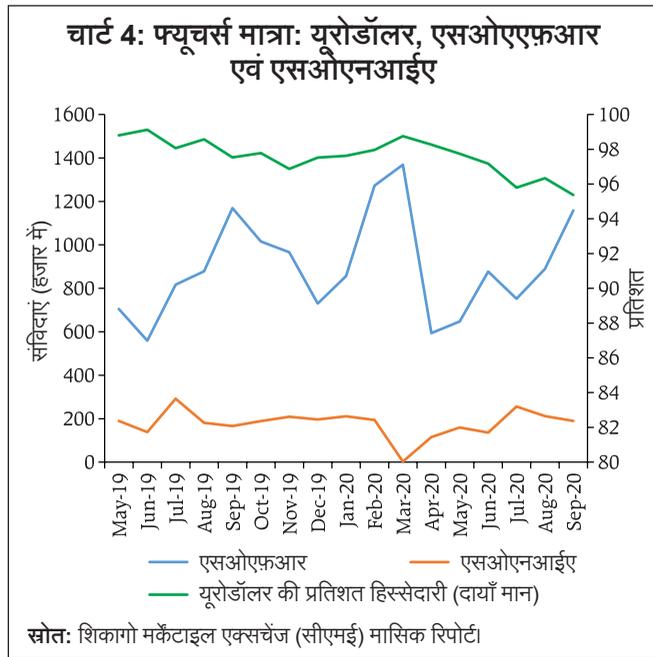
बेंचमार्क शब्द का विकास आदर्श रूप से बेंचमार्क सुधारों के समग्र जोड़ के अनुरूप वास्तविक लेनदेन पर आधारित होना चाहिए। टर्म स्ट्रक्चर्स का सबसे सरल निर्माण एकदिवसीय ब्याज दरों को कंपाउंड करना होगा, यानी, 'एरियर में कंपाउंडिंग'। हालांकि, ये टर्म संरचनाएँ प्रगामी दृष्टिकोण वाली लाइबोर के विपरीत होंगी। इसलिए, एआरआर भविष्य की ब्याज दरों या वित्तीय स्थितियों के बारे में बाजार की प्रत्याशाओं को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) सहित दुनिया भर के नीति निर्माता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एकदिवसीय एआरआर को बकाया राशि में मिला दिया जाना चाहिए और यह मानदंड बन जाना चाहिए और परिवर्तन प्रयासों को जोखिम-मुक्त दरों के अग्रेषित दिखने वाले संस्करणों के उभरने का इंतजार नहीं करना चाहिए (एफएसबी, 2019)। फिर भी, बाजार के कुछ हिस्से होंगे, जिन्हें प्रगामी अवधि के संदर्भ दरों की आवश्यकता होगी।

संविदाओं में चलनिधि का विकास, जो एआरआर को संदर्भित करता है, एक चुनौती बना हुआ है, और, कई मायनों में, मुर्गी-और-अंडा वाली समस्या है। गहन बाजार के तभी विकसित होने की संभावना है जब नए संविदा एआरआर का संदर्भ देना शुरू कर दें।



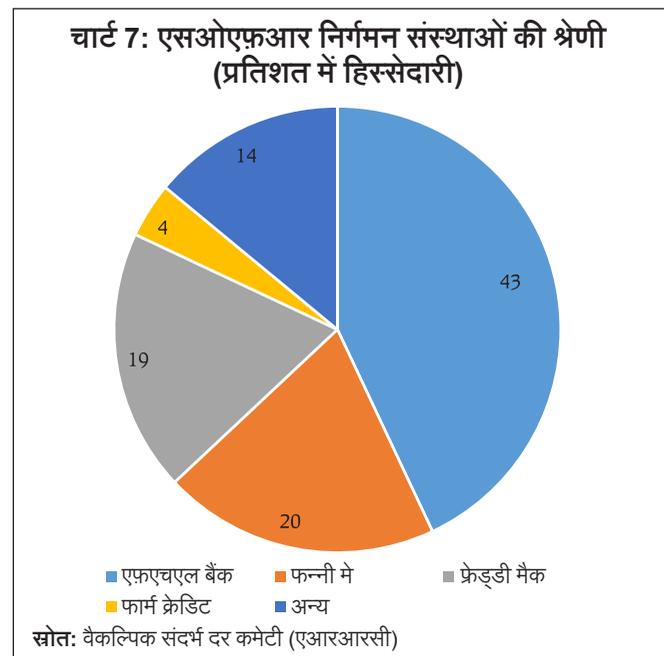
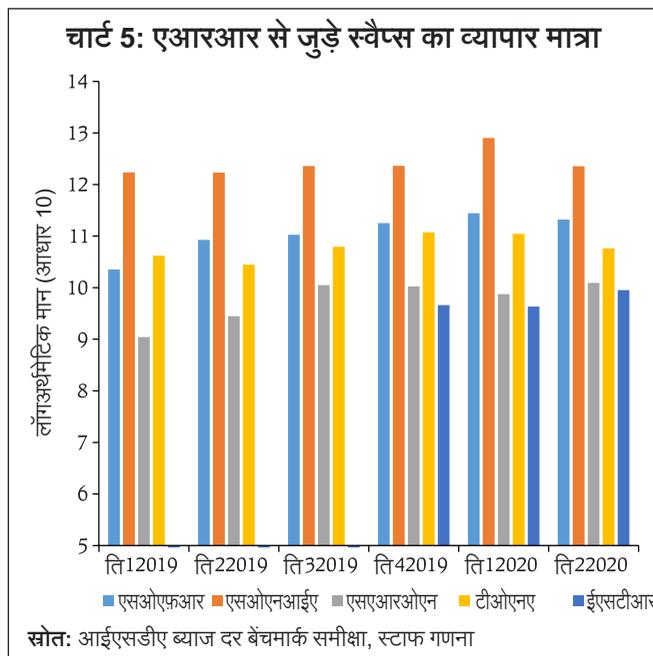
वर्तमान में, विशेष रूप से सेक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (एसओएफआर) और स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट (एसओएनआईए) से जुड़े बॉन्ड निर्गमन शुरू हो गए हैं और अब कुल फ्लोटिंग रेट बॉन्ड निर्गमन में इसकी उल्लेखनीय हिस्सेदारी है (चार्ट 2 और 3)। डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है। एसओएफआर और एसओएनआईए वायदा में ट्रेडिंग की मात्रा महीनों से बढ़ रही है। हालांकि, अभी भी कुल ब्याज दर वायदा बाजार में यूरोडॉलर वायदा की प्रमुख हीसेदारी है (चार्ट 4)।





एसओएफआर और एसओएनआईए को संदर्भित करने वाले स्वैप में ट्रेडिंग भी बढ़ रही है (चार्ट 5 और 6)। विशेष रूप से, अब एसओएनआईए को संदर्भित करने वाले स्वैप में व्यापार का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। ऋण खंड में, हालांकि, एआरआर को संदर्भित करने वाले नए ऋण संविदाएं केवल 23 ऋण संविदाओं तक सीमित हैं, जो वर्तमान में एआरआर (ऋण बाजार संघ, 2020) का संदर्भ देते हैं।

एआरआर- संदर्भित संविदाओं को अधिक चलनिधि प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर कई नियामकीय कदम उठाए जा रहे हैं। बॉन्ड संदर्भित एआरआर मुख्य रूप से अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हैं। ज्यादातर एसओएफआर संदर्भित निर्गमन फैंनी मॉई, फ्रेडी मैक और फेडरल होम लोन (एफएचएल) बैंकों जैसी संस्थाओं द्वारा हैं (चार्ट 7)। जुलाई 2020 से यूरो-मूल्यवर्गित इन्टररेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस) का मूल्य निर्धारण करने के लिए यूरोपीय शेयर बाजारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भुनाई पद्धति में



यूरो ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज (ईओएनआईए) के बजाए यूरो शॉर्ट टर्म रेट (ईएसटीआर) और अक्टूबर 2020 से यूएसडी-मूल्यवर्गित आईआरएस संविदाओं का मूल्य निर्धारण करने के लिए शिकागो मर्केटाइल एक्सचेंज (सीएमई) और लंदन क्लियरिंग हाउस (एलसीएच) द्वारा उपयोग की जाने वाली भुनाई पद्धति में फेड फंड्स रेट के बजाए एसओएफआर का उपयोग करने के निर्णय से एआरआर का संदर्भ देने वाले डेरिवेटिव्स को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। ईटीएस को संदर्भित स्वैप संविदाओं में ट्रेडिंग की मात्रा दोगुनी से अधिक है, जो कि वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 9 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही⁵ में 24.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। आगे चलकर, एआरआर-संदर्भित संविदाओं में चलनिधि बढ़ने की संभावना है क्योंकि अमेरिका और यूके में नियामक अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई समय सीमा प्रभावी हो जाएगी जिसके बाद संस्थाओं को लाइबोर का संदर्भ देने वाले संविदाओं को जारी करना बंद करना पड़ेगा। अप्रैल 2021 से, लाइबोर संदर्भित संपार्श्विकों के लिए उच्च हेयरकट्स को बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) द्वारा लागू किया जाएगा और 2021 के बाद से परिपक्व होने वाले इस तरह के संपार्श्विक स्टर्लिंग मोनेटरी फ्रेमवर्क के तहत बैंक ऑफ इंग्लैंड के परिचालन में उपयोग के लिए पात्र नहीं होंगे (बीओई, 2020)।

लाइबोर को संदर्भित बॉन्ड, ऋण और वित्तीय लिखतों की वृद्धि बही 1 जनवरी 2022 को लाइबोर के समापन के बाद भी जारी रहेगी। लाइबोर संदर्भित नई संविदाएं अभी भी हर दिन ग्रहण किए जा रहे हैं। इनमें से कई लाइबोर के समापन को भी रेखांकित करेंगे। ऐसे संविदाओं से निपटना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चुनौती है। ज्यादातर मामलों में, ऐसी कोई वापसी व्यवस्था नहीं होती है जो इस तरह की समाप्ति को पूरा करती है। इससे दो विशिष्ट मुद्दों उत्पन्न होते हैं।

सबसे पहले, संविदाओं को अलग-अलग बातचीत करके तय करना होगा और और वापसी संबंधी उपबंध को सम्मिलित करना होगा। उद्योग निकाय जैसे इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) और लोन मार्केट एसोसिएशन, हितधारकों के परामर्श से इस तरह के वापसी विकल्प विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 2020 को आईएसडीए ने फॉलबैक प्रोटोकॉल प्रकाशित किया। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि वापसी के संबंध में यथार्थ के बजाए प्रत्याशित पर सहमत होना है जिससे कि कुशल मूल्य निर्धारण और सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

व्युत्पन्न बाजारों में, आईएसडीए जैसे निकायों द्वारा कार्रवाई के कारण कमियों को अपनाने के लिए समझौते को अधिक मानकीकृत किया गया है। ऋण संविदा, जो कि आमतौर पर कस्टमाइज किए जाते हैं, सहित नगदी बाजार संविदा के मामले में चुनौतियाँ ज्यादा मुश्किल हैं जिसके कारण ऋण और अंतर्निहित व्युत्पन्न के बीच संभावित आधार जोखिम बढ़ जाता है और प्रत्येक संविदा को अलग-अलग तय करने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के कई संविदाओं में गैर-मानकीकृत विशेषताएं होती हैं, जिससे उन्हें बातचीत करके तय करने में मुश्किल हो सकती है ('टफ लीगेसी' संविदाएं)। यूके में, अन्य बातों के साथ-साथ इस तरह के संविदाओं से निपटने के लिए एक कानून प्रस्तावित किया गया है (आरएफआरडबल्यूजी, 2020)⁶। अमेरिका में भी इसी तरह के कानून की सिफारिश की गई है (एआरआरसी, 2020)।

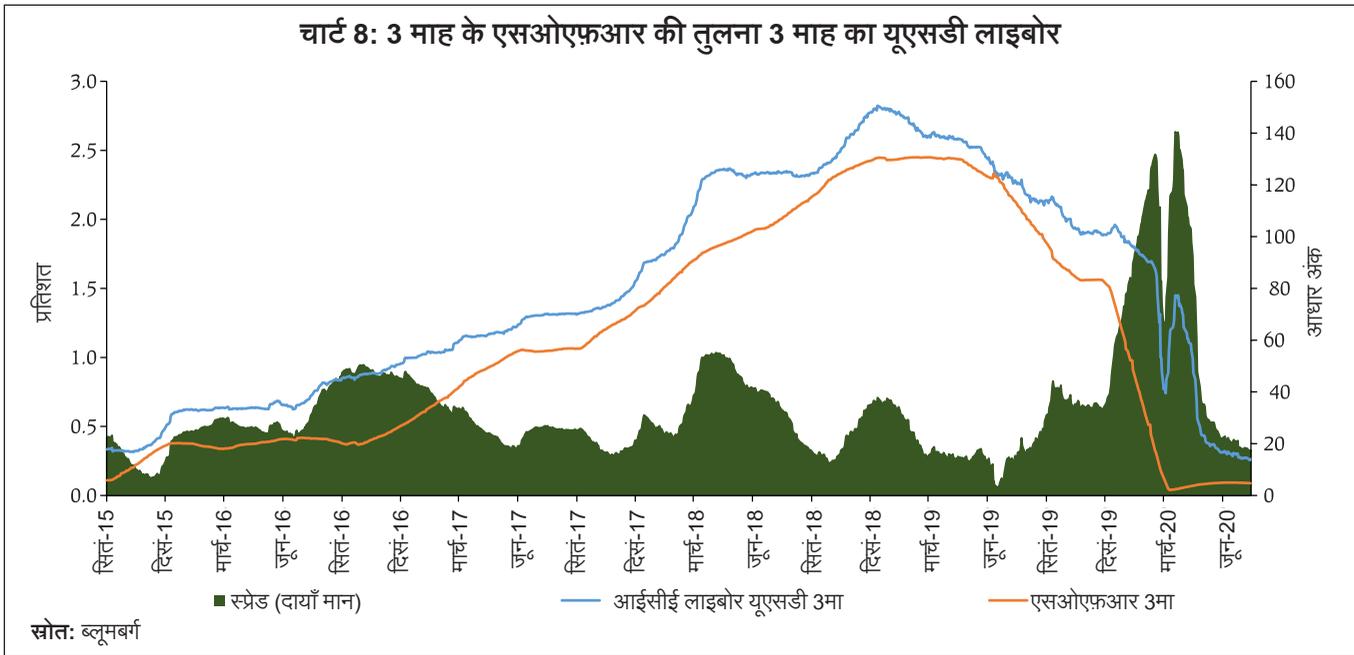
दूसरी चुनौती इस तथ्य से पैदा होती है कि एक फॉलबैक तंत्र के विकास के बावजूद, संविदाओं को पुनः तय करने के परिणामस्वरूप विजेता और हारने वाले होंगे। लाइबोर शब्द और एआरआर शब्द के बीच स्प्रेड्स में विभिन्न कारणों से भिन्नता हो सकती है। व्यापक प्रसार पर पुनर्मूल्यांकन और रूपांतरण किसी संविदा के लिए समकक्षों में से एक की तुलना में पर्याप्त भुगतान की आवश्यकता को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, मार्च 2020 में वित्तीय बाजारों में व्यवधान के कारण 3-माह वाले लाइबोर और 3 माह वाले एसओएफआर / एसओएनआईए के बीच प्रसार का विस्तार हुआ (चार्ट 8 और 9)।

उचित मूल्य में बड़े बदलाव के साथ, संशोधित संविदा को बिक्री के रूप में देखा जा सकता है और एक नए संविदा का निर्माण सम्बद्ध कर देनदारियों के लिए संभावित रूप से जोखिम भरा हो सकता है। हेज प्रभावशीलता मूल्यांकन के लिए अर्हक मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, तो संविदा के हेज पुनर्प्रयोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है। कर और लेखांकन से संबंधित मुद्दों को दूर करने की जरूरत होगी, जिसके लिए व्यापक ग्राहक जागरूकता अपेक्षित होगी। ये महत्वपूर्ण कानूनी और आचरण जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

जागरूकता पैदा करने और मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए विश्व स्तर पर हर संभव कई प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यूके, हांगकांग, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अधिकार-क्षेत्रों ने 'प्रिय सीईओ' पत्र जारी किए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय संस्थाओं से ग्राहकों को जागरूक करने के लिए, लाइबोर

⁵ आईएसडीए प्रकाशन: ट्रेडिंग टू आरएफआर रिव्यू: 2020 की तीसरी तिमाही और 30 सितंबर 2020 तक वर्ष

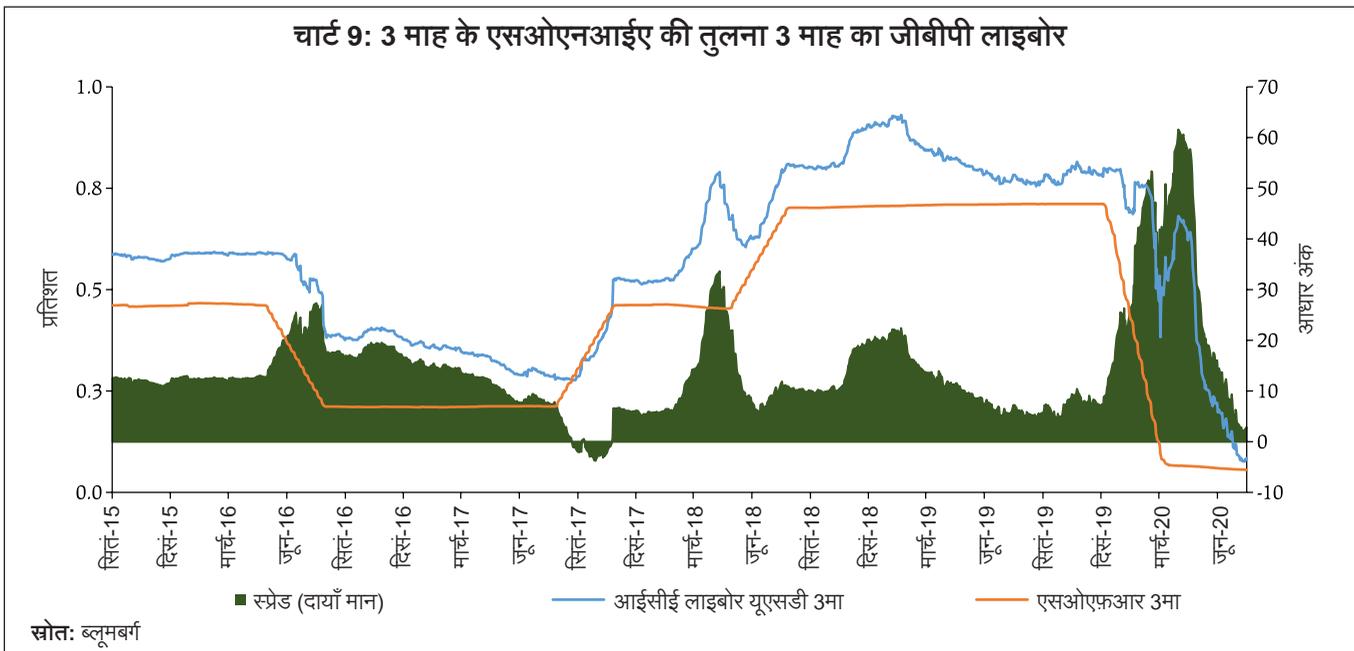
⁶ स्टर्लिंग जोखिम मुक्त संदर्भ दर संबंधी कार्य समूह



से संक्रमण के लिए आंतरिक समय सीमा निर्धारित करने, लाइबोर एक्सपोजर का आकलन करने और संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन करने का अनुरोध किया गया है। अमेरिका में कर अधिकारियों ने उन मुद्दों पर दिशा-निर्देश प्रकाशित किया है जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड ने कुछ लेखांकन पहलुओं पर दिशा-निर्देश जारी किया है जो संविदा के पुनर्निर्धारण के समय उत्पन्न हो सकते हैं।

IV. भारतीय संदर्भ

भारतीय वित्तीय प्रणाली में बेंचमार्क का उपयोग नया नहीं है। संविदाओं का कीमत निर्धारण करने और आस्तियों एवं देनदारियों का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कई प्रकार के विदेशी मुद्रा और ब्याज दर बेंचमार्क उपयोग में रही हैं। रिजर्व बैंक ऐसे बेंचमार्क की निष्ठा को बनाए रखने के लिए कदम



उठाता रहा है। लाइबोर के हेरफेर के संदर्भ में, इसने जून 2013 में वित्तीय बेंचमार्क संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्री पी विजया भास्कर) का गठन किया, ताकि भारत में वित्तीय बेंचमार्क को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों की समीक्षा की जा सके।⁷

समिति की सिफारिशों के मुताबिक, कर्ज, ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा बाजार में बेंचमार्क के लिए एक प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था, यानी, वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) की स्थापना की गयी थी। एफआईबीएल अब विभिन्न बेंचमार्क – एकदिवसीय मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (माइबोर); मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त दर (माइफोर); बाजार रिपो एकमुश्त दर (एमआरओआर); फॉरवर्ड प्रीमिया कर्व; विदेशी मुद्रा रुपया ऑप्शनस वोलेटलिटी मैट्रिक्स; और रुपया संदर्भ दर का प्रबंधन करता है। जून 2019 में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया, जिसका उद्देश्य शासन और जवाबदेही के स्वीकार्य मानकों के साथ-साथ बेंचमार्क प्रशासन प्रक्रिया में मानक की गुणवत्ता और अभिकलन पद्धति को सुनिश्चित करना है। छह वित्तीय बेंचमार्क, अर्थात्, माइबोर, माइफोर, अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया संदर्भ दर, ट्रेजरी बिल दरें, सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) का मूल्यांकन को जनवरी 2020 में महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में अधिसूचित किया गया।

भारत में, लाइबोर के एक्सपोजर लाइबोर से संबद्ध ऋण संविदाओं (जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (ईसीबी)); एफसीएनआर (बी) लाइबोर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दरों वाली जमाराशियाँ; और लाइबोर या लाइबोर पर आधारित एक घरेलू बेंचमार्क माइफोर से जुड़े डेरिवेटिव से उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक अनुमान से पता चलता है कि ईसीबी/एफसीसीबी के रूप में लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण संविदाएं और 281 बिलियन अमेरिकी डॉलर की व्युत्पन्न संविदाएं वर्ष 2021 के बाद समाप्त हो जाएंगी (सारणी 2)। हालांकि, ये आंकड़े स्थिर नहीं हैं, क्योंकि लाइबोर के नए संविदाओं पर हस्ताक्षर किया जाना जारी है।

⁷ <https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=761>

सारणी 2: भारत में लाइबोर-लिंकड एक्सपोजर

वित्तीय संविदा	एक्सपोजर (यूएसडी बिलियन)
बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (ईसीबी)*	74
एफसीएनआर (बी) जमा*	24
क्रॉस करेंसी स्वैप ⁸	83
एफसीवाई ब्याज दर स्वैप ⁸	260
माइफोर ब्याज दर स्वैप ⁸	91

* 31 मार्च 2020 तक; \$ 31 अगस्त 2020 के अनुसार।

* ईसीबी डेटा 31 मार्च 2020 तक का है। एफसीएनआर (बी) जमा से संबंधित डेटा बाह्य ऋण संबंधी नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट से लिया गया है और इसमें फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट (31,2020) दोनों शामिल हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का बाह्य ऋण: स्थिति रिपोर्ट 2019-20 (आर्थिक कार्य विभाग), विलयिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरबीआई स्टाफ गणना

इसके अलावा, लाइबोर से जुड़े सरकारी एक्सपोजर भी हैं। इनमें सरकार द्वारा बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों और अन्य देशों को दी जाने वाली ऋण-व्यवस्था से प्राप्त लाइबोर-संदर्भित ऋण शामिल हैं। बड़ी संख्या में व्यापार संविदाएं भी लाइबोर का संदर्भ देती हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश अल्पावधिक हैं और मौजूदा संविदाएं लाइबोर के समापन के बाद जारी नहीं रह सकती हैं।

दिसंबर 2021 के अंत में लाइबोर के समापन की तैयारी के लिए भारत और माइलस्टोन्स के लिए चुनौतियां अन्य देशों द्वारा सामना किए जाने वाले लोगों के समान हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए, जो कुछ अर्थों में, 'लाइबोर-ग्राहक' हैं, अर्थात्, वे प्रमुख देशों की लाइबोर ब्याज दरों पर भरोसा करते हैं।

भारत में, माइफोर - जिसके पास अपने घटकों में से एक के रूप में लाइबोर है - ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) बाजारों में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। वैश्विक एआरआर पर आधारित एक वैकल्पिक बेंचमार्क को एमआईएफओआर के स्थान पर विकसित करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड आईआरएस संविदाओं के लिए गारंटी निपटान प्रदान करता है जो एमआईएफओआर का संदर्भ देता है। वैकल्पिक बेंचमार्क प्रदान करने के लिए समाशोधन और निपटान व्यवस्था को भी संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

मौजूदा ऋण / व्युत्पन्न संविदाओं की संवीक्षा से पता चलता है कि लाइबोर की समाप्ति के लिए संविदात्मक फॉलबैक उपबंध मौजूदा संविदाओं में उपलब्ध नहीं हैं, जो वर्ष 2021 के बाद आगे जारी रहेगा। घरेलू बाजारों के लिए फॉलबैक उपबंध, लेकिन वैश्विक प्रथाओं पर आधारित पर होगा, इसलिए इसे विकसित करने की जरूरत है। वर्ष 2021 के बाद से लाइबोर के बंद हो जाने

के बाद इन सविदाओं को देश विशिष्ट एआरआर के विकल्प के रूप में अपनाना पड़ सकता है।

जैसा-जैसे हम संक्रमण की तारीख के करीब आएं, सभी सविदाएँ जो लाइबोर समाप्ति के बाद जारी रहेंगी, उन्हें फिर से तय और बदलने की जरूरत होगी। इसके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार सहभागियों के सभी वर्गों में पर्याप्त हितधारक जागरूकता पैदा करनी होगी। संबंधित लेखांकन और कर संबंधी मुद्दों को भी हल करने की आवश्यकता होगी। मौजूदा विनियमों, जो संदर्भ लाइबोर को एआरआर को संदर्भित करने वाले सविदाओं के लिए प्रदान करने हेतु संशोधित करने की आवश्यकता होगी। जैसा कि वैश्विक स्तर पर अधिकांश देशों में योजना बनाई जा रही है, एक निर्दिष्ट तारीख को भी अधिसूचित करने की जरूरत है जिसके बाद लाइबोर का उपयोग करके कोई नया सविदा नहीं किया जा सकता है। बेशक, यह काफी हद तक एआरआर से जुड़े नगदी ऋण और व्युत्पन्न बाजारों के विकास और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा घोषित निर्दिष्ट तारीख पर निर्भर करेगा।

माइफोर बेंचमार्क एक सिंथेटिक बेंचमार्क है, इसके घटकों के रूप में यूएसडी लाइबोर और यूएसडी आईएनआर फॉरवर्ड प्रीमियम के साथ एक समग्र दर है। अनिवार्य रूप से, माइफोर अमेरिकी डॉलर में उधार लेने की लागत को दर्शाता है और आईएनआर के लिए उसी की अदला-बदली करता है, इस प्रकार घरेलू रूप से ब्याज दर को दर्शाता है। माइफोर को संदर्भित आईआरएस सविदाओं का उपयोग बैंकों द्वारा ईसीबी उधारकर्ताओं को दी जाने वाली मुद्रा स्वैप की कीमत निर्धारित करने और उसे कवर करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में, देश में बकाया आईआरएस सविदाओं के लगभग पांचवें हिस्से को माइफोर के लिए संदर्भित किया गया है। लाइबोर के समापन के साथ ही माइफोर का विकल्प भी विकसित करना होगा। लाइबोर के स्थान पर यूएसडी आईएनआर फॉरवर्ड प्रीमियम; यूएसडीआईएनआर नगद / टॉम स्वैप दर (दोनों बकाया राशि में मिश्रित) के साथ दैनिक एसओएफआर; माइबोर (मांग मुद्रा बाजार लेनदेन पर आधारित एक बेजमानती दैनिक बेंचमार्क) और एमआरओआर (रिपो लेनदेन पर आधारित एक जमानती दैनिक बेंचमार्क) या ट्रेजरी बिल दर के साथ दैनिक एसओएफआर (बकाया राशि में मिश्रित) पर आधारित कई वैकल्पिक बेंचमार्क संभव हैं।

वैकल्पिक बेंचमार्क में से हरेक के अपने फायदे और समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए, फॉरवर्ड प्रीमियम के साथ एसओएफआर का उपयोग, माइफोर का लगभग नकल होगा, लेकिन इसमें एक प्रगामी-दृष्टिकोण और एक विमुखी दृष्टिकोण घटक का उपयोग

शामिल होगा। एसओएफआर और यूएसडी आईएनआर नगद / टॉम स्वैप दर का उपयोग, जो दोनों बकाया राशि में कंपाउंड किए गए हैं, इस मुद्दे से निपटेंगे लेकिन नकदी / टॉम स्वैप दरों पर आधारित बेंचमार्क के फॉरवर्ड प्रीमियम पर आधारित किसी बेंचमार्क की तुलना में अधिक अस्थिर होने की संभावना है। एमआरओआर एक बेंचमार्क है जो बैंक और गैर-बैंक प्रतिभागियों दोनों को शामिल करते हुए एक नगदी बाजार में एकदिवसीय लेनदेन पर आधारित है और इसलिए अंतरराष्ट्रीय एआरआर की विशेषताओं को बारीकी से साझा करता है। वर्तमान में, हालांकि, एमआरओआर का संदर्भ देने वाले आईआरएस सविदाएं प्रचलित नहीं हैं। माइबोर अल्पनगदी अंतर-बैंक मांग बाजार पर आधारित है लेकिन माइबोर - आधारित स्वैप देश में थोक बकाया आईआरएस सविदाओं को बताता है। किसी भी स्थिति में, माइबोर, एमआरओआर और टी-बिल दर घरेलू दरें हैं और एआरआर के रूप में उनके उपयोग से परस्परिक मुद्रा आधार स्वैप के लिए बाजार के विकास की आवश्यकता पड़ेगी। एआरआर के लिए सावधि संरचना प्राप्त करने से जुसंबद्ध मुद्दों, जैसा कि वैश्विक बाजारों में है, को भी हल करने की आवश्यकता होगी।

जैसा कि यह वैश्विक रूप से मामला बनता है, लाइबोर को संदर्भित करने वाली वित्तीय सविदाएं - दोनों ऋण और व्युत्पन्न सविदा - जो कि समापन के बाद भी अधिक समय तक टिकी रहेंगी, को उचित फॉलबैक भाषा के सम्मिलन को सुनिश्चित करने के लिए फिर से तय करने की आवश्यकता होगी। ग्राहक जागरूकता और कानूनी, कराधान और लेखा संबंधी मसलों को हल करना भी महत्वपूर्ण होगा। माइफोर से जुड़े आईआरएस सविदाओं के लिए परिवर्तन व्यवस्था देश के लिए अद्वितीय होगी, बल्कि इसे हैंडल करना भी अपेक्षाकृत कम मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस तरह के सविदाओं का केवल अंतर-बैंक बाजार में कारोबार किया जाता है।

इन मुद्दों के अलावा संक्रमण के लिए बैंकिंग की तैयारी और व्यापक वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता है। परिवर्तन से प्रभावित होने वाली बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए फिर से योजना बनाने की आवश्यकता होगी। लाइबोर का उपयोग करने वाले सभी आईटी सिस्टम को बदलना होगा। भारत में वित्तीय संस्थानों के साथ अक्सर आंतरिक और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के मिश्रित सेवाओं का उपयोग करके आईटी परिवर्तन आसानी से दूर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विभिन्न स्तरों पर कर्मियों को जागरूक करने और यहां तक कि उन्हें प्रशिक्षित करने की जरूरत पड़ेगी।

V. निष्कर्ष

रिज़र्व बैंक लाइबोर संक्रमण से संबंधित वैश्विक गतिविधियों में भाग ले रहा है और उसकी निगरानी कर रहा है और उसने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को प्रासंगिक मुद्दों पर परामर्श करने का काम सौंपा है। तब से आईबीए ने (i) लाइबोर संक्रमण व्यवस्था, (ii) दर एवं कार्य-पद्धति और (iii) बाजार सहभागियों तक पहुँच, पर तीन वर्कस्ट्रीम का गठन किया है। आईबीए ने अपने सदस्य बैंकों के बीच एक मार्गदर्शन नोट भी प्रसारित किया है ताकि वे विभिन्न मानदंडों, अर्थात्, लेखांकन, कर, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित पहलुओं पर लाइबोर संक्रमण के लिए अपनी तैयारियों का आकलन कर सकें। दरें और कार्य-पद्धति वर्कस्ट्रीम माइफोर के लिए एक स्वीकार्य विकल्प विकसित कर रही है, जबकि आउटरीच वर्कस्ट्रीम आने वाली चुनौती के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वेबिनार और सम्मेलनों के माध्यम से हितधारकों तक पहुंच रही है।

अगस्त 2020 में, रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 'प्रिय सीईओ' पत्र जारी किया, जिसमें बैंकों को लाइबोर समाप्ति के लिए तैयार रहने की जरूरत के बारे में कहा गया था। बैंकों को लाइबोर संदर्भ में होने वाले एक्सपोजर के साथ-साथ उन एक्सपोजर की पहचान करने जिसकी समाप्ति की तारीख से आगे भी जारी रहने की संभावना है; संक्रमण के लिए तैयारियों का आकलन करने और संबंधित जोखिमों की पहचान करने; और इस विषय पर ग्राहक जागरूकता सुनिश्चित करने को कहा गया था।

लाइबोर से अलग एक नए बेंचमार्क की ओर संक्रमण चुनौतियों से भरा होगा। प्रत्येक हितधारक - वित्तीय क्षेत्र; विनियामकों; कर, कानूनी और लेखांकन प्रणालियों; और वास्तविक क्षेत्र के प्रतिभागियों को भूमिका निभाने की जरूरत है।

प्रमुख देशों में वैकल्पिक संदर्भ दरों की पहचान की गई है, लेकिन इन दरों में नगदी बाजारों का विकास - निर्विघ्न संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य शर्त - शुरुआती चरण में है। एफएसबी ने लाइबोर के लिए एक वैश्विक संक्रमण रोडमैप तैयार किया है, जिसमें जोर दिया गया है कि कंपनियां अपने लाइबोर एक्सपोजर का आकलन करने की स्थिति में हों और फर्मों को संक्रमण के लिए आईएसडीए प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। एफएसबी ने यह भी सुझाव दिया है कि वर्ष 2020 के अंत तक, फर्म को अपने ग्राहकों को गैर-लाइबोर से संबद्ध ऋण की पेशकश करने की स्थिति में होनी चाहिए। हालांकि, इस रोडमैप को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों से महत्वपूर्ण प्रयासों की अपेक्षा है।

वित्तीय प्रणाली में अंतःस्थापित बेंचमार्क के लिए संक्रमण व्यवस्था में बाजार निकायों, विनियामकों, सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं में कई हितधारक शामिल हैं। लाइबोर से निर्बाध संक्रमण को सक्षम करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होगा।

संदर्भ

Bailey, A. (2017), "The Future of LIBOR", Speech delivered by Mr. Andrew Bailey, former Chief Executive of the FCA, at Bloomberg London, July 27, 2017.

Abrantes-Metz, R M., Kraten, M., Metz, A., and Seow, G. (2008), "LIBOR Manipulation?", *Mimeo*, Accessed from SSRN 1201389.

Mollenkamp, C. (2008, April 16), "Bankers cast doubt on key rate amid crisis", *The Wall Street Journal*, <https://www.wsj.com/articles/SB120831164167818299>.

Hou, D and Skeie, D. (2014), "LIBOR Origins, Economics, Crisis, Scandal, and Reform", *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports*, no. 667.

HM Treasury (2012), "The Wheatley Review of Libor: Final Report", September.

Schrimpf, A and Sushko, V. (2019), "Beyond LIBOR: a primer on the new benchmark rates", *BIS Quarterly Review*, March.

FSB (2019), "Reforming major interest rate benchmarks: Progress Report", December.

BOE (2020), "The Bank's risk management approach to collateral referencing LIBOR for use in the Sterling Monetary Framework – Market Notice", May.

RFRWG (2020), "Paper on the identification of Tough Legacy issues", May.

ARRC (2020), "Proposed Legislative Solution to Minimize Legal Uncertainty and Adverse Economic Impact Associated with LIBOR Transition", July.

RBI (2014), "Report of the Committee on Financial Benchmarks", February.

FSB (2020), "Global Transition Roadmap for LIBOR", October.

फिनटेक: रचनात्मक बदलाव की ताकत*

फिनटेक में वह ताकत है कि यह वित्तीय परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव ला सकती है, उपभोक्ताओं को अत्यंत प्रतिस्पर्धी दरों पर और अधिक विविधता से परिपूर्ण वित्तीय उत्पाद दे सकती है, और वित्तीय संस्थानों को अधिक कार्यक्षम बना सकती है। फिनटेक द्वारा लाए गए तीव्र और रूपांतरकारी बदलावों की निगरानी आवश्यक है, इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है ताकि समाज और विनियामक दोनों प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता के क्षेत्र में अंतर्निहित सतत परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। यह लेख इस क्षेत्र की सारगर्भित समीक्षा करता है जिसमें पूरी दुनिया और भारत दोनों संदर्भों में इसके विकास, इसकी विशेषताओं और इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार किया गया है। फिनटेक के माध्यम से स्थायी व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि वह डिजिटल आधार पर बंटे समाज के बीच की खाई को पाट सके और सभी ग्राहकों तक इसकी न्यायसंगत और व्यापक पहुंच हो।

परिचय

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आया है, जिसका श्रेय वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्मों को जाता है जो 'फिनटेक' के रूप में जानी जाती हैं। रचनात्मक उथल-पुथल लाने और बैंकिंग को सुविधाजनक बनाने में, 'फिनटेक' ने विभिन्न माध्यमों से आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अपना योगदान दिया है जिनमें लागत अनुकूलन, बेहतर ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। बैंकिंग से जुड़े मुख्य कार्यों जैसे भुगतान निपटान, परिपक्वता अवधि में परिवर्तन, जोखिम बंटवारा और पूंजी आबंटन को अलग-अलग कर पाना यदि संभव हो सका है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका फिनटेक की है (कार्नी, 2019)। सूचना और दूरसंचार (आईटी) क्रांति को आर्थिक संवृद्धि को गति देने वाली पांचवीं प्रौद्योगिकीय

* यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में कार्यरत राजस सरॉय, रमेश कुमार गुप्ता और शरत ढल द्वारा तैयार किया गया है। लेखकगण श्रीमती रेखा मिश्र और डॉ. महुआ रॉय से प्राप्त बहुमूल्य टिप्पणियों और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभारी हैं। इसमें व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को दर्शाते हों।

¹ परेज़ (2002) द्वारा परिभाषित पांच प्रौद्योगिकीय क्रांतियां हैं - औद्योगिक क्रांति, भाप और रेल युग, इस्पात युग, विद्युत और भारी इंजीनियरिंग युग, तेल, ऑटोमोबाइल और व्यापक उत्पादन युग और सूचना एवं संचार युग हैं।

क्रांति माना जाता है¹ और फिनटेक इस रचनात्मक बदलाव के केंद्र में है (हेंड्रिक्स और अन्य, 2018)। फिनटेक के उपयोग का दायरा भी बढ़ा है और यह क्रिप्टो आस्तियों से आगे बढ़ते हुए भुगतान, बीमा, स्टॉक, बॉन्ड, पीयर टु पीयर लेंडिंग, रोबो-एडवाइजर्स, रेगटेक और सुपटेक तक पहुंच गया है।

भारत में, बड़े बैंकों, आला बैंकों सहित मँझोले आकार के बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के साथ-ही-साथ फिनटेक और डिजिटल क्षेत्र भारतीय वित्तीय प्रणाली के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं (दास, 2020)। इस क्षेत्र में वह क्षमता है जो वित्तीय परिदृश्य में मूलभूत बदलाव ला सकती है जिससे उपभोक्ता के पास प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विकल्पों की भरमार होगी और वित्तीय संस्थान कम लागत पर सेवाएं देते हुए अपनी दक्षता में सुधार करेंगे। भारत सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजार के रूप में उभरा है और यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है (मनकोटिया, 2020)। आज, हम पैसे भेजने या प्राप्त करने, बिलों का भुगतान करने, सामानों और सेवाओं की खरीद, बीमा खरीदने, शेयर बाजारों में व्यापार करने, बैंक खाते खोलने और स्मार्टफोन का उपयोग करके ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋणों के लिए आवेदन करने जैसी जटिल वित्तीय प्रक्रियाओं को भौतिक रूप से किसी बैंक कर्मचारी के संपर्क में आए बिना ही अंजाम दे लेते हैं। भारत का डिजिटल भुगतान बाजार \$1 ट्रिलियन का है (पीआईबी, 2018)। यहाँ वर्ष 2019-20 के दौरान 3,435 करोड़ डिजिटल भुगतान दर्ज किए गए (अनुलग्नक 1)।

फिनटेक द्वारा वित्तीय सेवाओं में लायी गयी रोमांचक, तीव्र और क्रांतिकारी परिवर्तनों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता के क्षेत्र में अंतर्निहित सतत परिवर्तनों के साथ समाज और विनियामक दोनों कदम से कदम मिलाकर चल सकें। विनियामकों को रचनात्मक और अत्यंत सक्रियता वाला नजरिया रखना होगा और तकनीक की अच्छी जानकारी भी। इसके अलावा, उन्हें अपना ध्यान संस्थाओं से हटाकर उनके क्रियाकलापों पर केंद्रित करना होगा और साथ ही, उन्हें उनकी सुदृढ़ता के आकलन में तथा कलन गणित में महारत हासिल करनी होगी जिसे कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन (लैगार्ड, 2017)। इस प्रकार, नीति निर्माण और विनियमन उद्देश्यों के लिए उपयोगी चर्चा और समझ विकसित करने के उद्देश्य से यह लेख वित्तीय प्रौद्योगिकियों (फिनटेक) की एक सारगर्भित समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिसमें उनके विकास, उनकी विशेषताओं और उनके पीछे निहित प्रेरक कारकों पर प्रकाश डाला गया है।

हमने अपने मूल्यांकन में फिनटेक के भविष्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर गहन चिंतन किया है, जैसे कि डिजिटल स्वच्छता की स्थिति, डेटा का उपयोग और उसकी गोपनीयता। आगे आलेख को पांच भागों में बांटा गया है: भाग II में वैश्विक संदर्भ में फिनटेक क्रांति, जिसमें इसके इतिहास, इसके विकास और इसे अपनाए जाने पर चिंतन किया गया है; भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र, इसे सशक्त बनाने वाले कारकों, विविधता, निधीयन और बैंकों के साथ सहयोग पर चर्चा भाग III में की गयी है; भाग IV में इनके भावी विकास के मार्ग में चुनौतियों का उल्लेख है तथा भाग V में आगे के सफर की परिकल्पना प्रस्तुत है।

II. फिनटेक क्रांति: वैश्विक संदर्भ

फिनटेक की परिभाषा

फिनटेक की परिभाषा पर कोई आम सहमति नहीं है, तथापि इसे सामान्य तौर पर एक उद्योग के रूप में वर्णित किया जाता है जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय प्रणालियों और वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी को अधिक सक्षम बनाता है। यह "प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय नवोन्मेष है, जिसके परिणामस्वरूप नये कारोबारी मॉडल, अनुप्रयोग, प्रक्रियाएं और उत्पाद अस्तित्व में आते हैं और जिसका अनुषंगी प्रभाव यह होता है कि यह वित्तीय बाजारों और संस्थानों तथा वित्तीय सेवाओं के प्रावधान पर अत्यधिक प्रभाव डालती है (एफएसबी, 2019)"। फिनटेक "स्टार्ट-अप्स और अन्य कंपनियां हैं जो प्रौद्योगिकी (सारणी 1) का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत किए जाने वाले मूलभूत कार्यों का संचालन करती हैं और ऐसा करते हुए वे उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले संग्रहण, बचत, उधार, निवेश, भुगतान और अपने धन को सुरक्षित रखने के उनके तरीकों को प्रभावित करती हैं (मैकिंसी, 2016)।

आज की दुनिया ऐप-केंद्रित होती जा रही है और अब ग्राहक इस बात में उतनी रुचि नहीं लेते कि उन्हें एक ही सेवाप्रदाता से सारी सेवाएं प्राप्त हों बल्कि उनकी रुचि इस बात में अधिक होती है कि उन्हें सेवाएं बिना किसी बाधा के मिलें। फिनटेक इस गुणात्मक प्रत्याशा को साकार कर रही हैं और इनके आने से बहुत सारे पारंपरिक वित्तीय उत्पाद अब 'बाजार से बाहर' होना प्रारंभ हो गए हैं (बासोल और पटेल, 2018)। साथ ही साथ, फिनटेक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की पेशकश कई अन्य गैर-वित्तीय सेवाओं के साथ मिलाकर की जाने लगी है और ऐसा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से किया जा रहा है (बैंक ऑफ जापान, 2018)। उदाहरण के लिए, टैक्सी एग्रीगेटर्स राइड शेयरिंग के साथ-साथ गंतव्य पर पहुंचते ही तत्काल किराया भुगतान को भी संभव बनाते हैं।

फिनटेक: इतिहास और विकास

प्रौद्योगिकी-प्रेरित वित्तीय नवोन्मेष का एक लंबा इतिहास है। 1950 के दशक में, पहली बार क्रेडिट कार्ड का प्रयोग हुआ और इसके बाद 1960 के दशक में ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) आया, 1970 और 1980 के दशक में क्रमशः इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग और बैंकों में नए डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम की शुरुआत हुई तथा 1990 के दशक में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन दलाली का प्रारंभ हुआ (बासोल और पटेल, 2018)। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो ऑनलाइन क्रांति आयी, उसने इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ दिया और ई-कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग को संभव बनाया तथा पेपाल जैसे ऑनलाइन भुगतान प्लेटफार्मों की शुरुआत हो सकी। अगला दशक स्मार्ट प्रौद्योगिकी के उद्भव का साक्ष्य बना। स्मार्टफोन ने मानव हथेलियों में मौजूद एक शक्तिशाली कंप्यूटर का रूप ग्रहण कर लिया और ऐप-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर

सारणी 1: फिनटेक्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख क्षमतावर्धक प्रौद्योगिकियाँ

प्रौद्योगिकी	ब्योरा
एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस)	एपीआई के अंतर्गत नियमों और विनिर्देशों के एक पूरे सेट को शामिल करते हैं जिनका उपयोग करके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। उनसे मौजूदा अनुप्रयोगों के अलावा अन्य अनुप्रयोग तैयार करने की सहूलियत भी मिलती है।
क्लाउड कम्प्यूटिंग	कंप्यूटिंग क्षमता की सीमा और अनुकूलन-क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोसेसर को होस्ट करने का ऑनलाइन नेटवर्क, इससे लागत कम की जा सकती है।
बायोमीट्रिक्स	विशिष्ट और मापने योग्य मानवीय विशेषताओं का अध्ययन, जिसका उपयोग व्यक्तियों को वर्गीकृत करने और उनकी पहचान के लिए किया जा सकता है।
डीएलटी (वितरित लेजर तकनीक)	परिसंपत्तियों के लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल प्रणाली जिसमें एक ही समय में कई स्थानों पर ब्योरा दर्ज किया जाता है।
बिग डेटा	संरचित या असंरचित डेटा की बहुत बड़ी मात्रा जिसे विभिन्न डिजिटल टूल्स और सूचना प्रणालियों द्वारा तैयार किया जा सके, उसका विश्लेषण और उपयोग किया जा सके।
एआई (कृत्रिम बुद्धि) और एमएल (मशीनी अधिगम)	आईटी प्रणालियाँ जो ऐसे कार्य कर सकती हैं जिन्हें करने के लिए अन्यथा मानवीय क्षमताओं की आवश्यकता होती है। एमएल के तहत कम्प्यूटरों को मानव हस्तक्षेप के बिना डेटा से सीखने की क्षमता से लैस बनाया जाता है।

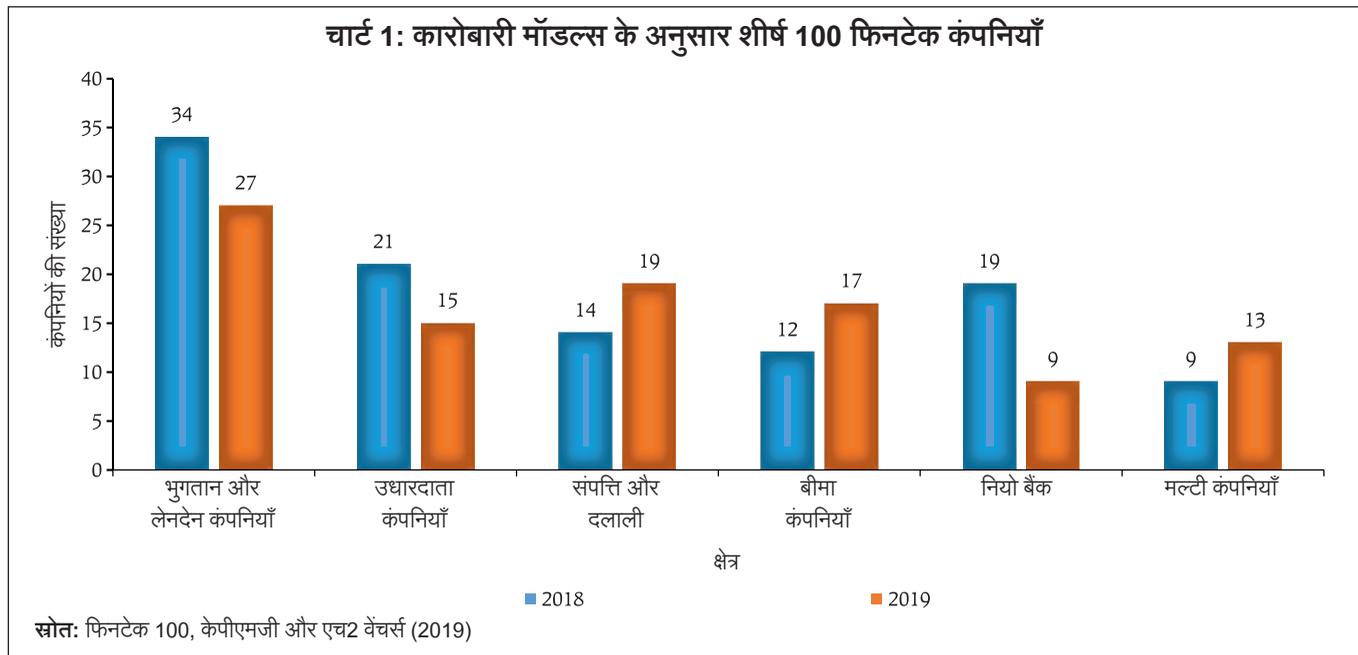
बढ़ने से सेवाओं में नवाचार, विविधता और साझेदारी को प्रोत्साहन मिला। बिटकॉइन के रूप में एक और महत्वपूर्ण नवोन्मेष 2009 में देखने को मिला। वर्तमान दशक 'रोबोट के उदय' को समर्पित है, जहां बड़े और अपारंपरिक डेटासेट के उद्भव के कारण एआई को सटीक भविष्यवाणियां करने और बैंकिंग को व्यक्तिकेंद्रित करने में सक्षम बनाया जा सका है (किंग, 2019)।

इस नए 'फिनटेक क्षेत्र ने अपने आधुनिक अवतार में जीएफसी के बाद गति पकड़ी क्योंकि फिनटेक उद्यमियों ने महसूस किया कि बैंकिंग सेवाओं को पारदर्शी, सुविधाजनक और किफायती बनाने की आवश्यकता है (हेंड्रिक्स और अन्य, 2018)। जीएफसी के बाद, बैंकों द्वारा प्रति आम जनता की धारणा खराब हो गई थी, क्योंकि बैंकों ने अपने उपभोक्ताओं के हितों की समुचित रक्षा की व्यवस्था किए बिना उनकी बचत को सबप्राइम उधार के लिए इस्तेमाल किया गया था। वित्तीय क्षेत्र से जुड़े बहुत से व्यवसायियों की नौकरियां चली गयीं या उनकी तनखाह कम को गयी जिससे फिनटेक जैसे साहसिक नवाचारों को प्रेरणा मिली (बकले और अन्य, 2016)। इसके अलावा, जीएफसी के बाद परंपरागत बैंकिंग के विनियमन को अधिक सख्त बनाए जाने की पहल से भी फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा मिला (कोर्टिना और अन्य, 2018)।

वर्तमान में, फिनटेक विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न रूपों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं (चार्ट 1)। शीर्ष 100 फिनटेक में, भुगतान करने वाली और उधारदाता कंपनियों का स्थान अब धन और दलाली, बीमा और बहु-क्षेत्र कंपनियाँ ले रही हैं² (केपीएमजी, 2019)।

फिनटेक को अपनाने हेतु माँग पक्ष का दबाव

वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण की पृष्ठभूमि में, वित्तीय सेवाओं के उपयोगकर्ताओं की बदलती जीवन शैली के अनुरूप ही उनकी जरूरतें भी दिन-ब-दिन अधिक विविधतापूर्ण और परिष्कृत होती गयी हैं। ऐसे क्षेत्रों में फिनटेक को अपनाने की दर अधिक देखी गयी है जहाँ लोगों की वित्तीय सेवाओं से जुड़ी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वित्तपोषण के परंपरागत तरीकों से प्रतिस्पर्धा कम है, समष्टि आर्थिक स्थितियाँ अनुकूल हैं, विनियमन निभावकारी है और जनसांख्यिकी अनुकूल है (फ्रॉस्ट, 2020)। 'ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स, 2019' के अनुसार, वैश्विक स्तर पर फिनटेक सेवाओं को अपनाने की दर में प्रगति हुई है जो 2015 में 16 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 33 प्रतिशत और 2019 में 64 प्रतिशत हो गयी है। इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं



² नियो-बैंक अपने ग्राहकों के साथ मुख्य रूप से या एकमात्र रूप से डिजिटल माध्यम से जुड़ते हैं और वे पारंपरिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता संगठनों के उत्पादों, उनके उपयोगकर्ताओं के अनुभव या उनके कारोबारी मॉडलों के समक्ष चुनौती पेश करते हैं; मल्टी-कंपनियां वे फिनटेक हैं जो ग्राहकों को विविध प्रकार के वित्तीय सेवा उत्पाद बड़ी संख्या में उपलब्ध कराती हैं।

के बावजूद, परंपरागत क्षेत्र के मुकाबले लोग फिनटेक को तरजीह देते हैं क्योंकि इसमें शुल्क कम है और आसानी से खाते खोले जा सकते हैं (ईवाई, 2019)।

फिनटेक को आपूर्ति-पक्ष का सहारा

पिछले एक दशक में फिनटेक की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए कई स्टार्ट-अप्स ने तरह-तरह के और अभिनव फिनटेक उत्पाद तैयार किए हैं। निवेशकों ने उत्साहपूर्वक उनका समर्थन किया है जिससे इस क्षेत्र में निवेश 2010 के \$5 बिलियन से बढ़कर 2019 में \$78 बिलियन हो गया है (चार्ट 2)।

फिनटेक्स का भौगोलिक वितरण

फिनटेक कंपनियों की एक अनूठी विशेषता रही है कि ये अपना क्षेत्र बदलती रही हैं चाहे वह इनकी गतिविधियों के केंद्र के रूप में हो या फिर इनके प्रभाव क्षेत्र की बात हो। केपीएमजी की फिनटेक100 के अनुसार, फिनटेक कंपनियों के लिए नया उत्पादक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका और यूरोप से बदलकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र होने जा रहा है; एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2017 में फिनटेक कंपनियों की संख्या 31 थी जबकि 2019 में यह संख्या बढ़कर 42 (सभी क्षेत्रों में उच्चतम) हो गयी। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के भीतर देखें तो, चीन को भारत, वियतनाम और कोरिया जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। भारत एक प्रमुख फिनटेक ताकत के

रूप में उभर रहा है और फिनटेक100 सूची में इसकी 8 कंपनियों ने अपनी जगह बना ली है।

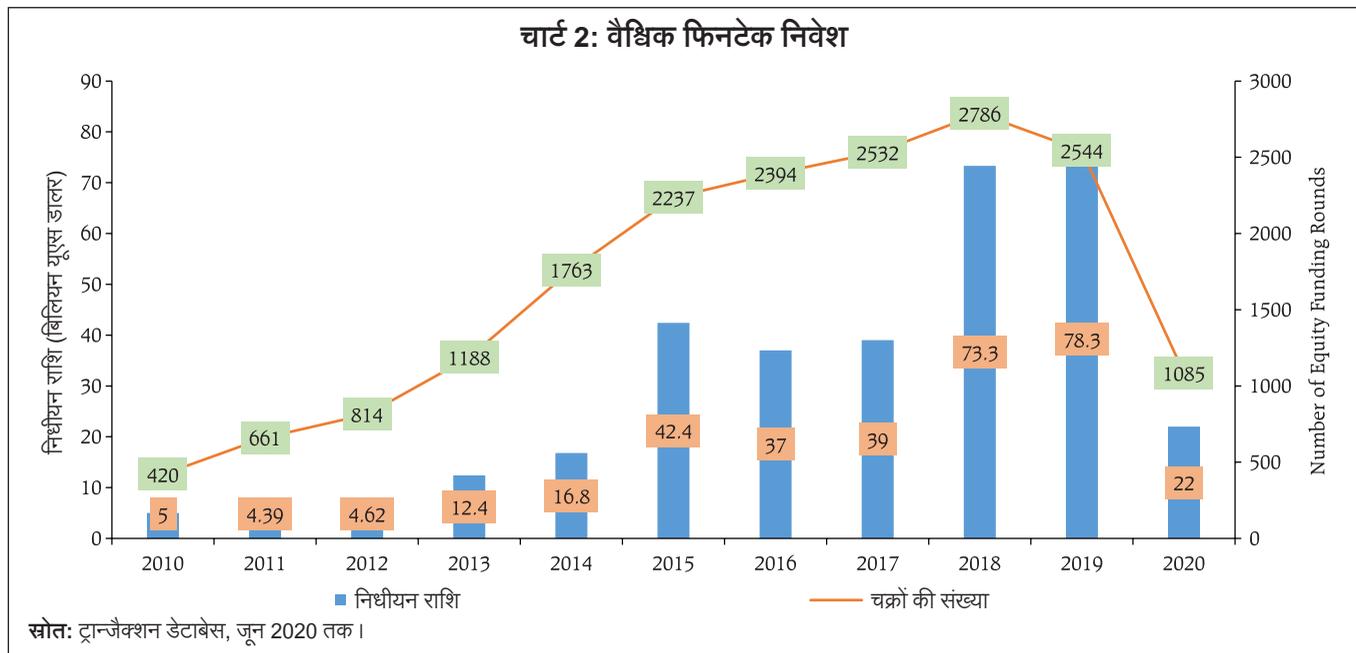
फिनटेक से होने वाले लाभ

दक्षता में वृद्धि

फिनटेक ने वित्तीय क्षेत्र की दक्षता और अधिक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है (फिलिपोन, 2020)। संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिनटेक ऋणदाताओं ने अन्य उधारदाताओं की तुलना में 15-30 प्रतिशत तेजी से प्रोसेसिंग करते हुए ऋण लेना आसान बना दिया है और इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि इन ऋणों में चूक की दर अपेक्षाकृत अधिक (सशर्त) रही हो (फर्स्टर और अन्य, 2018)।

वित्तीय समावेशन

सूचना की असंगति या उच्च लेनदेन लागत जैसी बाजार की विफलताओं पर काबू पा लेने से, फिनटेक्स वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करती हैं। एक बड़े चीनी प्लेटफॉर्म पर किए गए खुदरा उधारकर्ताओं पर सर्वेक्षण में, आधे से अधिक ने बताया कि उन्होंने इससे पहले किसी भी वित्तीय संस्था से कोई ऋण नहीं लिया था (डीयर और अन्य, 2015)। बिग डेटा और मशीनी लर्निंग तकनीकों के आने से उन मानवीय पूर्वाग्रहों को भी कम किया जा सकेगा जिनके कारण कुछेक चुनिंदा समूहों के प्रति भेदभाव किया जाता है (बार्टलेट और अन्य, 2018)।



³ पेटीएम पांचवें और ओला मनी आठवें स्थान पर रहा।

ऋण जोखिम में आयी कमी

क्रेडिट प्रावधानीकरण पर कुछेक बैंकों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने से अर्थव्यवस्था के समक्ष जो जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें कम करने में भी फिनटेक्स के प्रसार से मदद मिल सकती है क्योंकि ये क्रेडिट के और अधिक स्रोतों का विकल्प प्रदान करती हैं। क्रेडिट पर केंद्रित फिनटेक्स वाणिज्यिक बैंकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं क्योंकि उनमें से कुछ फिनटेक प्लेटफॉर्मों की क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं (क्लेसेन्स और अन्य, 2018)।

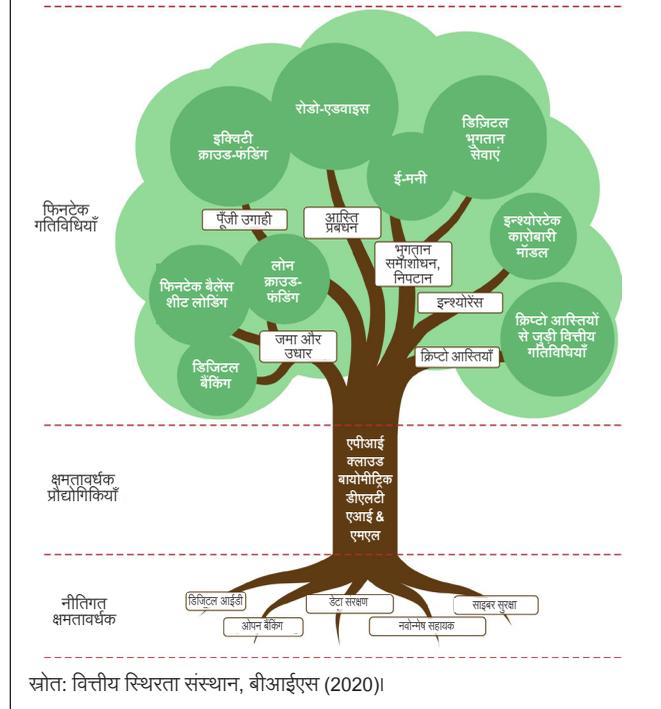
फिनटेक विनियमन

फिनटेक्स को दोधारी तलवार के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ इनसे कई लाभ हैं वहीं, इस प्रकार के नवोन्मेष डिजिटल रूप से निरक्षर और इंटरनेट से न जुड़ सकने वाले उपभोक्ताओं को पीछे छोड़ देते हैं और ये कभी-कभी उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा खतरों को बढ़ा भी सकते हैं जैसे कि गोपनीयता भंग होने की संभावनाएं और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम। इस प्रकार, विनियमन की भूमिका वैसे तो हर प्रकार की वित्तीय प्रणाली के लिए निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु फिनटेक जैसे नए आविष्कारों के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

फिनटेक में किसी केंद्रीय बैंक की दिलचस्पी वित्तीय क्षेत्र पर पड़ने वाले इसके प्रभाव तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति के लिए भी इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण होते हैं। विनियामकीय वातावरण, फिनटेक गतिविधियों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़े उसे जीवन प्रदान करती हैं (चार्ट 3)।

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के तत्वावधान में कराए गए एक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन के माध्यम से तेजी से उभर रहे फिनटेक के बारे में दुनिया भर के विनियामकों की प्रतिक्रियाओं को सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है (एरीट्रांड और अन्य, 2020)। हालांकि सर्वेक्षण में शामिल किए गए अधिकांश देशों में फिनटेक आधारित ऋण के लिए कोई समर्पित विनियामक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इनमें से कई देशों में डिजिटल भुगतान और क्राउडफंडिंग की जाती थी। बीमा क्षेत्र की बात की जाए तो मौजूदा विनियमों को मोटे तौर पर पर्याप्त माना गया। क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के मामले में लगभग सभी विनियामकों ने चेतावनी और स्पष्टीकरण जारी किए थे लेकिन कुछ देशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं में क्रिप्टो-आधारित लाइसेंस जारी किए जाने की शुरुआत होने की सूचनाएं भी मिलीं। जहाँ तक क्षमता वृद्धि करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रश्न है, अधिकांश विनियामकों द्वारा प्रौद्योगिकी से जुड़े तत्वों को शामिल करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में फेरबदल किया गया। एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई), क्लाउड कंप्यूटिंग और बायोमीट्रिक पहचान

चार्ट 3: विनियमन की भूमिका को रेखांकित करता फिनटेक ट्री



के मामले में विनियामक विशेष रूप से सक्रिय दिखे। क्लाउड कंप्यूटिंग पर अनेक फिनटेक्स की निर्भरता का परिणाम यह हुआ है कि यह वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रणालीगत आवश्यकता बन गयी है। आगे चलकर संभव है कि भविष्य में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हों जो केवल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध हों। ऐसे मामलों में, केंद्रीय बैंकों को इन-हाउस क्लाउड डेवलपमेंट का विकल्प चुनना पड़ सकता है अथवा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ करना होगा। उदाहरण के लिए, यूएस फेडरल रिजर्व ने ऑन-साइट निरीक्षण के लिए अमेज़न द्वारा दी जा रही क्लाउड सुविधाओं का दौरा किया है, जबकि यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण ने क्लाउड आउटसोर्सिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं (राजा, 2019)। यद्यपि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी अधिगम और डीएलटी के लिए विनियामकीय कार्रवाई जोखिम मूल्यांकन और सामान्य मार्गदर्शन तक ही सीमित रही है।

फिनटेक्स के आने के साथ ही, वित्तीय विनियामकों के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियाँ आ रही हैं। ये फर्म नए-नये आकार-प्रकार में आती हैं, इसलिए विवेकपूर्ण या जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए बनी बकेट्स में उन्हें फिट कर पाना आसान नहीं होता। गतिविधियों का दायरा जैसे-जैसे राष्ट्रीय से वैश्विक होता जा रहा है, वैसे-वैसे विनियमन को भी सीमाओं का अतिक्रमण करना होगा। इसके अलावा, अगर वित्तीय प्रणाली में पारंपरिक बैंकों का महत्व

कम हो जाता है, तो मुद्रा बाजार में उनके परिचालनों के स्थानापन्नों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रीय बैंकों को विचार करना पड़ सकता है ताकि मौद्रिक संचरण प्रभावी तरीके से होता रहे (लैगार्ड, 2017)।

III. भारत में फिनटेक परितंत्र का विकास

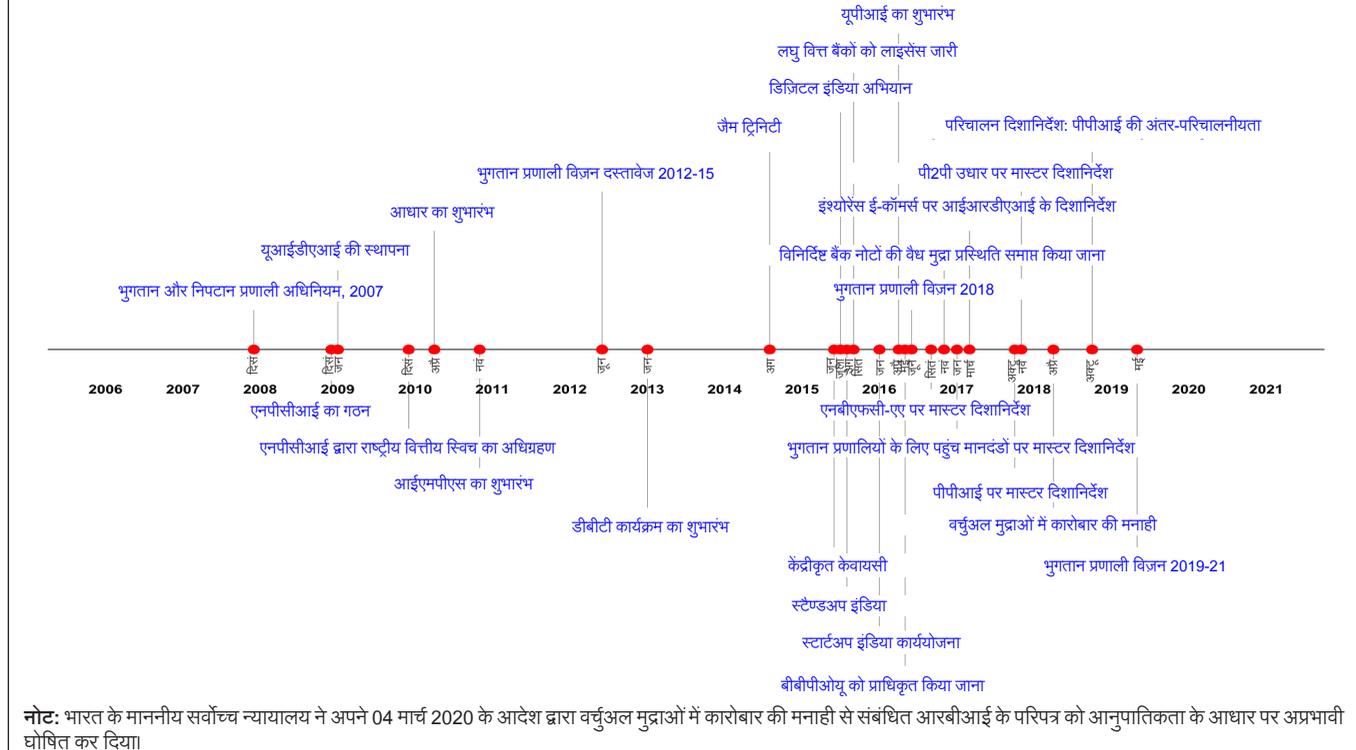
भारतीय फिनटेक की जड़ें पिछले कई दशकों के उन मूल प्रयासों में निहित हैं जो इस क्षेत्र के लिए प्रमुख क्षमतावर्धकों के विकास की दिशा में किए गए हैं। आज का भारतीय फिनटेक उद्योग जिस रूप में हमारे सामने है, वह प्रौद्योगिकीय क्षमतावर्धकों, विनियामकीय हस्तक्षेपों और कारोबारी अवसरों के साथ-साथ विशेष रूप से भारत से संबंधित कुछ अन्य विशेषताओं के अनूठे गठजोड़ का परिणाम है।

भुगतान प्रणालियों के विनियामक के रूप में, रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित, सुलभ और किफायती भुगतान प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने और इनकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और भुगतान प्रणालियों से अब तक वंचित आबादी वाले क्षेत्रों तक ये सेवाएं पहुंचाने के अनेक उपाय किए हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रिज़र्व बैंक के विज़न 2021 में चार लक्ष्यों (4सी) की परिकल्पना की गयी है, यथा – कॉम्पिटिशन अर्थात् प्रतियोगिता, कॉस्ट अर्थात् लागत, कन्वीनियंस अर्थात् सुविधा और कॉन्फिडेंस अर्थात् विश्वास।

विनियामकीय वातावरण

भारत ऐसे कुछेक विशिष्ट देशों में शामिल है जहाँ एक विशिष्ट भुगतान और निपटान कानून है, जो "भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है और जो इस उद्देश्य से और इससे जुड़े अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए रिज़र्व बैंक को नामित करता है"। रिज़र्व बैंक कुछ फिनटेक्स को एनबीएफसी लाइसेंस प्रदान करते हुए उनका प्रत्यक्ष रूप से विनियमन करता है (जैसे एनबीएफसी-पी2पी), अथवा उनके साथ जुड़े बैंकों और एनबीएफसी को विनियमित करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा की गयी एक पहल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का गठन हुआ जो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के परिचालन के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। पिछले एक साल के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा अपने विभिन्न मौद्रिक नीति विवरणों में भुगतान और निपटान प्रणाली में किए गए बदलावों को अनुबंध 2 में प्रस्तुत किया गया है। भारत द्वारा फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए किए गए अनुकूल नीतिगत उपायों को दर्शाती एक विनियामकीय समय-सारणी चार्ट 4 में दी गयी है।

चार्ट 4: भारतीय फिनटेक की विनियामकीय समय-सीमा



भारतीय फिनटेक के प्रमुख क्षमतावर्धक

इंटरनेट और स्मार्ट फोन की पहुँच

इंटरनेट और स्मार्टफोन के तीव्र और व्यापक प्रसार के कारण भारत में फिनटेक ने अपनी पहुँच में तेजी से विस्तार किया है (सारणी 2)।

अनुकूल जनसांख्यिकी

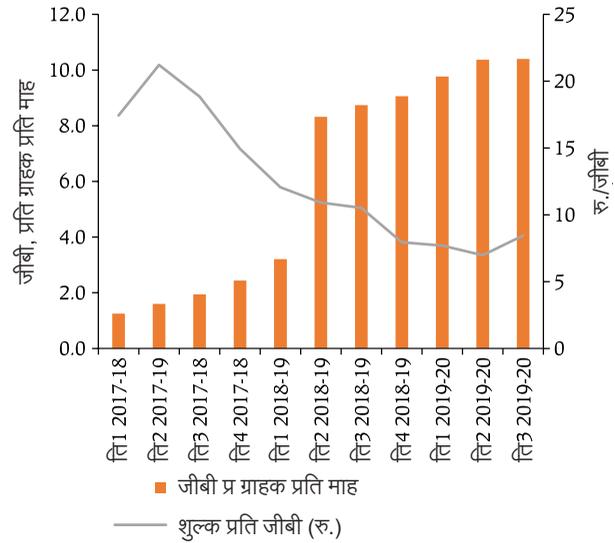
भारत का यह सौभाग्य है कि उसके बाजार में युवा आबादी अधिक है, जिनके द्वारा फिनटेक पर भरोसा करने और उसे अपनाए जाने की अधिक संभावना है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, देश में 1157.75 मिलियन वायरलेस उपभोक्ता थे, जिनमें 638 मिलियन शहरी और 519 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता

सारणी 2: संचार संकेतक

मानक	अवधि	संचयी राशि
टेलीफोन ग्राहक	31-मार्च-14 to 30-अप्रै-20	116.8 करोड़
टेलीफोन घनत्व	31-मार्च-14 to 30-अप्रै-20	86.6 %
इंटरनेट ग्राहक	31-मार्च-14 to 31-मार्च-20	74.3 करोड़
ब्रॉडबैंड ग्राहक	31-मार्च-14 to 31-मार्च-20	68.7 करोड़
वायरलेस डेटा का उपयोग	ति3 2019-20	21.402 पीटाबाइट्स
दूरसंचार का उपयोग (मासिक वायरलेस प्रति उपयोगकर्ता औसत आमदनी)	31-मार्च-14 to 31-दिस-19	₹ 78.7
दूरसंचार टावर	01-सित-17 to 27-जुला-20	6,05,788
भारतनेट के अंतर्गत जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें	31-अग-14 to 30-जून-20	1,41,098
दूरसंचार लाइसेंस	31-मार्च-14 to 30-जून-20	156

स्रोत: दूरसंचार विभाग, भारत सरकार (2020)।

चार्ट 5: वायरलेस डेटा का उपयोग और शुल्क



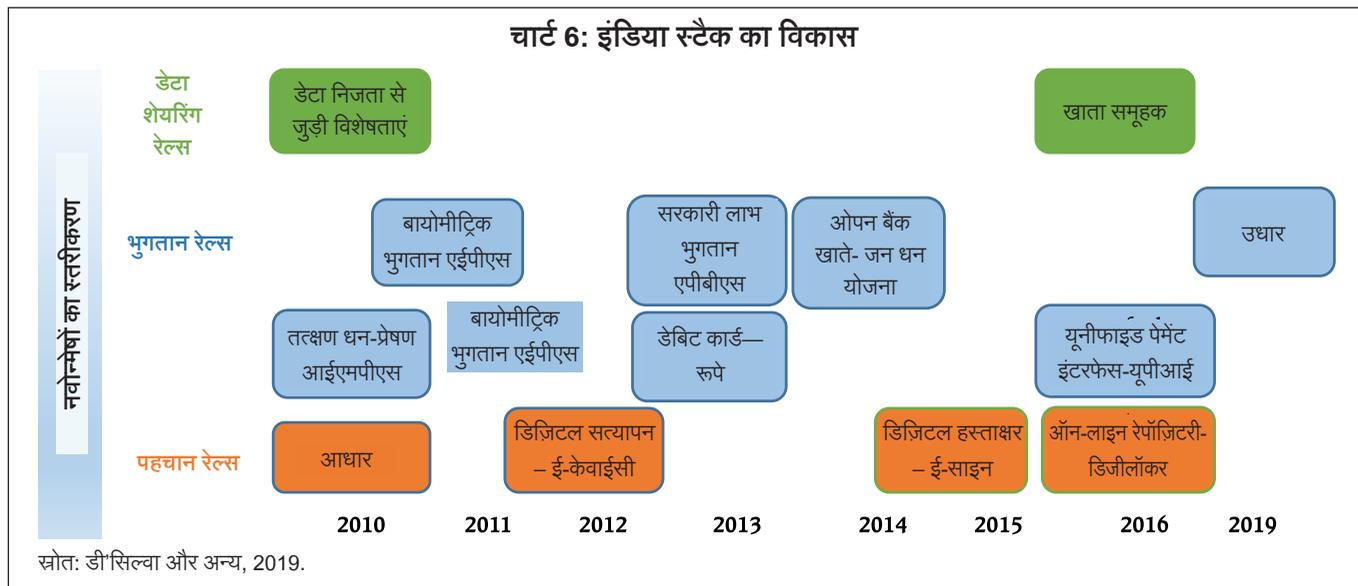
स्रोत: दूरसंचार विभाग, भारत सरकार (2020)।

शामिल थे (ट्राई, 2020)। ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स 2019 में भारत और चीन शीर्ष पर हैं और उनकी स्वीकार्यता दर 87 प्रतिशत है। जहाँ एक ओर प्रति व्यक्ति इंटरनेट उपयोग में वृद्धि हुई है, वहीं इसके टैरिफ में गिरावट आई है (चार्ट 5)।

इंडिया स्टैक

एक प्रगतिशील फिनटेक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के मूल में है 'इंडिया स्टैक'- प्रौद्योगिकियों और नीतियों का एक स्वदेशी सेट जो नवोन्मेषों को अधिक समर्थ बनाने का कार्य करता है (चार्ट 6)।

चार्ट 6: इंडिया स्टैक का विकास



'इंडिया स्टैक' मुख्यतया दो सिद्धांतों पर आधारित है - डिजिटल प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच वाली वस्तु बनाना और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का डिजाइन इस प्रकार तैयार करना कि यह डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से युक्त हो (डीसिल्वा और अन्य, 2019)। भुगतान प्रणाली के लिए इंडिया स्टैक का एक उदाहरण चार्ट 7 में दिखाया गया है। इंडिया स्टैक की आधारशिला है इसका आधार समर्थित होना, जिसका इस्तेमाल फिनटेक द्वारा कम सीमांत लागत पर एक विशिष्ट, सत्यापन योग्य पहचान तक पहुंचने के लिए किया जाता है। भारत के 1.25 बिलियन से अधिक निवासियों को आधार जारी किया गया है, और प्रतिदिन 30 मिलियन प्रमाणीकरण अनुरोधों की प्रोसेसिंग की जाती है (यूआईडीएआई, 2019)। सत्यापन के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदान किए गए विभिन्न प्लेटफॉर्म (ई-केवाईसी), डिजिटल सिग्नेचर (ई-साइन), क्लाउड स्टोरेज (डिजीलॉकर) और भुगतान का विकास आधार संख्या पर किया गया है, जिनका इस्तेमाल नवोन्मेषकर्ताओं द्वारा मूल्य के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है और अपना खुद का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता से उन्हें छुटकारा मिल जाता है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक महत्वपूर्ण क्षमतावर्धक है, जो खातों को पहचान लेता है और ग्राहकों को व्यापारी भुगतान और फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।

डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क

ऑनलाइन गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न डेटा तक व्यापक पहुंच फायदेमंद हो सकती है क्योंकि वे अक्सर शून्य सीमांत लागत पर प्राप्त किए जाते हैं और इनमें प्रतिद्वंद्विता नहीं होती⁴। डेटा तक खुली पहुंच ग्राहकों के लिए स्विचिंग लागत को कम कर सकती है और आम तौर पर इससे प्रतिस्पर्धा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। 2016 में, रिजर्व बैंक ने एक प्रकार की विनियमित डेटा फ़िड्यूशियरी संस्थाओं, जिन्हें खाता समूहक (एनबीएफसी-ए) कहा जाता है, के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया, जिससे ग्राहक से संबंधित डेटा को ग्राहक की जानकारी और सहमति के साथ विनियमित वित्तीय प्रणाली के भीतर साझा किया जा सके। विनियमित संस्थाओं (आरबीआई, सेबी, इरडा और पीएफआरडीए के अंतर्गत) को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सीमित समयावधि तक डेटा तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इनोवेशन सुविधाप्रदाता (फैसिलिटेटर) भी महत्वपूर्ण फिनटेक क्षमतावर्धक होते हैं। तेजी से विकसित होते फिनटेक क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' की स्थापना की है ताकि विनियमन को सुविधाजनक बनाया जा सके और इसके तहत नियंत्रित विनियामकीय वातावरण

चार्ट 7: भुगतान के लिए इंडिया स्टैक

प्रौद्योगिकी स्टैक	वाणिज्यिक अनुप्रयोग	इंडिया स्टैक
भुगतान का तरीका	विसा, मास्टर कार्ड	केंद्रीय बैंक
बड़े पैमाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लैटफॉर्म	गूगल मैप, एप्पल पे	फिनटेक कंपनियाँ वाणिज्यिक बैंक बैंकेतर भुगतान परिचालक
निजी कंपनियाँ		डेटा शेयरिंग रेल्स, भुगतान रेल्स, पहचान रेल्स
सरकारी क्षेत्र		
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष (सार्वजनिक निधीयन वाले)	इंटरनेट जीपीएस	इंटरनेट
दूरसंचार और कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकियाँ (हार्डवेयर)	स्मार्टफोन/टैबलेट/पीसी	स्मार्टफोन/टैबलेट/पीसी

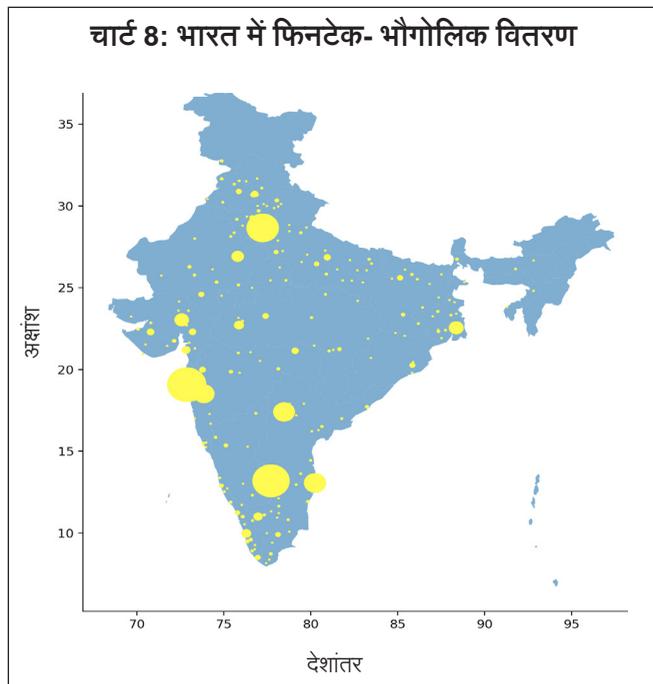
स्रोत: डी'सिल्वा और अन्य, 2019.

⁴ जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग किए जाने के फलस्वरूप दूसरों के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं हो जाती तब उस वस्तु की प्रकृति गैर-प्रतिस्पर्धी कही जाती है।

में नए उत्पादों के लाइव परीक्षण को संभव बनाया जा सकता है ताकि वित्तीय नवोन्मेषों के लाभों और जोखिमों के बारे में प्रामाणिक आंकड़े मिल सकें (आरबीआई, 2019)। विनियामक सैंडबॉक्स में भेजे जाने के लिए अनुप्रयोगों के पहले समूह का परिचालनात्मक विषय 'खुदरा भुगतान' तय किया गया था (आरबीआई, 2019)।

इंडियन फिनटेक: विविधता की ताकत

भारत के फिनटेक पारितंत्र की सबसे बड़ी पहचान है - बाजारों और अनुप्रयोगों की विविधता। यह देखा जाता है कि उभरते उद्योग अक्सर संकुलन प्रभाव से लाभ लेने के लिए क्षेत्र विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन फिनटेक इस प्रवृत्ति का पालन नहीं करती हैं (बासोल और पटेल, 2018)। हालांकि फिनटेक मुंबई, बेंगलूर, दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरीय शहरों में केंद्रित हैं, तथापि इनका विस्तार छोटे शहरों तक भी हो रहा है। मुंबई और बेंगलूर फिनटेक आंदोलन में सबसे आगे हैं और स्टार्टअप मुख्यालयों में से 42 प्रतिशत इन्हीं शहरों में स्थित हैं। जयपुर, पुणे और अहमदाबाद जैसे अन्य शहर भी फिनटेक के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं (मेडिसी और पिसाबाजार: इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2019)। ट्रैक्सन (Traxxn)



डेटाबेस के अनुसार, भारत में फिनटेक के रूप में वर्गीकृत कुल 4,680 कंपनियां हैं, जिन्हें मोटे तौर पर पंद्रह व्यावसायिक मॉडलों में वर्गीकृत किया जा सकता है (अनुलग्नक 3)।

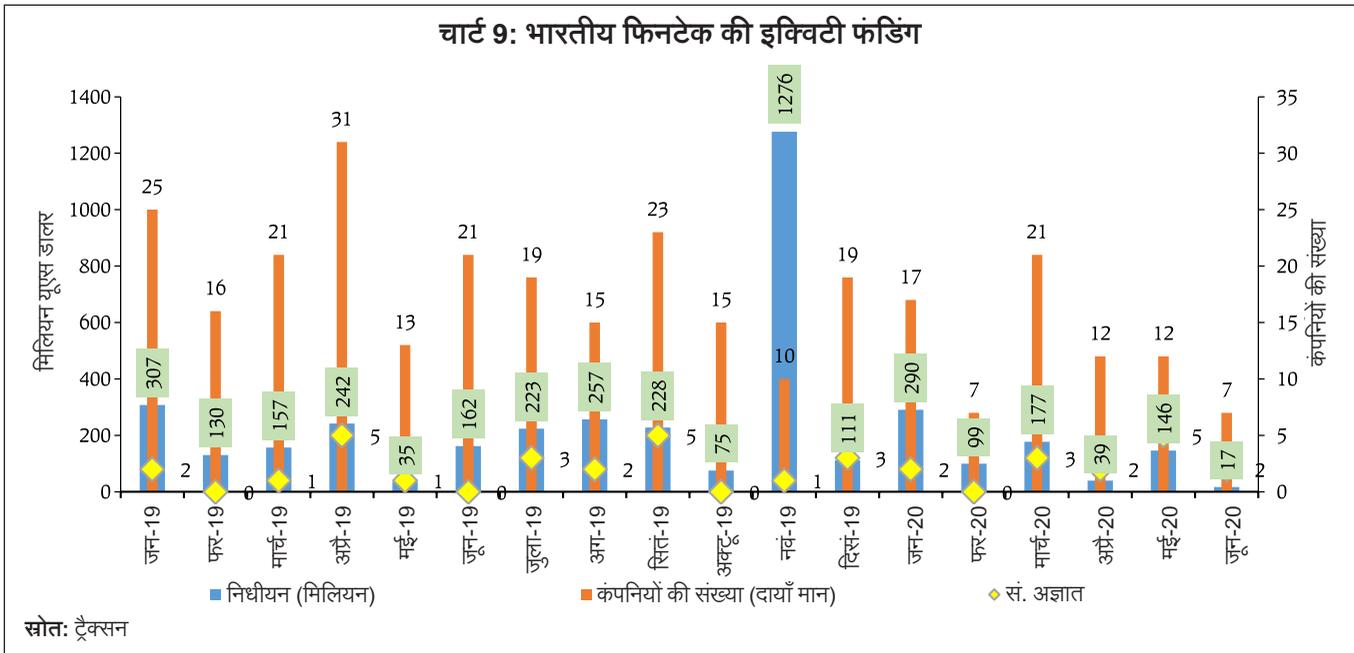
इक्विटी फंडिंग

स्टार्टअप्स इक्विटी के जरिए पैसा जुटाया करते हैं, क्योंकि आम तौर पर उनके पास कोई प्रकट आमदनी या संपार्श्विक नहीं होता जिसे वे बैंकों को प्रस्तुत कर सकें जो कि सामान्यतया ऋण देने में रूढ़िवादी होते हैं। किसी स्टार्टअप को उधार देने के लिए उस अपरंपरागत बिजनेस मॉडल की संभाव्य अर्जन क्षमता, संस्थापकों का उत्साह और उनकी योग्यता, व्यावसायिक माहौल, क्षेत्र विशेष का ज्ञान आदि जैसे नये मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा, वेंचर कैपिटल फर्म जैसे विशेष इक्विटी निवेशक अधिक 'व्यावहारिक' हो सकते हैं और वे स्टार्टअप का मार्गदर्शन इस प्रकार कर सकते हैं कि वे लंबे समय तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। इक्विटी फंडिंग से स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय के लिए एक दूरदर्शी योजना बनाने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि उन्हें तत्काल ऋण चुकौती दायित्वों से छुटकारा मिल जाता है।

ट्रैक्सन डेटाबेस के अनुसार, 2019-20 के दौरान 211 भारतीय फिनटेक कंपनियों ने 3.18 बिलियन यूएस डालर जुटाए (इक्विटी चरणों में और एंजल निवेशकों से) (चार्ट 9)। इन 211 के अलावा 25 अन्य फिनटेक ने भी फंड जुटाए लेकिन उन्होंने इसका ब्योरा साझा नहीं किया। इस धन उगाही को अप्रैल 2020 कोविड-19 के परिणामस्वरूप लगे लॉकडाउन के कारण धक्का लगा।

2019-20 के दौरान उगाहे गए \$ 3.18 बिलियन की राशि का वितरण बहुत ही असमान रहा जिसमें शीर्ष 10 कंपनियों (इक्विटी फंडिंग की दृष्टि से) की भागीदारी कुल धन संग्रह की लगभग दो तिहाई थी (अनुबंध 4)। इसमें से 1 बिलियन डॉलर नवंबर 2019 में अकेले पेट्टीएम द्वारा उगाहा गया था। धन उगाही वाले अधिकांश फिनटेक भुगतान क्षेत्र में कारोबार करते हैं। इक्विटी पाई चार्ट में सीड और सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज

⁵ स्टार्ट-अप्स प्रायः एक के बाद एक क्रम से या चक्रीय रूप से (सीड, सीरीज ए, बी, सी और इसी प्रकार आगे) इक्विटी की उगाही करते हैं जो मोटे तौर पर व्यापार में हुई संवृद्धि / आकार का अनुसरण करते हैं, और उस चरण में व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करते हैं। शुरुआती चरणों का उपयोग बाजार में पैर जमाने के लिए किया जा सकता है, जबकि बाद के चरणों का इस्तेमाल कारोबार विस्तार के लिए किया जा सकता है।

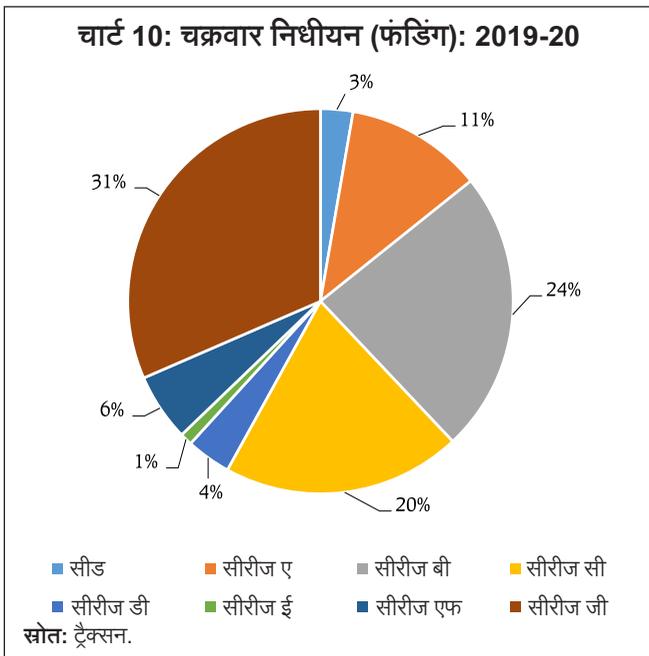


सी फंडिंग क्रमशः 14, 24 और 20 प्रतिशत थी (चार्ट 10)। पूरे वर्ष के फिनटेक फंडिंग का लगभग एक तिहाई पेट्टीएम द्वारा हाल के सीरीज़ जी राउंड में प्राप्त किया गया था।

फिनटेक और बैंक: पारस्परिक सहयोग

फिनटेक फर्मों को अब बैंकों द्वारा विघटनकारी ताकतों के रूप में नहीं देखा जाता। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि फिनटेक्स

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के क्षमतावर्धक के तौर पर कार्य करते हैं। तकनीकी नवोन्मेष को अपनाने के लिए बैंक कई रणनीतियों पर कार्य कर रहे हैं - फिनटेक कंपनियों में निवेश और फिनटेक अनुषंगी कंपनियों को प्रारंभ करने से लेकर अपने परिचालन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए फिनटेक्स के साथ सहयोग करने तक। बैंक और गैर-बैंक मिलकर भारतीय उपभोक्ता के समक्ष ऐसे विकल्प पेश कर रहे हैं जो नवोन्मेषी होने के साथ-साथ विश्वसनीय भी हैं (दास, 2020)। राजस्व और मुनाफे को बढ़ाने के लिए, वे नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे- बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन, दलाली और वित्तीय तकनीकों द्वारा समर्थित अन्य सेवाएं।



फिनटेक और बैंकों के बीच तालमेल के कई क्षेत्रों का अभी पता लगाया जाना है। फिनटेक्स के पास विशाल तकनीकी ज्ञान और नवोन्मेषी विचार तो होते हैं लेकिन उनके पास व्यापक ग्राहक आधार और वित्तीय उद्योग के नियमों और लाइसेंसिंग अनुशासन के पालन की निपुणता का अभाव होता है। पारंपरिक बैंकों के पास एक बड़ी ताकत होती है - भरोसेमंद होने से जुड़ी प्रतिष्ठा जो उन्होंने कई दशकों में कमायी होती है। बैंकों के पास पूँजी होती है और वे तीव्र प्रतिस्पर्धा झेल सकते हैं। उनके पास जोखिम प्रबंधन, स्थानीय नियमों और अनुपालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ-साथ अनुभव और आजमाया गया भरोसेमंद बुनियादी ढांचा भी होता है जिसका उन्हें लाभ होता है। वास्तव में, बैंकों का बाज़ार और ग्राहकों के बारे में ज़मीनी ज्ञान और पहले से मौजूद उनका

ग्राहक आधार फिनटेक परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक मूल्यवान साबित हो सकते हैं। संक्षेप में, बैंकों और फिनटेक फर्मों के अलग-अलग तुलनात्मक फायदे हैं और दोनों के बीच एक रणनीतिक सहयोग-आधारित साझेदारी से उन्हें अपने मूल क्षेत्रों में प्राप्त दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी मिलेगी (मुंद्रा, 2017)।

IV. भावी विकास के सम्मुख चुनौतियाँ

फिनटेक्स को भविष्य में कई अवसर मिलेंगे तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना होगा। यदि उन्हें अधिक कार्यकुशल, भरोसेमंद, निष्पक्ष और सुदृढ़ बनना है तो मोटे तौर पर उन्हें छह प्रकार की चिंताओं का समाधान ढूँढना होगा।

पहली, नवाचार के लिए अत्यधिक संभावनाएं मौजूद होने के बावजूद, सीमा-पार भुगतान अभी भी फिनटेक के लिए अछूता क्षेत्र है। धन-प्रेषण सुविधाओं का लाभ उठाने में प्रवासी श्रमिकों पर बोझ पड़ता है क्योंकि इन प्रेषणों की लागत बहुत अधिक होती है (डी'सिल्वा और अन्य, 2019)। सीमा-पार भुगतान का एक बड़ा हिस्सा संवाददाता बैंकों के माध्यम से सम्पन्न होता है, जिनकी घटती संख्या का परिणाम यह हो सकता है कि लागत और भी बढ़ जाएगी और अनौपचारिक, अविनियमित भुगतान नेटवर्कों की ओर रुख करना पुनः प्रारंभ हो जाएगा (कार्सटेंस, 2020)। भारत में, घरेलू भुगतानों की तुलना में सीमा-पार लेनदेन काफी धीमा है और इसके कुछ ही विकल्प उपलब्ध हैं, हालांकि आवश्यक व्यक्तिगत प्रेषण की मात्रा बहुत अधिक है (आरबीआई, 2019)। विभिन्न देशों में भुगतान प्रणालियों को अंतःप्रचालनीय बनाने के लिए, भुगतान निर्देशों को एक सर्वस्वीकार्य भाषा में अनूदित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए, सभी संबंधित देशों के मानकों और प्रथाओं में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और प्रत्येक घरेलू नेटवर्क के 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) और 'काला धन निरोधक' (एएमएल) ढांचे के बीच पारस्परिक विश्वास स्थापित होना चाहिए। हाल ही में, सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2019 में प्रायोगिक तौर पर यूपीआई को सिंगापुर नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (एनईटीएस) के साथ जोड़ा गया था (ईटी, 2019) जिससे यह समझ में आया कि वर्तमान व्यवस्था में ही रहते हुए उल्लेखनीय प्रगति की जा सकती है। यूपीआई प्रणाली के अंतर्गत निपटान विनियमित वित्तीय प्रणाली की परिधि के भीतर प्रचलित वैध मुद्रा में किया जाता है और इसीलिए इसमें स्टेबल क्वाइंस जैसी प्रणालियाँ जो बिगटेक्स द्वारा प्रबंधित होती हैं, उनकी तुलना में जोखिम कम होता है।

दूसरी, फिनटेक की बढ़ती लोकप्रियता डेटा इस्तेमाल पर दबाव बढ़ा सकता है, संरक्षण और गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं यदि सेवा प्रदाताओं के वैधानिक अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किए जाते। मशीन लर्निंग का गणित मौजूदा भेदभाव वाली व्यवस्था को बार-बार दोहरा सकता है और उसे स्थायी बना सकता है जिसमें समाज के कुछ कमजोर तबके अलग-थलग पड़ जाएंगे। जब भारतीय आबादी इंटरनेट और मोबाइल कवरेज बढ़ने से डेटा के मामले में अधिक समृद्ध हो जाएगी, तब अगली चुनौती यह होगी कि समुचित कानूनी और विनियामक हस्तक्षेप करते हुए उपभोक्ताओं को उनके द्वारा जेनेरेट किए गए डेटा के बल पर सशक्त बनाया जाए। नागरिक अपने डेटा पर ठीक उसी तरह नियंत्रण रखने की स्थिति में होने चाहिए जैसे अपनी किसी अन्य निजी संपत्ति पर। कई देशों से डेटा स्थानीयकरण की मांग उभर रही है। ऐसे में, समाधान के तौर पर एक ऐसा मॉडल विकसित किया जा सकता है जहां डेटा को स्थानीय रूप से संग्रहीत किया जाता हो और जिस पर विदेशों से केवल द्विआधारी (हां या नहीं) ऐसे प्रश्नों को पूछने की अनुमति हो, जो विनिर्दिष्ट किए गए हों और जिन पर वैश्विक रूप से सहमति बनी हो।

तीसरा, चूंकि फिनटेक के विस्तार के साथ-साथ प्रणाली-व्यापी जोखिम बढ़ने की संभावनाएं हैं, अतः वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव का निर्धारण करने की आवश्यकता है। क्रेडिट तक अपेक्षाकृत व्यापक पहुंच बनने और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण ऋण मानक कमजोर हो सकते हैं। चूंकि फिनटेक ऋणदाता जमा के बजाय ऋण और इक्विटी से अग्रिम देते हैं, ऋण मानक दिशानिर्देशों के अभाव के कारण अधिक चक्रिय और अस्थिर हो सकते हैं। इसके अलावा, विवेकपूर्ण ऋण वितरण परिधि के बाहर की क्रेडिट गतिविधियों से क्रेडिट संबंधी प्रतिचक्रिय नीतियाँ कम प्रभावी बन सकती हैं। फिनटेक के साथ कारोबार करने वाले बैंकों के सामने प्रतिष्ठा, साइबर तथा अन्य पक्ष से जुड़े जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

चौथा, फिनटेक द्वारा दी जा रही सेवाओं तक पहुंच भी असमान रही है। हालांकि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, तथापि, हमारे यहाँ अभी भी शहरी, पुरुषवर्ग और संपन्न तबके की ही पहुँच इंटरनेट तक है। ऑनलाइन बाजार पर भरोसा कम है और नमूने के तौर पर किसी उपयोगकर्ता को अपना पहला ऑनलाइन लेनदेन करने में 3-4 महीने लग जाते हैं। अधिकांश उपयोगकर्ता ऐसे हैं जो उत्पादों के बारे में अनुसंधान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद खरीद ऑफलाइन तरीके से ही करते हैं (ब्रायन एंड कंपनी,

2018)। हालांकि भारत में कुल बिक्री में 'माइक्रो-मर्चेन्ट' की हिस्सेदारी आश्चर्यजनक रूप से अधिक है, तथापि उन्हें इस कैशलेस क्रांति से अलग-थलग रखा गया है खास तौर पर छोटे शहरों में। मोबाइल-डेटा और स्मार्टफोन की पहुंच काफी बढ़ जाने बावजूद, कतिपय व्यवहारजनित कारणों जैसे- कराधान से जुड़ी भ्रांतियाँ, डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग करते समय तकनीकी ज्ञान का अभाव और सुरक्षा से जुड़े कथित खतरों – के कारण वित्तीय लेनदेन के लिए इनका उपयोग कम ही किया जाता है (आईएफएमआर, 2017)।

पांचवां मुद्दा उपभोक्ता संरक्षण और डिजिटल शिक्षा का है। विनियामकों के लिए यह आवश्यक है कि धोखाधड़ी का पता शुरुआत में ही लगाने पर जोर दिया जाए और साथ ही, वित्तीय साक्षरता के साथ डिजिटल साक्षरता को भी जोड़ दिया जाए ताकि भ्रांतियाँ दूर हो सकें। सुरक्षा के प्रावधानों और शिकायत निवारण तंत्र को सरल बनाने और उसका प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता है ताकि कम आय वाले समूहों की भागीदारी बढ़ायी जा सके। फिर भी, केवल वित्तीय साक्षरता और डिजिटल स्वच्छता पर्याप्त नहीं हो सकतीं। विभिन्न देशों का अनुभव यह बताता है कि नकदी के माध्यम से भुगतान करना एक आदत है, जो आमतौर पर बहुत धीरे-धीरे बदलती है। चीन में, रेहड़ी वाले, फकीर और यहां तक कि भिखारी भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करते हैं (जेनकिंस, 2018)। हालांकि, टोक्यो में हालत यह है कि दस में से छह रेस्तरां नकद भुगतान की अपेक्षा करते हैं (लुईस, 2019)। जैसे-जैसे गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं बढ़ती हैं, नकदी का इस्तेमाल बढ़ता है, जबकि बैंकों में लोगों का विश्वास बढ़ने के साथ-साथ इसमें गिरावट आती है (पीएनजी और टीएएन, 2020) इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने की नीतियों को यदि प्रोत्साहित करना है तो निजता की रक्षा और वित्तीय संस्थाओं में विश्वास से जुड़ी बुनियादी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

अंत में, नियामकों को इस मामले में तटस्थ रूप से कार्य करना होगा। फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर गठित कार्यदल (आरबीआई, 2018 ए) ने सचेत किया है कि विनियामकों वर्तमान में व्यवसायगत कंपनियों को न तो आवश्यकता से अधिक संरक्षण देना चाहिए, और न ही भेदकारी विनियामकीय बर्ताव करते हुए इस क्षेत्र में आने वाली नई कंपनियों को अनुचित प्रश्रय देना चाहिए। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बड़ी फर्मों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही, किफायती सेवाएं देने के लिए बेहतर डेटा भंडार वाली कुछ चुनिंदा कंपनियों के बीच आपसी समझौता हो जाएगा और फिर इस बात की आवश्यकता महसूस की जाएगी कि अपेक्षाकृत

छोटी और नवोन्मेषी फर्मों को नये सिरे से प्रोत्साहन प्रदान किया जाए ताकि प्रतिस्पर्धी तंत्र का विकास किया जा सके। हालांकि, तटस्थता के सिद्धांत का पालन करने के लिए, "प्राधिकारियों को कुछ ही प्रकार की गतिविधियों के लिए कठोर उपाय करके संतुष्ट होना पड़ेगा, जैसे कि जब इस प्लेटफॉर्म की बैलेंस शीट पर कोई दावा उत्पन्न हो जाता हो अथवा जब खुदरा निवेशक और उपभोक्ता इसमें शामिल हो जाएं" (क्लेसेन्स और अन्य, 2018)।

V. भावी दिशा

एक सुविधाप्रदाता विनियामक के तौर पर रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के कवरेज को अधिक व्यापक बनाते हुए स्टार्ट-अप को भी उसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कि डिजिटल भुगतान में सबसे बड़ी बाधा है, से जुड़ी समस्याओं का निदान करने और ऑफलाइन डिजिटल लेनदेन को संभव बनाने वाले नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत बैंक और गैर-बैंक सहित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) को अधिकृत किया गया है, कि वे कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके दूरस्थ या निकटवर्ती भुगतान के लिए ऑफलाइन भुगतान उपायों का प्रयोग कर सकेंगे (आरबीआई 2020बी)। वर्षों से, रिज़र्व बैंक डिजिटल भुगतानों के लिए सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देता आया है जैसे प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक का प्रावधान तथा प्रत्येक लेनदेन के लिए ऑनलाइन अलर्ट का अनिवार्य होना। इन उपायों से ग्राहकों का विश्वास और उनकी सुरक्षा भावना काफी बढ़ी है और इसके फलस्वरूप डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता भी। भविष्य में फिनटेक को विनियामक अनुपालन और साइबर जोखिमों के प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी। उन्हें साइबर-जोखिम निवारण फ्रेमवर्क तैयार करते हुए उसे लागू करना होगा और नियमित रूप से उसका भेद्यता परीक्षण भी करते रहना पड़ेगा।

आजकल भारतीय फिनटेक को अब तक की उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ रहा है – कोविड-19 महामारी। एक सर्वेक्षण से, जिसमें 250 भारतीय स्टार्टअप्स को शामिल किया गया था, इस बात की पुष्टि होती है कि बड़े पैमाने पर इस महामारी का कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, हालांकि इनमें से फिनटेक स्टार्टअप्स के समक्ष सबसे कम बाधाएं आर्यीं (फिक्की-आईएएन, 2020)। विशेषज्ञों का मानना है कि नई फर्मों को निश्चित रूप से नुकसान झेलना पड़ेगा परंतु ऐसे स्टार्ट-अप और बिगटेक जो भुगतान, ई-कॉमर्स और ऑन-लाइन लर्निंग जैसे लाभप्रद क्षेत्रों से जुड़े हैं, वे व्यापार के मार्ग में आए इन

व्यवधानों से पार पाने में सक्षम रहेंगे। आज समय की माँग है कि स्टार्टअप्स के बीच अंतर-परिचालन के स्तर को बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए तभी बाजार की माँग और उसके बदलते नजरिए के प्रति एक समन्वित प्रतिक्रिया आ सकेगी। यह महामारी इस विश्वास को भी चुनौती देती है कि फिनटेक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं; जो कि एक ऐसा विषय है जिस पर भविष्य में भी शोध किया जाएगा, यह पता लगाने के लिए कि क्या भारतीय फिनटेक अपने उन कमजोर ग्राहकों के लिए तब मददगार साबित हुईं जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, या वे उनकी जरूरतों को पूरा करने में असहाय सिद्ध हुईं। एक स्वस्थ और स्थायी कारोबारी पारिस्थितिकी को संभव बनाने के लिए यह जरूरी है कि फिनटेक कंपनियाँ डिजिटल आधार पर ग्राहकों के बीच मौजूद अंतराल को कम करने का प्रयास करें और शहरी तथा ग्रामीण सभी क्षेत्रों में और विभिन्न उत्पादक और उपभोग क्षेत्रों में समान रूप से समुचित और व्यापक ग्राहक सहभागिता को प्रोत्साहित करें।

संदर्भ

Aldasoro, I., Gambacorta, L., Giudici, P., and Leach, T., (2020), "Operational and Cyber Risks in the Financial Sector", *BIS Working Paper*, February

Bain & Company., (2018), "Unlocking Digital for Bharat: \$50 Billion Opportunity"

Bank of Japan., (2018), "FinTech Special Edition – Financial Innovation and FinTech", *Payment and Settlement Systems Report Annex Series*, September

Bartlett, R., A. Morse, R. Stanton, and N. Wallace, (2018), "Consumer-lending Discrimination in the Era of FinTech" *Working paper*

Basole R., and Patel, S. (2018), "Transformation through Unbundling: Visualizing the Global FinTech Ecosystem", *Service Science*, Vol. 10, No. 4, pp. 1-18, December

Buckley, R., A. W. Douglas and B.N. Janos, (2016), "The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?", *SSRN Electronic Journal* 47(4):1271-1319, January

Carney, M. (2019), "Enabling the FinTech Transformation: Revolution, Restoration or Reform?", *BIS Central Bankers' Speeches*

Carstens, A., (2020), "Shaping the Future of Payment", *BIS Quarterly Review*, March

Claessens, S., Frost, J., Turner, G., Zhu, F., (2018), "FinTech Credit Markets across the World: Size, Drivers and Policy Issues", *BIS Quarterly Review*, September

Cortina, J. and Schmukler, S., (2018), "The FinTech Revolution: A Threat to Global Banking?", *World Bank Group Chile Centre and Malaysia Hub*, April 14

Das, S. (2019), "Opportunities and Challenges of FinTech", *Keynote Address Delivered at the NITI Aayog's FinTech Conclave*, March 25

Das, S. (2020), "Banking Landscape in the 21st Century", *Speech Delivered at the Mint Annual Banking Conclave*, 2020, February 24

Deer, L., J. Mi and Y. Yuxin, (2015), "The Rise of Peer-to-Peer Lending in China: An Overview and Survey Case Study", *Association of Chartered Certified Accountants*

DoT (2020), Online Dashboard of Department of Telecommunications, *Government of India*, accessed on July 31, 2020

D'Silva, D., Filková, Z., Packer, F., and Tiwari, S., (2019), "The Design of Digital Financial Infrastructure: Lessons from India" *BIS Papers*, December

Ehrentraud, J., Ocampo, D., Garzoni, L., and Piccolo, M., (2020), "Policy Responses to FinTech: A Cross Country Overview", *BIS*, January

EY Global Financial Services, (2019), "Global FinTech Adoption Index"

FICCI and IAN, (2020), "Survey on the Impact of Covid-19 on Indian Start-ups", June

Frost, J., (2020), "The Economic Forces Driving FinTech Adoption Across Countries", *BIS Working Paper*, February

FSB, (2019), "FSB Report Assesses FinTech Developments and Potential Financial Stability Implications", *Press Release, Financial Stability Board*, February 14

- Fuster, A., M. Plosser, P. Schnabl, and J. Vickery, (2019), "The Role of Technology In Mortgage Lending" *The Review of Financial Studies* 32(5), 1854–1899
- G7 Working Group on Stablecoins, (2019), "Investigating the Impact of Global Stablecoins", October
- Government of India, (2019), "The Personal Data Protection Bill"
- Hendrikse, R., Bassens, D., and Meeteren, M., (2018), "The Appleization of Finance: Charting Incumbent Finance's Embrace of FinTech", *Finance and Society* 4(2): 159-80
- IFMR, (2017), "The Evolving Financial Ecosystem for Micro-Merchants in India", *IFMR LEAD and Mastercard Centre for Inclusive Growth*, September
- Jenkins, P (2018), "We Don't Take Cash: Is this the Future of Money?", *Financial Times*, May 10.
- King, R. (2019), "2020: FinTech and Beyond", *Central Banking*, December 31
- KPMG and H2 VENTURES, (2019), "Fintech100 Leading Global FinTech Innovators"
- KPMG, (2020), "Pulse of FinTech H2 2019", February
- Lagarde, C., (2017), "Central Banking and FinTech – A Brave New World?", *Speech, IMF*, September 2017
- Lewis, L (2019), "Japan's Cash Addiction will not be Easily Broken", *Financial Times*, January 9
- Libra Association Members, (2020), "The Libra Blockchain", *White Paper*
- Mankotia, A., (2020), "FinTech and Financial Services", *BFSI*
- Mckinsey and Company, (2016), "Fintechnicolor – The New Picture in Finance"
- Mckinsey Global Institute, (2019), "Digital India", March
- Ministry of Finance, Government of India, (2019), "Report of the Steering Committee on Fintech Related Issues"
- Mundra, S., (2017), "Financing MSMEs: Banks & FinTechs – Competition, Collaboration or Competitive Collaboration?", *Speech delivered at the NAMCABS Seminar organised by the College of Agricultural Banking*, February 20
- NPCI, (2018), "NPCI Statement pertaining to Whatsapp BHIM UPI Beta Launch", *Press Release*, February 16
- NPCI, (2019a), "Rationalisation of BHIM UPI MDR", *Press Release*, August 30
- NPCI, (2019b), "Big Push to Digital Payments through Debit Cards - Rationalization of Merchant Discount Rate (MDR) for RuPay Debit Card", *Press Release*, September 13
- Parthasarathy, S., (2020), "Decoding the Supreme Court's Cryptocurrency Judgment", *BloombergQuint*, March 11
- Perez, C., (2002), "Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages", *Elgar Publishing, Inc.*
- Philippon, T., (2020), "On FinTech and financial Inclusion", *BIS Working Papers*, February
- PIB, (2018), "Digital Payments Set to Become a Trillion-Dollar Market in Next Five Years : NITI Aayog", July 31
- Png, I. and Tan, C., (2020), "Privacy, Trust in Banks, and Use of Cash", *MAS Macroeconomic Review*, April
- RBI, (2018a), "Report of the Working Group on FinTech and Digital Banking", February 08
- RBI, (2018b), "Prohibition on Dealing in Virtual Currencies", *Notification*, April 6
- RBI, (2019a), "Reserve Bank Announces Opening of the First Cohort under the Regulatory Sandbox", *Press Release*, November 4

RBI (2019b), "Technical Specifications for All Participants of the Account Aggregator (AA) Ecosystem", *Notification*, November 8

RBI (2019c), "Benchmarking India's Payment Systems", *Report*, June

RBI, (2020), "Master Direction on Issuance and Operation of Prepaid Payment Instruments", February 28

RBI, (2020b), "Statement on Developmental and Regulatory Policies", August 6

The Economic Times, (2019), "BHIM UPI goes International; QR Code-Based Payments Demonstrated at Singapore FinTech Festival", November 13

TRAI (2020), "Highlights of Telecom Subscription Data as on 31 March 2020", *Press Release no. 49/2020*, Telecom Regulatory Authority of India

UIDAI (2019), "Now 125 Crore Residents of India have Aadhaar", *Press Release*, Unique Identification Authority of India, December 31

संलग्नक 1: डिजिटल लेनदेन

	मात्रा (लाख)			मूल्य (रु.करोड़)		
	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
1. अधिक मूल्य वाले क्रेडिट अंतरण (आरटीजीएस - ग्राहक और इंटरबैंक)	1,244	1,366	1,507	11,67,12,478	13,56,88,187	13,11,56,475
2. खुदरा क्रेडिट अंतरण (ए ई पी एस, ए पीबीएस, ईसीएस, आईएमपीएस, एनएसीएच, एनईएफटी, यूपीआई)	58,793	1,18,750	2,06,661	1,88,14,287	2,60,97,655	2,85,72,100
3. डेबिट अंतरण और सीधा डेबिट (भीम, आधार पे, ईसीएस, एनएसीएच, एनईटीसी)	3,788	6,382	8,957	3,99,300	6,56,232	8,26,036
4. कार्ड भुगतान (पीओएस टर्मिनलों और ऑनलाइन लेनदेन पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड)	47,486	61,769	73,012	9,19,035	11,96,888	15,35,765
5. प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	34,591	46,072	53,318	1,41,634	2,13,323	2,15,558
कुल डिजिटल भुगतान	1,45,902	2,34,339	3,43,455	13,69,86,734	16,38,52,285	16,23,05,934

स्रोत: भारिबैं वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20.

संलग्नक 2: विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य: भुगतान और निपटान प्रणाली के बारे में निर्णय

दिनांक	लिया गया निर्णय
फर 07, 2019	भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन
अप्रै 04, 2019	भारत की भुगतान प्रणालियों को बेंचमार्क करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
अप्रै 04, 2019	सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों और मुआवजे के समाधान के संबंध में लगने वाले समय को एकसमान बनाने हेतु फ्रेमवर्क को लागू करना।
जून 06, 2019	आरटीजीएस और एनईएफटी लेनदेन के लिए आरबीआई द्वारा लगाए गए शुल्क को हटाया जाना।
जून 06, 2019	एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति
अग 07, 2019	एनईएफटी की 24x7 उपलब्धता
अग 07, 2019	भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के लिए बिलर श्रेणियों का विस्तार
अग 07, 2019	भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू), व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली (ट्रेड्स), और व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) का 'ऑन-टैप' प्राधिकरण
अग 07, 2019	केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री का गठन
अक्टू 04, 2019	बड़े गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) निर्गमनकर्ताओं द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति (एक करोड़ से अधिक बकाया पीपीआई)
अक्टू 04, 2019	भुगतान संबंधी सूक्ष्म डेटा का प्रसार
अक्टू 04, 2019	टियर III-VI केंद्रों में कार्डों के माध्यम से डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ)
अक्टू 04, 2019	डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम जिले
दिसं 05, 2019	केवल बैंक खाते से लॉडिंग एवं केवल डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले मात्र ₹10,000 तक की खरीद हेतु एक नए पीपीआई का शुभारंभ ग्राहक के संबंध में केवल न्यूनतम जानकारी अपेक्षित।
दिसं 05, 2019	पहले, उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों के लिए एनबीएफसी-पी2पी समग्र सीमाएं ₹10 लाख होती थीं, जबकि किसी भी एक उधारकर्ता के प्रति किसी एक ऋणदाता के जोखिम की अधिकतम सीमा ₹50,000 थी। यह प्रस्ताव किया गया कि पी2पी ऋणदाता की सभी उधारकर्ताओं के प्रति समग्र जोखिम सीमा को बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया जाए।
दिसं 05, 2019	एटीएम स्विच एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं के साथ संविदात्मक करारों में विनियमित संस्थाओं द्वारा बेसलाइन साइबर सुरक्षा नियंत्रण अनिवार्य किया जाएगा।
फर 06, 2020	एक "डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स" (डीपीआई) का प्रकाशन
फर 06, 2020	डिजिटल भुगतान प्रणाली हेतु एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए एक रूपरेखा तैयार करना ताकि सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और कीमत निर्धारण आदि पर सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
फर 06, 2020	अखिल भारतीय चेक ट्रेंकेशन प्रणाली की स्थापना करना
अग 06, 2020	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का दायरा बढ़ाना जिससे स्टार्ट-अप को उसमें शामिल किया जा सके।
अग 06, 2020	कार्ड और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके ऑफलाइन खुदरा भुगतान की योजना
अग 06, 2020	डिजिटल भुगतानों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर)
अग 06, 2020	चेक के लिए निश्चय भुगतान प्रक्रिया
अग 06, 2020	रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र की स्थापना
अक्टू 09, 2020	तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) की चौबीसों घंटे उपलब्धता
अक्टू 09, 2020	भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्राधिकार प्रमाणपत्रों (सीओए) की वैधता को स्थायी बनाना

टिप्पणी: उपर्युक्त से संबंधित अद्यतन जानकारी भा. रि. बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में उपलब्ध है।

संलग्नक 3: कारोबारी मॉडलों के आधार पर भारतीय फिनटेक

कारोबारी मॉडल	कारोबारी मॉडल*	ब्योरा
निवेश टेक	990	विविध वित्तीय परिसंपत्तियों पर शोध और निवेश हेतु खुदरा और संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध मंच।
भुगतान	978	कंपनियां जो पारंपरिक वेब आधारित और ऑफलाइन भुगतान चक्र में भाग लेती हैं; भुगतान का वैकल्पिक मोड प्रदान करती हैं, और सुरक्षा, विश्लेषण, प्लेटफॉर्म, आदि से जुड़े मामलों में भुगतान कंपनियों का सहयोग करती हैं।
वित्त एवं लेखांकन टेक	906	संगठनों के वित्त और लेखा विभागों के कामकाज को स्वचालित बनाना।
वैकल्पिक उधार	702	ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म (बैलेंस शीट लेंडर्स, मार्केटप्लेस, पी 2 पी लेंडर्स के साथ-साथ लीड जनरेटर) और क्षमतावर्धक
बैंकिंग टेक	369	बैंकिंग उद्योग के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवाएं शामिल हैं।
क्रिप्टोकॉरेसियाँ	342	बिटकॉइन और अन्य डिजिटल मुद्रा उत्पाद तथा सेवाएं
क्राउडफंडिंग	185	ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां लोग, संगठन आम जनता से पैसा जुटाते हैं।
इंटरनेट फर्स्ट इंश्योरेंस प्लैटफॉर्मर्स	161	उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाने वाला प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म जिस पर वे अपने बीमा की खरीद और उसका प्रबंधन कर सकते हैं।
बीमा आईटी	98	मुख्य रूप से बीमा उद्योग के लिए सॉफ्टवेयर उत्पाद और डेटा समाधान
रेगटेक	95	मुख्य रूप से वित्तीय संस्थाओं और विनियामकों के लिए प्रौद्योगिकीय उत्पाद जिनकी सहायता से वे अधिक सक्षम तरीके से विनियमों का कार्यान्वयन और निगरानी कर सकें
रोबो एडवाइज़री	68	खुदरा निवेशकों के लिए स्वचालित, कम लागत वाली निवेश सेवाएं और स्वचालित निवेशों के लिए तकनीकी समाधान।
धन-प्रेषण	46	सीमा-पार धन अंतरण समाधान और सेवाएं
फॉरेक्स टेक	32	प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, जिनमें इंटरनेट-फर्स्ट प्लैटफॉर्मर्स तथा विदेशी मुद्रा बाजार हेतु सॉफ्टवेयर शामिल हैं।
इस्लामिक फिनटेक	7	इंटरनेट-फर्स्ट प्लैटफॉर्मर्स और शरिया-अनुपालक वित्त हेतु सॉफ्टवेयर
नियोक्ता बीमा	6	कर्मचारी बीमा लाभ के प्रबंधन हेतु विविध समाधान।

* स्रोत: ट्रैक्सन डेटाबेस. चूंकि कई कंपनियों के एक से अधिक कारोबारी मॉडल हैं, अतः कुल योग 4,680 से अधिक है।

संलग्नक 4: वर्ष 2019-20 के दौरान जुटायी गयी निधि के आधार पर शीर्ष भारतीय फिनटेक

रैंक	कंपनी	स्थापित	निधीयन चक्र	जुटायी गयी कुल राशि (मिलियन\$)	ब्योरा
1	पेटीएम	2010	सीरीज़ जी	1000	उपभोक्ता द्वारा भुगतान के लिए ऐप-आधारित वॉलेट
2	भारतपे	2017	सीरीज़ ए, बी, सी	154.3	क्यूआर कोड आधारित भुगतान ऐप
3	पॉलिसीबाजार	2008	सीरीज़ एफ	150	ऑनलाइन बीमा तुलना प्लैटफॉर्म
4	सीआरईडी	2018	सीरीज़ ए, बी	145.6	क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान हेतु रिवाईड आधारित प्लैटफॉर्म
5	खाताबुक	2016	एंजेल, सीड, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी	140.6	डिजिटल लेज़र खाता बही
6	एको	2017	सीरीज़ सी	101.6	प्रौद्योगिकी-समर्थित स्वचालित बीमा
7	जेस्टमनी	2015	सीरीज़ बी	30.47	ऑनलाइन प्लैटफॉर्म फॉर प्वाइंट ऑफ़ सेल फाइनेंसिंग
8	लेंडिंगकार्ट	2014	सीरीज़ सी, डी	87.87	एसएमई को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन प्लैटफॉर्म
9	इनक्रेड	2016	सीरीज़ ए	85.9	एसएमई, उपभोक्ता & वैयक्तिक, आवास तथा शिक्षा ऋण पर केंद्रित वैकल्पिक उधार प्लैटफॉर्म
10	पाइन लैब्स	1998	सीरीज़ सी	85	ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए पीओएस सॉफ्टवेयर समाधान
11	बिलडेस्क	2000	सीरीज़ सी	84.8	भुगतान गेटवे
12	डिजिट इश्योरेंस	2016	सीरीज़ सी	84.35	व्यक्तियों के लिए बीमा प्लैटफॉर्म

स्रोत: ट्रेक्सन डेटाबेस

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक	97
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	98
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	99
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	100
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	101
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	101
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	102
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	103
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	104
9	कुल चलनिधि राशियां	104
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	105
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	105
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	106
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	106
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	107
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	108
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	109
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	110
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	111
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	111
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	111
21	थोक मूल्य सूचकांक	112
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	116
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	116
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	117
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	117
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	118
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	119
28	वाणिज्यिक पत्र	119
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	119
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	120

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	121
32	विदेशी मुद्रा भंडार	121
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	121
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	122
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	122
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	123
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	123
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	124
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	125
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	126
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	127
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	128
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	129
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	131
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	132
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	133
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	134
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	135
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	136

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

— = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2019-20	2018-19	2019-20		2020-21
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	3.9	5.6	4.8	3.0	-22.8
1.1.1 कृषि	4.0	1.6	3.0	5.9	3.4
1.1.2 उद्योग	0.8	1.4	3.8	-0.01	-33.8
1.1.3 सेवाएं	5.0	8.3	5.5	3.5	-24.3
1.1क अंतिम खपत व्यय	6.3	7.3	5.6	4.2	-19.2
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-2.8	4.4	4.6	-6.5	-47.1
	2019-20	2019		2020	
	1	अग.	सित.	अग.	सित.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-0.8	-1.4	-4.6	-8.0	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	7.9	9.7	9.4	10.9	10.5
2.1.2 ऋण	6.1	10.2	8.8	5.5	5.1
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	6.1	10.1	8.7	5.5	5.1
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	10.6	2.1	7.1	21.8	20.3
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	9.4	13.1	12.0	14.7	14.4
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.9	9.8	9.6	12.6	12.2
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	18.75	18.75	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.6	4.9	4.8	3.7	3.6
3.4 ऋण-जमा अनुपात	76.4	75.7	75.7	72.1	72.0
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	60.3	-44.4	-0.9	-25.4	-14.3
3.6 निवेश-जमा अनुपात	27.6	28.0	28.6	30.7	31.1
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	36.2	96.5	93.3	101.9	100.6
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.40	5.40	5.40	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	4.00	5.15	5.15	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.65	5.65	5.65	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.65	5.65	5.65	4.25	4.25
4.5 आधार दर	8.15/9.40	8.95/9.40	8.95/9.40	7.40/9.00	7.40/9.00
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.40/7.90	7.90/8.40	7.80/8.30	6.65/7.20	6.65/7.15
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	5.90/6.40	6.35/7.10	6.25/7.00	5.00/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	3.00/3.50	3.25/3.50	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.05	5.36	5.31	3.43	3.41
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.36	5.41	5.41	3.24	3.36
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.97	5.63	5.50	3.49	3.58
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.94	5.72	5.60	3.59	3.73
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.71	6.70	6.85	6.12	6.04
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	74.84	71.76	70.84	73.35	73.73
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.64	79.24	77.32	87.07	86.04
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	8.98	3.85	3.98	3.76	3.74
3-माह (%)	5.93	4.18	3.95	3.90	3.80
6-माह (%)	5.05	4.24	4.23	4.01	3.91
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.76	3.3	4.0	6.7	7.3
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	7.54	6.3	7.0	5.6	5.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.69	1.2	0.3	0.2	1.3
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	6.77	6.5	5.5	1.6	5.1
6.3.2 ईंधन और पावर	-1.63	-3.5	-6.7	-9.7	-9.5
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	0.29	0.0	-0.4	1.3	1.6
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-7.66	-12.9	-12.0	-26.0	-19.6
7.2 निर्यात	-5.06	-6.5	-6.6	-12.6	6.0

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2019-20	2019	2020				
		अक्तू.	अक्तू. 2	अक्तू. 9	अक्तू. 16	अक्तू. 23	अक्तू. 30
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2412993	2231090	2653562	2675166	2679925	2688064	2688725
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	10	11	16	17	12	10	12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2413003	2231101	2653578	2675183	2679937	2688074	2688737
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	103439	89777	116725	116776	117374	118351	117206
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2308718	2140619	2535931	2557496	2561665	2568845	2570667
1.2.3 रुपया सिक्का	846	705	922	911	898	878	864
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1187409	830440	1332952	1360249	1396755	1428984	1439019
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	101	101	100	100	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	43	42	42	43	43	43
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	536186	548240	455586	439497	449669	437010	453999
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7603	4492	5382	5414	5188	5137	5623
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3445	2857	2632	2503	2580	2527	2405
2.1.1.7 अन्य बैंक	32641	32264	26454	26061	26083	25878	26036
2.1.1.8 अन्य	605100	241723	842640	886464	913041	958146	950693
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	2291	721	115	167	51	143	120
2.1.2 अन्य देयताएं	1350333	1093743	1379007	1381517	1388574	1411775	1424609
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2537742	1924183	2711959	2741766	2785329	2840759	2863628
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	10	11	16	17	12	10	12
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1006357	794682	1173132	1194115	1226227	1270748	1300811
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	50477	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1967	670	13169	15478	14867	6463	4190
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	285623	22273	119525	117467	115455	115451	115757
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	25142	25142	24237	24127	23320
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	10064	5716	12830	12840	12841	12853	12931
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	2300	721	11082	11083	4445	10409	10480
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1042951	994053	1203119	1210858	1231475	1243425	1239727
2.2.6 अन्य आस्तियां	137993	106057	153944	154766	155770	157273	156400
2.2.6.1 सोना	127644	102091	150127	150938	151710	152974	151494

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	विक्रय	क्रय	दीर्घावधि रिपो परिचालन	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	एनबीफसी/एचएफसीएस के लिए विशेष चलनिधि योजना **	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सितं.1, 2020	-	715178	-	-	104	-120	-	-	555	-	-	-	-	-714639
सितं.2, 2020	-	709520	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-709305
सितं.3, 2020	-	728123	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	492	-727626
सितं.4, 2020	-	687713	-	-	0	-	-	10000	7132	-	-	-	-	-690581
सितं.5, 2020	-	7255	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-7255
सितं.6, 2020	-	13	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-9
सितं.7, 2020	-	669621	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-669529
सितं.8, 2020	-	648065	-	-	1614	-	-	-	-	-	-	-	-	-646451
सितं.9, 2020	-	640443	-	-	990	-	-	-	770	-	-	-	-	-638683
सितं.10, 2020	-	640135	-	-	60	-	-	-	1980	-	-	-	98	-637997
सितं.11, 2020	1000##	630509	-	-	0	155	-	9900	10000	-	-	-	-	-629254
सितं.12, 2020	-	880	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-880
सितं.13, 2020	-	181	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-181
सितं.14, 2020	0##	591681	-	-	101	-	-	-	935	-24536	-	-	-	-615181
सितं.15, 2020	-	561810	-	-	0	-	-	-	2300	-25006	-	-	66	-584450
सितं.16, 2020	-	468946	-	-	6	-	-	-	1970	-24775	-	-	522	-491223
सितं.17, 2020	-	447539	-	-	70	-	-	-	1640	-24537	-	-	189	-470177
सितं.18, 2020	-	408353	-	-	4	-	-	10000	10000	-24718	-	-	550	-432517
सितं.19, 2020	-	19886	-	-	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-19621
सितं.20, 2020	-	332	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-332
सितं.21, 2020	-	365617	-	-	0	840	-	-	1960	-	-	-	-	-362817
सितं.22, 2020	-	411505	-	-	0	-	-	-	1755	-	-	-	49	-409701
सितं.23, 2020	-	406841	-	-	0	-	-	-	1335	-	-	-	-	-405506
सितं.24, 2020	-	424974	-	-	0	-	-	-	1205	-	-	-	373	-423396
सितं.25, 2020	-	436263	-	-	50	896	-	-	0	-	-	-	-	-435317
सितं.26, 2020	-	2353	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-2351
सितं.27, 2020	-	384	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-384
सितं.28, 2020	-	425051	-	-	9	15	-	-	2475	-	-	-	-	-422552
सितं.29, 2020	-	454917	-	-	1249	-	-	-	2800	-	-	-	20	-450848
सितं.30, 2020	-	486320	-	-	0	-	-	-	3620	-	-	-	551	-482149

नोट: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) शामिल हैं।

** 01 जुलाई 2020 के आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार

& Negative (-) sign indicates repayments done by Banks.

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		सित्त.	अग.	सित्त.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	45097	5614	5307	8172
1.1 क्रय (+)	72205	6514	8524	13322
1.2 विक्रय (-)	27108	900	3217	5150
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	312005	39595	39505	60803
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	45097	11351	34315	42487
(करोड़ ₹)	312005	75009	257164	317967
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-4939	-7483	10351	13881

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		सित्त.	अग.	सित्त.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7713	475	0	0
1.2 विक्रय (-)	7713	475	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-500	0	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	30 सितंबर 2020 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	1300	0	1300
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	4957	0	4957
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	16684	0	16684
4. 1 वर्ष से अधिक	960	10020	-9060
कुल (1+2+3+4)	23901	10020	13881

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2019-20	2019	2020					
		अक्तू. 25	मई 22	जून 19	जुला. 31	अग. 28	सितं. 25	अक्तू. 23
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	1262	4373	1400	310	80	300	50	6
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	10000	2800	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	4782	1884	1372	326	30	-	-	-
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	50000	50000	65000	65000	65000	65000
4.2 बकाया	-	-	21369	26894	34376	34166	37691	36488
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	6044	6257	24141	27530	34486	34466	37741	36494

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्जिम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2019-20	2019	2020		
		सितं. 27	अग. 28	सितं. 11	सितं. 25
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2349748	2089198	2583111	2600240	2585212
1.1 संचलन में नोट	2420964	2160124	2654096	2669875	2656476
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25605	25281	25708	25708	25708
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	97563	96950	97436	96086	97715
2 जनता की जमाराशियां	1776200	1557208	1702537	1680269	1739732
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1737692	1525227	1662573	1638205	1696910
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	31981	39964	42064	42822
3 एम₁ (1 + 2)	4125948	3646406	4285648	4280509	4324944
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	137494	150963	150963	150963
5 एम₂ (3 + 4)	4276911	3783900	4436611	4431472	4475907
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	12674016	12167762	13362349	13458611	13414790
7 एम₃ (3 + 6)	16799963	15814167	17647997	17739119	17739734
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	390764	433441	433441	433441
9 एम₄ (7 + 8)	17233404	16204931	18081438	18172560	18173175

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		सितं. 27	अग. 28	सितं. 11	सितं. 25
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	4837135	5613739	5617989	5518318
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	992192	936889	1015146	976999	836430
1.1.1 सरकार पर दावे	1047808	999374	1194026	1196995	1196304
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1045314	998915	1184993	1170380	1185788
1.1.1.2 राज्य सरकारें	2494	459	9033	26615	10516
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां	55616	62485	178880	219996	359874
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	55573	62443	178838	219954	359832
1.1.2.2 राज्य सरकारें	43	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3968170	3900246	4598593	4640990	4681888
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	10378946	10876306	10890235	10933906
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13166	8103	11565	13844	14740
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11025478	10370843	10864741	10876391	10919166
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10370861	9766854	10216227	10227647	10271581
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	637776	592065	638172	638153	637509
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	16842	11924	10342	10591	10076
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3801036	3266036	4202376	4209461	4230223
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	3590402	3048039	3957722	3964807	3985569
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	3590636	3048248	3957965	3965050	3985812
3.1.2 विदेशी देयताएं	234	209	243	243	243
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	210634	217997	244655	244655	244655
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26024	26451	26451	26451
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3026427	2693973	3070875	3005016	2969164
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1378342	1065938	1421949	1408599	1384384
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1648085	1628035	1648926	1596417	1584780
एम₃ (1+2+3+4-5)	16799963	15814167	17647997	17739119	17739734

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019		2020	
		सितं. 27	अग. 28	सितं. 11	सितं. 25
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4125948	3646406	4285648	4280509	4324944
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	9745776	9041399	10223166	10260713	10285434
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	16923893	15976308	17752801	17828409	17826693
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2089198	2583111	2600240	2585212
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	14226198	13514101	14857059	14927549	14942443
1.2.1 मांग जमाराशियां	1737692	1525227	1662573	1638205	1696910
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	12488506	11988874	13194485	13289343	13245533
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5619828	5394993	5937518	5980204	5960490
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	182922	88084	85476	73353
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6868678	6593881	7256967	7309139	7285043
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	31981	39964	42064	42822
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	309439	341028	272668	258557	256217
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16856406	16085854	17466357	17484106	17430220
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	4837135	5613739	5617989	5518318
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	992192	936889	1015146	976999	836430
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3968170	3900246	4598593	4640990	4681888
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11896044	11248719	11852618	11866117	11911902
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	13166	8103	36368	38291	40026
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11882878	11240616	11816250	11827826	11871876
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	846284	859018	940213	939977	940628
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26024	26451	26451	26451
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3612303	2995699	4067798	4099584	4110620
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3048039	3957722	3964807	3985569
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	21900	-52340	110076	134777	125051
2.4 पूंजी खाता	2670439	2385844	2828647	2840728	2811108
2.5 अन्य मदें (निवल)	900725	745425	979157	941004	929489

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2019-20	2019		2020	
		सितं.	जुला.	अग.	सितं.
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	16923893	15976308	17727030	17752801	17826693
2 डाकघर जमाराशियां	433441	390762	433441	433441	433441
3 एल₁ (1 + 2)	17357334	16367070	18160471	18186242	18260134
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	57479	2932	43663	40802	35344
4.1 सावधि मुद्रा उधार	7928	2656	8425	7940	3114
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	46249	31	31750	29300	28700
4.3 सावधि जमाराशियां	3302	245	3489	3561	3531
5 एल₂ (3 + 4)	17414812	16370002	18204134	18227044	18295478
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	31905
7 एल₃ (5 + 6)	17446717	16401907	18327383

टिप्पणी: नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देनदारियों पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019		2020	
		सितं. 27	अग. 28	सितं. 11	सितं. 25
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2186148	2680547	2696326	2682927
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	570065	472795	468067	463610
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	505131	532442	439411	434587	429915
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	31981	39964	42064	42822
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3029707	2788194	3193305	3206456	3189358
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	791299	780069	631082	623798	561723
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	992192	936889	1015146	976999	836430
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	989741	936472	1006155	950426	825956
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1044468	998152	1184242	1169645	1185063
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1044468	998152	1184242	1169645	1185063
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	846	763	751	735	725
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	55573	62443	178838	219954	359832
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	2451	417	8991	26573	10474
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-214059	-164923	-420432	-391492	-314733
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-214059	-164923	-395629	-367045	-289447
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	13166	8103	36368	38291	40026
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	5920	2373	-	-	-
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	24803	24447	25286
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26024	26451	26451	26451
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3048039	3957722	3964807	3985569
2.3.1 सोना	230527	190217	273025	279568	264971
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3359893	2857839	3684714	3685256	3720615
2.4 पूंजी खाता	1165066	950734	1254854	1253664	1223306
2.5 अन्य मदें (निवल)	213276	115204	167095	154935	161078

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

Item	मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
		2019-20	2019		2020			
			सितं. 27	अग. 28	सितं. 4	सितं. 11	सितं. 18	सितं. 25
		1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)		3029707	2788194	3193305	3216001	3206456	3220303	3189358
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा		2447312	2186148	2680547	2687356	2696326	2690467	2682927
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां		543888	570065	472795	488825	468067	487789	463610
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां		38507	31981	39964	39821	42064	42048	42822
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण		992192	936889	1015146	1037110	976999	848892	836430
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण		-214059	-164923	-395629	-414682	-367045	-258457	-289447
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण		13166	8103	11565	13530	13844	13844	14740
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां		3590402	3048039	3957722	3946000	3964807	3998255	3985569
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं		26348	26024	26451	26451	26451	26451	26451
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं		1378342	1065938	1421949	1392407	1408599	1408681	1384384

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		सितं. 27	अग. 28	सितं. 11	सितं. 25
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	13381983	12727573	14008954	14078775	14093146
1.1.1 मांग जमाराशियां	1617003	1408886	1541081	1516484	1576060
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11764979	11318687	12467873	12562291	12517086
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5294241	5093409	5610543	5653031	5632689
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	182922	88084	85476	73353
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6470739	6225278	6857330	6909260	6884397
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	309439	341028	272668	258557	256217
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14966910	14320681	15520259	15572082	15654684
2.1.1 सरकार को ऋण	3738696	3689379	4359336	4399674	4437464
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11228214	10631302	11160923	11172407	11217220
2.1.2.1 बैंक ऋण	10370861	9766854	10216227	10227647	10271581
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10319097	9706769	10150286	10163792	10205154
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11378	11018	11559	11721	12345
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8653	3374	1886	2025	1629
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	837321	850056	931250	931015	931666
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	21900	-52340	110076	134777	125051
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	315641	250991	364293	372587	361222
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	185510	178888	167864	169267	169257
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	108231	124442	86353	68542	66914
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	899410	784346	922291	887641	806963
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	536186	532442	439411	434587	429915
2.3.2 उपलब्ध नकदी	87260	86981	87251	86009	87601
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-275964	-164923	-395629	-367045	-289447
2.4 पूंजी खाता	1481202	1410939	1549623	1562893	1563631
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	715597	573146	721381	694274	673704
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	495445	407969	481042	479911	484513
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	65654	-44722	73801	73831	71093

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 27, 2020 की स्थिति	2019	2020		
		सितं. 27	अग. 28	सितं. 11	सितं. 25
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3747349	3692753	4361222	4401699	4439092
2 वाणिज्यिक पत्र	104526	93829	85249	86104	92022
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	14106	11508	11746	11758	11862
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	75415	66724	72540	72571	71294
3.3 अन्य	5734	5595	5032	5038	5037
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	125710	122282	124406	125448	123873
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	226559	251811	306420	305069	304478
4.3 अन्य	191690	187785	150313	150217	148503
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	35610	22829	44412	44620	40302
5.2 वित्तीय संस्थाएं	97665	87703	131117	130189	132981

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति									
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
	2019-20	2019		2020		2019-20	2019		2020	
		सित्त.	अग.	सित्त.	अग.		सित्त.	अग.	सित्त.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	219	219	209	209	142	142	133	133		
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	320240	267832	287863	282298	314513	262670	282629	277070		
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	239943	192431	222515	221020	234348	187729	217476	215993		
1.2 बैंकों से उधार राशि	64001	63486	49330	45238	64001	63163	49330	45238		
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16295	11916	16018	16040	16163	11777	15824	15839		
2 अन्य के प्रति देयताएं	14905949	14141052	15447179	15498954	14480607	13779901	15016838	15070047		
2.1 कुल जमाराशियां	13975551	13253770	14589173	14674557	13567492	12906461	14176793	14262404		
2.1.1 मांग	1653242	1440859	1576862	1611231	1617003	1408886	1541091	1576060		
2.1.2 मीयादी	12322309	11812911	13012311	13063326	11950489	11497575	12635702	12686343		
2.2 उधार	313908	344756	277321	260783	309439	341028	272668	256217		
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	616491	542526	580685	563614	603676	532412	567377	551427		
3 रिजर्व बैंक से उधार	285623	47478	253645	121530	285623	47478	253645	121495		
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 अन्य	285623	47478	253645	121530	285623	47478	253645	121495		
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	643038	634626	541243	531962	623446	619423	526662	517516		
4.1 उपलब्ध नकदी	89671	88943	89431	89708	87260	86981	87251	87601		
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	553367	545683	451812	442254	536186	532442	439411	429915		
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	323680	375036	279701	280685	260238	318410	219489	218322		
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	181460	264299	180377	187654	155401	237242	148257	153334		
5.1.1 चालू खाते में	17204	15901	14740	16431	14457	13081	12609	14410		
5.1.2 अन्य खातों में	164256	248397	165636	171224	140945	224162	135648	138924		
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	43335	37829	34222	33898	20273	20426	12448	11399		
5.3 बैंकों को अग्रिम	38266	28373	25023	21840	30531	25585	24494	21374		
5.4 अन्य आस्तियां	60619	44536	40080	37292	54032	35157	34290	32214		
6 निवेश	3865544	3791535	4488286	4571329	3747349	3692753	4361222	4439092		
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3850819	3781817	4479884	4563193	3738696	3689379	4359336	4437464		
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14724	9719	8401	8135	8653	3374	1886	1629		
7 बैंक ऋण	10705336	10052171	10546725	10602888	10370861	9768854	10216158	10271581		
7क खाद्यान्न ऋण	82172	87117	96346	96831	51763	60085	65941	66427		
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	10480934	9840009	10379425	10440066	10149509	9560550	10050841	10110780		
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	26214	25150	19412	20531	25658	24352	19148	20266		
7.3 देशी बिल - भुनाए गए	147209	128567	104517	95221	145683	126360	103201	94174		
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20866	24504	16559	18608	20458	24243	16317	18357		
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	30114	33940	26813	28463	29554	33348	26651	28004		

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2020
		सितं. 27	अग. 28	सितं. 25		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	9263134	8680216	9112035	9183525	-0.9	5.8
1.1 खाद्यान्न ऋण	51590	59887	65708	66204	28.3	10.5
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	9211544	8620329	9046327	9117321	-1.0	5.8
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1157796	1127794	1168075	1194488	3.2	5.9
1.2.2 उद्योग	2905151	2774883	2778672	2774867	-4.5	0.0
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	381825	361328	354546	360833	-5.5	-0.1
1.2.2.2 मझौले	105598	104989	107386	120210	13.8	14.5
1.2.2.3 बड़े	2417728	2308566	2316740	2293824	-5.1	-0.6
1.2.3 सेवाएं	2594945	2361867	2551467	2576254	-0.7	9.1
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	144466	142605	148575	147616	2.2	3.5
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20051	18772	20089	19828	-1.1	5.6
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	45977	40419	47282	48378	5.2	19.7
1.2.3.4 नौवहन	6557	5963	4987	5099	-22.2	-14.5
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	177085	171733	175191	175455	-0.9	2.2
1.2.3.6 व्यापार	552392	508039	567367	566336	2.5	11.5
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	263397	217325	265152	263499	0.0	21.2
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	288995	290714	302215	302837	4.8	4.2
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	229770	218088	230759	230025	0.1	5.5
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	807383	713510	796763	802552	-0.6	12.5
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	611264	542738	560454	580965	-5.0	7.0
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2553652	2355785	2548113	2571712	0.7	9.2
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	9298	5445	9053	6661	-28.4	22.3
1.2.4.2 आवास	1338964	1253190	1349501	1359824	1.6	8.5
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	79496	64192	62568	63167	-20.5	-1.6
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5334	5105	6313	6325	18.6	23.9
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	108094	99372	104833	105640	-2.3	6.3
1.2.4.6 शिक्षा	65745	68229	64865	65146	-0.9	-4.5
1.2.4.7 वाहन ऋण	220609	203446	219769	221388	0.4	8.8
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	726112	656806	731211	743561	2.4	13.2
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2897461	2759852	2842996	2884154	-0.5	4.5
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1146624	1118871	1154411	1180052	2.9	5.5
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1149394	1056600	1104504	1127110	-1.9	6.7
1.2अ.2.1 विनिर्माण	381826	361328	354546	360833	-5.5	-0.1
1.2अ.2.2 सेवाएं	767568	695272	749958	766277	-0.2	10.2
1.2अ.3 आवास	449945	454566	473151	464642	3.3	2.2
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	38237	32077	32139	32333	-15.4	0.8
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	51906	53921	52013	51898	-0.0	-3.8
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	388	410	443	515	32.7	25.6
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	731409	696626	743473	743792	1.7	6.8
1.2अ.8 निर्यात ऋण	16114	14454	13959	14831	-8.0	2.6

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2020
			सितं. 27	अग. 28		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	2905151	2774883	2778672	2774867	-4.5	0.0
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	43927	41380	41419	41366	-5.8	0.0
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	154146	142388	155228	148446	-3.7	4.3
1.2.1 चीनी	27382	27424	21348	20783	-24.1	-24.2
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19240	17923	18156	18412	-4.3	2.7
1.2.3 चाय	5375	5558	5373	5587	3.9	0.5
1.2.4 अन्य	102149	91483	110351	103664	1.5	13.3
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	16522	14973	14430	14961	-9.4	-0.1
1.4 वस्त्र	192424	186773	188159	188917	-1.8	1.1
1.4.1 सूती वस्त्र	89283	84020	85318	84905	-4.9	1.1
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2116	2168	2059	2420	14.4	11.6
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26074	25295	26792	26996	3.5	6.7
1.4.4 अन्य वस्त्र	74951	75290	73990	74596	-0.5	-0.9
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11098	11044	11809	11856	6.8	7.4
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	12233	12082	12792	13039	6.6	7.9
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	30965	29973	32742	33118	7.0	10.5
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	75834	53576	54850	60536	-20.2	13.0
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	202949	180523	173975	175174	-13.7	-3.0
1.9.1 उर्वरक	49066	36835	35383	34167	-30.4	-7.2
1.9.2 औषधि और दवाइयां	53427	49177	48558	50111	-6.2	1.9
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	42233	39110	36176	35851	-15.1	-8.3
1.9.4 अन्य	58223	55401	53858	55045	-5.5	-0.6
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	50415	47007	48780	49187	-2.4	4.6
1.11 कांच और कांच के सामान	8777	9387	8666	8989	2.4	-4.2
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	58689	60809	57809	58324	-0.6	-4.1
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	350325	354021	344005	343016	-2.1	-3.1
1.13.1 लोहा और स्टील	262396	269955	256866	252654	-3.7	-6.4
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	87929	84066	87139	90362	2.8	7.5
1.14 सभी अभियांत्रिकी	157259	163374	139390	140249	-10.8	-14.2
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	30159	35168	27558	27706	-8.1	-21.2
1.14.2 अन्य	127100	128206	111832	112543	-11.5	-12.2
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	82606	83038	89286	90109	9.1	8.5
1.16 रत्न और आभूषण	59515	65637	54220	55619	-6.5	-15.3
1.17 निर्माण	104288	100074	103744	104600	0.3	4.5
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1053913	1003786	1023148	1015238	-3.7	1.1
1.18.1 पावर	559774	557170	549080	551886	-1.4	-0.9
1.18.2 दूरसंचार	143760	115017	125386	114825	-20.1	-0.2
1.18.3 सड़क	190676	185293	196875	198304	4.0	7.0
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	159703	146306	151807	150223	-5.9	2.7
1.19 अन्य उद्योग	239266	215038	224220	222123	-7.2	3.3

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

I मद्	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2019-20	2019	2020						
		अग. 30	जून 19	जुला. 26	जुला. 03	जुला. 17	जुला. 31	अग. 14	अग. 28
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	31	31	31	31	31	31	31
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	124101.8	64114.5	126309.6	126689.0	126452.9	127076.2	126359.1	125939.1	126547.5
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	26213.8	18923.0	24214.0	23797.4	25074.2	25271.3	24479.1	24074.5	24751.6
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5295.0	5228.2	4365.2	4100.6	4876.4	4823.2	4000.0	3821.7	3773.1
2.1.1.2 अन्य	14,523.6	10115.9	13836.4	13675.2	13533.9	13870.4	13837.0	13677.4	14264.3
2.1.2 बैंकों से उधार	100.0	0.0	199.9	110.0	0.0	0.0	268.7	135.0	264.9
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	6295.2	3579.0	5812.5	5911.7	6663.9	6577.6	6373.3	6440.4	6449.2
2.2 मीयादी देयताएं	167684.5	107029.1	177293.4	177574.4	176605.2	176793.3	174061.7	172745.5	171640.9
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	56564.0	52121.4	62670.0	62430.6	62166.3	61276.4	59247.7	58983.7	57209.2
2.2.1.2 अन्य	109578.2	53998.7	112473.2	113013.8	112919.0	113205.8	112522.0	112261.6	112283.2
2.2.2 बैंकों से उधार	630.2	54.5	635.1	630.0	629.9	629.9	629.9	629.9	629.9
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	912.1	854.5	1515.1	1500.1	890.0	1681.1	1662.1	870.2	1518.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	52772.2	42816.5	54148.6	55983.2	55890.4	56131.0	57274.5	57354.0	53795.3
4.1 मांग	13764.4	14751.5	11750.2	12464.4	12098.1	12152.6	14236.6	14067.2	13174.5
4.2 मीयादी	39007.8	28065.1	42398.4	43518.8	43792.3	43978.5	43037.9	43286.7	40620.8
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	9428.2	5387.6	7247.2	7422.0	6999.4	7149.1	7112.2	6875.5	6841.4
5.1 उपलब्ध नकदी	750.5	331.4	751.6	710.0	685.9	677.3	552.6	572.4	592.3
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	8677.8	5056.2	6495.6	6712.1	6313.4	6471.7	6559.6	6303.2	6249.1
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1521.7	1078.9	2099.1	2019.9	1049.6	1134.0	965.4	809.9	807.4
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	50626.9	30940.3	53092.2	53708.4	55424.4	55598.4	56888.2	58199.1	55743.6
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	25283.9	16766.5	29405.7	29380.8	29114.7	28181.5	25336.5	25269.1	25414.9
9 बैंक ऋण (10.1+11)	110905.5	62585.4	112198.2	111349.3	110067.3	111344.7	112074.1	112631.8	113285.8
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	110901.5	62584.1	112197.6	111348.7	110066.6	111344.0	112073.4	112631.2	113285.2
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	81300.1	74819.4	79958.6	80858.7	80854.4	81068.7	80109.4	79793.4	77827.8
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	4.0	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2019-20			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	सित्त.'19	अग.'20	सित्त.'20(अ)	सित्त.'19	अग.'20	सित्त.'20(अ)	सित्त.'19	अग.'20	सित्त.'20(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	146.3	149.6	147.5	145.5	156.1	159.6	149.5	161.3	164.3	147.0	158.0	161.3
1.1 अनाज और उत्पाद	140.7	143.2	141.4	140.1	146.9	146.0	142.7	151.5	150.6	140.9	148.4	147.5
1.2 मांस और मछली	163.3	161.4	162.6	161.9	183.9	186.6	158.7	193.1	193.8	160.8	187.1	189.1
1.3 अंडा	142.1	145.7	143.5	138.3	149.5	159.0	141.6	157.3	164.7	139.6	152.5	161.2
1.4 दूध और उत्पाद	146.5	146.0	146.3	145.7	153.4	153.6	144.9	153.9	153.6	145.4	153.6	153.6
1.5 तेल और चर्बी	127.1	121.8	125.1	125.1	140.4	142.6	120.8	134.4	135.7	123.5	138.2	140.1
1.6 फल	144.0	148.8	146.2	143.8	147.0	147.4	149.8	155.4	155.7	146.6	150.9	151.3
1.7 सब्जी	163.5	187.8	171.7	163.4	178.8	200.5	192.4	202.0	225.9	173.2	186.7	209.1
1.8 दाल और उत्पाद	133.7	132.0	133.1	132.2	149.3	150.3	130.3	150.8	152.2	131.6	149.8	150.9
1.9 चीनी और उत्पाद	112.0	113.4	112.5	112.8	115.1	115.0	114.0	118.9	117.9	113.2	116.4	116.0
1.10 मसाले	145.6	145.1	145.5	144.2	160.0	160.9	143.8	160.9	161.3	144.1	160.3	161.0
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	138.8	130.2	135.2	138.5	145.4	147.3	130.0	137.7	139.2	135.0	142.2	143.9
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	157.6	156.7	157.2	157.2	161.6	162.0	156.4	164.4	164.6	156.8	162.9	163.2
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	166.3	169.0	167.0	165.7	182.9	183.0	168.6	188.7	188.8	166.5	184.4	184.5
3 कपड़ा और जूते	151.3	143.7	148.3	151.0	154.6	155.1	143.3	148.1	148.3	147.9	152.0	152.4
3.1 कपड़ा	152.0	145.7	149.5	151.7	155.4	155.8	145.3	150.2	150.5	149.2	153.4	153.7
3.2 जूते	146.9	132.4	140.9	146.6	149.9	150.6	132.2	136.3	136.1	140.6	144.3	144.6
4 आवास	--	152.2	152.2	--	--	--	152.2	156.3	156.5	152.2	156.3	156.5
5 ईंधन और लाइट	148.6	131.5	142.2	146.9	146.4	146.9	126.6	137.2	137.2	139.2	142.9	143.2
6 विविध	145.6	135.9	140.9	145.4	153.7	154.3	135.7	146.0	146.2	140.7	150.0	150.4
6.1 घरेलू सामान और सेवा	150.6	138.7	145.0	150.3	151.6	152.1	138.3	145.4	145.2	144.6	148.7	148.8
6.2 स्वास्थ्य	153.6	142.1	149.3	153.4	159.1	159.6	141.9	150.0	150.9	149.0	155.6	156.3
6.3 परिवहन और संचार	132.6	122.2	127.1	131.6	144.6	146.3	121.2	135.1	135.5	126.1	139.6	140.6
6.4 मनोरंजन	148.3	135.9	141.3	148.3	152.8	152.4	135.9	141.8	142.1	141.3	146.6	146.6
6.5 शिक्षा	159.8	150.9	154.5	160.2	161.1	162.6	151.6	154.9	155.7	155.2	157.5	158.6
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	139.2	138.4	138.9	140.2	157.4	156.2	139.0	159.8	158.0	139.7	158.4	156.9
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	147.3	145.1	146.3	146.7	155.4	157.6	144.7	154.0	155.2	145.8	154.7	156.5

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2019-20	2020		
				सित्त.	अग.	सित्त.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	-	-	-	118
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	980	976	1026	1037
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	986	983	1033	1043

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2019-20	2019		2020	
		सित्त.	अग.	सित्त.	अग.
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	37018	37927	52917	50784	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42514	46682	67717	63337	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			सितं.	जुला.	अग. (अ)	सितं. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	121.8	121.3	121.0	121.7	122.9
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	143.3	143.0	145.1	146.3	150.3
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	155.8	155.4	161.3	162.1	168.1
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.6	160.1	161.1	159.5	158.3
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	174.7	175.2	181.8	187.4	210.0
1.1.1.3 दूध	4.440	146.7	145.7	152.1	152.1	153.8
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	147.0	144.7	151.9	153.4	150.7
1.1.1.5 मसाले	0.529	143.9	145.1	143.0	143.8	149.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.0	143.0	164.7	157.7	172.1
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	128.7	126.8	123.8	127.9	126.7
1.1.2.1 फाइबर	0.839	128.2	129.4	116.0	118.9	121.2
1.1.2.2 तिलहन	1.115	151.4	154.5	154.1	155.7	155.5
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	104.8	104.2	104.8	104.8	104.6
1.1.2.4 फूल	0.204	238.0	181.7	173.3	235.0	203.4
1.1.3 खनिज	0.833	154.5	154.8	166.5	166.3	166.5
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	147.4	149.8	160.6	162.5	160.6
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	179.0	172.3	187.0	179.7	187.0
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	85.3	88.0	71.0	71.0	72.0
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	102.2	100.6	90.7	91.4	91.0
1.2.1 कोल	2.138	125.3	124.8	126.4	126.4	126.4
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	138.1	136.5	141.6	141.6	141.6
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	129.1	129.9	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	92.3	90.5	77.1	78.2	77.7
1.2.3 बिजली	3.064	111.8	110.0	101.0	101.0	101.0
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	118.3	117.9	118.7	119.3	119.8
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	133.9	134.1	137.8	138.7	140.0
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.5	136.8	135.3	135.2	138.0
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	136.1	141.5	137.0	136.7	146.1
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	113.7	119.6	119.8	119.7
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	119.3	115.7	130.1	133.7	136.7
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	145.0	145.6	145.9	144.3	145.3
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	146.3	147.5	144.2	144.1	143.7
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	135.5	138.0	112.6	110.4	106.6
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	133.5	132.9	137.6	137.8	137.8
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.3	120.2	120.5	120.0	119.7
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	127.2	127.6	128.2	127.5	127.5
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.7	137.9	132.1	134.4	132.4
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	139.7	144.0	171.6	174.3	179.5
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	132.4	131.9	145.9	145.8	146.0
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	128.7	127.9	130.2	133.6	134.0
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	159.9	165.1	144.3	146.8	143.2
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	173.6	179.9	167.4	168.3	171.1
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	123.6	123.9	125.0	125.1	124.6
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	117.8	118.3	121.1	120.6	120.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	125.7	126.8	126.6	126.7	127.1
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	130.5	129.8	129.7	130.4	129.0
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	153.4	154.6	157.6	155.2	157.9
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	153.4	154.6	157.6	155.2	157.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			सितं.	जुला.	अग. (अ)	सितं. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.7	117.6	112.9	113.1	113.4
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	107.9	107.9	100.6	100.3	101.2
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	130.1	129.1	127.1	128.0	127.8
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	114.5	115.9	114.4	114.9	114.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	134.5	135.6	131.0	131.3	131.0
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.1	142.1	150.2	149.0	154.8
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.8	117.8	116.8	119.1	114.5
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.3	138.8	136.4	136.4	138.1
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.2	139.4	137.8	137.2	137.8
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	135.9	137.0	132.6	134.3	138.8
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	118.6	118.6	117.7	118.3	118.1
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	105.5	104.8	102.1	102.5	102.4
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	136.3	135.3	138.5	137.9	138.4
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.3	120.8	119.7	120.8	120.3
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	133.7	134.1	134.3	134.7	134.6
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.2	120.0	120.2	119.1	118.4
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	135.5	135.2	136.8	137.2	136.6
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	176.2	176.1	180.2	188.0	188.2
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	131.8	124.7	124.6	127.5
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.1	120.7	119.9	119.6	119.8
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	125.0	125.0	121.4	121.3	121.6
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	115.0	113.4	119.5	118.7	119.9
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	121.2	121.2	117.9	117.9	116.8
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	150.6	149.9	152.7	153.3	155.1
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	150.6	149.9	152.7	153.3	155.1
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	117.5	117.7	115.9	115.8	116.0
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	119.9	120.3	114.5	114.8	114.7
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.1	123.1	123.4	123.5	123.2
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	112.4	113.7	111.1	111.3	112.7
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	122.6	122.8	124.2	124.6	124.8
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.7	114.3	113.1	112.6	114.0
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	118.6	118.3	119.8	119.7	119.3
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	114.2	113.7	113.6	112.5	112.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	97.9	98.1	90.8	88.4	88.4
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	127.3	125.8	130.0	130.2	129.2
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	127.3	125.8	130.0	130.2	129.2
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	108.5	108.2	107.3	107.5	108.7
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	99.2	97.8	97.5	97.7
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.5	94.1	92.1	91.6	91.7
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	115.4	114.8	114.2	114.8	116.7
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	116.7	116.9	117.3	117.2	116.8
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	124.5	123.1	126.0	127.5	128.3
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	108.7	109.6	109.1	108.1	108.9
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	102.8	102.7	105.3	107.0	107.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	113.9	114.5	108.6	106.9	107.9
1.3.13.5 सीमेन्ट, गूना और प्लास्टर	1.645	119.5	119.9	121.5	120.9	119.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			सित्त.	जुला.	अग. (अ)	सित्त. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.6	121.2	124.7	126.1	124.1
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	120.2	119.1	119.3	119.6	120.4
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	86.6	89.8	77.6	77.6	77.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	106.2	104.4	103.8	106.5	107.9
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	100.6	95.5	96.4	101.5	103.6
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	107.7	103.9	101.0	109.2	110.8
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	95.1	93.5	94.9	97.5	97.3
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	105.5	103.4	102.8	103.9	105.8
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	108.7	106.4	105.4	109.0	112.1
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	102.8	99.6	101.2	102.6	103.2
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	102.9	101.0	103.3	102.8	105.6
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.2	124.8	123.3	125.1	123.6
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.0	106.9	107.2	109.2	110.6
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	112.8	114.2	106.5	108.1	107.4
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	146.5	149.2	146.1	145.1	144.3
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.5	115.3	113.3	113.2	113.3
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	113.9	113.6	111.4	110.8	110.0
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	124.4	123.4	121.7	120.6	122.2
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	104.7	106.0	99.0	99.0	99.0
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	100.5	100.2	95.9	98.4	99.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	100.5	100.5	101.7	101.9	102.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	124.0	124.2	123.7	123.6	122.9
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	110.4	109.9	109.6	109.1	109.1
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	98.1	97.9	97.5	97.2	96.8
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.0	135.1	135.1	135.1	135.1
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	117.0	117.6	114.8	114.2	114.3
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.8	97.3	99.1	98.0	97.9
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	111.5	112.9	106.0	106.0	106.1
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	139.1	136.5	141.7	141.9	142.9
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.6	102.8	103.5	103.5	103.0
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	110.2	109.5	112.1	108.8	111.2
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.3	110.6	112.6	113.0	112.2
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	109.0	107.7	114.0	114.5	112.5
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.0	116.8	116.3	117.0	116.9
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	109.9	105.0	93.7	93.0	93.3
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	109.7	109.5	110.9	111.6	113.3
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	111.9	110.5	110.9	110.0
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.9	120.7	118.2	118.3	118.6
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	108.7	107.7	108.4	107.3
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	113.1	113.6	112.9	113.6	113.7
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.8	105.2	104.9	106.2	104.4
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.9	120.1	117.4	118.2	119.6
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.2	111.7	110.8	112.2	111.2
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	110.1	109.6	110.6	109.2	111.8
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.0	80.0	81.5	81.6	81.9
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	111.5	112.4	112.0	111.8	113.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			सित्त.	जुला.	अग. (अ)	सित्त. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	130.9	135.2	127.9	128.2	127.8
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	120.6	121.1	120.6	121.5	121.7
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.1	108.8	108.3	107.7	108.7
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.1	74.2	75.1	75.3	75.2
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	125.2	121.5	125.7	128.1	128.3
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.7	122.3	121.9	123.9	122.3
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	126.3	126.5	126.9	127.2	128.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.0	66.6	64.6	64.3	64.4
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	114.5	113.7	117.3	116.9	117.5
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	115.2	114.7	118.7	117.6	118.5
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	113.7	112.6	115.9	116.1	116.4
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	118.0	117.9	125.6	125.7	126.3
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	106.4	106.7	105.7	105.8	105.8
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	114.3	114.3	124.0	124.1	124.9
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	128.9	128.0	128.7	128.7	128.9
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	126.1	125.7	127.4	127.5	127.5
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	130.9	131.1	127.7	128.2	129.5
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	130.9	131.1	127.7	128.2	129.5
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	112.7	114.1	134.1	135.6	136.1
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	109.9	111.3	132.4	134.0	134.5
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.0	176.0	166.5	159.1	163.0
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	129.7	129.2	130.9	130.9	131.1
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	136.9	136.0	143.9	144.2	142.6
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	162.1	162.4	167.3	167.5	166.9
2 खाद्य सूचकांक	24.378	147.6	147.4	152.5	153.3	157.6

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2018-19	2019-20	अप्रैल-अगस्त		अगस्त	
				2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	130.1	129.0	129.8	97.4	126.2	116.1
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	107.9	109.6	103.3	84.5	92.0	83.0
1.2 विनिर्माण	77.63	131.5	129.6	130.6	94.1	128.4	117.4
1.3 बिजली	7.99	156.9	158.4	169.9	152.3	165.7	162.7
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	126.1	127.0	127.1	106.1	121.9	108.4
2.2 पूंजीगत माल	8.22	108.4	93.3	96.5	50.4	88.7	75.0
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	126.2	137.7	135.1	96.8	135.9	126.6
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	141.7	136.6	138.3	95.7	130.7	127.7
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	130.4	119.0	126.6	66.8	122.0	109.4
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.5	145.3	143.8	130.9	144.4	139.6

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-सितंबर			
	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2020-21	2019-20
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	2020926	550782	816467	27.3	41.6
1.1 कर राजस्व (निवल)	1635909	458508	607429	28.0	36.8
1.2 करेतर राजस्व	385017	92274	209038	24.0	66.7
2 पूंजीगत प्राप्ति	224967	14635	20598	6.5	17.2
2.1 ऋण की वसूली	14967	8854	8239	59.2	55.6
2.2 अन्य प्राप्ति	210000	5781	12359	2.8	11.8
3 कुल प्राप्ति (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	2245893	565417	837065	25.2	40.2
4 राजस्व व्यय	2630145	1313574	1301082	49.9	53.2
4.1 ब्याज भुगतान	708203	305652	270696	43.2	41.0
5 पूंजी व्यय	412085	165836	187537	40.2	55.4
6 कुल व्यय (4+5)	3042230	1479410	1488619	48.6	53.4
7 राजस्व घाटा (4-1)	609219	762792	484615	125.2	99.9
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	796337	913993	651554	114.8	92.6
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	88134	608341	380858	690.2	879.8

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2020-21

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2019		2020				
		सितं. 27	अग. 21	अग. 28	सितं. 4	सितं. 11	सितं. 18	सितं. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	10165	24901	9209	8100	5564	4544	11608	13536
1.2 प्राथमिक व्यापारी	9190	10155	15931	17932	22066	32928	23928	32019
1.3 राज्य सरकारें	8173	70211	42164	44094	48959	49959	49459	55395
1.4 अन्य	48004	70022	160782	157140	152897	140950	140450	127184
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	66419	77199	171880	170892	173239	179260	181249	181537
2.2 प्राथमिक व्यापारी	43302	48024	65468	63853	65689	65867	64214	65936
2.3 राज्य सरकारें	13386	8104	4453	4348	4368	4383	4383	4323
2.4 अन्य	22465	27026	99218	110486	113920	113885	113341	114302
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	49660	62849	135072	133144	131928	135225	135202	133861
3.2 प्राथमिक व्यापारी	70672	67912	84137	93620	99594	111621	114334	125921
3.3 राज्य सरकारें	11945	18060	17526	16676	17890	16576	16576	16502
3.4 अन्य	70576	53578	133781	132012	133019	123667	127297	122943
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	155112	131653	134404	138620	86211	73694	71851	102540
4.4 अन्य	617	375	659	687	568	829	765	604
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	423957	538041	939620	952296	969134	978865	982041	993460

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य	संख्या	कुल अंकित मूल्य					
									प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
अग. 26	12000	105	90881	4045	20	11996	4045	16041	99.20	3.2367
सितं. 2	12000	110	64625	6341	16	11999	6341	18340	99.21	3.1939
सितं. 9	12000	80	49026	3494	23	11996	3494	15490	99.20	3.2294
सितं. 16	12000	75	38550	8303	31	11997	8303	20300	99.18	3.3195
सितं. 23	12000	84	29965	12332	41	11997	12332	24330	99.17	3.3578
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
अग. 26	13000	91	43819	0	51	13000	0	13000	98.29	3.4889
सितं. 2	13000	115	50527	0	48	13000	0	13000	98.30	3.4600
सितं. 9	13000	136	31763	0	109	13000	0	13000	98.28	3.5200
सितं. 16	13000	119	35500	0	68	13000	0	13000	98.26	3.5462
सितं. 23	13000	101	33086	6	63	12994	6	13000	98.25	3.5779
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
अग. 26	10000	83	31265	0	43	10000	0	10000	96.54	3.5891
सितं. 2	10000	78	27130	1100	33	10000	1100	11100	96.56	3.5692
सितं. 9	10000	71	24714	0	49	10000	0	10000	96.51	3.6300
सितं. 16	10000	91	29230	0	63	10000	0	10000	96.45	3.6897
सितं. 23	10000	81	24373	0	50	10000	0	10000	96.41	3.7312

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1	2	2
सितं.	1, 2020	1.80-4.10	3.42
सितं.	2, 2020	1.80-4.10	3.42
सितं.	3, 2020	1.80-4.05	3.42
सितं.	4, 2020	1.80-4.05	3.39
सितं.	5, 2020	2.15-3.95	2.63
सितं.	7, 2020	1.80-4.10	3.41
सितं.	8, 2020	1.80-4.05	3.39
सितं.	9, 2020	1.80-4.05	3.42
सितं.	10, 2020	1.80-4.05	3.41
सितं.	11, 2020	1.50-4.05	3.41
सितं.	14, 2020	1.80-4.00	3.42
सितं.	15, 2020	1.80-4.05	3.41
सितं.	16, 2020	1.80-4.00	3.40
सितं.	17, 2020	1.80-4.05	3.43
सितं.	18, 2020	1.80-4.00	3.40
सितं.	19, 2020	2.40-3.80	3.41
सितं.	21, 2020	1.80-4.00	3.42
सितं.	22, 2020	1.80-4.00	3.40
सितं.	23, 2020	1.80-4.00	3.42
सितं.	24, 2020	2.00-4.00	3.43
सितं.	25, 2020	1.50-4.00	3.40
सितं.	28, 2020	1.80-4.00	3.42
सितं.	29, 2020	1.80-3.90	3.40
सितं.	30, 2020	1.80-4.00	3.42
अक्तू.	1, 2020	1.80-3.90	3.40
अक्तू.	3, 2020	2.50-3.30	2.67
अक्तू.	5, 2020	1.80-4.00	3.41
अक्तू.	6, 2020	1.80-3.90	3.43
अक्तू.	7, 2020	1.80-3.90	3.44
अक्तू.	8, 2020	1.80-3.90	3.43
अक्तू.	9, 2020	1.50-3.90	3.39
अक्तू.	12, 2020	1.80-3.90	3.41
अक्तू.	13, 2020	1.80-3.90	3.39
अक्तू.	14, 2020	1.80-3.90	3.41
अक्तू.	15, 2020	1.80-3.85	3.40

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2019	2020			
	सितं. 27	अग. 14	अग. 28	सितं. 11	सितं. 25
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	188101.00	99835.00	90410.00	87710.00	75570.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	25997.21	1358.53	3502.17	617.75	6492.55
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.30-6.76	3.66-6.19	3.44-6.37	4.07-4.40	3.51-5.75

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2019	2020			
	सितं. 30	अग. 15	अग. 31	सितं. 15	सितं. 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	459742.10	380587.65	372600.80	418270.55	362310.10
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	94892.90	61152.00	68405.75	106924.35	86727.40
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.30-11.99	3.31-11.79	3.17-13.14	3.10-8.87	3.32-11.86

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2019	2020					
		सितं. 27	अग. 21	अग. 28	सितं. 4	सितं. 11	सितं. 18	सितं. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	26815	34535	23599	19387	16962	22402	19386	20575
2 नोटिस मुद्रा	3660	662	426	5150	4592	311	5988	382
3 मीयादी मुद्रा	790	660	936	492	636	367	827	857
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	300691	250695	413808	420081	339659	287427	352176	310900
5 बाजार रिपो	221719	167207	319124	388951	316977	305622	364146	309908
6 कापॉरेट बांड में रिपो	2468	871	560	300	2020	518	436	4666
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	82200	53940	63978	59780	49525	48919	52906
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	93960	97160	62320	69966	88596	61854	59775	44251
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5800	8198	3397	3552	4984	4415	3768	3902
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3720	9037	502	4053	4713	3753	11096	13686
10.2 182-दिवसीय	2380	3621	9678	9139	4107	4483	7513	6978
10.3 364-दिवसीय	2900	6024	1892	2105	1591	2263	2215	1373
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	2310		3228					
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	111070	124040	81017	88815	103991	76768	84366	70190
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	355	445	4457	3779	4953	5606	2059

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2019-20		2019-20 (अप्रै.-सित्त.)		2020-21 (अप्रै.-सित्त.)*		सित्त. 2019		सित्त. 2020*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	72	64926	42	58998	24	76882	5	34	5	1723
1ए प्रीमियम	70	43259	42	37684	24	73568	5	24	5	1623
1.1 पब्लिक	57	9867	33	7978	13	16892	5	34	3	1353
1.1.1 प्रीमियम	55	9434	33	7851	13	14317	5	24	3	1282
1.2 राइट्स	15	55059	9	51020	11	59990	—	—	2	370
1.2.1 प्रीमियम	15	33825	9	29833	11	59251	—	—	2	341
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 बांड और डिबेंचर	34	14984	20	7793	5	882	4	495	—	—
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	34	14984	20	7793	5	882	4	495	—	—
3.1.1 पब्लिक	34	14984	20	7793	5	882	4	495	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 कुल (1+2+3)	106	79910	62	66791	29	77764	9	530	5	1723
4.1 पब्लिक	91	24851	53	15771	18	17773	9	530	3	1353
4.2 राइट्स	15	55059	9	51020	11	59990	—	—	2	370

टिप्पणी: अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2019-20	2019		2020			
			सितं.	मई	जून	जुला.	अग.	सितं.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2219854	185642	145128	165935	177271	169563	202694
	मिलियन अमरीकी डॉलर	313361	26024	19182	21912	23638	22708	27584
1.1 तेल	करोड ₹	292340	24527	12900	13949	13253	14304	26501
	मिलियन अमरीकी डॉलर	41289	3438	1705	1842	1767	1916	3615
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1927514	161115	132228	151987	164019	155259	176193
	मिलियन अमरीकी डॉलर	272072	22586	17477	20070	21871	20792	23970
2 आयात	करोड ₹	3360954	268891	172505	161322	213524	220082	222708
	मिलियन अमरीकी डॉलर	474709	37695	22800	21303	28472	29473	30308
2.1 तेल	करोड ₹	925168	64816	26610	37496	48974	48095	42812
	मिलियन अमरीकी डॉलर	130550	9086	3517	4951	6530	6441	5826
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2435787	204075	145896	123826	164550	171987	179896
	मिलियन अमरीकी डॉलर	344159	28609	19283	16352	21942	23032	24482
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1141100	-83249	-27377	4613	-36253	-50520	-20014
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-161348	-11670	-3618	609	-4834	-6766	-2724
3.1 तेल	करोड ₹	-632828	-40289	-13709	-23547	-35722	-33792	-16311
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-89262	-5648	-1812	-3109	-4763	-4525	-2212
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-508273	-42960	-13668	28161	-531	-16728	-3703
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-72087	-6022	-1806	3719	-71	-2240	-512

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2019	2020					
			अक्तू. 11	सितं. 4	सितं. 11	सितं. 18	सितं. 25	अक्तू. 2
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	3124442	3964198	3982893	4003182	3989568	3990840	4034267
	मिलियन अमरीकी डॉलर	439712	542013	541660	545038	542021	545638	551505
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	2898265	3644856	3658364	3683211	3679789	3679213	3721726
	मिलियन अमरीकी डॉलर	407880	498362	497521	501464	499941	503046	508783
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	190277	274417	279568	274993	264971	266852	267715
	मिलियन अमरीकी डॉलर	26778	37521	38020	37440	35999	36486	36598
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1046	1048	1048	1048	1048	1048	1048
	करोड ₹	10169	10841	10895	10889	10836	10794	10826
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1431	1482	1482	1483	1472	1476	1480
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	25731	34083	34066	34090	33972	33982	34000
	मिलियन अमरीकी डॉलर	3623	4647	4637	4651	4608	4631	4644

* अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2019-20	2019	2020		2019-20	2020-21
		अग.	जुला.	अग.	अप्रै.-अग.	अप्रै.-अग.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130581	130515	135097	137812	4043	4864
1.1 एफसीएनआर (बी)	24244	23895	22471	22473	725	-1771
1.2 एनआर (ई) आरए	90367	91136	96076	98436	2496	6042
1.3 एनआरओ	15969	15483	16550	16904	822	592

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019-20	2020-21	2019	2020	
		अप्रै.-सितं.	अप्रै.-सितं.	सितं.	अग.	सितं.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43013	21307	22859	1981	17689	2412
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	56006	27587	27740	2950	18371	3288
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	74390	36046	39929	4444	19150	4314
1.1.1.1.1 इक्विटी	51734	26778	30781	2856	17602	3021
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	3265	2864	172	55	64	2
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	39364	20108	26887	2150	17314	2373
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7348	3124	2945	536	109	531
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1757	682	778	116	116	116
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	14175	6813	7420	1155	1155	1155
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	8482	2455	1727	433	393	138
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18384	8459	12189	1494	779	1026
1.1.1.2.1 इक्विटी	18212	8403	12174	1482	777	1024
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	173	56	15	12	2	2
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12993	6280	4881	968	683	876
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	7572	3296	2201	486	283	419
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3151	1575	1583	263	263	263
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5674	2568	2225	478	197	1028
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3403	1159	1128	258	60	834
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	1403	7319	7909	2383	6769	-748
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	552	7161	8122	2225	6737	-332
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	-851	-158	212	-157	-32	416
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	44417	28626	30768	4364	24458	1664

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019	2020		
		सितं.	जुला.	अग.	सितं.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	18760.69	1592.36	995.16	1156.62	1648.17
1.1 जमाराशियां	623.37	46.86	48.43	46.55	123.46
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	86.43	7.40	5.03	5.85	8.26
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	431.41	34.74	33.84	27.37	73.61
1.4 उपहार	1907.71	129.29	129.75	124.99	225.36
1.5 दान	22.33	1.55	1.42	0.68	0.61
1.6 यात्रा	6955.98	642.88	246.17	303.21	358.12
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3439.74	242.83	243.61	232.86	416.70
1.8 चिकित्सा उपचार	33.90	2.24	2.54	1.65	2.51
1.9 विदेश में शिक्षा	4991.07	467.23	277.50	405.48	427.87
1.10 अन्य	268.75	17.36	6.87	7.98	11.68

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2018-19	2019-20	2019	2020	
			अक्तूबर	सितंबर	अक्तूबर
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	72.64	73.28	73.35	70.81	70.69
1.2 रीर	114.01	116.75	117.29	118.33	118.13
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	74.18	74.33	74.32	71.92	71.89
2.2 रीर	116.32	119.61	120.10	121.95	121.92
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	63.07	63.59	63.90	59.76	59.58
1.2 रीर	121.70	125.76	126.70	125.92	124.84
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	92.88	93.63	94.10	88.01	87.74
2.2 रीर	94.20	97.32	98.07	97.47	96.64

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2019-20	2019	2020	
		सितं.	अग.	सितं.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1292	118	97	99
1.2 राशि	38011	4139	1715	5223
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	41	1	1	-
2.2 राशि	14921	750	36	-
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1333	119	98	99
3.2 राशि	52932	4889	1751	5223
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.00	6.10	4.92	3.32
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.17	1.86	1.66
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-25.00	0.00-11.30	0.00-9.03	0.00-11.00

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अप्रैल-जून 2019			अप्रैल-जून 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	299344	285360	13984	249201	229355	19846
1 चालू खाता (1.1+1.2)	160681	175686	-15004	122408	102634	19774
1.1 पण्य	82707	129481	-46774	52308	62326	-10017
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	77974	46204	31769	70100	40309	29791
1.2.1 सेवाएं	52196	32120	20075	46807	26304	20503
1.2.1.1 यात्रा	6950	6203	747	1848	2757	-909
1.2.1.2 परिवहन	5343	6104	-761	4866	4216	649
1.2.1.3 बीमा	588	409	179	565	378	186
1.2.1.4 जीएनआईई	151	307	-155	148	330	-182
1.2.1.5 विविध	39164	19098	20066	39380	18622	20758
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	22811	1812	20998	22622	1849	20773
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11475	11715	-239	11282	11514	-232
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1287	519	769	1009	1062	-52
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	700	284	415	707	304	403
1.2.2 अंतरण	19963	1999	17964	18223	1237	16986
1.2.2.1 आधिकारिक	35	295	-260	27	258	-231
1.2.2.2 निजी	19928	1705	18224	18196	979	17217
1.2.3 आय	5815	12085	-6270	5070	12768	-7698
1.2.3.1 निवेश आय	4463	11446	-6983	3706	12098	-8392
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1352	639	713	1364	669	695
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	138298	109674	28624	126793	126241	552
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	88733	69898	18835	74487	74237	250
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	21555	7563	13993	11973	12365	-392
2.1.1.1 भारत में	21171	3976	17194	11829	9735	2094
2.1.1.1.1 इक्विटी	16665	3957	12708	6993	9725	-2732
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3349		3349	3957		3957
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1157	19	1138	879	10	869
2.1.1.2 विदेश में	384	3586	-3202	144	2630	-2486
2.1.1.2.1 इक्विटी	384	1592	-1208	144	1117	-972
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	788	-788	0	796	-796
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1206	-1206	0	718	-718
2.1.2 संविभाग निवेश	67178	62335	4843	62514	61872	642
2.1.2.1 भारत में	67073	61916	5156	61869	60772	1098
2.1.2.1.1 एफआईआई	67073	61916	5156	61869	60772	1098
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	50491	47378	3112	52749	48334	4414
2.1.2.1.1.2 ऋण	16582	14538	2044	9121	12437	-3317
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	105	419	-314	644	1100	-456
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	22209	12648	9561	18508	16227	2281
2.2.1 बाह्य सहायता	3018	1550	1468	5735	1645	4090
2.2.1.1 भारत द्वारा	2	29	-27	2	27	-26
2.2.1.2 भारत को	3016	1521	1495	5733	1618	4116
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	9763	3660	6103	3756	5369	-1613
2.2.2.1 भारत द्वारा	881	742	140	442	1003	-562
2.2.2.2 भारत को	8881	2918	5963	3315	4366	-1051
2.2.3 भारत को अल्पावधि	9428	7438	1990	9017	9213	-196
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	8028	7438	590	9017	8412	605
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1400	0	1400	0	801	-801
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	17713	14280	3433	17690	15460	2230
2.3.1 वाणिज्य बैंक	17713	13897	3816	17690	14693	2997
2.3.1.1 आस्तियां	6339	3595	2744	6865	4383	2482
2.3.1.2 देयताएं	11375	10302	1072	10825	10310	515
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	10780	8026	2754	10653	7653	3000
2.3.2 अन्य	0	383	-383	0	767	-767
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	60	-60	0	55	-55
2.5 अन्य पूंजी	9643	12789	-3146	16108	20261	-4153
3 भूल-चूक	365	0	365	0	480	-480
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	13984	-13984	0	19846	-19846
4.1 आईएमएफ				0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		13984	-13984		19846	-19846

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अप्रैल-जून 2019			अप्रैल-जून 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2081832	1984578	97254	1890800	1740218	150582
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1117480	1221831	-104351	928766	778731	150034
1.1 पण्य	575199	900495	-325296	396887	472892	-76006
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	542281	321335	220945	531879	305839	226040
1.2.1 सेवाएं	363004	223387	139617	355144	199578	155566
1.2.1.1 यात्रा	48335	43139	5196	14024	20918	-6894
1.2.1.2 परिवहन	37157	42451	-5294	36918	31992	4926
1.2.1.3 बीमा	4088	2846	1242	4286	2872	1415
1.2.1.4 जीएनआईई	1052	2133	-1081	1123	2504	-1381
1.2.1.5 विविध	272372	132817	139554	298793	141293	157500
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	158639	12604	146036	171642	14027	157615
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	79808	81470	-1663	85604	87365	-1761
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	8953	3608	5346	7659	8056	-396
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4865	1976	2889	5364	2309	3055
1.2.2 अंतरण	138837	13904	124933	138268	9387	128881
1.2.2.1 आधिकारिक	242	2048	-1806	205	1959	-1754
1.2.2.2 निजी	138595	11855	126740	138063	7428	130635
1.2.3 आय	40440	84045	-43605	38467	96874	-58407
1.2.3.1 निवेश आय	31039	79602	-48563	28120	91796	-63677
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9401	4443	4958	10347	5077	5270
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	961814	762747	199067	962034	957847	4187
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	617107	486115	130992	565164	563268	1895
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	149908	52595	97313	90846	93819	-2973
2.1.1.1 भारत में	147234	27655	119579	89752	73864	15889
2.1.1.1.1 इक्विटी	115899	27522	88377	53061	73787	-20726
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	23291	0	23291	30021	0	30021
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	8045	133	7911	6671	77	6594
2.1.1.2 विदेश में	2673	24939	-22266	1094	19955	-18862
2.1.1.2.1 इक्विटी	2673	11075	-8402	1094	8472	-7378
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5478	-5478	0	6038	-6038
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	8386	-8386	0	5446	-5446
2.1.2 संविभाग निवेश	467199	433520	33679	474318	469449	4869
2.1.2.1 भारत में	466467	430607	35860	469430	461102	8328
2.1.2.1.1 एफआईआई	466467	430607	35860	469430	461102	8328
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	351144	329501	21644	400227	366734	33493
2.1.2.1.1.2 ऋण	115323	101107	14216	69203	94368	-25165
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	732	2913	-2181	4888	8347	-3459
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	154456	87960	66495	140429	123124	17305
2.2.1 बाह्य सहायता	20988	10780	10208	43513	12481	31031
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	12	208	-197
2.2.1.2 भारत को	20974	10579	10395	43501	12273	31228
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	67896	25451	42446	28501	40739	-12238
2.2.2.1 भारत द्वारा	6131	5157	974	3350	7612	-4262
2.2.2.2 भारत को	61766	20294	41472	25151	33127	-7976
2.2.3 भारत को अल्पावधि	65571	51730	13841	68416	69904	-1488
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	55835	51730	4105	68416	63825	4591
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	9737	0	9737	0	6079	-6079
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	123189	99311	23878	134220	117303	16917
2.3.1 वाणिज्य बैंक	123189	96648	26540	134220	111481	22739
2.3.1.1 आस्तियां	44083	25000	19082	52088	33257	18831
2.3.1.2 देयताएं	79106	71648	7458	82132	78223	3908
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	74973	55820	19153	80826	58063	22763
2.3.2 अन्य	0	2662	-2662	0	5823	-5823
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	418	-418	0	419	-419
2.5 अन्य पूंजी	67063	88944	-21881	122221	153732	-31511
3 भूल-चूक	2538	0	2538	0	3640	-3640
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	97254	-97254	0	150582	-150582
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	97254	-97254	0	150582	-150582

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अप्रैल-जून 2019			अप्रैल-जून 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	160681	175657	-14977	122408	102610	19798
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	134903	161602	-26699	99115	88629	10486
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	82707	129481	-46774	52308	62326	-10017
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	82183	118031	-35848	52172	61638	-9466
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	524	0	524	137	0	137
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		11450	-11450	0	688	-688
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	52196	32120	20075	46807	26304	20503
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	33	18	14	77	6	71
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	45	413	-368	32	128	-97
1.अ.ख.3 परिवहन	5343	6104	-761	4866	4216	649
1.अ.ख.4 यात्रा	6950	6203	747	1848	2757	-909
1.अ.ख.5 निर्माण	754	754	0	659	625	34
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	588	409	179	565	378	186
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1287	519	769	1009	1062	-52
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	319	2091	-1771	399	1847	-1448
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	23604	2207	21397	23395	2269	21126
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11475	11715	-239	11282	11514	-232
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	532	631	-99	500	347	153
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	151	307	-155	148	330	-182
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1114	750	364	2026	823	1203
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5815	12085	-6270	5070	12768	-7698
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1352	639	713	1364	669	695
1.आ.2 निवेश आय	3247	11246	-7999	3096	11916	-8820
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1607	4790	-3183	1349	7410	-6061
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	46	2503	-2457	24	1222	-1198
1.आ.2.3 अन्य निवेश	163	3938	-3774	66	3280	-3214
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1431	15	1415	1657	4	1653
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1216	200	1016	610	182	428
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	19963	1971	17992	18223	1212	17010
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	19928	1705	18224	18196	979	17217
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	19303	1217	18086	17596	739	16857
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	625	487	138	600	240	360
1.इ.2 सामान्य सरकार	34	266	-232	26	234	-207
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	87	909	-822	91	871	-780
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	11	824	-813	5	790	-786
2.2 पूंजी अंतरण	76	85	-9	86	81	5
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	138212	122778	15434	126703	145241	-18538
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	21555	7563	13993	11973	12365	-392
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	21171	3976	17194	11829	9735	2094
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	20014	3957	16057	10950	9725	1225
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	16665	3957	12708	6993	9725	-2732
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3349		3349	3957	0	3957
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1157	19	1138	879	10	869
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1157	19	1138	879	10	869
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	384	3586	-3202	144	2630	-2486
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	384	2380	-1996	144	1912	-1768
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	384	1592	-1208	144	1117	-972
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		788	-788	0	796	-796
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1206	-1206	0	718	-718
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1206	-1206	0	718	-718
3.2 संविभाग निवेश	67178	62335	4843	62514	61872	642
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	67073	61916	5156	61869	60772	1098
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	50491	47378	3112	52749	48334	4414
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	16582	14538	2044	9121	12437	-3317
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	105	419	-314	644	1100	-456
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	6703	5182	1521	11241	11303	-63
3.4 अन्य निवेश	42776	33714	9061	40975	39854	1121
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	10780	8409	2371	10653	8420	2233
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	383	-383	0	767	-767
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	10780	8026	2754	10653	7653	3000
3.4.2.3 सामान्य सरकार				0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र				0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	19714	11080	8633	16528	14054	2474
3.4.3अ भारत को ऋण	18830	10310	8520	16085	13024	3061
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	884	770	113	443	1031	-588
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	46	176	-131	40	47	-7
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	9428	7438	1990	9017	9213	-196
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	2808	6611	-3803	4737	8119	-3382
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	13984	-13984	0	19846	-19846
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण				0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए				0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए				0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	13984	-13984	0	19846	-19846
4. कुल आस्तियां / देयताएं	138212	122778	15434	126703	145241	-18538
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	77743	59493	18250	75768	72422	3346
4.2 ऋण लिखत	57661	42691	14971	46198	44853	1345
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	2808	20594	-17787	4737	27966	-23228
5. निवल भूल-चूक	365		365	0	480	-480

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	अप्रैल-जून 2019			अप्रैल-जून 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1117477	1221634	-104157	928760	778544	150216
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	938203	1123882	-185679	752031	672471	79560
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	575199	900495	-325296	396887	472892	-76006
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	571553	820866	-249314	395848	467673	-71825
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	3646	0	3646	1038	0	1038
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	79629	-79629	0	5219	-5219
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	363004	223387	139617	355144	199578	155566
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिवल वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	227	127	100	588	45	542
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	312	2872	-2560	241	975	-733
1.अ.ख.3 परिवहन	37157	42451	-5294	36918	31992	4926
1.अ.ख.4 यात्रा	48335	43139	5196	14024	20918	-6894
1.अ.ख.5 निर्माण	5245	5244	1	5003	4743	260
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4088	2846	1242	4286	2872	1415
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	8953	3608	5346	7659	8056	-396
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2221	14539	-12318	3026	14016	-10990
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	164158	15349	148809	177507	17215	160292
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	79808	81470	-1663	85604	87365	-1761
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3700	4390	-690	3792	2632	1160
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1052	2133	-1081	1123	2504	-1381
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	7747	5217	2529	15373	6247	9126
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	40440	84045	-43605	38467	96874	-58407
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9401	4443	4958	10347	5077	5270
1.आ.2 निवेश आय	22585	78213	-55628	23494	90414	-66921
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	11179	33314	-22134	10234	56223	-45989
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	321	17407	-17086	185	9273	-9088
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1136	27386	-26250	500	24885	-24385
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	9949	107	9842	12574	34	12540
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	8454	1389	7065	4626	1382	3244
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	138835	13707	125128	138262	9200	129063
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	138595	11855	126740	138063	7428	130635
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	134248	8465	125782	133511	5606	127905
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4347	3390	957	4553	1822	2731
1.इ.2 सामान्य सरकार	239	1852	-1612	199	1772	-1573
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	603	6322	-5719	690	6611	-5921
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	76	5731	-5655	34	5996	-5961
2.2 पूँजी अंतरण	527	591	-64	656	615	41
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	961214	853875	107338	961350	1102005	-140655
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	149908	52595	97313	90846	93819	-2973
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	147234	27655	119579	89752	73864	15889
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	139190	27522	111668	83082	73787	9295
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	115899	27522	88377	53061	73787	-20726
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	23291	0	23291	30021	0	30021
3.1.अ.2 ऋण लिखत	8045	133	7911	6671	77	6594
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	8045	133	7911	6671	77	6594
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	2673	24939	-22266	1094	19955	-18862
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	2673	16553	-13880	1094	14510	-13416
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	2673	11075	-8402	1094	8472	-7378
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5478	-5478	0	6038	-6038
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	8386	-8386	0	5446	-5446
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	8386	-8386	0	5446	-5446
3.2 संविभाग निवेश	467199	433520	33679	474318	469449	4869
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	466467	430607	35860	469430	461102	8328
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	351144	329501	21644	400227	366734	33493
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	115323	101107	14216	69203	94368	-25165
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	732	2913	-2181	4888	8347	-3459
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	46618	36037	10581	85289	85765	-476
3.4 अन्य निवेश	297489	234470	63019	310898	302390	8507
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	74973	58482	16490	80826	63886	16940
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	2662	-2662	0	5823	-5823
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	74973	55820	19153	80826	58063	22763
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	137100	77059	60042	125407	106637	18770
3.4.3.अ भारत को ऋण	130956	71701	59255	122045	98817	23228
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	6145	5358	787	3361	7820	-4459
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	318	1226	-908	306	358	-53
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	65571	51730	13841	68416	69904	-1488
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	19527	45974	-26447	35943	61605	-25662
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	97254	-97254	0	150582	-150582
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	97254	-97254	0	150582	-150582
4. कुल आस्तियां / देयताएं	961214	853875	107338	961350	1102005	-140655
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	540675	413751	126924	574885	549501	25384
4.2 ऋण लिखत	401012	296897	104115	350523	340318	10205
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	19527	143227	-123700	35943	212187	-176244
5. निवल भूल-चूक	2538	0	2538	0	3640	-3640

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2019-20		2019		2020			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	182957	418239	173165	417609	182957	418239	185442	419312
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	118442	395426	113118	399712	118442	395426	120210	395918
1.2 अन्य पूंजी	64515	22813	60047	17897	64515	22813	65233	23394
2 संविभाग निवेश	3847	246701	5012	266822	3847	246701	4303	241581
2.1 इक्विटी	602	134778	1806	151162	602	134778	824	138961
2.2 ऋण	3246	111923	3206	115660	3246	111923	3480	102621
3 अन्य निवेश	52422	427438	54140	429324	52422	427438	52489	432702
3.1 व्यापार ऋण	1460	104277	2121	107226	1460	104277	1233	103988
3.2 ऋण	6741	179767	9762	173725	6741	179767	7435	184385
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	26011	130761	24169	133846	26011	130761	27741	132942
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18210	12634	18089	14529	18210	12634	16080	11387
4 रिज़र्व्स	477807		429837		477807		505702	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	717033	1092378	662155	1113756	717033	1092378	747937	1093595
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-375345		-451601		-375345		-345658

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2019-20	2019	2020		विव 2019-20	2019	2020	
		सितं.	अग.	सितं.		सितं.	अग.	सितं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	-	-	2.28	2.70	-	-	12576300	13397758
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	-	-	0.96	1.08	-	-	8614891	9021412
1.1.1 आउटराइट	-	-	0.52	0.61	-	-	867395	881023
1.1.2 रेपो	-	-	0.27	0.29	-	-	3793333	4115039
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	-	-	0.18	0.19	-	-	3954162	4025350
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	-	-	1.28	1.60	-	-	3749569	4238877
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	-	-	0.03	0.03	-	-	211840	137470
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	-	-	116.77	130.11	-	-	7292380	9489066
1.1 ग्राहक लेनदेन	-	-	115.29	128.49	-	-	6382552	7993814
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	-	-	1.49	1.61	-	-	909828	1495252
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)	-	-	23968.09	25506.62	-	-	2556825	2817678
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	-	-	0.89	0.96	-	-	46	51
2.2 एपीबीएस \$	-	-	1196.39	1059.85	-	-	8313	6243
2.3 आईएमपीएस	-	-	2461.25	2796.08	-	-	235137	248662
2.4 एनएसीएच जमा \$	-	-	1775.18	1179.79	-	-	84468	68176
2.5 एनईएफटी	-	-	2346.09	2468.27	-	-	1930552	2165515
2.6 यूपीआई @	-	-	16188.28	18001.67	-	-	298308	329032
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	-	-	0.92	0.89	-	-	15	14
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)	-	-	857.28	926.42	-	-	67146	78240
3.1 भीम आधार पे @	-	-	19.50	15.28	-	-	253	205
3.2 एनएसीएच नामे \$	-	-	791.81	857.43	-	-	66830	77958
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	-	-	45.96	53.71	-	-	63	77
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	-	-	4914.48	5110.11	-	-	122089	126220
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	-	-	1425.11	1486.71	-	-	50311	51134
4.1.1 पीओएस आधारित \$	-	-	659.47	713.37	-	-	21001	21986
4.1.2 अन्य \$	-	-	765.64	773.33	-	-	29310	29148
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	-	-	3489.38	3623.40	-	-	71778	75086
4.2.1 पीओएस आधारित \$	-	-	1647.47	1758.83	-	-	29525	30422
4.2.2 अन्य \$	-	-	1841.91	1864.57	-	-	42253	44664
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	-	-	4932.61	4625.96	-	-	16808	16683
5.1 वॉलेट	-	-	3967.82	3616.58	-	-	13000	13258
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	-	-	964.79	1009.37	-	-	3808	3425
5.2.1 पीओएस आधारित \$	-	-	29.20	32.50	-	-	737	910
5.2.2 अन्य \$	-	-	935.59	976.87	-	-	3072	2515
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	-	-	519.83	612.71	-	-	425462	485243
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	-	-	519.72	612.63	-	-	425252	485114
6.2 अन्य	-	-	0.11	0.08	-	-	210	128
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	-	-	35192.30	36781.81	-	-	3188330	3524064
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	-	-	35309.07	36911.91	-	-	10480709	13013130
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	-	-	34789.24	36299.21	-	-	10055248	12527887

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2019-20	2019	2020		वि. व. 2019-20	2019	2020	
		सितं.	अग.	सितं.		सितं.	अग.	सितं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	-	-	19521.47	20919.08	-	-	667279	704109
1.1 इंटर-बैंक \$	-	-	1682.30	1907.78	-	-	138564	145405
1.2 इंटर-बैंक \$	-	-	17839.17	19011.30	-	-	528715	558703
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	-	-	2651.34	2822.04	-	-	3006656	3436124
2.1 इंटर-बैंक @	-	-	557.18	594.83	-	-	1494618	1678942
2.2 इंटर-बैंक @	-	-	2094.17	2227.20	-	-	1512038	1757182
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	-	-	4884.50	5094.80	-	-	238675	243667
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	3.66	4.36	-	-	184	217
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	4860.29	5067.91	-	-	237778	242649
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	20.55	22.53	-	-	713	801
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	-	-	32.48	33.62	-	-	134	123
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	27.89	29.39	-	-	129	118
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	4.60	4.23	-	-	5	5
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	-	-	814.30	717.65	-	-	19513	17096
5.1 एईपीएस @	-	-	814.30	717.65	-	-	19513	17096

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	वि. व. 2019-20	2019		2020	
		सितं.	अग.	सितं.	अग.
	1	2	3	4	
भुगतान प्रणाली अवसंरचना					
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	-	-	9132.03	9241.29	
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	-	578.31	586.94	
1.2 डेबिट कार्ड	-	-	8553.73	8654.35	
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	-	-	20134.06	19960.47	
2.1 वॉलेट @	-	-	18482.49	18287.99	
2.2 कार्ड @	-	-	1651.58	1672.48	
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	-	-	2.33	2.34	
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	-	2.09	2.10	
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	-	0.24	0.24	
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	-	-	3.07	3.28	
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	-	-	51.07	51.86	
6 भारत क्यूआर @	-	-	22.99	23.96	
7 UPI QR *	-	-	-	604.07	

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

*: New inclusion w.e.f. September 2020; Includes only static UPI QR Code

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. ECS (Debit and Credit) has been merged with NACH with effect from January 31, 2020.

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2019		2020	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115714	9839	15814	15184	16911
	बकाया	918459	899191	1015010	1030037	1046766
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91108	7130	12117	11091	11460
	बकाया	618418	606920	693812	704903	716363
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	2360	3455	3106	2690
	बकाया	140247	134863	150462	153568	156258
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	-19	-31	-25	-20
	बकाया	3107	2877	2984	2959	2939
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	0	-827	-2	-3
	बकाया	10	-8	-18	-20	-23
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	928	1753	1712	1887
	बकाया	192658	191653	203460	205172	207059
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1184	2070	2133	2131
	बकाया	55708	54446	69464	71597	73728
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2451	4296	3999	4494
	बकाया	124292	121687	152622	156621	161115
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	70179	86344	88247	90327
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5824	6749	6854	6970
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6910	7328	7397	7464
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	38774	52201	54123	56354
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	215	1401	168	281
	बकाया	102401	101407	114842	115010	115291
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	11	0	0	0
	बकाया	-26	-26	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16067	1732	3326	3524	3937
	बकाया	221517	219257	240900	244267	248022
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	1262	2272	2458	2619
	बकाया	98492	94795	110050	112508	115127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	3	0	0	1
	बकाया	263	300	-289	-289	-288
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1609	-971	-1713	-1120
	बकाया	19303	21232	6782	5069	3949
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	2065	2025	2782	2452
	बकाया	93630	91314	113273	116055	118507
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	12	0	-1	0
	बकाया	2	-47	-179	-180	-180
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	-1	0	-2	-15
	बकाया	-80	-82	-82	-84	-99
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11745	11345	11188	11006
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8539	977	371	569	1514
	बकाया	78524	73014	80298	80867	82381

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2019			2020	
	जून 1	सित्त. 2	दिस. 3	मार्च 4	जून 5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	6072243	6314426	6512659	6486585	6704983
1. वाणिज्य बैंक	39.05	39.66	39.05	40.41	38.98
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.36	0.42	0.39	0.39	0.36
3. बीमाकृत कंपनियां	24.88	24.86	24.90	25.09	26.24
4. म्यूच्युअल फंड	0.64	0.77	1.53	1.43	2.02
5. सहकारी बैंक	2.17	2.01	1.97	1.90	1.86
6. वित्तीय संस्थाएं	1.05	1.15	1.14	0.53	1.19
7. कॉरपोरेट	0.99	0.92	0.84	0.81	0.78
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.27	3.31	3.33	2.44	1.79
9. भविष्य निधियां	5.35	4.87	4.93	4.72	4.96
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.67	14.99	14.72	15.13	14.70
11. अन्य	6.57	7.05	7.23	7.17	7.11
11.1 राज्य सरकार	2.02	1.99	1.97	2.05	1.99

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2019			2020	
	जून 1	सित्त. 2	दिस. 3	मार्च 4	जून 5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	2826935	2905169	3047353	3265990	3393099
1. वाणिज्य बैंक	32.57	32.53	32.46	34.99	33.54
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.81	0.72	0.64	0.76	0.74
3. बीमाकृत कंपनियां	33.94	33.39	32.50	31.63	30.85
4. म्यूच्युअल फंड	1.24	1.12	1.20	1.14	1.74
5. सहकारी बैंक	4.65	4.24	4.16	4.12	4.38
6. वित्तीय संस्थाएं	0.44	0.33	0.31	0.11	1.96
7. कॉरपोरेट	0.32	0.28	0.31	0.30	0.31
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.08	0.05	0.04	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	21.88	22.36	23.66	22.22	21.70
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	4.08	4.98	4.73	4.71	4.78
11.1 राज्य सरकार	0.14	0.16	0.17	0.18	0.18

श्रेणी	खजाना बिल				
	2019			2020	
	जून 1	सित्त. 2	दिस. 3	मार्च 4	जून 5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	524618	538041	514588	538409	881362
1. वाणिज्य बैंक	53.60	50.81	45.19	61.06	46.11
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.85	1.92	2.07	2.26	1.48
3. बीमाकृत कंपनियां	5.13	5.55	5.76	7.45	4.64
4. म्यूच्युअल फंड	13.00	14.08	20.42	13.24	23.45
5. सहकारी बैंक	2.54	2.55	2.07	2.55	1.95
6. वित्तीय संस्थाएं	2.14	1.82	2.12	0.58	1.67
7. कॉरपोरेट	1.67	1.57	1.66	1.89	1.43
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.07	0.01	0.01	0.02	0.05
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
11. अन्य	19.99	21.70	20.70	10.95	7.95
11.1 राज्य सरकार	15.59	17.91	16.36	6.22	4.35

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	3760611	4265969	4515946	5040747	5875914	6470254
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
2. कुल प्राप्तियां	3778049	4288432	4528422	5023352	5779396	6524526
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	952410	1064704	997097	1102729	1408183	1409995
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2020 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1182	30	1939	29	1520	17
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	118	28	110	20	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	304	6	418	4	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	531	29	114	5
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1212	30	406	18
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	250	29	1137	29	358	9
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	6540	21	-	-	-	-
16	मणिपुर	52	28	153	19	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	44	17	-	-
19	नगालैंड	277	30	312	30	126	19
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	440	21	413	15	-	-
23	राजस्थान	1167	26	704	7	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	1240	30	1576	30	698	21
26	त्रिपुरा	51	5	10	1	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	429	30	262	19	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8356	821	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1487	2	--	-
3	असम	4498	55	--	-
4	बिहार	7026	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4462	--	1	4750
6	गोवा	600	302	--	-
7	गुजरात	10357	483	--	-
8	हरियाणा	2099	1211	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	89	--	--	-
12	कर्नाटक	4267	--	--	18500
13	केरल	2166	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	925	--	-
15	महाराष्ट्र	41466	430	--	15000
16	मणिपुर	381	101	--	-
17	मेघालय	--	36	9	-
18	मिज़ोरम	466	39	--	-
19	नगालैंड	1656	33	--	-
20	उड़ीसा	13501	1465	85	20485
21	पुदुचेरी	296	--	--	807
22	पंजाब	700	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6679	--	40	14678
25	तेलंगाना	5704	1243	--	-
26	त्रिपुरा	374	9	--	-
27	उत्तराखंड	473	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3189	80	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9770	539	214	-
	कुल	130062	7776	665	76220

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21						2020-21 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	जुलाई		अगस्त		सितंबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	30200	23824	42415	33444	5000	4417	5250	4667	7000	6417	31250	27168
2	अरुणाचल प्रदेश	719	693	1366	1287	-	-	-	-	-	-	428	428
3	असम	10595	8089	12906	10996	500	500	-	-	2300	2300	3300	3300
4	बिहार	14300	10903	25601	22601	4000	4000	4000	4000	4000	4000	12000	11000
5	छत्तीसगढ़	12900	12900	11680	10980	-	-	1300	1300	700	700	2000	2000
6	गोवा	2350	1850	2600	2000	200	200	200	200	400	400	1500	1400
7	गुजरात	36971	27437	38900	28600	2700	1950	5000	4000	5500	4500	19780	15823
8	हरियाणा	21265	17970	24677	20677	2000	2000	3000	3000	4500	4500	18500	16700
9	हिमाचल प्रदेश	4210	2108	6580	4460	500	500	-	-	-	-	500	-300
10	जम्मू और कश्मीर	6684	4927	7869	6760	800	300	800	300	1405	1405	4705	3205
11	झारखंड	5509	4023	7500	5656	-	-	-	-	-	-	-	-500
12	कर्नाटक	39600	32183	48500	42500	5000	5000	7000	7000	10000	10000	29000	29000
13	केरल	19500	13984	18073	12617	1500	1500	1000	1000	2000	2000	15930	15930
14	मध्य प्रदेश	20496	15001	22371	16550	2000	2000	2000	2000	2000	2000	11000	11000
15	महाराष्ट्र	20869	3107	48498	32998	8000	7000	3000	2154	14000	12000	48500	43777
16	मणिपुर	970	667	1757	1254	150	150	100	100	-	-	700	700
17	मेघालय	1122	863	1344	1070	200	200	-	-	600	550	800	750
18	मिज़ोरम	0	-123	900	745	150	150	-	-	132	132	442	342
19	नगालैंड	822	355	1000	423	150	150	-	-	150	150	500	400
20	उड़ीसा	5500	4500	7500	6500	-	-	-	-	-	-	3000	3000
21	पुदुचेरी	825	475	970	470	-	-	-	-	225	225	225	225
22	पंजाब	22115	17053	27355	18470	1250	1250	2250	1750	4410	3010	12110	9410
23	राजस्थान	33178	20186	39092	24686	6000	5000	3450	2950	3500	3500	27450	22138
24	सिक्किम	1088	795	809	481	-	-	-	-	148	148	615	615
25	तमिलनाडु	43125	32278	62425	49826	10000	8131	9250	7375	3250	2000	48000	42069
26	तेलंगाना	26740	22183	37109	30697	3000	2583	3000	2583	4500	4083	22961	20044
27	त्रिपुरा	1543	1387	2928	2578	-	-	-	-	400	400	400	300
28	उत्तराखंड	46000	33307	69703	52744	1000	-	1000	-200	6000	4000	13500	3267
29	उत्तरप्रदेश	6300	5289	5100	4500	-	-200	-	-	1500	1500	2500	1800
30	पश्चिम बंगाल	42828	30431	56992	40882	5500	4500	4000	3500	4500	3000	22000	14000
	कुल	478323	348643	634521	487454	59600	51281	55600	47679	83120	72920	353596	298989

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम्₂ और एनएम्₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओ/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रेडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

○ बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

○ जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

This data may vary from previous publications due to adjustments across components with availability of new data.

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

--: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2020	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2018-19	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2019-20 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1 और 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेय, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।